आरआईएस
वार्षिक रिपोर्ट
2020–21

RIS
Research and Information System
for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

विषय वस्तु

अध्यक्ष का संदेश v

महानिदेशक की रिपोर्ट..vii

1. वैश्विक आर्थिक पद्धति एवं सहयोगः जी20 1

2. विकास सहयोग..15

3. ब्रिक्स... 39

4. इब्सा.. 43

5. व्यापार 47

6. वित्त.. 55

7. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) 63

8. स्वास्थ्य...79

9. नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनमी)............................ 85

10. ऊर्जा.. 91

11. वैश्विक विकास केंद्र (जीडीसी)............................ 95

12. आसियान–भारत.. 99

13. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम 107

14. अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद 109

15. सूचना एवं आंकड़ा केन्द्र....................................123

16. मानव संसाधन 127

17. वित्तीय विवरण.. 129

संचालन परिषद

अध्यक्ष

डॉ. मोहन कुमार

पदेन सदस्य

श्री हर्षवर्धन श्रिन्गला
विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
(29 जनवरी, 2020 से)

श्री तरुण बजाज
सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
(अप्रैल, 2021 तक)

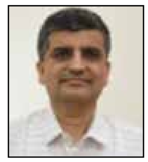

श्री अजय सेठ
सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
(अप्रैल, 2021 से)

प्रोफेसर आशुतोष शर्मा
सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय *(अप्रैल, 2021 तक)*

डॉ रेनू स्वरुप
सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय *(अप्रैल, 2021 से)*

डॉ. अनूप वधावन
वाणिज्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(जून, 2021 तक)

श्री बी.वी.आर. सुब्रमनयम
वाणिज्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(जून, 2021 से)

श्री राहुल छाबड़ा
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय
(जुलाई, 2021 तक)

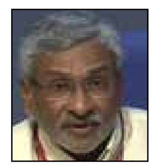

श्री दामु रवि
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय
(जुलाई, 2021 से)

अपदेन सदस्य

श्री शेषाद्री चारी
अध्यक्ष, चाईना स्टडी सेन्टर, माहे, मनीपाल

श्री जयंत दासगुप्ता
डब्ल्यूटीओ में भारत के पूर्व राजदूत

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
पुर्व उप गर्वनर, आरबीआई

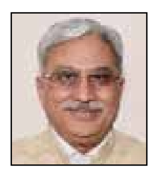

डॉ शैलेश नायक
निदेशक, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज

सदस्य सचिव (पदेन)

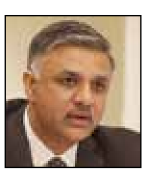

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

अनुसंधान सलाहकार परिषद

अध्यक्ष

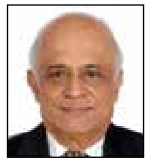

श्री एस. टी. देवरे
पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय

सदस्य

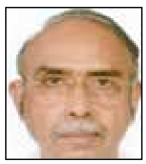

प्रोफेसर एन. एस. सिद्धार्थन
मानद प्राध्यापक, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स

प्रोफेसर पुलिन बी. नायक
भूतपूर्व निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स

सुश्री सिंधुश्री खुल्लर
भूतपूर्व सीईओ, नीति आयोग

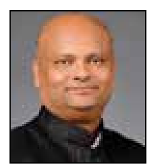

श्री अनुपम रे
सह सचिव (पी पी एण्ड आर)
विदेश मंत्रालय

विशेष आमंत्रित सदस्य

डॉ नागेश कुमार
प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र एस्कैंप के दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय (संयुक्त राष्ट्र एस्कैप–एसएसडब्ल्यूए), नई दिल्ली

सदस्य सचिव

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

राजदूत डॉ मोहन कुमार

अध्यक्ष का संदेश

2020 यदि वह साल था, जिसमें वास्तव में कोविड का प्रकोप हुआ, तो 2021 वह वर्ष था जिसमें सभी संबंधित परिणामों के साथ इसका पूर्ण प्रभाव महसूस किया गया। हर तरह से, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि इतिहास में हाल के दिनों की सबसे चुनौतीपूर्ण में से एक के रूप में दर्ज होगी।

आरआईएस जैसे नीतिगत थिंक–टैंक कोविड के प्रभाव से बच नहीं सकते थे। लेकिन वे जो कर सकते थे वह यह कि वे मुकाबला करने के अभिनव और रचनात्मक तरीके ढूंढ सकते हैं। और मुझे यह बताते हुए विशेष रूप से गर्व हो रहा है कि आरआईएस ने ऐसा किया भी और ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में बेहतर परिणाम देने में सफल भी रहे। महानिदेशक की रिपोर्ट और उसके बाद आने वाली वार्षिक रिपोर्ट, दोनों ही इस बात की गवाही देते हैं।

यह अवधि गहन लॉकडाउन के साथ शुरू हुई, जिसमें किसी भी तरह के शारीरिक संपर्क पर रोक थी। धीरे–धीरे, लेकिन निश्चित तौर पर, हर किसी का "वेबिनार" के साथ परिचय हुआ। यह एक ऐसा शब्द था, जो तब तक शायद ही इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि, वेबिनार कभी भी वैयक्तिक रूप से होने वाली बैठकों का विकल्प नहीं हो सकता, परंतु आरआईएस ने जी–20, ब्रिक्स, ईबसा और आसियान और वैश्विक विकास केंद्र जैसे विषयों पर वेबिनार आयोजित करके इस संकट काल को एक अवसर में बदल दिया। कुछ मायनों में, दूर के स्थानों, जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इटली और साथ् ही, रूस, के विशेषज्ञों से जुड़ना आसान हो गया। धीरे–धीरे, वेबिनार की संख्या बढ़ती गई और पहले से कहीं अधिक पारस्परिक विचार–विमर्श हुए, और वह भी संकटों से भरे इस साल में।

आसियान इंडिया सेंटर (एआईसी) ने विदेश मंत्रालय को नीतिगत इनपुट प्रदान करना जारी रखा कि कैसे ऐक्ट ईस्ट नीति को सर्वोत्तम तरीके से लागू किया जाए। इसमें केंद्र के प्रमुख प्रोफेसर प्रबीर डे ने अहम भूमिका निभाई।

आरआईएस नीतिगत सलाह प्रदान करने के अपने कार्य को बहुत गंभीरता से लेता है। विगत में, आरआईएस ने नीति आयोग, आयुष मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और अपने मूल मंत्रालय – विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया है। इन सबका विवरण वार्षिक रिपोर्ट में देखा जा सकता है।

आरआईएस अपनी मूल क्षमता: दक्षिणीय सहयोग, कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय व्यापार और निवेश के साथ–साथ वैश्विक शासन को न भूला है, और न ही भूल सकता है। इसमें विज्ञान कूटनीति, दक्षिण एशियाई ऊर्जा समूह के साथ–साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विषयों को जोड़ा जा सकता है। यह गर्व की बात है कि आरआईएस ने आर्थिक, व्यापार, लोक नीति और शासन के मुद्दों पर देश में अग्रणी नीतिगत थिंक–टैंक में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। इसलिए, आरआईएस ने वर्षों से जो अनुसंधान किए हैं, उन्हें विश्वसनीयता और प्रामाणिकता दी जानी चाहिए।

एक नीतिगत थिंक–टैंक उसके संकाय और कर्मचारियों जैसे ही होता है। मैं इस अवसर पर इसके महानिदेशक और पेशेवरों की उनकी समर्पित टीम के निपुण नेतृत्व वाली आरआईएस टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं शासी परिषद और आम सभा का उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। और, अंत में, आरआईएस विदेश मंत्रालय का निरंतर अपना अमूल्य समर्थन देने के लिए ऋणी है।

मोहन कुमार

महानिदेशक की रिपोर्ट

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

वित्तीय वर्ष 2020–2021 तब शुरू हुआ जब अभूतपूर्व कोविड–19 स्वास्थ्य संकट पूरी तरह से दुनिया को जकड़ रहा था। लॉकडाउन ने सभी सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों को ठप कर दिया। महामारी से फैला अंधेरा हर तरफ अपना जाल फैला चुका था। ऐसे में, निराशाजनक स्थिति को देखते हुए और कोविड–19 संकट का साहसपूर्वक सामना करने का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रोत्साहित होकर, आरआईएस ने जल्द ही घर से काम करने की नई शैली को अपना लिया।

संस्थान ने कोविड–19 के कारण उत्पन्न असामान्य स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों पर विचार–विमर्श करने और संकट का सामूहिक रूप से सामना करने के लिए क्षेत्रीय, उप–क्षेत्रीय, बहुपक्षीय सहयोग पर एक नया आख्यान विकसित करने पर ऑनलाइन परामर्श के लिए भागीदार संस्थानों और दुनिया भर के विशेषज्ञों के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाना आरंभ किया। विभीषिका के परिणाम का विश्लेषण करने में संकाय सदस्यों ने भी कड़ी मेहनत की। आरआईएस ने डायरी के तीन विशेष अंक निकाले, जिनमें महामारी से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे वैश्विक साझेदारी, अंतर–राज्य प्रवासी, औषधि उद्योग, वित्तीय क्षेत्र में अनिश्चितता, दुनिया पर संक्रामक प्रभाव, डब्लयूएचओ की भूमिका, खाद्य और पोषण सुरक्षा, वैश्विक बहुपक्षवाद, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली, समग्र रूप से विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के अतिरिक्त "एक विश्व" की भावना में सहयोगात्मक प्रयास, जिससे 'सबके द्वारा सबका कल्याण' हो सके, आदि। वर्तमान आरआईएस वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 में कोविड–19 संकट के दौरान आरआईएस के कार्यक्रम का विवरण दिया गया है।

इसके अलावा, आरआईएस ने अपने कार्यों को बढ़ाया भी है। जी–20 विशिष्ट अनुसंधान में योगदान और विभिन्न हितधारकों और अन्य जुड़ाव समूहों के साथ इसके जुड़ाव का विस्तार हो रहा है। निम्नलिखित खंड विभिन्न क्षेत्रीय और बहुपक्षीय आर्थिक मुद्दों में आरआईएस की गहरी भागीदारी पर चर्चा करते हैं।

विकास सहयोग

आरआईएस अपने वैश्विक आर्थिक शासन और सहयोग कार्यक्रम के तहत अकादमिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में संलग्न है। इसने भारत के विकास सहयोग के लिए डेटा बेस विकसित करने, विकास सहयोग के विश्लेषण के लिए अर्थमितीय–आधारित तकनीक, दक्षिणीय सहयोग और त्रिकोणीय सहयोग, एसडीजी के एजेंडा के हिस्से के रूप में संधारणीय विकास को स्थानीय बनाने, संयुक्त राष्ट्र@75, कोविड–19 महामारी के दौरान विकास सहयोग, आदि पर अपने शोध को और आगे बढ़ाया है।

ब्रिक्स और ईबसा

वैश्विक आर्थिक शासन और सहयोग स्तंभ के तहत, आरआईएस ने विशिष्ट विशेषज्ञता विकसित की है और ब्रिक्स सहयोग पर इसका एक समर्पित कार्यक्रम तैयार है। आरआईएस ब्रिक्स शैक्षणिक संस्थानों, थिंक–टैंक और नागरिक समाज संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है; और अतीत में ब्रिक्स सिविल फोरम और ब्रिक्स अकादमिक फोरम की मेजबानी कर चुका है। आरआईएस ब्रिक्स पर विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य विभागों को नियमित रूप से नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2021 को चिह्नित करने के लिए ब्रिक्स सिविल फोरम 2021 और ब्रिक्स अकादमिक फोरम 2021 को आयोजित करने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय द्वारा एक बार फिर आरआईएस को सौंपी गई है। इस संबंध में तैयारी और

कार्यशालाएं शुरू कर दी गई हैं। प्रस्तावित ब्रिक्स आर्थिक सम्मेलन 2021 के लिए आरआईएस को वित्त मंत्रालय द्वारा उनके ज्ञान भागीदार के रूप में भी नामित किया गया है। इससे पहले भी आरआईएस ने ब्रिक्स आर्थिक मंच के लिए वित्त मंत्रालय के साथ भागीदारी की थी।

व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग स्तंभ के हिस्से के रूप में, आरआईएस ईबसा सहयोग के शुरुआती प्रतिपादकों और समर्थकों में से एक है। आरआईएस वर्तमान में ईबसा फैलोशिप कार्यक्रम की मेजबानी करता है जिसकी घोषणा 2016 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसके अलावा, आरआईएस आईबीएसए में भागीदार प्रबुद्ध मंडलों के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है, ईबसा अकादमिक फोरम की मेजबानी करता है और ईबसा मामलों पर विदेश मंत्रालय को नियमित रूप से नीतिगत इनपुट प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

आरआईएस में व्यापार के मुद्दों पर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तर पर चर्चा, शोध और विश्लेषण जारी है। संकाय ईरान, मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित क्षेत्रों में लगा हुआ है। भारत और चीन के बीच व्यापार को 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के संदर्भ में परखा जाता है। आरआईएस की प्रमुख रिपोर्टें – *'विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट'* और *'दक्षिण एशिया विकास सहयोग रिपोर्ट'* को लाने की तैयारी चल रही है। क्षेत्रीय स्तर पर, बिम्सटेक और अफ्रीका महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते Africa Continental Free Trade Agreement (एफसीएफटीए) पर अध्ययन चल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के संरचनात्मक सुधार, ई–कॉमर्स, व्यापार और पर्यावरण, विशेष और विभेदक उपचार, वैश्विक और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला और प्रतिस्पर्धा नीति के मुद्दों सहित व्यापार से संबंधित नए मुद्दों पर शोध किया जा रहा है।

वित्त से संबंधित मुद्दे

जैसा कि सर्वविदित है, दुनिया भर में वित्तीय क्षेत्र नए उत्पादों और सेवाओं, संबद्ध जोखिमों, व्यापार मॉडल और विनियमों के रूप में तेजी से विकसित हो रहे हैं। फिनटेक, डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो परिसंपत्तियां नए वित्तीय नवाचार हैं जो स्पष्ट रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए वित्तीय मध्यस्थता के पारंपरिक मॉडल से कुछ क्षेत्रों को अलग करने और इसे बहुत कम लागत पर और ग्राहकों की सुविधानुसार कुशलतापूर्वक पैकेज करने की बड़ी क्षमता प्रदान करते हैं। तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय क्षेत्र की यह नई लहर केंद्रीय बैंकों और मौद्रिक अधिकारियों द्वारा समान ध्यान देने की मांग करती है, विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आकस्मिक जोखिम और कमजोरियों का आकलन करने और आवश्यक नियामक परिवर्तन करने के लिए। वित्तीय क्षेत्र के बढ़ते और नवोन्मेषी क्षेत्रों पर फोकस होने के साथ–साथ कुछ पारंपरिक मुद्दे, जैसे अवसंरचना वित्त और विकास वित्त हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण हो गए हैं। अवसंरचना के वित्तपोषण और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण में अंतराल को पाटने में विकास वित्त संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका दुनिया के कई देशों में फिर से सामने आई है। इनमें से कुछ क्षेत्रों में अवसरों, जोखिमों और चुनौतियों की जांच करने के लिए, आरआईएस ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से वर्ष 2020–2021 में कई शोध अध्ययन और वेबिनार श्रृंखला शुरू की।

समान विकास के लिए एसटीआई का लाभ उठाना

इसी तरह, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आरआईएस की कार्य योजना सबसे स्फूर्त और वैविध्यपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक है, जो सार्वजनिक वस्तुओं की सेवा के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के अनुप्रयोगों पर केंद्रित है। आरआईएस की कार्य योजना मौजूदा और उभरती प्रौद्योगिकियों के सेट पर केंद्रित है और समकालीन विकासात्मक चुनौतियों की एक श्रृंखला को संबोधित करने की दिशा में उनके निर्माण, व्यावसायीकरण, प्रसार के लिए नीति मार्गों की खोज करता है। तीव्र तकनीकी परिवर्तन अक्सर अपने साथ कई प्रकार के लाभ और जोखिम लाता है, जिन्हें सुदृढ़ नीति निर्माण के लिए बेहतर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। एक समान विकास और तरक्की को बढ़ावा देने के लिए एसटीआई के

अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने हेतु एसटीआई की कार्य योजना परिवर्तनकारी विकास मार्गों को बढ़ावा देने की दिशा में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और तकनीक के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान कूटनीति और सतत् विकास लक्ष्यों पर कार्यक्रम के साथ मिलकर काम करता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र का महत्व

जब महामारी ने स्वास्थ्य से जुड़ी अभूतपूर्व चुनौतियां पेश कीं, आरआईएस के स्वास्थ्य कार्यक्रम ने और गति पकड़ी। इसमें स्वास्थ्य और कल्याण के व्यापक पहलुओं को शामिल किया गया है जो वर्तमान परिदृश्य में और नीति निर्माताओं से की जाने वाली अपील को देखते हुए सीधे तौर पर प्रासंगिक हैं। कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धी और इसमें सहयोग के एक एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। इसलिए, कार्यक्रम का फोकस औषधीय नीति, पारंपरिक चिकित्सा, स्वास्थ्य राजनेय, एसडीजी–3, सभी के लिए स्वास्थ्य और सबका कल्याण और भलाई की अवधारणाएं, सीमित नहीं है। टीम अन्य विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सीएसओ (सीएसओ) और नीति निर्माताओं के साथ परामर्श, सेमिनार/वेबिनार और सम्मेलनों के माध्यम से नियमित रूप से मिलकर काम कर रही है।

नीली अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयाम

नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा आज व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित कर रही है। ब्लू इकोनॉमी में पर्यावरण संधारणीयता के साथ उच्च आर्थिक विकास को लक्षित करने के लिए समुद्र और महासागरों से परे गतिविधियों, हितधारकों और नीतियों को शामिल किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बीई के योगदान का अनुमान लगाने के लिए कोई आम तौर पर सहमत वैश्विक ढांचा नहीं है, और आरआईएस वर्तमान में भारत और उसके पड़ोसी देशों में बीई के आकलन के लिए एक ढांचा विकसित करने पर काम कर रहा है। इसके अलावा, ब्लू ट्रेड, जो समुद्री व्यापार से अलग है, वैश्विक व्यापार साहित्य में एक नई अवधारणा के रूप में उभर रहा है। आरआईएस ने ब्लू ट्रेड के आकलन के लिए एक ढांचा विकसित किया है। भारत में, ब्लू ट्रेड जीडीपी और देश के समग्र व्यापार की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। बीई के एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में, विश्व व्यापार संगठन में मत्स्य सब्सिडी वार्ता भारत में छोटे और सीमांत मछुआरों और अन्य संसाधन–गरीब तटीय देशों के लिए मात्स्यिकी सब्सिडी को कम करने / समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। आरआईएस विश्व व्यापार संगठन में मत्स्य सब्सिडी वार्ता के मुद्दे का विश्लेषण कर रहा है। आरआईएस ने बीई के विभिन्न आयामों पर बहस को आगे बढ़ाने हेतु विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों / नीति निर्माताओं की धारणाओं को साझा करने के लिए ब्लू इकोनॉमी फोरम के रूप में एक मंच का गठन किया है।

ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना

चूंकि ऊर्जा सहयोग के मुद्दे ने अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है, आरआईएस ने भारत और उसके पड़ोसियों के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा पर दक्षिण एशिया समूह (सेज) का शुभारंभ किया। प्रख्यात विशेषज्ञों, व्यवसायियों/पेशेवरों और उद्योग प्रतिनिधियों के नेतृत्व में समूह नीतिगत रास्ते तलाश रहा है और भारत के पड़ोसी देशों के बीच बिजली पर परस्पर संपर्क निर्माण के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर रहा है। क्षेत्रीय बिजली व्यापार के पारस्परिक लाभ को स्वीकार करते हुए, सेज क्षेत्रीय सहयोग नेटवर्क भी बना रहा है और एक क्षेत्र–व्यापी बिजली व्यापार नेटवर्क बनाने के लिए प्रमुख हितधारकों के बीच संवाद की सुविधा प्रदान कर रहा है।

वैश्विक विकास केंद्र

भारतीय विकास के अनुभवों को दूसरे देशों तक ले जाने के लिए आरआईएस में (जीडीसी) की शुरुआत की गई है। यह भारत के स्वदेशी रूप से विकसित विकास सहयोग मानदंडों – जो वैश्विक दक्षिण में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और सार्वभौमिक लचीलापन और संधारणीयता को बढ़ावा देते हैं – के

माध्यम से भारत के कुछ विश्व स्तर पर प्रशंसित अनुभवों और प्रथाओं को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। जीडीसी विनिमयी अधिगम (क्रॉस–लर्निंग) और नवाचार को बढ़ाने के लिए भागीदार संस्थानों, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने वाली सरकारी एजेंसियों, प्रबुद्ध मंडलों (थिंक–टैंक) और सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ जुड़ने को प्रोत्साहित करता है।

आसियान–भारत साझेदारी को सुदृढ़ करना

आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) आसियान–भारत साझेदारी को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एआईसी आसियान देशों और भारत के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य सहयोग को मजबूत करना और उनके बीच संबंधों को पोषित करना है। एआईसी आसियान–भारत संबंधों को महत्वपूर्ण और व्यवहार्य दिशा प्रदान करने में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम नेतृत्व में काम करता है। 2020–21 में, एआईसी ने आभासी सम्मेलनों का आयोजन किया और विभिन्न मुद्दों, जैसे हिंद–प्रशांत में व्यापार, संपर्क और समुद्री परिवहन; उत्पादन नेटवर्क, ऊर्जा सहयोग, त्रिपक्षीय राजमार्ग और भारत के पूर्वोत्तर पर प्रभाव आदि, पर विचार करने के लिए अध्ययन किया।

वार्षिक रिपोर्ट पहले के अनुच्छेदों (पैराग्राफ) में जो कहा गया है उसकी पृष्ठभूमि में आरआईएस के कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। यह स्वास्थ्य संकट, विशेष रूप से कोविड–19, की पृष्ठभूमि में आरआईएस द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर आयोजित नीतिगत संवादों की संख्या का भी विवरण देता है। इसी तरह, रिपोर्ट उन प्रकाशनों को भी सूचीबद्ध करती है जिन्हें संस्थान ने महामारी के मद्‌देनजर नीतिगत अनुसंधान परिणामों का प्रसार करने के लिए और नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और चिकित्सकों के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग के उद्देश्य से प्रकाशित किया है, जैसे विवरणी (रिपोर्ट), चर्चा पत्र, नीति संक्षेप, पत्रिकाएं इत्यादि। संकाय सदस्यों ने बाहरी नीति संवादों और प्रकाशनों में भी योगदान दिया।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों मोर्चों पर देश के समक्ष खड़ी कई आर्थिक चुनौतियों पर शोध को लेकर अपनी दृष्टि और मिशन का विस्तार करने के लिए संस्थान को अपने शासी परिषद और अनुसंधान सलाहकार परिषद द्वारा निर्देशित किया जाना जारी है। हम अध्यक्ष, राजदूत डॉ मोहन कुमार और आरआईएस संचालन परिषद और जनरल बॉडी के सदस्यों के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए तथा राजदूत सुधीर देवारे और अन्य आरएसी सदस्यों का आरआईएस के अनुसंधान एजेंडा को सुदृढ़ करने में उनकी बहुमूल्य सलाह के लिए आभारी हैं।

हम इस अवसर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर, हमारे कार्यों के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखने और प्राप्त समर्थन के लिए, भारत सरकार, विशेष रूप से विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नीति आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, आयुष मंत्रालय और अन्य सहयोगी संगठन के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम अपने कार्यक्रमों के विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने में उनके निरंतर समर्थन के लिए संकाय और प्रशासन, दोनों में सभी सहयोगियों को भी धन्यवाद करते हैं।

सचिन चतुर्वेदी

1

वैशविक आर्थिक पद्धति एवं सहयोगः जी20

जैसा कि राष्ट्र जी –20 की अध्यक्षता के लिए तैयार हो रहा है, आरआईएस ने जी –20 विशिष्ट अनुसंधान में अपनी भागीदारी और योगदान में वृद्धि की है, और साथ ही, टी–20, एस–20, बी–20 और अन्य संलग्न समूहों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ अपने संपर्क का विस्तार कर रहा है। यह खंड इस संबंध में आरआईएस के कार्यक्रम का विवरण देता हैं।

आरआईएस में जी–20 कार्य में जी–20 नीति के संक्षेप विवरण में योगदान, जी–20 महत्वपूर्ण मुद्दों पर आंतरिक शोध और *'जी–20 डाइजेस्ट'* का प्रकाशन शामिल है। आरआईएस संकाय द्वारा कुल 10 नीति संक्षिप्त प्रस्तावों को *टी*-20 इटली द्वारा स्वीकार किया गया है। अन्य जी-20 देशों के टी-20 संस्थानों के सहयोग से तैयार किए गए स्वीकृत नीति संक्षेप शीघ्र ही टी-20 इटली की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की आशा है।

इसके अलावा, टी-20 सऊदी अरब को प्रस्तुत नीति संक्षिप्त प्रस्तावों (प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों) को उपयुक्त आरआईएस नीति संक्षिप्त में परिवर्तित किया जा रहा है। उनके टी-20 योगदान से संबंधित आरआईएस संकाय द्वारा जी–20 के चुनिंदा विषयों पर शोध पत्र जारी हैं। विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख विचारकों द्वारा लेखों के योगदान को देखते हुए भारत और अन्य देशों में जी–20 बिरादरी द्वारा *'जी–20 डाइजेस्ट'* पर तेजी से ध्यान दिया जा रहा है।

जी–20 में सेवा व्यापार

डॉ प्रियदर्शी दाश और सुश्री सब्या राय

सेवा व्यापार वैसे भी विश्व स्तर पर विकसित हो रहा है और माना जा रहा है कि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सेवाओं के व्यापार विस्तार की बहुत बड़ी संभावना है। अलग–अलग द्विपक्षीय व्यापार डेटा के अभाव और देशों द्वारा डेटा रिपोर्टिंग में अंतराल के कारण, सेवाओं के निर्यात और आयात की संभावनाओं की पूरी समझ का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जाता है। हालांकि, अमेज़ॅन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आदि जैसे ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा सक्षम ट्रेडिंग व्यवहार में बदलाव कई सेवा क्षेत्रों में वृद्धि को दर्शाता है। जी–20, एक गतिशील अंतर्राष्ट्रीय समूह होने के नाते, सेवा व्यापार को बढ़ावा देने और नियंत्रित करने में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। जी–20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में मुद्दों को शामिल किए जाने में कोई कमी न होना यह बताता है कि सेवाओं के व्यापार को समझने में एक विशाल ज्ञान–अंतराल है। वस्तुओं के विपरीत, सेवाओं में व्यापार बाधाएं गुणात्मक और विभिन्न देशों में विविध हैं। जी–20 के भीतर सेवाओं के निर्यात और आयात के रुझानों, जी–20–विकासशील देशों के संबंध में उभरते प्रतिरूप, जी–20 शिखर सम्मेलन और आधिकारिक ट्रैक में उन प्रवृत्तियों और प्रतिरूप की झलक, और वैश्विक सेवाओं के व्यापार और नियम बनाने के लिए एक बाजार के रूप में जी–20 की भूमिका की जांच करना महत्वपूर्ण है। सेवा व्यापार में उभरती प्रवृत्तियों, व्यापार बाधाओं और नीतिगत मुद्दों का खाका तैयार करने के अलावा, अध्ययन अनुभवजन्य रूप से उस कारक की जांच करता है जो जी –20 देशों के बीच सेवाओं के प्रवाह को निर्धारित करता है।

टी-20 नीति के संक्षिप्त विवरण में आरआईएस का योगदान

आरआईएस सक्रिय रूप से जी–20 के टी–20 एंगेजमेंट ग्रुप को नीति संक्षिप्त में योगदान दे रहा है। आरआईएस द्वारा दिए गए निम्नलिखित टी–20 नीति संक्षिप्त को टी–20 इटली ने स्वीकार कर लिया है।

क्रम संख्या	टास्क फोर्स	टास्क फोर्स थीम	नीति संक्षिप्त शीर्षक	लेखक
1	1	कोविड–19 और स्वास्थ्य	चिकित्सा उपचार और टीकों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल – आवश्यकता और आगे की राह	टी सी जेम्स और अन्य
2	3	व्यापार, निवेश और विकास	जी –20 में कृषि में बाजार पहुंच का विस्तारः महामारी के बाद के युग में व्यापार नियमों में बाधाओं और असमानताओं को संबोधित करना	प्रियदर्शी दाश और श्रेया कंसल
3			व्यापार वित्त और व्यापार से संबंधित अवसंरचना निवेश में वैश्विक अंतर को दूर करने के लिए जी–20–सुविधा वाले विशेषज्ञताप्राप्त सार्वजनिक–निजी क्षेत्रक गैर–संप्रभु वित्त पोषण तंत्र	राजीव खेर, अरुण नायर
4	5	2030 एजेंडा और विकास सहयोग	महामारी के बाद SDG के लिए STIः निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए TFM और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का सुदृढ़ीकरण	सचिन चतुर्वेदी, सब्यसाची साहा
5			विकास सहयोग में प्रभावी निजी क्षेत्र की भागीदारी पर कंपाला सिद्धांतों को मुख्यधारा में लाना	सचिन चतुर्वेदी और अन्य
6			आरंभिक बचपन के लिए जी–20 नीति नेतृत्वः 2030 संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभाव उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण साधन	पी के आनंद, कृष्ण कुमार और अन्य
7	6	सामाजिक सामंजस्य और लोक हितकारी व्यवस्थाओं का भविष्य	हम कैसे जानें कि लक्ष्य हासिल हुए हैं? प्रभावी और लचीली सामाजिक कल्याण प्रणाली विकसित करने की कुंजी के रूप में प्रारंभिक बचपन की निगरानी और मूल्यांकन की एकीकृत प्रणाली	पी के आनंद, कृष्ण कुमार और अन्य
8	7	अवसंरचना निवेश और वित्तपोषण	डिजिटल और संधारणीय अवसंरचनाः पीपीपी ढांचे में अभिनव निजी क्षेत्र की भागीदारी की खोज	सचिन चतुर्वेदी, प्रियदर्शी दाश और अन्य
9			अफ्रीका में बेहतर अवसंरचना परियोजना चक्र के लिए जी–20 का सहयोग	प्रियदर्शी दाश और अन्य
10			एक नई संधारणीय अर्थव्यवस्था की अवसंरचनाः वितरण, शहरीकरण, शासन	सचिन चतुर्वेदी और अन्य

2020 में, आरआईएस ने अच्छी संख्या में नीतिगत संक्षिप्त प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। उनमें से कुछ को टी–20 सऊदी अरब द्वारा प्रकाशित किया गया है। अन्य प्रस्तावों को जी–20 पर आरआईएस नीति के संक्षिप्त विवरण के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें एसडीजी रोडमैप के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) पर जी–20 नेतृत्व और वैश्विक पायलट कार्यक्रम की प्रासंगिकता; जी–20 में विकास गतिशीलता को सुदृढ़ करने के लिए व्यापारः जीवीसी और प्रौद्योगिकी गहन व्यापार पर ध्यान देना; संधारणीय खाद्य सुरक्षा के लिए ऊर्जा, जल और खाद्य के बीच परस्पर संबंध; संधारणीय विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना; एसडीजी को बढ़ावा देने के लिए जी–20 देशों में साझा लेकिन विभेदित प्रवासन से जुड़ी रणनीतियां; जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास से निपटनाः यूएनएफसीसीसी से परे जाना; फिनटेक क्रांतिः विकासशील देशों में अवसर और जोखिम; संधारणीय और गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के लिए अभिनव वित्तपोषण; प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में तेजी लाना; गतिशील मुद्दे–आधारित गठबंधन और प्रभावी क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से वैश्विक व्यापार शासन में सुधार; और एसडीजी और जी–20 में विकास सहयोग के लिए एक शासन संरचना को संस्थागत बनानाः एक बहुकेंद्रित दृष्टिकोण शामिल हैं।

जी–20 में कृषि– प्राथमिकताओं का आकलन

डॉ प्रियदर्शी दाश और सुश्री श्रेया कंसल

जी–20 के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, खासकर जी–20–विकासशील देशों के लिए। कृषि उत्पादों में व्यापार और संबंधित नीति–निर्माण वैश्विक स्तर पर काफी विवादित रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन द्वारा बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का कोई नया दौर नहीं होने के मद्देनजर, कृषि व्यापार की बातचीत के लिए बहुपक्षीय मार्गों पर तेजी से विचार किया जा रहा है। कृषि व्यापार के लिए किसी वैश्विक ढांचे के अभाव में, जी–20 से कृषि व्यापार के मुद्दों को गंभीरता से लेने की अपेक्षा की जा सकती है। इस प्रेरणा के साथ, यह लेख्य इस बात की पड़ताल करता है कि क्या जी–20 प्रक्रिया में कृषि को उचित महत्व मिला है। जी–20 नेताओं के शिखर सम्मेलन और कृषि मंत्रियों के ट्रैक का गहराई से अध्ययन किया जाता है ताकि जी–20 ने वर्षों से मुद्दों के जिस विस्तार को प्राथमिकता दी है, उन्हें समझा जा सके और यह कि वे दुनिया और विशेष रूप से विकासशील देशों द्वारा सामना की जाने वाली समकालीन चुनौतियों के अनुरूप कितने सुसंगत हैं।

कृषि पर टी–20 नीति का संक्षिप्त विवरण जल्द ही टी–20 इटली की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा, बिम्सटेक (BIMSTEC) में कृषि पर एक प्रायोजित आरआईएस–आईएफपीआरआई पीआरसीआई (RIS-IFPRI PRCI) परियोजना कृषि पर मौजूदा ज्ञान को बढ़ाएगी।

विकासशील देशों में हरित वित्त: वैश्विक व जी–20 ढांचे और विनियम को विकसित करना

डॉ प्रियदर्शी दाश और सुश्री कृतिका खन्ना

जी –20 और विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए अवसंरचना निवेश एक सर्वप्रधान नीति उपकरण बना रहेगा। दायित्व प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे हरित और स्वच्छ ऊर्जा, संधारणीय और लचीली अवसंरचना, आदि की पहचान करने पर, और उन क्षेत्रों में परियोजनाओं को निधि देने के लिए नवीन वित्तपोषण साधनों की खोज करने पर टिका हुआ है। पारंपरिक वित्तपोषण जैसे बैंक ऋण और रियायती द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण वित्तपोषण के पूरे विस्तार को पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता है। इसके अलावा, अवसंरचना के वित्तपोषण को जलवायु शमन और अनुकूलन से जोड़ने के लिए, हरित बांड को बढ़ावा दिया जा सकता है। हरित बांड जारी करने के अलावा, लक्षित निवेश को आकर्षित करने के लिए वैश्विक स्तर पर हरित वित्तपोषित उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला की परिकल्पना की जा रही है। विकासशील देशों को इस लहर से लाभ उठाना चाहिए और पेरिस समझौते की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए। इसके लिए बीमा कंपनियों, पेंशन फंड आदि जैसे रूढ़िवादी संस्थागत निवेशकों और बेकार पड़े घरेलू बचत के दोहन के संदर्भ में नवाचारों की आवश्यकता होगी। अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए खुदरा निवेशकों को जुटाने हेतु निवेश के प्रतिफल के बारे में जागरूकता की आवश्यकता होगी, भले ही उन निवेशों से जुड़े कथित जोखिम पहले से ही अधिक हों। वित्तीय नवाचारों में स्थानीय मुद्रा–अभिधान ऊर्जा वित्त बांड, संधारणीय ऊर्जा, लचीली शहरी परिवहन प्रणाली, अत्याधुनिक अवसंरचना परिसंपत्तियां आदि शामिल हो सकते हैं। उधार लेने की लागत और हरित बांड जारी करने की लागत विकासशील देशों में स्पष्ट रूप से अधिक है। घरेलू स्तर पर हरित वित्त के संग्रहण को बढ़ावा देने, विनियमित करने और सुव्यवस्थित करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बेसल ढांचे सहित उचित और सामंजस्यपूर्ण नियामक प्रणाली की आवश्यकता है।

आरआईएस, सीआईआई और आईएनएसए के बीच संयुक्त गठबंधन

जी20 पर सार्थक इनपुट उत्पन्न करने में तालमेल लाने के लिए विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) नामक तीन संस्थानों के बीच एक संयुक्त गठबंधन का गठन किया गया था। आरआईएस पिछले कई सालों से टी20 में योगदान दे रहा है। इसी तरह, सीआईआई देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने उद्योग संघों में से एक है और बी20 प्रक्रिया में भारत का एक महत्वपूर्ण हितधारक है। इसके अलावा, आईएनएसए देश में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्थान है, जिसमें जी20 विज्ञान और नवाचार एजेंडा में महत्वपूर्ण योगदान देने की संभावना है। संयुक्त शक्ति और तालमेल के साथ, इस गठबंधन का लक्ष्य जी20 प्रक्रिया को व्यापक बौद्धिक समर्थन प्रदान करना है।

नेट जीरो (Net zero): भारत के विकल्प

श्री ऑगस्टीन पीटर

2050 तक 'नेट जीरो' जीएचजी उत्सर्जन को बहुपक्षीय मंचों पर लाया जा रहा है। अमेरिका ने राष्ट्रपति बिडेन के नियंत्रण में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। देशों पर कूटनीतिक दबाव बढ़ रहा है, खासकर भारत पर जो निरपेक्ष रूप से तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। नेट जीरो का मतलब है कि जो भी कार्बन फुटप्रिंट्स वातावरण में डाल रहे हैं, उन्हें कार्बन सिंक द्वारा बेअसर किया जाना है जो कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को अवशोषित करते हैं। दूसरे शब्दों में, सभी शेष मानव जनित ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को वातावरण से जीएचएस को हटाकर संतुलित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग के स्रोत का 76 प्रतिशत है। IEA से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जी–20 देशों ने 2019 में CO2 उत्सर्जन का 85 प्रतिशत (1990 में 92 प्रतिशत के मुकाबले) योगदान दिया। पांच जी–20 देशों में 2019 में 1000 से अधिक MTCO2e था। ये हैं पीआर चीन (9802), यूएस (4766), भारत (2309), रूस (1587) और जापान (1066)। विश्व भर के उत्सर्जन का 58 प्रतिशत हिस्सा इन पांच देशों द्वारा होता है। यदि हम प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन पर विचार करें, तो जी–20 देशों में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा लगभग 15.3 tCO2 के साथ शीर्ष पर हैं। भारत 1.7 tCO2 के साथ प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के सबसे निचले पायदान पर है, जबकि प्रति व्यक्ति विश्व औसत 4.4 tCO2 है। और पांच जी–20 देशों (अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया और मैक्सिको) का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विश्व औसत से कम है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पेरिस समझौते के पक्षकार देशों द्वारा घोषित किया जाना था, और पेरिस समझौते के बाद 191 एनडीसी दायर किए गए थे। एनडीसी को हर पांच साल में संशोधित किया जाना है। हालांकि, महामारी बाधक बन गई। जी–20 देशों में से चीन, अमेरिका और भारत ने अभी तक संशोधित प्रतिबद्धताएं पेश नहीं की हैं।

कई देशों द्वारा नेट जीरो लक्ष्य घोषित किए गए हैं, जिन्हें 2050/60 तक हासिल किया जाना है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने इस आशय के कानून भी पारित किए हैं। नवीनतम घोषणा चीन द्वारा की गई है जिसने सार्वजनिक रूप से 2030 तक उत्सर्जन के चरम पर पहुंचने और 2060 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है। जर्मनी, जापान और अमेरिका भी उन देशों की इस श्रेणी में आते हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से लक्षित वर्ष घोषित किए हैं। नेट जीरो से पहले, उत्सर्जन का चरम पर पहुंचना आवश्यक है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जी –20 देशों में से 14 पहले ही 1990 से 2018 के बीच चरम पर पहुंच चुके हैं, आखिरी 2018 में दक्षिण कोरिया चरम पर था। भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मैक्सिको को अभी चरम पर पहुंचना रह गया है।

अप्रैल 2021 में 40 देशों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति बिडेन की आभासी बैठक ने जलवायु सरोकारों को बढ़ावा दिया। 2005 के स्तर से 2030 तक अमेरिकी उत्सर्जन में 50–52 प्रतिशत की कटौती करने की उनकी प्रतिज्ञा को महत्वाकांक्षी माना जा सकता है, हालांकि आवश्यकता की दृष्टि से यह कम हो सकता है।

यूएन ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) का लक्ष्य 2020 तक कम से कम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक केवल 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए गए हैं। यह विकासशील देशों द्वारा अपनी जलवायु प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए 2030 तक 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आवश्यकताओं के तहत है।

31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 के दौरान ग्लासगो, यूके में नियत सीओपी26 (COP26) महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहला पंचवर्षीय 'वैश्विक स्टॉक टेक' है। महामारी और आरोग्य प्राप्ति के वैश्विक प्रयास सीओपी26 पर चर्चा को प्रभावित करेंगे। संधारणीय आरोग्य प्राप्ति एक बड़े बहस का मुद्दा होगा। सीओपी26 के नजदीक आने पर कूटनीतिक दबाव और बढ़ना तय है। 58 देशों ने पहले ही 'नेट जीरो' उत्सर्जन लक्ष्य तिथियों की घोषणा कर दी है। एनडीसी को भी संशोधित किया जाना है।

भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक होने के साथ–साथ सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे हैं: (i) चरम पर पहुंचने की एक यथोचित अंतिम तिथि और नेट जीरो प्राप्त करने की एक उचित अंतिम तिथि घोषित करना और (ii) साथ ही, यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया में देश के संभावित विकास पथ से समझौता नहीं किया गया है। जलवायु और विकास के उद्देश्यों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है।

कोयले को जलवायु कूटनीति का तड़ित–चालक कहा गया है। भारत की योजना 2026 तक 60 गीगावॉट कोयला बिजली क्षमता जोड़ने की है। लेकिन, मौजूदा कोयला संयंत्रों में से अधिकांश लगभग 50þ क्षमता पर काम कर रहे हैं। फंडिंग एक समस्या है। लेकिन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं ने आज तक ज्यादा संशय नहीं दिखाई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ने से बिजली की मांग बढ़ेगी और फिर कोयले की मांग बढ़ेगी। नवीकरणीय लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को देखते हुए, कोयला–प्रथम रणनीति के साथ जारी रखना उपयुक्त नहीं हो सकता है। इसके अलावा, ईएसजी को ध्यान में रखते हुए, समय बीतने के साथ कोयला संयंत्र के लिए धन भी समाप्त हो जाएगा।

भारत गैस का 'ब्रिज फ्यूल' के रूप में उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन गैस की मौजूदा कीमत व्यवस्था को एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है। आने वाले कुछ समय के लिए कोयला और तेल भारत के ऊर्जा टोकरे में बने रहेंगे। लेकिन हमें उन्हें साफ–सुथरा बनाने की जरूरत है। निकट भविष्य में जीएचजी कटौती और एक दशक में हाइड्रोजन के प्रवेश को सक्षम करने के लिए संक्रमण ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की महत्वपूर्ण स्थिति पर भी विचार किया जाता है।

हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और निर्माण (FAME) योजना लागू की गई थी और अप्रैल 2019 में FAME नीति में बदलाव की घोषणा की गई, जिसमें प्रोत्साहनों को काफी हद तक बढ़ाया गया।

<u>भारत के लिए आगे की राह क्या है?</u>

(i) एक अभिनव जलवायु शासन प्रणाली को शीघ्रता से विकसित करने की आवश्यकता है।

(ii) जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करनाः कोयला और तेल पर काम करनाः अभी क्या स्थिति है और उचित समय सीमा के भीतर नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे की राह क्या है।

(iii) प्रमुख क्षेत्रों पर काम करनाः हरित गतिशीलता को बढ़ावा देना; पर्यावरण के अनुकूल इमारतों को बढ़ावा देना; सीमेंट, स्टील आदि जैसे क्षेत्र।

(iv) हरित हाइड्रोजन का उपयोगः सरकार हरित हाइड्रोजन के उपयोग का दायित्व तेल रिफाइनरियों, उर्वरक फर्मों जैसे उपयोगकर्ता उद्योगों को देने की योजना बना रही है। MNRE ने देश में हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला बनाने और हाइड्रोजन उत्पादन की लागत को कम करने की दृष्टि से अंतर–मंत्रालयी परामर्श के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन दस्तावेज का मसौदा परिचालित किया है। औद्योगिक उपयोग के अलावा, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी का उपयोग बिजली के भंडारण और संभावित रूप से वाहन चलाने के लिए भी किया जा सकता है।

(v) भारत के लिए कारगर प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उन्हें व्यवहार्य परियोजनाओं में विकसित करना। जलवायु परिवर्तन पर भारत–अमेरिका सहयोग के अनुसार किफायती प्रौद्योगिकियों पर अमेरिका के साथ समन्वय करना।

(vi) प्रभावित लोगों और उद्योगों के लिए न्यायोचित संक्रमण योजनाओं को क्रियान्वित करना।

(vii) वित्त पोषण के लिए पूंजी के नए साधनों और स्रोतों के अधिक सुचारू प्रवाह को सक्षम बनाना। प्रौद्योगिकी और वित्त के मामले में अमेरिकी समर्थन काम आएगा।

(viii) सरकार 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की योजना बना रही है। ई–20 ईंधन (20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल) के उपयोग से उस स्रोत से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में 30–50 प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद है।

(ix) वैश्विक जलवायु संबंधी कार्रवाई को और अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए विकसित देशों को क्या करना चाहिए?

सीओपी26 की दौड़ में, जहां तक निवल शून्य (नेट जीरो) का संबंध है, उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित केंद्रित मुद्दों पर अनुसंधान की आवश्यकता हैः

(i) पीकिंग (चरम) और नेट जीरो कब हासिल करना है। जी–20 देश के रूप में भारत पर कम से कम एक संभावित लक्ष्य वर्ष घोषित करने का दबाव है। चीन ने 2030 और 2060 को पीकिंग और नेट जीरो वर्ष घोषित किया है। भारत निश्चित रूप से 2030 में चरम पर नहीं पहुंच सकता। हम आर्थिक विकास में चीन से एक दशक से भी अधिक समय से पीछे हैं। तो चरम 2040 से पहले नहीं हो सकता। यानी 2070 से पहले नेट जीरो हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या एक जी–20 सदस्य होने के नाते भारत के लिए यह एक प्रस्तुत करने योग्य तारीख होगी? शर्मिंदगी नहीं होगी? वे कौन–सी रणनीतियां होनी चाहिए जिसे भारत को सूत्रबद्ध करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए? इस प्रयास में हमारे गठबंधन सहयोगी कौन होंगे?

चीन बनाम भारत की तुलना दिलचस्प है और यह इस मुद्दे पर निर्णय लेने में मदद भी करेगी। पूर्ण स्तर पर भारत का जीएचजी उत्सर्जन चीन के एक चौथाई से भी कम है। जहां भारत के ऊर्जा मिश्रण में कोयले की वर्तमान हिस्सेदारी 50 प्रतिशत है, वहीं चीन की 62 प्रतिशत है। और, चीन द्वारा अकेले 2020 में 17 नए कोयला बिजली संयंत्रों को जोड़े जाने की सूचना है। चीन की कुल सौर उत्पादन क्षमता 200 गीगावॉट है, जबकि भारत की कुल सौर क्षमता केवल 39 गीगावॉट है। इसके अलावा, चीन की विनिर्माण क्षमता लगभग 100 गीगावॉट है, जबकि भारत की केवल 10 गीगावॉट है (इसमें RIL द्वारा हाल ही में घोषित योजनाएं शामिल नहीं हैं)। भंडारण एक और बाधा है। चीन का इस क्षेत्र में वास्तव में एकाधिकार है। भारत को हरित हाइड्रोजन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और हाल ही में घोषित हाइड्रोजन मिशन को जोर–शोर से आगे बढ़ाया जाएगा।

(ii) दो–आयामी रणनीति का पालन करने की आवश्यकता हैः (i) तेज गति से नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि; (ii) परिवहन, विनिर्माण, इस्पात, रसायन, शिपिंग, सीमेंट, विमानन, अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण आदि जैसे क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करना।

(iii) सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी' के सिद्धांत को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारत जैसे विकासशील देशों की दहलीज पर विकसित देशों की ऐतिहासिक गलतियां नहीं रखी जा सकतीं।

भारत एकमात्र जी–20 देश है जिसकी गतिविधियां पेरिस समझौते के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ने से रोकने के लक्ष्य के अनुरूप हैं। क्या भारत को नेट जीरो वर्ष घोषित करने में जल्दबाजी करनी चाहिए? या भारत को नेट जीरो के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन लक्ष्य तिथि घोषित करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

भारत को वैश्विक मानकों और पारदर्शिता के साथ–साथ विश्वसनीय नेट जीरो लक्ष्यों के लिए भी काम करने की आवश्यकता है। जैसा कि प्रतिष्ठित राजनयिक श्याम सरन ने कहा, "भारत के लिए ... यह महत्वपूर्ण है कि शमन पेरिस समझौते के अन्य प्रमुख तत्वों पर हावी न हो। अनुकूलन और शमन के समान कार्यक्रम होने चाहिए।"

(iv) भारत द्वारा परिकल्पित उत्सर्जन व्यापार योजना से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।

(v) हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को नीतिगत सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। अनुसंधान एवं विकास निवेशों की हामीदारी के रूप में समर्थन एक ऐसा विचार है जिसका विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। यह बताया गया है कि सरकार हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए रिफाइनरियों और उर्वरक फर्मों को आगे बढ़ा सकती है।

(vi) हरित संक्रमण के लिए पूंजी कैसे आकर्षित करें?

(vii) निर्दिष्ट क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों को यथाशीघ्र नेट जीरो तक पहुंचने के लिए राजी करना पड़ सकता है।

नेट जीरो पर अनुसंधान कार्यक्रम में मुद्दे के उपर्युक्त आयामों को शामिल करने का प्रस्ताव है, विशेष रूप से सीओपी26 को ध्यान में रखते हुए। विशिष्ट मुद्दों पर शोध पत्र प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है। मुद्दों के उपर्युक्त कुछ आयामों पर संगोष्ठी प्रस्तावित हैं।

फिनटेक क्रांतिः विकासशील देशों के लिए अवसर और जोखिम

डॉ प्रियदर्शी दाश

पिछले 20 वर्षों से, जी–20 ने सदस्य देशों और विश्व अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के भविष्य को बनाए रखने के लिए अनुकूली पर्यवेक्षी और नियामक प्रणालियों के साथ मजबूत, लचीला और सुनम्य वित्तीय प्रणालियों की वकालत की है। जी–20 का एक प्रमुख मुद्दा उभरती हुई फिनटेक सहित दुनिया भर में वित्तीय क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के साथ–साथ सुसंगत वैश्विक नियामक ढांचे का निर्माण करना है। फिनटेक (Fintech) और इंसुरटेक (InsurTech) के विकास के रूप में, क्षेत्रों को वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण, लघु और मध्यम उद्यमों (SME), कौशल विकास आदि जैसे प्रमुख सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के साथ कुशलता से जोड़ा जा सकता है। जी–20 को फिनटेक को एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में देखना चाहिए और सदस्य राज्यों और सहकर्मी गैर–जी–20 विकासशील देशों के बीच संभवतः एक टास्क फोर्स और फिनटेक पर कार्य समूहों के माध्यम से आम सहमति बनाना चाहिए, विशेष रूप से उद्योग आयामों, वित्तीय समावेशन और नियामक ढांचे पर। चूंकि बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन जोखिमों की प्रकृति और दायरा, विशेष रूप से सामान्य तृतीय–पक्ष सेवा प्रदाताओं से उत्पन्न होने वाले साइबर जोखिम, बढ़ गए हैं, इसलिए देशों के लिए सबसे बड़ी सार्वजनिक नीति चुनौतियां अब डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और मनी लॉन्ड्रिंग निरोध का अनुपालन और आतंकवादी प्रतिबद्धताओं के वित्तपोषण का मुकाबला करना है।

"फिनटेक और फिनटेक–सक्षम सेवा में यूके–भारत द्विपक्षीय व्यापार पर ESRC-ICSSR सहयोगात्मक परियोजनाः उभरते रुझान और विकास की संभावना" शीर्षक वाली एक प्रायोजित परियोजना से, जिसका अध्ययन RIS द्वारा एसेक्स विश्वविद्यालय, ISID, GIFT और अन्य के साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है, आगे फिनटेक पर समझ को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

महिला उद्यमियों के तहत प्रतिबद्धता – वित्त पहल (वी–फाई): महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक पहल – जारी

डॉ बीना पांडे

महिला सशक्तिकरण के लिए महिला–20 (W-20) और वी–फाई (We-Fi) की स्थापना जी–20 की दो सबसे महत्वपूर्ण पहल हैं। वी–फाई पहल के औचित्य का विश्लेषण करते हुए, पर्चा इसकी शासन संरचना, वी–फाई सचिवालय के संविधान, कार्यान्वयन भागीदारों और वित्तीय संरचना पर फोकस करेगा। यह विकासशील देशों में वित्त तक पहुंच बढ़ाने, प्रशिक्षण–परामर्श तक पहुंच बढ़ाने, बाजारों तक पहुंच बढ़ाने और सक्षम वातावरण में सुधार के माध्यम से महिलाओं के क्षमता निर्माण पर भी प्रकाश डालेगा। इसके अलावा, वी–फाई पहल द्वारा किए गए संपूर्ण प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो का विश्लेषण देश विशिष्ट, कार्यक्षेत्र, लक्षित लाभार्थियों, और समयरेखा (क्रमविकाश) और लाभार्थियों पर इसके प्रभाव का उल्लेख करेगा, चाहे वह किसी की एसडीजी की आवश्यकताएं पूरी करता हो।

अध्ययन में निम्नलिखित घटक होंगेः परिचय – जी–20 पहलः महिला सशक्तिकरण के लिए डब्ल्यू –20 और वी–फाई की स्थापना जी–20 की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से दो हैं। वी–फाई का औचित्य – फोकस होगाः शासन संरचना, वी–फाई सचिवालय के गठन, कार्यान्वयन भागीदारों, वित्तीय संरचना, और वित्तपोषण के विभिन्न दौरों की स्थिति पर। विकासशील देशों में वित्त तक पहुंच बढ़ाने, प्रशिक्षण–परामर्श तक पहुंच बढ़ाने, बाजारों तक पहुंच बढ़ाने और सक्षम वातावरण में सुधार के माध्यम से महिलाओं में क्षमता निर्माण। परियोजना पोर्टफोलियो – विश्लेषणः विभिन्न विकासशील देशों में कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं, पूर्ण परियोजनाएं, चल रही परियोजनाएं और स्वीकृत परियोजनाएं। वी–फाई पहल द्वारा शुरू की गई ये सभी परियोजनाएं देश–विशिष्ट, कार्यक्षेत्र, लक्षित लाभार्थियों, और समयरेखा (क्रमविकाश) और लाभार्थियों पर इसके प्रभाव का उल्लेख करेगा, चाहे वह किसी की एसडीजी की आवश्यकताएं पूरी करता हो। यह आगे की राह के उल्लेख के साथ समाप्त होगा।

जी–20 में कामकाजी महिलाओं पर कोविड–19 का प्रभावः नीतिगत प्रतिक्रिया

डॉ बीना पांडे

वर्तमान में दुनिया कोविड–19 महामारी के भीषण प्रभावों का सामना कर रही है। पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और यहां तक कि बच्चे भी इस महामारी के गंभीर प्रभावों से अछूते नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग इस कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं क्योंकि कोई भी प्रामाणिक दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।

इन अभूतपूर्व परिस्थितियों में, जी–20 देशों में कोविड–19 का खामियाजा महिलाओं को अधिक भुगतना पड़ा है, दोहरी जिम्मेदारियां उठाते हुए, विशेष रूप से कामकाजी महिलाएं को, जिन्हें घर का काम और घर से काम, दोनों साथ–साथ करना पड़ा है। इस लेख में, महिला रोजगार की वर्तमान स्थिति और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा, यह घरेलू काम करने और चुनौतियों और अवसरों का सामना करते हुए संगठनात्मक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के संदर्भ में घर से काम करने और घर पर काम करने की महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी पर भी प्रकाश डालेगा। यह इस संदर्भ में सभी संबंधित जी–20 सरकार के हस्तक्षेप पर भी प्रकाश डालेगा।

'वर्ष 2022 में भारत की जी20 अध्यक्षता के लिए प्राथमिकताएं: सहभागिता समूहों की भूमिका' पर वेबिनार

जी20 दरअसल व्यापार एवं निवेश, आर्थिक विकास एवं वित्तीय स्थिरता, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), जलवायु परिवर्तन और डिजिटल अर्थव्यवस्था के मुद्दों के साथ–साथ कई अन्य क्षेत्रों पर भी एक महत्वपूर्ण वैश्विक फोरम के रूप में कार्य करता है। अतीत में अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ–साथ वर्तमान लीडर्स समिट और अन्य ट्रैक की भांति ही वर्ष 2022 में भारत की जी20 अध्यक्षता पर विशेष रूप से विकासशील देशों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी। भारत के जी20 शेरपा माननीय श्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में भारत वर्ष 2022 में जी20 प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी कमर कस रहा है।

भारत के जी20 शेरपा माननीय श्री सुरेश प्रभु

आधिकारिक ट्रैक के अलावा विभिन्न सहभागिता समूह जैसे कि थिंक टैंक 20 (टी20), वुमन 20 (डब्ल्यू20), बिजनेस 20 (बी20), सिविल 20 (सी20), साइंस 20 (एस20), इत्यादि लीडर्स समिट के लिए तरह–तरह के विचारों और समाधानों को अभिव्यक्त या सुस्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक सहभागिता समूह के अद्वितीय दृष्टिकोण एवं ताकत की सामूहिक समझ को बढ़ावा देने और आम या साझा क्षेत्रों पर एक समन्वित विवरण तैयार करने के उद्देश्य से आरआईएस ने 11 मई 2020 को 'वर्ष 2022 में भारत की जी20 अध्यक्षता के लिए प्राथमिकताएं: सहभागिता समूहों की भूमिका' पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम की शुरुआत आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के आरंभिक संबोधन और आरआईएस के चेयरमैन राजदूत (डॉ.) मोहन कुमार के भाषण के साथ हुई। भारत के जी20 शेरपा माननीय श्री सुरेश प्रभु ने विशेष भाषण दिया। इसके बाद एक पैनल परिचर्चा आयोजित की गई: डब्ल्यू20: प्रोफेसर पाम राजपूत, प्रोफेसर एमेरिटस, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़; टी20: प्रोफेसर रजत कथूरिया, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीआरआईईआर, नई दिल्ली; बी20: श्री प्रणव कुमार, प्रमुख–अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, सीआईआई, नई दिल्ली; एस20: डॉ. साधना रेलिया, प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सहयोग विशेषज्ञ एवं टिप्पणीकार; और सी20: श्री हर्ष जेटली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाणी, नई दिल्ली इस अवसर पर प्रमुख पैनलिस्ट थे। परिचर्चा के बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आखिर में आरआईएस के सहायक प्रोफेसर डॉ. प्रियदर्शी दाश ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

'वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए भविष्य का रोडमैप: जी20 रियाद शिखर सम्मेलन और उससे आगे' पर विचार

इटली, इंडोनेशिया और भारत (Italy, Indonesia and India & the three *I*'s) को बहुपक्षवाद की भावना को पुनर्जीवित करने और दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह को जलवायु परिवर्तन को कम करने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, जी7 और जी20 में भारत के शेरपा को रेखांकित करने के लिए सामूहिक समाधान निकालने में मदद करने में महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका निभाने की आवश्यकता है, माननीय श्री सुरेश प्रभु ने कहा। CII के सहयोग से RIS द्वारा आयोजित 'फ्यूचर रोडमैप फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी: रिफ्लेक्शंस ऑन जी20 रियाद समिट एंड बियॉन्ड' शीर्षक के एक आभासी सम्मेलन में बोलते हुए, माननीय श्री प्रभु ने कहा कि असमानता, अस्थिर ऋण, कम निवेश स्तर, पर्याप्त नौकरियों और स्थिर वेतन के अभाव जैसी स्थितियों के कारण कोविड–19 महामारी के वैश्विक विस्फोट से पहले ही बहुपक्षवाद पर छानबीन की जा

श्री निकोलस पिनौड, OECD G20 शेरपा

हाई–टेक कंपनी समूह के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति पर CII राष्ट्रीय समिति के सह–अध्यक्ष श्री दीप कपूरिया

RIS के अध्यक्ष राजदूत डॉ मोहन कुमार

RIS के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

रही थी। तथापि, इन चुनौतियों की वैश्विक प्रकृति को देखते हुए, उन्होंने कहा, "बहुपक्षवाद से इनकार न केवल एक मूर्खता है, बल्कि अधिक आपदाओं के लिए एक निश्चित नुस्खा भी है।"

उन्होंने कहा कि तीनों 'I' – इटली, इंडोनेशिया और भारत – को अपने–अपने जी20 अध्यक्षता वर्षों के दौरान सक्रिय कदम उठाने चाहिए "बाकी दुनिया को यह याद दिलाने के लिए कि समाधान (इन समस्याओं का) 'मैं' कहने में नहीं, बल्कि 'हम' में है।" उन्होंने कहाः "तीनों 'I' भविष्य को आकार दे सकते हैं और उन्हें वैश्विक शासन के मुद्दों पर एक साथ काम करना चाहिए। जी20 को न केवल दुनिया का मार्गदर्शन और नेतृत्व करना चाहिए, बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से यह दिखाना चाहिए कि वे मानवता और विश्व के भविष्य के प्रति जिम्मेदार भी हैं।" उनके अनुसार, डिजिटलीकरण और चौथी औद्योगिक क्रांति की चुनौतियों से निपटने और यह सुनिश्चित करने के अलावा कि कोविड–19 वैक्सीन दुनिया भर में उपलब्ध है, जी20 को पेरिस जलवायु समझौते और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी20 को रोजगार सृजन और कौशल विकास को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। संयोग से, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने बहुपक्षवाद के लिए अपने समर्थन का संकेत दिया है और यह भी कि पेरिस जलवायु समझौते के साथ–साथ अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में फिर से शामिल होगा। (ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका को WHO से बाहर कर लिया था और जलवायु परिवर्तन शमन पर पेरिस समझौते से बाहर हो गया था)।

OECD जी20 के शेरपा महामहिम श्री निकोलस पिनौद ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि हालांकि आर्थिक प्रोत्साहन उपायों और कोविड–19 वैक्सीन के विकास ने उपभोक्ताओं और व्यवसाय जगत के विश्वास को बढ़ाया है, लेकिन संक्रमण की दूसरी लहर व्यापक रूप से अनिश्चितता की ओर ले जा रही है। जारी मौजूदा संकट की पहली लहर के बाद से निजी निवेश में आभासी ठहराव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह उत्पादकता और विकास प्रभावित करेगा और इससे श्रम बाजार में युवाओं के एकीकरण में देरी होगी, वैश्विक मांग में मंदी आएगी, खपत में कमी होगी और आगे यह विकास को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन और खुदरा जैसे क्षेत्र, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाओं को रोजगार मिला हुआ था, बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि लाखों लोग फिर से गरीबी में धकेले जाएंगे। उन्होंने कहा कि संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि बैंकों को मिलने वाला परिस्थितिजन्य लाभ और नकारात्मक जोखिम आर्थिक सुधार को कमजोर कर सकते हैं। ऋण संचय और परिस्थितिजन्य लाभ (लीवरेज) में वृद्धि धीमी आय वृद्धि के साथ संयुक्त रूप से अत्यधिक लीवरेज जारीकर्ताओं की कॉर्पोरेट ऋण संधारणीयता को कम कर रही है। उन्होंने आगे कि 2020 में गैर–निष्पादित ऋणों (non-performing loans – NPL) में उछाल से बैंकों की इच्छा और उधार देने की क्षमता कम होने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में कॉरपोरेट दिवालियापन की सुनामी आने की संभावना है। साथ ही, उन्होंने कहा कि संरचनात्मक समस्याओं के साथ–साथ कॉरपोरेट्स के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक अच्छी दिवाला व्यवस्था (insolvency regime) और शोधन अक्षमता (bankruptcy) कानूनों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इटली की जी20 अध्यक्षता और 3Ps – लोग, भूमण्डल और समृद्धि (People, Planet और Prosperity), की इसकी प्राथमिकता का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इससे असमानताओं से निपटने, समान अवसरों को बढ़ावा देने, पेरिस समझौते और SDG से संबंधित प्रतिबद्धताओं को लागू करने, नई तकनीक और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने और जीवन की बेहतर गुणवत्ता और लचीलापन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हुए, जी20 अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी और श्रम संसाधनों को पुनरू आवंटित करने, एक सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा तंत्र और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से लोगों की सहायता करने के साथ–साथ सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को लाने की आवश्यकता है, जिसमें कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। श्री पिनौड ने कहा कि संधारणीय और लचीले ढंग से पुनर्निर्माण के लिए बहुपक्षवाद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन चुनौतियों में बहुत सारे सीमापार तत्व भी शामिल हैं। RIS के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि इस साल सऊदी अरब में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों को आगे बढ़ाने के अलावा कौशल विकास और गुणवत्तायुक्त अवसंरचना निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत है। इस अवसर पर RIS के अध्यक्ष राजदूत डॉ मोहन कुमार और हाई–टेक कंपनी समूह के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति पर CII राष्ट्रीय समिति के सह–अध्यक्ष श्री दीप कपूरिया ने भी अपने वक्तव्य दिए। जी20 में T20 (थिंक–टैंक) प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के अलावा, RIS 2022 में भारत की जी20 अध्यक्षता के लिए सार्थक इनपुट उत्पन्न करने के हिस्से के रूप में जी20 मुद्दों पर एक द्वि–मासिक प्रकाशन '*द जी20 डाइजेस्ट*' निकाल रहा है।

‘भारत में बी–20 वैश्विक संवाद’ पर डिजिटल सम्मेलन

जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पेरिस समझौते के बारे में जारी मतभेद को दूर करने की आवश्यकता है। जी–7 और जी–20 में भारत के शेरपा माननीय श्री सुरेश प्रभु ने कहा, ‘दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों और कारोबारी संगठनों यानी क्रमशः जी20 एवं बी20 को पेरिस जलवायु समझौते को आगे बढ़ाने को प्राथमिकता देने, डिजिटल खाई को पाटने, बेहतरीन बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करने, मूल्य श्रृंखलाओं एवं चिकित्सा आपूर्ति को मजबूत करने और खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है।

आरआईएस द्वारा 7 अक्टूबर 2020 को सीआईआई और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सहयोग से ‘भारत में बी–20 वैश्विक संवाद’ विषय पर आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में माननीय श्री सुरेश प्रभु, जो सांसद (राज्य सभा) भी हैं, ने भारत द्वारा वर्ष 2022 में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किए जाने का जिक्र किया और कहा कि वैसे तो भारत इस दौरान अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके साथ ही वह अन्य देशों द्वारा अपनी जी20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में किए गए कार्यों को भी आगे बढ़ाएगा। बी–20 या बिजनेस20 दरअसल जी20 देशों का कारोबारी समुदाय है और यह टी20 (थिंक टैंक), डब्ल्यू20 (महिला), सी20 (सिविल सोसायटी), वाई20 (युवा), एस20 (विज्ञान), एल20 (श्रम) और यू20 (शहरी) सहित अन्य सहभागिता समूहों के साथ मिलकर जी20 शिखर सममेलनों के लिए आवश्यक जानकारियां और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है। जी20 की अध्यक्षता बारी–बारी से इसके प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक साल के लिए संभाली जाती है। वर्तमान में जी20 की अध्यक्षता सऊदी अरब संभाल रहा है जो वर्ष 2021 के लिए इसकी अध्यक्षता इटली को सौंप देगा।

वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन (शुद्ध–शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन) और वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए माननीय श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि वैश्विक समस्याओं को हल करने के अपने दृष्टिकोण के तहत भारत ‘वसुधैव कुटुम्बकम (‘दुनिया एक परिवार है)’ के अपने दर्शन का पालन करेगा। यह सवाल करते हुए कि यदि कोई भी सदस्य देश गंभीर समस्याओं से जूझ रहा हो, तो वैश्विक समुदाय अपने आपको समृद्ध कैसे मान सकता है, उन्होंने कारोबारी समुदाय से न केवल मुनाफा कमाने पर, बल्कि समाज के सबसे निचले तपके के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करने को कहा। माननीय श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि कंपनियों को जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ–साथ डिजिटल खाई को पाटने में भी मदद करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पेरिस जलवायु समझौते (अमेरिका ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया है) के बारे में जारी मतभेद को दूर करने की जरूरत है।

इस अवसर पर विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) श्री राहुल छाबड़ा ने जी20 को पेश की गई हालिया बी20 रिपोर्ट का उल्लेख किया और कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाने के साथ–साथ उत्पादक क्षेत्रों में फिर से मजबूती बहाल करके अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विशाल घरेलू मांग को पूरा करने की आवश्यकता के बावजूद भारत ने अपनी चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखलाओं को खुला रखा है और कई देशों को जेनेरिक दवाएं एवं चिकित्सा उपकरण मुहैया कराए हैं। महामारी के मौजूदा प्रकोप के दौरान भारत ने त्वरित कार्रवाई टीमों, सूचना आदान–प्रदान प्लेटफॉर्मों और वेबिनारों के जरिए स्वास्थ्य सेवा संबंधी प्रशिक्षण के सहारे अन्य देशों की मदद की। इसके अलावा, भारत ने कई देशों को आवश्यक समर्थन प्रदान करके ‘जी20 की ऋण अदायगी स्थगन पहल’ को आगे बढ़ाया।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने कहा कि यह संस्थान कारोबारियों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और सिविल सोसायटी समूहों सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा पेश किए जाने वाले विचारों में सामंजस्य स्थापित करने में जुटा रहा है, ताकि नीति निर्माताओं के लिए उन्हें अत्यंत आसानी से समझना और जी20 के स्तर पर लागू करना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जी20 में टी20 (थिंक–टैंक) प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के अलावा आरआईएस इस संबंध में जी20 के मुद्दों पर *'द जी20 डाइजेस्ट'* नामक एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में भारत की जी20 अध्यक्षता के लिए सार्थक जानकारियां सृजित करने के तहत ही इस पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। आरआईएस के चेयरमैन राजदूत डॉ. मोहन कुमार ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। बी20 सऊदी अरब के अध्यक्ष श्री यूसेफ अब्दुल्ला अल–बेन्यान ने कहा कि सऊदी अरब ने अपनी जी20 अध्यक्षता के दौरान कारोबार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण और व्यापार व निवेश से संबंधित मुद्दों को सुलझाने को भी प्राथमिकता दी है।

माननीय श्री सऊद बिन मोहम्मद अल–सती, भारत में सऊदी अरब के राजदूत; श्री नौशाद फोर्ब्स, पूर्व अध्यक्ष, सीआईआई एवं अध्यक्ष, सीआईआई की अंतर्राष्ट्रीय परिषद; और श्री चंद्रजीत बनर्जी, महानिदेशक, सीआईआई ने भी इस कार्यक्रम के दौरान अपने–अपने विचार व्यक्त किए।

आरआईएस जी–20 डाइजेस्ट

पिछले कुछ वर्षों में जी20 एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच के रूप में उभरा है, और जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन को दुनिया भर में दिलचस्पी और संदेह की नजर से देखा जाता है। जी20 की क्रमिक ने वित्तीय क्षेत्र से परे मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित किया है; प्रत्येक का व्यापार और निवेश, वैश्विक शासन और सामाजिक क्षेत्र पर संभावित प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक अध्यक्षता ने नियमित मुद्दों के साथ नए मुद्दों को जोड़कर शिखर सम्मेलन की प्रक्रिया में योगदान दिया है जिसके परिणामस्वरूप एक व्यापक और विविध जी20 एजेंडा बन गया है। मुद्दों की विविधता और जटिल चुनौतियों, जिनसे दुनिया जूझ रही है, को देखते हुए जी20 से उम्मीदें कई गुना बढ़ गई हैं। जी20 के उदय, और भविष्य की वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में इसकी भूमिका और कार्यों समझना और आकलन करना अनिवार्य है। जी20 और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इसके निहितार्थों पर नए विचारों को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए, RIS तुलना करने, अंतर बताने और नए ज्ञान का सृजन के लिए एक मंच के रूप में एक तिमाही पत्रिका *'जी20 डाइजेस्ट'* प्रकाशित करता है। यह जी20 देशों और दुनिया, जिसमें विकासशील और कम विकसित देश शामिल हैं, के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

प्रकाशन कार्यक्रम

नीतिगत सार–पत्र

#99 **एसडीजी के लिए एसटीआईः जी20 साझेदारी और राष्ट्रीय अनिवार्यताए** द्वारा सचिन चतुर्वेदी, सब्यसाची साहा

नीतिगत सार–पत्र

#100 **जी20 शेरपा और वित्त ट्रैकः समानताएं एवं अवसर** द्वारा प्रियदर्शी दाश, सोनल गर्ग व सभ्या राय

जी–20 पर भविष्य की पहल

3Is- ओईसीडी विकास केंद्र ने हाल ही में बहुपक्षवाद, शिक्षा, मानव विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के मुद्दों को संबोधित करने के लिए इटली, इंडोनेशिया और भारत के चुनिंदा प्रबुद्ध मंडलों को शामिल करते हुए '3आई' (3Is) नामक एक पहल शुरू की है। आरआईएस जी–20 मुद्दों पर भारतीय दृष्टिकोण में योगदान करने के अलावा जी–20 मुद्दों को पूरी तरह से संबोधित करने की इस पहल का हिस्सा है। पहल ने फोकस क्षेत्रों और पहल के हिस्से के रूप में की जाने वाली गतिविधियों की पहचान करके संकल्पना का चरण पूरा कर लिया है।

जी–20 अनुसंधान मंचः आरआईएस (भारत); सीएसआईएस (इंडोनेशिया); एलईपीएम (इंडोनेशिया विश्वविद्यालय) और ईआरआईए (जकार्ता) सैद्धांतिक रूप से एक संयुक्त पहल शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसे अस्थायी रूप से जी –20 रिसर्च फोरम कहा जाता है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण वैश्विक विकास के मुद्दों पर इंडोनेशिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के आगामी विकासशील देशों के राष्ट्रपतियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। अध्ययन के अलावा फोरम सरकारों और आधिकारिक टी–20 प्रक्रिया के बीच सेतु का काम करेगा।

प्रदान की गई विश्लेषणात्मक सहायता

- विदेश मंत्रालय के सचिव (आर्थिक संबंध) को बी–20 वैश्विक वार्ता पर सम्मेलन के लिए वार्ता बिंदु उपलब्ध कराए गए।
- भारत के जी –20 अध्यक्षता के लिए संभावित विषय 'भारत के नए विकास प्रतिमान और अनुभवों को साझा करना', 2020 पर एक नोट प्रस्तुत किया गया।
- वित्त मंत्रालय के डीईए द्वारा आयोजित जी–20 आभासी वित्तीय ट्रैक बैठक (जी–20 वर्चुअल फाइनेंस ट्रैक मीटिंग) के समक्ष एक नोट प्रस्तुत किया गया।
- विदेश मंत्रालय में एमईआर डिवीजन को 'जी –20 शेरपा और वित्तीय ट्रैकः सामान्यताएं और अवसर' पर एक नीति संक्षिप्त प्रदान किया गया।

2
विकास सहयोग

आरआईएस अपने वैश्विक आर्थिक शासन व्यवस्था और सहयोग कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में संलग्न है। साथ ही, इसने डेटा आधारित भारत के विकास सहयोग को विकसित करने, विकास सहयोग का विश्लेषण करने के लिए अर्थमितीय आधारित तकनीक, दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग, एसडीजी के एजेंडा के हिस्से के रूप में सतत विकास का स्थानीयकरण, यूएन@75, COVID–19 महामारी के दौरान विकास सहयोग, आदि पर अपने शोध को और आगे बढ़ाया है। विकास सहयोग में अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों में, आरआईएस ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से शैक्षणिक संस्थानों और विकास एजेंसियों के साथ सहयोग किया और कई वेबिनार, ऑनलाइन बातचीत और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए। इसके अतिरिक्त, इसने नियमित रूप से रिपोर्ट, नीति संक्षिप्त, चर्चा पत्र और एक समर्पित जर्नल *डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू* (DCR) प्रकाशित किया है। निम्नलिखित अनुभाग कुछ विवरण प्रस्तुत करते हैं।

एसडीजी: राज्यों का विकास, और सांख्यिकीय रूपरेखा

डॉ पी के आनंद और श्री कृष्ण कुमार

इस कार्यक्रम के विशिष्ट घटक निम्नलिखित हैं: सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तीनों आयामों में एसडीजी की तीव्र उपलब्धि के लिए नीति, रणनीति और कार्य बिंदुओं को कवर करते हुए निगरानी और क्षमता निर्माण; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाकर साक्ष्य–आधारित नीतिगत निर्णयन में सहायता के लिए भारत की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली को और अधिक जीवंत बनाने के लिए उसे विकसित करना; तीव्र विकास के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान–प्रदान, क्षेत्र का दौरा, क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बातचीत, विभिन्न हितधारकों के साथ विचार–विमर्श आदि के माध्यम से राज्यों के साथ संवाद; तथा सीमा पार विकास भागीदारी और विचारों के आदान–प्रदान, क्षेत्रीय परियोजनाएं, तकनीकी और आर्थिक सहयोग आदि के माध्यम से परस्पर लाभ के लिए दक्षिणीय सहयोग।

विदेशों में भारत के विकास सहयोग पर एक डेटाबेस विकसित करना

प्रोफेसर एस के मोहंती, डॉ सुशील कुमार, सुश्री अदिति गुप्ता और सुश्री श्वेता शाजू

इस डेटाबेस की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें डेवलपमेंट कॉम्पेक्ट के सभी तौर–तरीके शामिल हैं, जैसे क्षमता निर्माण (विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति, मेजबान देश में प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां, तीसरे देश का प्रशिक्षण, स्वयंसेवकों की तैनाती, व्यवहार्यता अध्ययन और प्रोटोटाइप उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र का संचालन), अनुदान (नकद में अनुदान, वस्तु के रूप में अनुदान, ऋण माफी और मानवीय सहायता), रियायती वित्त (क्रेडिट की लाइन, खरीदार को क्रेडिट), व्यापार और बाजार पहुंच (शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना, व्यापार में सुगमता के लिए अवसंरचना में सुधार, व्यापार संवर्धन और व्यापार सहयोगी सेवाएं, व्यापार सुविधा सेवाएं प्रदान करना, नियामक क्षमता में सुधार के लिए सहायता, निवेश निधि प्रदान करना और अंतर क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (तकनीकी सहयोग, संयुक्त वैज्ञानिक और शैक्षणिक अनुसंधान, लाइसेंस देने वाली टर्नकी परियोजनाएं या आईपीआर व्यवस्था से छूट, क्षमता निर्माण के घटक के साथ या बिना प्रौद्योगिकी हस्तांतरण)। डेटाबेस द्विपक्षीय प्रवाह के साथ–साथ बहुपक्षीय प्रवाह का विवरण देता है। इसका कवरेज भारत के विकास सहयोग मंत्रालयों और क्षेत्रकों के प्रवाह और क्षेत्रीय संस्थानों के साथ भारत के विकास सहयोग के बारे में विवरण देता है। डेटाबेस की समयावधि वर्ष 1946 से अब तक की है।

डेटाबेस में निम्नलिखित मंत्रालय और विभाग शामिल हैं

- विदेश मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- आयुष मंत्रालय
- वाणिज्य विभाग
- कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग
- कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
- शिक्षा मंत्रालय

हिंद–प्रशांत अनुसंधान कार्यक्रम 2021–22

हिंद–प्रशांत क्षेत्र ने हाल के वर्षों में वैश्विक समृद्धि और शांति के स्रोत के रूप में महत्व प्राप्त किया है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के किनारे दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका और प्रशांत में तटीय देशों का भौगोलिक प्रसार उच्च आर्थिक विकास, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, आजीविका विविधीकरण और अधिक से अधिक आबादी के बीच संवाद का विशाल अवसर प्रस्तुत करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, आसियान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और भारत सहित सभी प्रमुख देशों ने हिंद–प्रशांत क्षेत्र में व्यापक जुड़ाव के लिए अपना विजन और रणनीति तैयार की है। जहां हिंद–प्रशांत पर इन सभी देश की रणनीति एक व्यापक कैनवास को कवर करती है, वहीं भारत ने 'समावेशीता' के महत्व को रेखांकित करते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद–प्रशांत यानी फ्री एंड ओपन इंडो–पैसिफिक (एफओआईपी) की अवधारणा को व्यापक बनाया है। जून 2018 में सिंगापुर में शांगरी–ला संवाद में, भारत के प्रधान मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि हिंद–प्रशांत में भारत की अपनी भागीदारी हिंदी के पांच 'स' पर आधारित होगीः सम्मान; संवाद; सहयोग, शांति, और समृद्धि, जो मोटे तौर पर अन्य देशों की स्थिति के साथ प्रतिध्वनित होती है।

हिंद–प्रशांत को अब तक मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने, नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से एक रणनीतिक निर्माण के रूप में देखा जाता रहा है। हालांकि एफओआईपी का रणनीतिक घटक शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, फिर भी हिंद–प्रशांत प्रतिमान के आर्थिक एजेंडे को मजबूत करने की आवश्यकता है। एफओआईपी के विकास के आख्यान को ठोस बनाने के लिए, क्षेत्र के देश दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) और त्रिकोणीय सहयोग (टीआरसी) की भावना में परस्पर लाभकारी और मानव–केंद्रित आर्थिक सहयोग की पहल पर विचार कर सकते हैं। इन पहलों से व्यापार और निवेश प्रवाह, अवसंरचना में निवेश, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को गहरा करने और लोगों से लोगों और व्यापार से व्यापार साझेदारी को बढ़ाने के रूप में ठोस आर्थिक परिणाम मिल सकते हैं।

हाल के वर्षों में, भारत ने हिंद–प्रशांत क्षेत्र में व्यापक विकास साझेदारी को अपनाया है। दक्षिण एशियाई और पूर्वी अफ्रीकी देशों में दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) और त्रिकोणीय सहयोग (टीआरसी) के ढांचे के तहत कई परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सहक्रियात्मक सहयोग की अधिक संभावना को देखते हुए, भारत क्षेत्रीय भागीदारों के साथ अधिक गहन जुड़ाव के महत्व को रेखांकित करता है। इसके अलावा, भारत के लिए त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय विकास सहयोग के नए क्षितिज का पता लगाने के लिए हिंद–प्रशांत महत्वपूर्ण है। विकास साझेदारी के विशिष्ट क्षेत्रों में विकास नवाचार, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सामुदायिक विकास, शिक्षा और अनुसंधान और विकास, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विविधीकरण और जमीनी स्तर पर विकास, डिजिटलीकरण शामिल हो सकते हैं।

कोविड –19 महामारी के प्रकोप ने हिंद–प्रशांत क्षेत्र सहित दुनिया में विकास की गति को प्रभावित किया है। इसने मानवता को उन प्राथमिकताओं और उभरती चुनौतियों के बारे में जागृत किया है, जिन्हें अभिनव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते, हिंद–प्रशांत को क्षेत्रीय देशों को व्यवस्थित आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने और लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा करने हेतु उपयुक्त नीतियों और पहलों को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इन विकासों के आलोक में, सहयोग के कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और विकास साझेदारी के विशिष्ट तौर–तरीकों की पहचान करना अनिवार्य है। आरआईएस आसियान, बिम्सटेक, हिंद महासागर और एशिया–अफ्रीका सहयोग पर अपने शोध कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इनमें से कुछ मुद्दों पर काम कर रहा है। उस प्रयास के हिस्से के रूप में, आरआईएस हिंद–प्रशांत आर्थिक सहयोग पर संबंधित क्षेत्रों में जीडीसी का लाभ उठाएगा, जिसमें चुनिंदा क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा जो उपर्युक्त कार्यक्रमों से संचित ज्ञान पर निर्भर होंगे। कार्यक्रम में तीन एकीकृत और परस्पर मजबूत करने वाले घटक होंगे, जैसे अनुसंधान, पक्ष–समर्थन और नीति–निर्माण में योगदान।

सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण – पूर्वोत्तर भारत का नजरिया

आरआईएस और पूर्वोत्तर प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं हिमायत फाउंडेशन (नेत्र) ने 'सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण – पूर्वोत्तर भारत का नजरिया' विषय पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। इस श्रृंखला में पहला वेबिनार 4 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। प्रोफेसर कनक हलोई, अध्यक्ष, नेत्र ने इसकी अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रमुख वक्ता ये थेः डॉ. सिलादित्य चटर्जी, सलाहकार, एसडीजी के लिए केंद्र, असम सरकार; प्रोफेसर मिलिंदो चक्रबर्ती, विजिटिंग फेलो, आरआईएस एवं एसोसिएट डीन, जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी; और डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस। डॉ. जयंत चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर–एनईआरसी ने इसका संचालन किया। ज्ञान साझेदार ये थेः संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम; सतत विकास लक्ष्यों के लिए केंद्र, असम सरकार; और जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हरियाणा।

दूसरा वेबिनार 11 जुलाई 2020 को 'असम में एसडीजी के स्थानीयकरण के मुद्दों और चुनौतियों' पर आयोजित किया गया। डॉ. पी.के. आनंद, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने इसकी अध्यक्षता की। प्रो. ज्योतिराज पाठक, प्रमुख, राजनीति विज्ञान विभाग, बोडोलैंड विश्वविद्यालय और नेत्र फाउंडेशंस के संस्थापक सदस्य इसके संचालक थे। पैनलिस्ट ये थेः श्री रूपक मजुमदार, आईएएस, आयुक्त, परिवर्तन और विकास विभाग, असम सरकार; डॉ. अभिजीत शर्मा, निदेशक, भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी; श्री जीबन चानरा फुकन, सलाहकार, एसडीजी के लिए केंद्र, असम; प्रो. पॉली वाउकुलीन, प्रमुख, महिला अध्ययन विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय; और डॉ. सैयद सुल्तान काजी, निदेशक, पूर्वोत्तर विकास फाउंडेशन, असम। ज्ञान साझेदार राजनीति विज्ञान विभाग, बोडोलैंड विश्वविद्यालय था।

तीसरा वेबिनार 18 जुलाई 2020 को 'त्रिपुरा में एसडीजी के स्थानीयकरण के मुद्दों और चुनौतियों' विषय पर आयोजित किया गया। श्री कृष्ण कुमार, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने सत्र की अध्यक्षता की और डॉ. सुभ्राबरन दास, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने इसका संचालन किया। पैनलिस्ट ये थेः श्री ए.के. चंदा, संयुक्त निदेशक, नियोजन (अर्थशास्त्र और सांख्यिकी) विभाग, त्रिपुरा सरकार; डॉ. वी.टी. द्रालॉन्ग, कुलपति, मार्टिन लूथर ईसाई विश्वविद्यालय, मेघालय; प्रो. चंद्रिका बसु मजुनदार, डीन, कला एवं वाणिज्य संकाय, त्रिपुरिया यूनिवर्सिटी; डॉ. जयंत चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर–एनईआरसी, असम; और डॉ. श्रीलेखा रॉय, कार्यकारी निदेशक, जीएचएटी, त्रिपुरा। इस सत्र के लिए ज्ञान साझेदार ये थेः ग्रामीण प्रबंधन विभाग, आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, त्रिपुरा।

चौथे वेबिनार, जो 25 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था, के दौरान 'सिक्किम में एसडीजी के स्थानीयकरण के मुद्दों और चुनौतियों' पर फोकस किया गया। प्रो. टी.सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने इसकी अध्यक्षता की। ज्ञान साझेदार सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग था। इस सत्र में पैनलिस्ट ये थेः प्रो. महेंद्र पी. लामा, दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू एवं मुख्य आर्थिक सलाहकार, सिक्किम सरकार; डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, आईएएस, सिक्किम सरकार के पूर्व मुख्य सचिव; डॉ. संध्या थापा, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, समाजशास्त्र विभाग, सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय; डॉ. दुर्गा प्रसाद छेत्री, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, राजनीति विज्ञान विभाग, सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय; और डॉ. सरला खलिंग, क्षेत्रीय निदेशक, अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट, ईस्टर्न हिमालय नॉर्थ–ईस्ट इंडिया।

इस श्रृंखला का पांचवां वेबिनार 1 अगस्त 2020 को 'मेघालय में एसडीजी के स्थानीयकरण के मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर आयोजित किया गया। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस और पूर्व प्रोफेसर एवं डीन, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जेएनयू ने इस सत्र की अध्यक्षता की। ग्रामीण विकास विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेघालय ज्ञान साझेदार था। डॉ. बेमिन टाडे, पूर्व सलाहकार (स्वास्थ्य), पूर्वोत्तर परिषद, मेघालय; डॉ. पी.एस. निआंगलांग, मुख्य नियोजन अधिकारी एवं प्रमुख, एसडीजी सेल, मेघालय सरकार; डॉ. देइग्रेशिया नोंगकिनरिह, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग, डॉ. पापिया दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रामीण विकास विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेघालय; और सुश्री मेफेरीन राइटाहियांग, अध्यक्ष, ग्रासरूट, शिलांग, मेघालय इस अवसर पर पैनलिस्ट थे।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँः विकास सहयोग

श्रृंखला के तहत छठा वेबिनार 'मिजोरम में एसडीजी के स्थानीयकरण के मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर 8 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया। श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, वरिष्ठ सहायक फेलो, आरआईएस ने वेबिनार की अध्यक्षता की। श्री नवीन वर्मा, पूर्व सचिव, डोनर मंत्रालय, भारत सरकार ने 'मिजोरम राज्य में समावेशी विकास' के बारे में चर्चा की, जिसके बाद अनेक प्रस्तुतियां दी गईं। ये प्रस्तुतियां डॉ. सी. वनलालरामसंगा, सचिव, नियोजन एवं कार्यान्वयन विभाग, मिजोरम सरकार द्वारा 'मिजोरम में एसडीजी के स्थानीयकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा की गई पहल' विषय पर; डॉ. सी. लालफाकजुअली, सहायक प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजॉल द्वारा 'मिजोरम में एसडीजी के स्थानीयकरण से संबंधित महिला–पुरुष मुद्दे' पर; डॉ. बिधु कांति दास, सहायक प्रोफेसर, प्रबंधन विभाग, मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजॉल द्वारा 'मिजोरम में औद्योगिक विकासः एमएसएमई के विशेष संदर्भ के साथ' विषय पर; और प्रो. तलुंगा, सचिव, यंग मिजो एसोसिएशन एवं परीक्षा नियंत्रक, मिजोरम विश्वविद्यालय द्वारा 'मिजोरम में एसडीजी के स्थानीयकरण में सीएसओ की भूमिका' विषय पर दी गईं। इस अवसर पर अध्यक्ष ने समापन भाषण दिया।

श्रृंखला के तहत सातवां वेबिनार 'अरुणाचल प्रदेश में एसडीजी के स्थानीयकरण के मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर 14 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया। राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने वेबिनार की अध्यक्षता की। वेबिनार के दौरान ये प्रस्तुतियां दी गईंः प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, माननीय कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश द्वारा 'अरुणाचल प्रदेश में एसडीजी के स्थानीयकरण में आजीविका और समावेशी विकास के मुद्दे' विषय पर; श्री प्रशांत एस. लोखंडे, आयुक्त, निवेश एवं नियोजन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 'अरुणाचल प्रदेश में एसडीजी के स्थानीयकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा की गई पहल' विषय पर; प्रो. केसांग देगी, प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश द्वारा 'अरुणाचल प्रदेश में एसडीजी के स्थानीयकरण से संबंधित महिला–पुरुष एवं बाल मुद्दे' विषय पर; डॉ. नारायण साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडी एंड पीआर, एनईआरसी, गुवाहाटी द्वारा 'अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय सरकार एवं एसडीजी का स्थानीयकरण' विषय पर; और श्री प्रदीप कुमार बेहरा, वरिष्ठ पत्रकार, अरुणाचल प्रदेश द्वारा 'अरुणाचल प्रदेश में एसडीजी के स्थानीयकरण में सिविल सोसायटी संगठनों और मीडिया की भूमिका' विषय पर।

श्रृंखला में आठवां वेबिनार 'मणिपुर में एसडीजी के स्थानीयकरण के मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर 22 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया। राजदूत भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान कूटनीति फेलो, आरआईएस ने वेबिनार की अध्यक्षता की। इस दौरान ये प्रस्तुतियां दी गईंः प्रो. ई. बिजॉयकुमार सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय द्वारा 'मणिपुर में एसडीजी के स्थानीयकरण में समावेशी विकास के मुद्दे' विषय पर; सुश्री कुलका रानी देवी, संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग, मणिपुर सरकार द्वारा "मणिपुर में एसडीजी के स्थानीयकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा की गई पहल' विषय पर; सुश्री थिंगरिफि लुंघारवो, कार्यकारी सचिव, पर्वतीय स्वदेशी ज्ञान केंद्र द्वारा 'मणिपुर में एसडीजी के स्थानीयकरण से संबंधित महिला–पुरुष मुद्दे' विषय पर; डॉ. एन. सुरजीतकुमार; प्रमुख, जनजातीय अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय परिसर, मणिपुर एवं पूर्व विजिटिंग स्कॉलर, यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटर्सरैंड, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका द्वारा 'मणिपुर में एसडीजी और जनजातीय विकासः समस्या एवं संभावनाएं' विषय पर; और डॉ. कनक हलोई, प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर–एनईआरसी (सेवानिवृत्त) एवं अध्यक्ष, नेत्र फाउंडेशन द्वारा "मणिपुर में एसडीजी के स्थानीयकरण में स्थानीय सरकार की भूमिका' विषय पर। इस श्रृंखला के तहत अंतिम वेबिनार 29 अगस्त, 2020 को 'नागालैंड में एसडीजी के स्थानीयकरण के मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वागत भाषण डॉ. दुर्गा प्रसाद छेत्री, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, राजनीतिक विभाग, सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। डॉ. डी. के. भल्ला, सीनियर रेजिडेंट कमिश्नर, नागालैंड सरकार ने इसकी अध्यक्षता की और इसके साथ ही वेबिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर ये प्रस्तुतियां दी गईंः श्री नोसाजोल चार्ल्स, अपर विकास आयुक्त, नियोजन एवं समन्वय विभाग, नगालैंड द्वारा "नगालैंड में एसडीजी के स्थानीयकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा की गई पहल" विषय पर; डॉ. रोंगसेन एओ, सहायक प्रोफेसर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, असम द्वारा 'नगालैंड में एसडीजी के स्थानीयकरण में सतत कृषि' विषय पर; डॉ. पेटेखरे, महिला अध्ययन केंद्र, नगालैंड विश्वविद्यालय द्वारा 'नागालैंड में एसडीजी के स्थानीयकरण से संबंधित महिला–पुरुष मुद्दे' विषय पर; डॉ. कनक हलोई, प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर–एनईआरसी (सेवानिवृत्त) एवं अध्यक्ष, नेत्र फाउंडेशन द्वारा 'नागालैंड में स्थानीय सरकार और एसडीजी का स्थानीयकरण' विषय पर; और डॉ. अंबा जमीर, निदेशक, सतत विकास फाउंडेशन, नगालैंड द्वारा 'नगालैंड में एसडीजी के स्थानीयकरण में सिविल सोसायटी संगठनों की भूमिका' विषय पर।

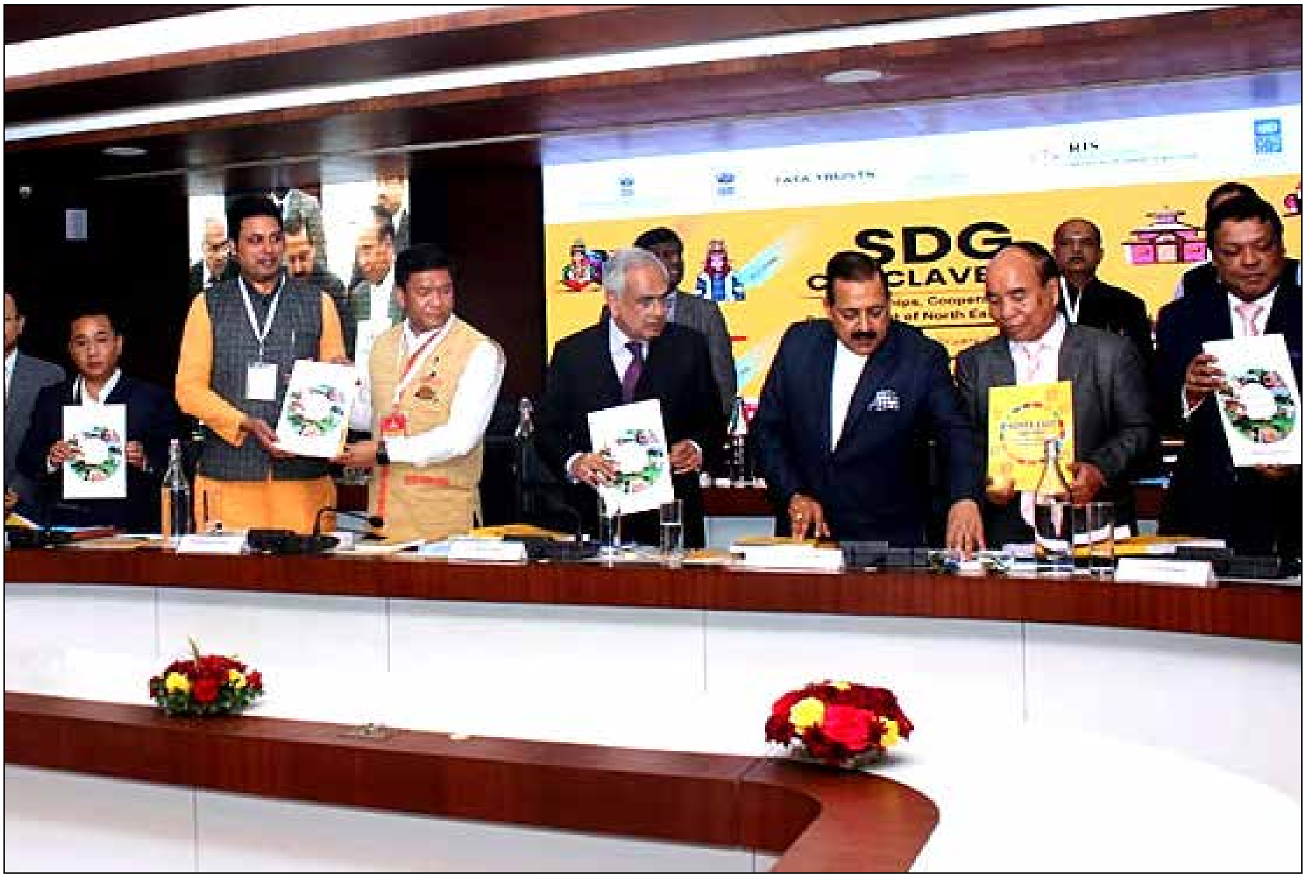

24–26 फरवरी, 2020 को असम के गुवाहाटी में 'पूर्वोत्तर एसडीजी कॉन्क्लेव' का आयोजन किया गया जिसमें केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।

एसडीजी कॉन्क्लेव 2020 – पूर्वोत्तर राज्यों की साझेदारियां, सहयोग और विकास

आरआईएस को नीति आयोग ने पूर्वोत्तर एसडीजी कॉन्क्लेव के लिए अपने ज्ञान साझेदार के रूप में नामित किया था जो 24–26 फरवरी 2020 को गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया और जिसमें केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इस कवायद में अन्य साझेदारों में असम सरकार, टाटा ट्रस्ट्स और यूएनडीपी शामिल थे। आरआईएस को पूर्वोत्तर और एसडीजी पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो सितंबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच के छह माह की अवधि में तैयार की गई थी।

पूर्वोत्तर में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ अक्सर उच्चतम राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर व्यापक सलाह–मशविरा करने और आरआईएस के संकाय सदस्यों द्वारा विभिन्न राज्यों की राजधानियों के क्षेत्र दौरे (फील्ड विजिट) करने के बाद ही इस रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया। जमीनी हकीकत और दृष्टिकोण को समझने के लिए स्थानीय संसाधन व्यक्तियों और नेत्र फाउंडेशन के साथ मिलकर एक कार्यशाला अक्टूबर 2019 में आयोजित की गई थी। इस बारे में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। रिपोर्ट में ये अध्याय शामिल थेः राज्य की पहल एवं एसडीजी का स्थानीयकरण; आर्थिक समृद्धि एवं सतत आजीविका के वाहक; जलवायु अनुकूल कृषि व विविधीकरण; पोषण, स्वास्थ्य एवं खुशहाली; शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता; संचार, कनेक्टिविटी व बुनियादी ढांचागत विकास; और एसडीजी का वित्तपोषण।

'भारत–वियतनाम एसएंडटी सहयोगः संभावनाएं और परिप्रेक्ष्य' विषय पर वेबिनार

आरआईएस ने नई दिल्ली स्थित वियतनाम दूतावास के सहयोग से 24 जून 2020 को 'भारत–वियतनाम एसएंडटी सहयोगः संभावनाएं और परिप्रेक्ष्य' विषय पर वेबिनार आयोजित किया। भारत में वियतनाम के राजदूत माननीय फाम सनाह चाऊ और वियतनाम में भारत के राजदूत श्री प्रणय वर्मा ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वेबिनार के प्रमुख वक्ताओं में ये शामिल थेः श्री संजीव वार्ष्णेय, प्रमुख और सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग (आईबीसीडी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत; प्रोफेसर डॉ. ले वान टोन, वैज्ञानिक परिषद के अध्यक्ष, भारतीय अध्ययन केंद्र; श्री अरविंद गुप्ता, संस्थापक, आईस्प्रिट एवं डिजिटल इंडिया फाउंडेशन; डॉ. ले थई हैंग नगा, उप प्रधान संपादक, भारतीय और एशियाई अध्ययन के लिए पत्रिका, भारतीय एवं दक्षिण पश्चिम एशियाई अध्ययन संस्थान; और डॉ. बी. बालाकृष्णन, पूर्व भारतीय राजदूत एवं विज्ञान कूटनीति फेलो, आरआईएस। इस सेमिनार का उद्देश्य भारत और वियतनाम के एसएंडटी समुदायों के बीच जुड़ाव सुनिश्चित करना था।

एक–दूसरे पर निर्भर दुनिया में दक्षिणीय सहयोग का विस्तार करना

आरआईएस ने प्रेसिडेंशियल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ कोलंबिया (एपीसी–कोलंबिया) के परामर्श से 10–11 सितंबर 2020 को 'एक–दूसरे पर निर्भर दुनिया में दक्षिणीय सहयोग का विस्तार करना' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। पहला सत्र 10 सितंबर 2020 को 'अंतर–निर्भरता और एकजुटताः ऐसे साझेदारों के बीच कार्य जिन्हें एक–दूसरे की जरूरत है' विषय पर आयोजित किया गया। दूसरा सत्र 11 सितंबर 2020 को 'कोविड–19 के बाद असंगत संवादः जो आप जानना चाहते हैं, लेकिन जिसे आप पूछ नहीं पाए हैं' विषय पर आयोजित किया गया।

प्रथम सत्र में इस पर चर्चा हुई कि प्रत्येक क्षेत्र में साझा या आम भाषाओं, इतिहास, प्रभाव क्षेत्रों और विकास संबंधी समस्याओं वाले देश शामिल हैं। ये अंतर–निर्भरताएं दक्षिणीय सहयोग का आधार हैं – एक देश में विकसित समाधानों को दूसरे देश में अनुकूल बनाने के साथ–साथ उसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है, ताकि सभी लोगों की भलाई हो सके। लेकिन इस अंतर–निर्भरता में भी एक जोखिम शामिल है। वैश्विक संकट की स्थिति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि हमारी अर्थव्यवस्थाएं, हमारी राजनीतिक प्रणालियां और हमारे समाज हमारे पड़ोसियों को घेरने वाली समस्याओं के प्रति कितने असुरक्षित हैं। चाहे हम जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, पूंजी के प्रवाह या बीमारी के फैलने पर चर्चा कर रहे हों या नहीं, लेकिन यह सत्य है कि कुछ परिस्थितियां कई देशों को हिला देती हैं और वैसे में संयुक्त प्रयास करना अत्यंत आवश्यक होता है।

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने 'कोविड–19 के बाद असंगत संवादः जो आप जानना चाहते हैं, लेकिन जिसे आप पूछ नहीं पाए हैं' विषय पर आयोजित दूसरे सत्र के दौरान प्रस्तुति दी। आरआईएस की ओर से प्रोफेसर मिलिंदो चक्रबर्ती, विजिटिंग फेलो ने भी इसमें भाग लिया। सत्र के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि कोविड–19 महामारी ने हमारी सरकारों, कंपनियों एवं संगठनों को आकलन करने और गंभीर सामाजिक–आर्थिक प्रभावों वाले वायरस के विस्तार को रोकने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए त्वरित रूप से सीखने वाले मार्ग पर अग्रसर कर दिया है जो हमारी अंतर–निर्भरता के कारण स्वयं भी संक्रामक हैं। लॉकडाउन के कारण जीवन जिस तरह से आभासी या वर्चुअल हुआ है उससे पहले से ही महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय और शहरी प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय हैं, और जिसके लिए दक्षिणीय सहयोग के तहत अभिनव तौर–तरीके ढूंढ़ने होंगे। हालांकि, मौजूदा हालात के कारण उन अन्य आवश्यक मुद्दों से हमारा ध्यान पूरी तरह से विचलित नहीं होना चाहिए, जिन पर चर्चा करना अत्यंत जरूरी है।

भारत और कोटे डी आइवर के बीच सहयोग की पहलों को मजबूत बनाना

आरआईएस ने अबिदजान स्थित भारतीय दूतावास और आइवरी कोस्ट की सरकार के साथ साझेदारी में 17 सितंबर 2020 को भारत और कोटे डी आइवर के बीच सहयोग की पहलों को मजबूत बनाने पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

Webinar in progress

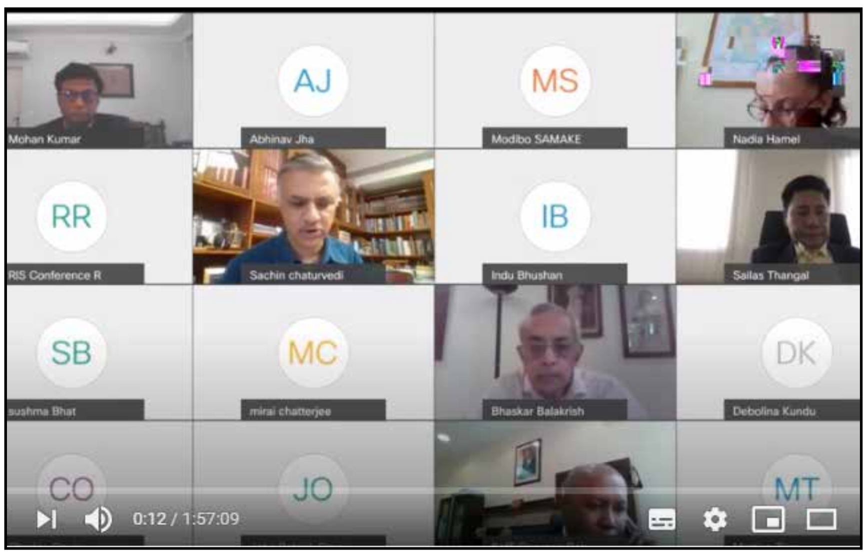

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता आरआईएस के चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार ने की। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और कोटे डी आइवर में भारत के राजदूत सैलस थंगल ने स्वागत भाषण दिए। मुख्य भाषण श्री पैट्रिक अची, राष्ट्रपति कार्यालय में माननीय मंत्री, कोटे डी आइवर द्वारा दिया गया। 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रणालियां लागू करने में भारत–कोटे डी आइवर सहयोग के लिए अवसर' विषय पर आयोजित प्रथम सत्र की अध्यक्षता कोटे डी आइवर में भारत के राजदूत सैलस थंगल ने की। आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी – पीएमजेएवाई) एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सीईओ डॉ. इंदु भूषण; और पीएचएफआई के अध्यक्ष डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी ने इस सत्र के दौरान विशेष भाषण दिए।

'कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत–कोटे डी आइवर सहयोग के अवसर' पर आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता आरआईएस के विज्ञान कूटनीति फेलो डॉ. भास्कर बालाकृष्णन ने की। प्रतिष्ठित पैनलिस्ट ये थेः डॉ. आनंद कुमार सिंह, उप महानिदेशक (बागवानी विज्ञान), आईसीएआर, जिन्होंने खेती प्रणाली, जलवायु अनुकूलन खेती, एनआरएम, इत्यादि पर संभावित तकनीकी सहयोग के बारे में बताया.; और डॉ. टी.पी. राजेंद्रन, पूर्व सहायक महानिदेशक, आईसीएआर एवं सहायक फेलो, आरआईएस ने एकीकृत कीट प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति, कृषि रसायनों और जैविक कच्चे माल जैसे कि जैव उर्वरकों, सूक्ष्मजीव कीटनाशकों सहित जैव कीटनाशकों की नियामकीय प्रणाली, कृषि संबंधी कच्चे माल के गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन, कृषि संबंधी अच्छे तौर–तरीकों के जरिए खेत जिंस सुरक्षा आश्वासन के बारे में बताया।

तीसरा सत्र 'स्वयं–सहायता समूहों (एसएचजी) एवं किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ); और किफायती आवास के लिए नीतियां लागू करने में भारत–कोटे डी आइवर सहयोग के अवसर' विषय पर आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता भारतीय विकास सहयोग फोरम (एफआईडीसी) के अध्यक्ष डॉ. राजेश टंडन ने की। पैनलिस्ट ये थेः डॉ. मिराई चटर्जी, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, स्व–नियोजित महिला संघ (सेवा); और प्रोफेसर डॉ. देबोलीना कुंडू, शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान (एनआईयूए)।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँः विकास सहयोग

डॉ. एस. जयशंकर, भारत के माननीय विदेश मंत्री और माननीय श्री फेलिप सोला, अर्जेंटीना के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उपासना मंत्री वेबिनार को संबोधित करते हुए।

नई विश्व व्यवस्था में भारत और अर्जेंटीना

भारतीय दूतावास, अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं पराग्वे और आरआईएस ने सीआईपीपीईसी के साथ मिलकर 6 नवंबर, 2020 को 'नई विश्व व्यवस्था में भारत और अर्जेंटीना' विषय पर एक आभासी (वर्चुअल) वेबिनार आयोजित किया। माननीय डॉ. एस. जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री और माननीय श्री फेलिप सोला, अर्जेंटीना के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उपासना मंत्री ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

माननीय मंत्री डॉ. जयशंकर ने अपने संबोधन में इस बात पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अर्जेंटीना के साथ हमारे संबंधों को वर्ष 2019 में एक रणनीतिक साझेदारी में परिणत कर दिया गया, जब हमारे राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो गए थे। पिछले दस वर्षों में हमारा द्विपक्षीय व्यापार दोगुने से भी अधिक हो गया है, और अर्जेंटीना में कई भारतीय कंपनियों की उपस्थिति तथा भारत में अर्जेंटीना की अनेक कंपनियों की मौजूदगी से हमारे मजबूत आर्थिक संबंध अब और भी अधिक प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। हालांकि, कृषि, खनन एवं खनिज, तेल व गैस, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और मोटर–वाहन (ऑटोमोटिव्स) के क्षेत्र में आपसी सहभागिता बढ़ाने के लिए पूरकता या पारस्परिक आदान–प्रदान की अब भी व्यापक गुंजाइश है। अर्जेंटीना के लोग दरअसल भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता के मुरीद हैं। अर्जेंटीना इसके साथ ही भारत की सामूहिक सांस्कृतिक चेतना में विशेष स्थान रखता है। अर्जेंटीना में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक योग विशेषज्ञों की मौजूदगी और बड़ी संख्या में योग स्कूलों को खोला जाना अपने आप में इस सच्चाई को अभिव्यक्त करता है।

वेबिनार में उद्घाटन और समापन सत्र सहित कुल तीन मुख्य सत्र थे। उद्घाटन सत्र को अर्जेंटीना में भारत के राजदूत श्री दिनेश भाटिया, आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी, और सीआईपीपीईसी की कार्यकारी निदेशक डॉ. जूलिया पोमारेस ने संबोधित किया। राजदूत दिनेश भाटिया ने वेबिनार के संदर्भ के बारे में बताया और इसके साथ ही हमारे सामान्य सिद्धांतों, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, कूटनीति, रुचि व मूल्य में हमारे आपसी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी की दृष्टि से दोनों देशों के बीच हमारे मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला। इस दौरान दो रणनीतिक साझेदारों भारत और अर्जेंटीना के बीच के संबंधों की मौजूदा स्थिति और भविष्य के बारे में विचार–विमर्श किया गया। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने डिजिटल दुनिया में नई विश्व व्यवस्था को सटीक स्वरूप देने और जी–20 की सऊदी अध्यक्षता के प्रति ब्यूनस आयर्स से आ रही दक्षिणीय सहयोग से जुड़ी पूरी गाथा का विस्तार करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे साझा प्रयासों की सराहना की। डॉ. जूलिया पोमारेस ने अर्जेंटीना एवं भारत के बीच विकास सहयोग और वैश्विक दक्षिण में अनुसंधान संबंधी पहल में संभावित साझेदारी पर विशेष जोर दिया क्योंकि डिजिटलकरण से दोनों ही देशों के श्रम बाजार काफी प्रभावित होंगे।

'भारत–अर्जेंटीना द्विपक्षीय संबंध' पर आयोजित पहले सत्र की अध्यक्षता डॉ. टी. सी. ए. राघवन, महानिदेशक, विश्व मामलों की भारतीय परिषद ने की। सत्र में पैनलिस्ट ये थेः प्रो. सुनंदा सेन, अर्थशास्त्र की पूर्व प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, डॉ. मारिया फ्लोरेंसिया रूबियोलो, कोर्डोबा कैथोलिक विश्वविद्यालय – कॉनिकेट और डॉ. मैनुअल गोन्जालो, जनरल सरमिएंटो नेशनल यूनिवर्सिटी–यूएनडीईसी, और श्री बर्नाबे मलाकाल्जाल, क्विल्म्स नेशनल यूनिवर्सिटी – कॉनिकेट – टॉरक्वाटो डि टेला यूनिवर्सिटी ने भारत एवं अर्जेंटीना के बीच द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग और कोविड काल के बाद व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की संभावनाओं पर आयोजित व्यापक परिचर्चा का संचालन किया। सत्र के दौरान द्विपक्षीय व्यापार के मौजूदा प्रवाह, रणनीतिक साझेदारी, व्यापार में और भी अधिक विविधीकरण लाने की संभावनाओं तथा दोनों देशों के बीच समानता पर गौर किया गया, क्योंकि दोनों ही देश महामारी के दौरान कुछ वृहद आर्थिक संकेतकों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। सत्र के दौरान कुछ प्राथमिकताओं के साथ–साथ विशेषकर व्यापार व निवेश और

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ: विकास सहयोग

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) में सहयोग वाले फोकस क्षेत्र पर भी प्रकाश डाला गया। इस दौरान स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में केंद्रित व गहन सहयोग पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि प्रौद्योगिकी और तकनीकी व्यवधान विभिन्न देशों के सामने कई चुनौतियां उत्पंन्न कर देते हैं, जिनसे निपटने के लिए बहुराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्र के पास देने के लिए संभवतः कुछ पर्याप्त नहीं है और निर्यात दायरे को व्यापक बनाना होगा और इसके साथ ही इसका स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार मांग बढ़ाने की कोशिश कर रही है। विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत बुनियादी ढांचागत सुविधाएं और ऊर्जा चुनौतियां दोनों ही देशों के लिए चिंता का प्रमुख विषय हैं जिन पर और भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः भारत और अर्जेंटीना के पास एक बेहतर स्थिति में पहुंचने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य व बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के जरिए समावेशिता को प्रोत्साहित करने के लिए आपस में हाथ मिलाने; एसटीआई सहयोग का सशक्तिकरण करने; और आपस में मिलकर काम करने हेतु बहुपक्षवाद का विस्तार करने के लिए व्यापक गुंजाइश है।

'भूमंडलीकरण, डिजिटलीकरण और अनुसंधान पहलः वैश्विक दक्षिण से सबक' विषय पर आयोजित दूसरे संवादात्मक सत्र की अध्यक्षता सुश्री इरेन ब्रांबिला, वितरण, श्रम एवं सामाजिक अध्ययन केंद्र ने की। इसमें चार पैनलिस्ट ये थेः डॉ. रजत कथूरिया, निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद; डॉ. उर्वशी अनेजा, संस्थापक निदेशक, टैन्डम रिसर्च; डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस और श्री रामिरो अलब्रियू, आर्थिक विकास के वरिष्ठ शोधकर्ता, सीआईपीपीईसी। सभी वक्ताओं ने प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर विशेष जोर दिया और इसके साथ ही एआई जैसी नई तकनीकों की क्षमता का उपयोग करने के तरीकों तथा एक समावेशी, सतत एवं न्यायसंगत समाज की अगुवाई करने में इसके विशिष्ट योगदान पर विचार–विमर्श किया। सत्र के दौरान भारत एवं अर्जेंटीना के वर्तमान विकास पथ पर फोकस किया गया और इसके साथ ही इस बारे में एक रोडमैप पेश किया गया कि आखिरकार कैसे और भी अधिक आत्मनिर्भर बनना संभव है एवं प्रौद्योगिकी किस तरह से उत्पादकता बढ़ा सकती है। आम तौर पर, बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जाने संबंधी प्रतिकूल प्रभाव के लिए प्रौद्योगिकी को ही दोषी ठहराया जाता है, लेकिन यह भी सच है कि इसमें सतत उपभोग और उत्पादन से जुड़ा सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता होती है। वक्ताओं ने इस बात पर चर्चा की कि हम आर्थिक विकास के लिए पारंपरिक क्षेत्र में नई जान कैसे डाल सकते हैं।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने 'कोविड काल के बाद नई विश्व व्यवस्था में भारत और अर्जेंटीना' विषय पर आयोजित तीसरे सत्र में एक प्रस्तुति दी। सत्र की अध्यक्षता श्री रिकार्डो कैरिसियोफी, आर्थिक विकास कार्यक्रम के वरिष्ठ शोधकर्ता, सीआईपीपीईसी ने की। इस दौरान अन्य प्रख्यात वक्ता ये थेः श्री जॉर्ज चेडिएक, पूर्व निदेशक, संयुक्त राष्ट्र दक्षिणीय सहयोग कार्यालय, प्रो. हर्ष वी पंत, अध्ययन निदेशक एवं प्रमुख, रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और सुश्री ग्लेडिस लेचिनी, रोसारियो नेशनल यूनिवर्सिटी – कोनिकेट। प्रो. चतुर्वेदी ने बहुपक्षवाद के मुद्दे पर प्रकाश डाला और वैश्विक दक्षिण के बीच मतभेद का मुद्दा उठाया। अतः बहुपक्षवाद के विचार पर नए सिरे से गौर करने का समय अब आ गया है। इसके साथ ही अधिक उत्तरदायी, अभिनव, रचनात्मक और ज्यादा सक्रियता वाली भागीदारी पर वैश्विक समझौता करने की जरूरत है। भारत और अर्जेंटीना को नैतिक सिद्धांतों पर फिर से अमल सुनिश्चित करने के लिए आपस में हाथ मिलाना चाहिए। प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि हमें एक–दूसरे के सांस्कृतिक जुड़ाव को समझने के लिए और भी ज्यादा सिद्धांतकारों या विचारकों की आवश्यकता है, ताकि वैश्विक दक्षिण में और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना संभव हो सके।

अंतिम समापन भाषण माननीय डॉ. एस. जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री और माननीय श्री फेलिप सोला, अर्जेंटीना के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उपासना मंत्री ने दिए। श्री सोला ने हमारे पारंपरिक समर्थन और व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सहयोग एवं कूटनीति में लंबे समय तक चलने वाले रणनीतिक गठबंधन पर प्रकाश डाला। भारत और अर्जेंटीना की कई संयुक्त परियोजनाएं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष सहयोग समझौतों, ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था, आईटी, जैव–प्रौद्योगिकी, कृषि–प्रौद्योगिकी, इत्यादि के क्षेत्र में हैं, क्योंकि दोनों ही देशों का अत्यंत लंबा शाश्वत साझा इतिहास रहा है और उनमें एक–दूसरे की संस्कृति के लिए आत्मीयता एवं सम्मान है। अतः दोनों ही राष्ट्र आपसी संबंधों को और भी अधिक प्रगाढ़ कर सकते हैं।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँः विकास सहयोग

'कोविड–19 और दक्षिण एशिया में मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने के उपायः सीखने और सहयोग के अवसर'

हाल के अध्ययनों में अनुमान लगाया गया है कि दक्षिण एशिया की एक चौथाई से भी अधिक आबादी कम से कम एक मानसिक स्वास्थ्य विकार से निश्चित तौर पर पीड़ित है। विश्व आर्थिक फोरम का अनुमान है कि विश्व स्तर पर मानसिक बीमारियों के परिणामस्वरूप वर्ष 2010 और वर्ष 2030 के बीच 16.1 ट्रिलियन अमेरिकी डालर का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कोविड–19 ने इस स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ दिया है। इसकी मुख्य वजहें महामारी से जुड़ा भय एवं अनिश्चितता, अनजान या अपरिचित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के कारण बढ़ता सामाजिक अलगाव, और वित्तीय नुकसान हैं। दक्षिण एशिया में ज्ञान और संसाधनों के आदान–प्रदान के जरिए दक्षिणीय सहयोग इन चिंताओं को दूर करने और इस बारे में सक्रिय रणनीतियां बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। हालांकि, इस मुद्दे को सुलझाने पर अब तक जो भी चर्चाएं की गई हैं और नीतिगत रणनीतियां अपनाई गई हैं वे बेहद अपर्याप्त रही हैं। इन मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए आरआईएस ने एक प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान संगठन 'संगत' के साथ मिलकर 24 नवंबर 2020 को 'कोविड–19 और दक्षिण एशिया में मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने के उपायः सीखने और सहयोग के अवसर' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। कोविड–19 के मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन करने, इस क्षेत्र में अपनाई जा रही स्वास्थ्य प्रणालियों एवं तंत्रिका विज्ञान संबंधी उपायों पर चर्चा करने, और आगे की राह के बारे में योजना बनाने के लिए इस वेबिनार ने शिक्षाविदों एवं नीति निर्माताओं के साथ–साथ पूरे दक्षिण एशिया के मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान विशेषज्ञों को एकजुट किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। प्रो. के. श्रीनाथ रेड्डी, अध्यक्ष, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने उद्घाटन भाषण दिया और प्रो. विक्रम पटेल, वैश्विक स्वास्थ्य और सामाजिक चिकित्सा विभाग, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने मुख्य भाषण दिया।

इसके बाद आयोजित पैनल परिचर्चा का संचालन डॉ. अनंत भान, प्रमुख, संगत, भोपाल ने किया। इसमें उपस्थित पैनलिस्ट ये थेः डॉ. सुनीमले मदुरावाला, अनुसंधान अर्थशास्त्री, नीतिगत अध्ययन संस्थान, कोलंबो; डॉ. रोहुल्ला अमीन, बिरूनी संस्थान, काबुल; प्रो. पुष्पा प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, मनोरोग विभाग, किस्ट मेडिकल कॉलेज, नेपाल; श्री मोहम्मद कमरुज्जमां, वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी, नीतिगत संवाद केंद्र, ढाका; प्रोफेसर सुरिंदर जायसवाल, उप निदेशक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई; प्रो. नीरज जैन, निदेशक, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुड़गांव; डॉ. ईश्वर वी. बसवाराडडी, निदेशक, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली; और सुश्री शुभ्रता प्रकाश, निदेशक, नीति आयोग, नई दिल्ली।

कोविड–19 से निपटने के लिए बहुपक्षीय उपायः दक्षिण एशिया की ओर से परिप्रेक्ष्य

'कोविड–19 से निपटने के लिए बहुपक्षीय उपाय – दक्षिण एशिया की ओर से परिप्रेक्ष्य' विषय पर वेबिनार 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया। यह वेबिनार नीतिगत संवाद केंद्र (सीपीडी) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा आरआईएस, सतत विकास नीतिगत संस्थान (एसडीपीआई), श्रीलंका के नीतिगत अध्ययन संस्थान और व्यापार, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण पर दक्षिण एशिया वॉच (एसएडब्ल्यूटीईई) के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। नीतिगत संवाद केंद्र (सीपीडी) के अध्यक्ष प्रोफेसर रहमान सोभन ने इसकी अध्यक्षता की। कार्यक्रम की शुरुआत नीतिगत संवाद केंद्र (सीपीडी) की कार्यकारी निदेशक डॉ. फहमीदा खातून के आरंभिक भाषण के साथ हुई। मुख्य प्रस्तुति श्री ओलिवियर कट्टानियो, इकाई के प्रमुख, नीतिगत विश्लेषण एवं रणनीति, विकास सहयोग निदेशालय, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी), और डॉ. देबाप्रिया भट्टाचार्य, प्रतिष्ठित फेलो, सीपीडी एवं अध्यक्ष, सदर्न वॉयस द्वारा दी गई। इसके बाद क्षेत्रीय साझेदारों ने अपने–अपने विचार व्यक्त किएः प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; डॉ. आबिद काइयूम सुलेरी, कार्यकारी निदेशक, सतत विकास नीतिगत संस्थान (एसडीपीआई), पाकिस्तान; डॉ. दशनी वीराकून, कार्यकारी निदेशक, श्रीलंका का नीतिगत अध्ययन संस्थान (आईपीएस), श्रीलंका; और डॉ. पुष्पा शर्मा, कार्यकारी निदेशक, व्यापार, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण पर दक्षिण एशिया वॉच (एसएडब्ल्यूटीईई), नेपाल। क्षेत्रीय साझेदारों द्वारा अपने–अपने विचार व्यक्त करने के बाद परिचर्चा आयोजित की गई। इसके बाद डॉ. ए. बी. मिर्जा अजीजुल इस्लाम, कार्यवाहक सरकार के पूर्व सलाहकार, वित्त एवं नियोजन मंत्रालय ने विशेष भाषण दिया और श्री जॉर्ज मोरीरा डा सिल्वा, विकास सहयोग निदेशालय के निदेशक, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) ने वीडियो संदेश भेजा। सीपीडी के अध्यक्ष प्रोफेसर रहमान सोभन ने समापन भाषण दिया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँः विकास सहयोग

भारत–श्रीलंका संबंध

आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र, आईसीडब्ल्यूए, पाथफाइंडर फाउंडेशन और एशियन कनफ्लुएंस ने 29 अक्टूबर 2020 को 'भारत–श्रीलंका संबंधः नई विश्व व्यवस्था में भारत–श्रीलंका संबंधों को मजबूत करना' विषय पर संयुक्त रूप से वर्चुअल (आभासी) संवाद आयोजित किया। डॉ. टी सी ए राघवन, महानिदेशक, विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) ने इसकी अध्यक्षता की। एशियन कनफ्लुएंस के कार्यकारी निदेशक श्री सब्यसाची दत्ता ने स्वागत भाषण दिया। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और राजदूत बर्नार्ड गुनेटिलेके, अध्यक्ष, पाथफाइंडर फाउंडेशन ने आरंभिक भाषण दिए। एडमिरल जयनाथ कोलोमबेज (सेवानिवृत्त), विदेश सचिव, श्रीलंका ने मुख्य भाषण दिया।

पैनल परिचर्चा की अध्यक्षता राजदूत, अशोक के. कांथा, निदेशक, चीनी अध्ययन संस्थान (आईसीएस), और श्रीलंका में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त ने की। डॉ. गणेशन विघ्नराज, वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, लंदन; प्रो. रोहन समरजीवा, संस्थापक अध्यक्ष, लिरनेशिया, कोलंबो; और श्री विश गोविंदसामी, समूह के प्रबंध निदेशक, सनशाइन होल्डिंग्स पीएलसी एवं उपाध्यक्ष, द सीलोन चैंबर ऑफ कॉमर्स, कोलंबो इस अवसर पर श्रीलंका की ओर से मुख्य वक्ता थे। भारत की ओर से डॉ. समाथा मल्लेम्पति, रिसर्च फेलो, आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली; प्रो. बिस्वजीत नाग, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, दिल्ली; और श्री एम.एस. नेगी, वाइस–प्रेसीडेंट (ऋण), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), कोलंबो ने इन चर्चाओं की अगुवाई की।

माननीय श्री गोपाल बागले, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त, कोलंबो ने समापन भाषण दिया और डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर, आरआईएस स्थित एआईसी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

आईसीडब्ल्यूए, आरआईएस, केएनडीए, और कीप के बीच द्विपक्षीय संवाद पर एमओयू का हस्ताक्षर समारोह

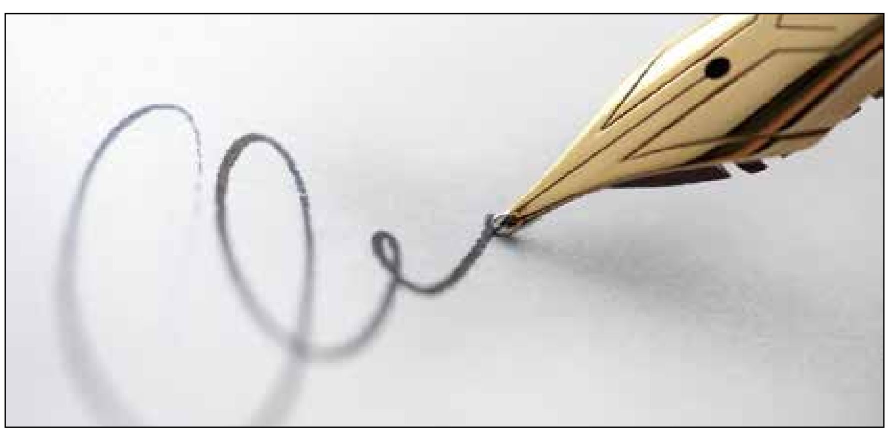

आईसीडब्ल्यूए और आरआईएस ने 22 अक्टूबर 2020 को आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कोरिया गणराज्य की कोरिया राष्ट्रीय राजनयिक अकादमी (केएनडीए) और कोरिया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति संस्थान (कीप) के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। प्रो. वोंगी चोए (प्रमुख, आसियान–भारतीय अध्ययन केंद्र, केएनडीए) ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। डॉ. किम जून–ह्यूंग, कुलाधिपति, केएनडीए; डॉ. टी.सी.ए. राघवन, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए; डॉ. जंग सुंग चुन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कीप; और डॉ. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने भाषण दिए। इसके बाद एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन, कोरिया गणराज्य में भारत की राजदूत; और राजदूत शिन बोंगकिल, भारत में कोरिया गणराज्य के राजदूत ने विशेष भाषण दिए। खुली परिचर्चा के बाद डॉ. जोजिन जॉन, रिसर्च फेलो, आईसीडब्ल्यूए ने समापन भाषण दिया।

सतत विकास हेतु उत्कृष्ट कार्यों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारियां

दिल्ली VI की ओर अग्रसर होने पर वेबिनार श्रृंखला के तहत नेस्ट, यूएनडीपी, आरआईएस और अनाहुआक, मेक्सिको ने 18 दिसंबर 2020 को 'लैटिन अमेरिका में सतत विकास हेतु उत्कृष्ट कार्यों को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणीय साझेदारियों' पर संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया। वर्ष 2013 से ही दक्षिणी प्रदाताओं के सम्मेलन (दिल्ली प्रोसेस) में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत संबंधित हितधारकों के बीच एसएससी से जुड़े मुद्दों और उभरती चुनौतियों पर चर्चाएं होती रही हैं।

एसएससी से जुड़ी अनेक वार्षिक बैठकें और विशेष चर्चाएं दरअसल विशेषज्ञों, प्रोफेशनलों, शिक्षाविदों, थिंक टैंकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए अपने–अपने अनुभवों एवं ज्ञान को साझा करने का अनूठा मंच बन गईं। वर्तमान कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ जुड़ाव एवं संपर्क बनाना, अपने हितों की पूर्ति को बढ़ावा देना, और एसएससी संबंधी प्रयासों से जुड़ी चिंताओं को दूर करना था, ताकि वर्तमान कोविड–19 संकट से बेहतर ढंग से उबरने के लिए विभिन्न देशों को आवश्यक सहयोग मिल सके।

उत्कृष्ट '1978 ब्यूनस आयर्स कार्य योजना' में कामयाबी पाने की आकांक्षा रखते हुए 'दक्षिणीय सहयोग पर द्वितीय संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सम्मेलन (बीएपीए 40)' ने अंततः इस मुख्य प्रश्न का हल सुझाने का मंच उपलब्ध कराया: सतत विकास में दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) का ठोस योगदान क्या है? मुख्य चुनौती यह आकलन करना है कि क्या एसएससी कार्यक्रम और परियोजनाएं विकासशील देशों की गरीबी मिटाने, असमानता घटाने एवं उच्च मूल्य वाली अधिक–से–अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ा रही हैं (अर्थात एसडीजी2: 'शून्य भुखमरी', एसडीजी8: 'उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास' और एसडीजी17: 'लक्ष्यों के लिए साझेदारियां')। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और डॉ. सांद्रा सोसो, उप–निवासी प्रतिनिधि, यूएनडीपी मेक्सिको के आरंभिक भाषणों के साथ हुई। इसके बाद 'सतत विकास हेतु उत्कृष्ट कार्यों को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणीय साझेदारियां: चुनौतियां और अवसर' विषय पर सत्र आयोजित किया गया।

मुख्य वक्ता ये थे: डॉ. गेब्रियल टेरेस, कार्यकारी निदेशक के सलाहकार, एमेक्ससिड; डॉ. पाउलो एस्टेवेस, ब्रिक्स नीतिगत केंद्र के निदेशक; डॉ. मार्टिन रिवेरो, सामाजिक सामंजस्य एवं एसएससी इकाई के समन्वयक, एसईजीआईबी; और डॉ. लिडिया फ्रॉम सीईए, कार्यकारी निदेशक, मेसोअमेरिकन एकीकरण एवं विकास परियोजना। डॉ. कार्लोस कोर्टेस जिया, एमेक्ससिड–यूएनडीपी सहयोग कार्यक्रम के समन्वयक, यूएनडीपी मेक्सिको इस अवसर पर चर्चाकर्ता एवं संचालक थे।

पैनलिस्टों ने संबंधित क्षेत्र में एसएससी संबंधी अभिनव दृष्टिकोणों के तहत लैटिन अमेरिका में सतत विकास हेतु उत्कृष्ट कार्यों को बढ़ावा देने में एसएससी के योगदान वाले ठोस उदाहरणों और बिना शर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों की चुनौतियों एवं अवसरों को साझा करने पर केंद्रित किया। डॉ. जॉर्ज ए. पेरेज–पिनेडा, नेस्ट मेक्सिको/यूनिवर्सिडाड अनाहुआ मेक्सिको ने समापन भाषण दिया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँः विकास सहयोग

बीएनपीटीटी की पांचवीं बैठक

नीतिगत थिंक टैंकों के बिम्सटेक नेटवर्क (बीएनपीटीटी) की वर्चुअल पांचवीं बैठक आरआईएस द्वारा 21–22 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई। इस बैठक में बिम्सटेक के सात सदस्य देशों के थिंक टैंकों के 22 प्रतिनिधियों और बिम्सटेक सचिवालय के सात पदाधिकारियों ने भाग लिया।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने बैठक की अध्यक्षता की। सुश्री रीवा गांगुली दास, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत ने मुख्य भाषण दिया। बिम्सटेक सचिवालय के महासचिव तेनजिन लेकफेल ने हाल के वर्षों में बिम्सटेक की उपलब्धियों पर विशेष भाषण दिया और उन प्राथमिकताओं एवं पहलों को साझा किया जिन पर जल्द ही अमल किया जाना है।

इस बैठक के दौरान वर्ष 2018 में भूटान के थिंपू में आयोजित बीएनपीटीटी की चौथी बैठक में घोषित निर्णयों और प्रतिबद्धताओं की दिशा में हुई प्रगति का जायजा लिया गया। इस क्षेत्र में कोविड–19 से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों और बिम्सटेक क्षेत्र में आर्थिक बेहतरी के लिए रोडमैप पर फोकस किया गया। जहां एक ओर बिम्सटेक सहयोग के लिए विभिन्न सेक्टरों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया, वहीं दूसरी ओर कुछ विशेष सेक्टरों और मुद्दों को वर्ष 2021 में होने वाले पांचवें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इनमें बिम्सटेक एफटीए वार्ताओं का जल्द समापन करना, कुछ विशेष सेक्टरों में क्षेत्र के भीतर व्यापार की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सेक्टर–वार मूल्य श्रृंखलाओं पर विशेष जोर देने की आवश्यकता, स्वास्थ्य क्षेत्र एवं चिकित्सा उपकरणों में वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक जैसे उभरते सेक्टर, इत्यादि शामिल हैं।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी की अगुवाई वाले आरआईएस के प्रतिनिधिमंडल में प्रो. एस. के. मोहंती, प्रो. प्रबीर डे, प्रो. टी.सी. जेम्स, डॉ. प्रियदर्शी दाश, डॉ. सब्यसाची साहा, डॉ. के. रवि श्रीनिवास, सुश्री प्रतिवा शॉ, सुश्री पंखुरी गौड़ और सुश्री सभ्या राय सहित 10 संकाय सदस्य शामिल थे। आरआईएस की टीम ने बिम्सटेक सहयोग एजेंडे के दायरे एवं विविधीकरण के साथ–साथ बैठक के अन्य खंडों में सक्रिय योगदान के अलावा आगामी पांचवें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के लिए प्राथमिकताओं एवं सिफारिशों पर भी मेजबान संस्थान की प्रस्तुति दी।

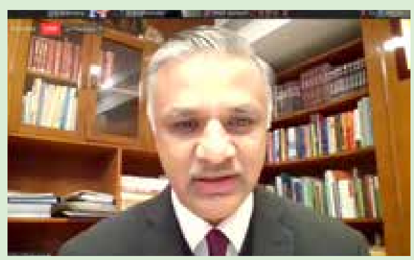

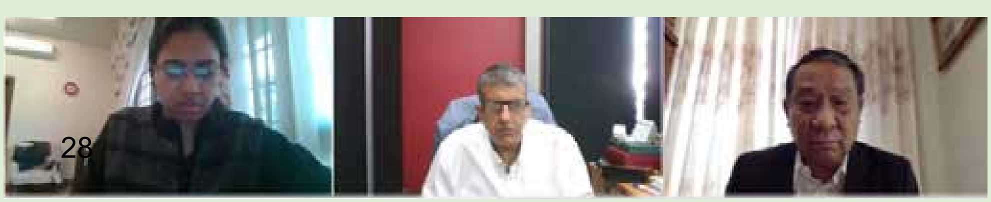

टीकों, दवाओं तक पहुंच और कूटनीति

भारत की वैक्सीन कूटनीतिः सद्भावना उत्पन्न

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के बाद भारत की वैक्सीन कूटनीति पर प्रकाश डालना देश की विकास साझेदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। माननीय विदेश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने कहा कि अब तक 70 से भी अधिक देशों को लगभग 60 मिलियन 'मेड–इन–इंडिया कोविड–19 वैक्सीन खुराकों' की आपूर्ति की जा चुकी है जिससे दुनिया भर में सद्भावना उत्पन्न हो रही है और भारत की वैश्विक साख बढ़ रही है।

आरआईएस द्वारा 20–21 मार्च 2021 को आयोजित भारतीय विकास सहयोग फोरम (एफआईडीसी) की पहली वार्षिक संगोष्ठी, जिसे 'विकास सहयोग संवाद' के रूप में पेश किया जा रहा है, को संबोधित करते हुए श्री मुरलीधरन ने 'विकास साझेदारी' को भारत की विदेश नीति के एक प्रमुख अवयव के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि भारत की विकास साझेदारी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह मानव केंद्रित है और सतत विकास पर आधारित है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत की विकास साझेदारी में कोई भी आदेशात्मक या दोहन करने की शर्त नहीं है, और इसके बजाय यह भागीदार देशों को अपनी क्षमता को हासिल करने का अवसर प्रदान करती है।

मंत्री महोदय ने कहा, 'कोविड–19 महामारी के प्रकोप के बाद भारत ने आवश्यक दवाएं भेजकर दुनिया भर के देशों को मानवीय सहायता प्रदान की है, भारत विभिन्न वेबिनार मॉड्यूल के माध्यम से क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, त्वरित कार्रवाई दलों को भेज रहा है, और सूचना साझाकरण प्लेटफॉर्म (दक्षिण एशिया में) विकसित कर रहा है।' उन्होंने कहा कि इन प्रयासों ने वैश्विक संकट के इस समय में अन्य विकासशील देशों के साथ भारत की एकजुटता को भी दर्शाया है।

उन्होंने ये बातें ऐसे समय में कही हैं जब महामारी के मौजूदा प्रकोप के साथ–साथ संसाधनों के सृजन में वैश्विक क्षमता पर महामारी के प्रभाव के कारण एजेंडा 2030 को अपनी पूर्व–निर्धारित समय–सीमा के भीतर बनाए रखने से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर विकास सहयोग का महत्व काफी बढ़ गया है।

अनुदान सहायता, ऋण रेखा (एलओसी) के साथ–साथ क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता सहित भारत की विकास साझेदारी के विभिन्न तत्वों का उल्लेख करते हुए श्री मुरलीधरन ने कहा कि अनुदान सहायता के रूप में 4 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक दिए गए हैं जो बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा एवं सद्भावना उत्पन्न करने वाले स्वास्थ्य और दीर्घकालिक साझेदारी सहित अनेक क्षेत्रों को कवर करती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारत ने 64 देशों को कुल 31.6 अरब अमेरिकी डालर की 311 एलओसी प्रदान की है जो विकासशील देशों में सामाजिक–आर्थिक विकास और क्षमता निर्माण से जुड़ी 657 परियोजनाओं को कवर करती हैं। उन्होंने कहा कि इन एलओसी की बदौलत भारत से विदेशी बाजारों को बिजली, परिवहन, कनेक्टिविटी, कृषि, सिंचाई और विनिर्माण सहित अनेक क्षेत्रों से जुड़ी वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास साझेदारी के तहत 'एक्ट ईस्ट' नीति सहित अपने पड़ोस में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से संबंधित पहलों पर भी केंद्रित किया जाता रहा है। अब तक 7.69 अरब अमेरिकी डॉलर की इस तरह की 104 परियोजनाओं का कार्यान्वयन हाथ में लिया गया है, जिनमें से 47 पूरी हो गई हैं, और ये दो देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्कों के साथ–साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने क्षमता निर्माण पर भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रमों के साथ–साथ दक्षिण पूर्व एशिया में मंदिरों सहित धरोहर स्थलों के संरक्षण और बहाली के जरिए विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी विस्तार से बताया।

भारत के विकास सहयोग पर एक बहु–हितधारक प्लेटफॉर्म के रूप में एफआईडीसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के विकास सहयोग संबंधी अनुभवों पर विचार–विमर्श एवं साझा करने और इनका प्रचार–प्रसार करने के लिए सिविल सोसायटी, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाता है। कोरोना वायरस की वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए विकास सहयोग का महत्व काफी बढ़ गया है, और इसके साथ ही अन्य देशों को भारत का समर्थन और भी अधिक मजबूत हो गया है।

मौजूदा हालात को देखते हुए 'एफआईडीसी वार्षिक संगोष्ठी 2021ः विकास सहयोग संवाद' हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया, ताकि इस आशय का एक स्पष्ट और प्रभावकारी रोडमैप तैयार किया जा सके। राजदूत डॉ. मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस; प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; और डॉ. राजेश टंडन, अध्यक्ष एफआईडीसी एवं अध्यक्ष, प्रिया ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का विवरण आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँः विकास सहयोग

भारत के साथ त्रिकोणीय सहयोग में वैश्विक रुझान

आरआईएस और ओईसीडी के विकास सहयोग निदेशालय (डीसीडी) ने प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी एवं डॉ. नादिन पिफर–सोयलर के एक शोध–पत्र (पेपर) 'भारत के साथ त्रिकोणीय सहयोग में वैश्विक रुझान . सिविल सोसायटी संगठनों के साथ बेहतर सहयोग के लिए उभरते नीतिगत विकल्प' के विमोचन के लिए 25 जनवरी 2021 को एक वेबिनार का आयोजन किया। इस शोध–पत्र के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए इस वर्चुअल कार्यक्रम में सरकारों, सिविल सोयायटी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधिगण एकजुट हुए।

इस कार्यक्रम की शुरुआत ओईसीडी विकास सहयोग निदेशालय (डीसीडी) के निदेशक श्री जॉर्ज मोरेरा डा सिल्वा के स्वागत और मंचन के साथ हुई। श्री अखिलेश मिश्रा, अपर सचिव, विकास भागीदारी प्रशासन, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने त्रिकोणीय सहयोग में भारत की रुचि पर आरंभिक भाषण दिया। ओईसीडी विकास सहायता समिति (डीएसी) की अध्यक्ष डॉ. सुसाना मूरहेड ने भारत के साथ काम करने में डीएसी की रुचि के बारे में बताया, जिसमें त्रिकोणीय साझेदारियों के जरिए काम करना भी शामिल है। डॉ. राजेश टंडन, अध्यक्ष, भारतीय विकास सहयोग फोरम (एफआईडीसी) और संस्थापक– अध्यक्ष, प्रिया ने त्रिकोणीय सहयोग पर एफआईडीसी और सीएसओ से जुड़े परिप्रेक्ष्य के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. एना फर्नांडिस, प्रमुख, दूरदर्शिता, आउटरीच और नीतिगत सुधार (फॉर) यूनिट, ओईसीडी/डीसीडी ने इन लेखकों के साथ परिचर्चा का संचालन किया: प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक,

आरआईएस और डॉ. नादिन पिफर–सोयलर, ओईसीडी डीसीडी / दूरदर्शिता, आउटरीच और नीतिगत सुधार (फॉर) यूनिट। इसके बाद प्रख्यात प्रतिभागियों के साथ चर्चा हुई जिनमें विकास विकल्प बोर्ड के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. अशोक खोसला; डॉ. करेन क्लिमोवस्की, उप मिशन निदेशक, यूसेड इंडिया; सुश्री रेनाना झाबवाला, स्व–रोजगार महिला संघ (सेवा) भारत बोर्ड की अध्यक्ष; और डॉ. कार्लोस कॉररिया, कार्यकारी निदेशक, दक्षिण केंद्र शामिल थे।

इस शोध–पत्र में 1950 के दशक की शुरुआत से ही त्रिकोणीय सहयोग में भारत की सहभागिता पर प्रकाश डाला गया है। त्रिकोणीय सहयोग से जुड़ी परियोजनाओं को मुख्यतः सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ), निजी क्षेत्र, अनुसंधान संस्थानों और अन्य गैर–सरकारी चैनलों के माध्यम से लागू किया गया है। 1950 के दशक में भारत त्रिकोणीय सहयोग के विभिन्न तौर–तरीकों से जुड़ गया था जिनमें विशेषज्ञता साझा करने के लिए त्रिकोणीय साझेदारियां, प्रवासियों के लिए संयुक्त त्रिकोणीय सहयोग, भारत की ओर से संसाधन के योगदान के साथ त्रिकोणीय साझेदारियां, त्रिकोणीय साझेदारियों में भारतीय सिविल सोसायटी संगठनों की सहभागिता के लिए सहयोग शामिल थे।

रामकृष्ण मिशन के माध्यम से ही भारत पहली बार त्रिकोणीय सहयोग में शामिल हुआ था। वर्ष 1964 में भारत ने विकासशील देशों के साथ अपने तकनीकी सहयोग को संस्थागत स्वरूप देने के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) कार्यक्रम बनाया था। 1990 के दशक के उत्तरार्ध से भारत ने बहुपक्षीय पहलों में अपनी सहभागिता बढ़ा दी है, ताकि विकासशील देशों के साथ अपने सहयोग को बढ़ाया जा सके। भारत इसके साथ ही जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इत्यादि सहित कई साझेदार देशों के साथ त्रिकोणीय सहयोग में जुटा रहा है।

भारत सरकार दक्षिणीय सहयोग के सिद्धांतों के लिए अब भी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में त्रिकोणीय सहयोग के प्रति भारत का नजरिया वर्ष 2014 से और भी अधिक विकसित हुआ है। अब ओईसीडी और डीएसी के सदस्य देशों के साथ अपेक्षाकृत अधिक जुड़ाव है। इस शोध–पत्र (पेपर) में भारतीय त्रिकोणीय सहयोग को बढ़ाने में सिविल सोसायटी की भूमिका का उल्लेख किया गया है और इसके साथ ही यह बताया गया है कि भारत के साथ त्रिकोणीय साझेदारियों के लिए नए अवसर खुल गए हैं। सीएसओ भारत के साथ त्रिकोणीय साझेदारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीएसओ ने कई सामाजिक और आर्थिक नीतिगत क्षेत्रों पर काम किया है। भारतीय सीएसओ ने भारत में लंबे समय से चले आ रहे कई घरेलू मुद्दों को प्राथमिकता दी है और उन पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने गरीबी, असमानता और लोगों को अलग–थलग रखे जाने के मुद्दों को सुलझा करके भारत में हाशिए पर पड़े विभिन्न समूहों के लाभ के लिए काफी काम किया है। राजस्थान स्थित बेयरफुट कॉलेज एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जहां भारतीय सीएसओ को दक्षिणीय सहयोग से जुड़ने के लिए सरकार से आवश्यक सहयोग प्राप्त हुआ है। आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, 'आधार (बायो–मीट्रिक)' पर आधारित सेवाओं की डिलीवरी जैसे भारत के प्रमुख कार्यक्रमों से जुड़े अनुभव दरअसल कुछ ऐसी विकासात्मक पहल हैं जिन्हें अन्य विकासशील देशों में भारतीय सीएसओ द्वारा दोहराया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र@75 और दक्षिणीय सहयोग: उभरती भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

आरआईएस और जर्मन विकास संस्थान (जीडीआई)/ ड्यूशेज इंस्टीट्यूट फर एंटविकलुंगस्पोलिटिक (डीआईई) ने 16 फरवरी 2021 को 'संयुक्त राष्ट्र@75 और दक्षिणीय सहयोग: उभरती भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों' पर एक वेबिनार की सह–मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव श्री बान की मून ने इस वेबिनार में अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि पारंपरिक दानदाता यानी अमीर राष्ट्र ऐसे समय में सहायता राशि में कटौती कर रहे हैं जब विकासशील देशों को अपनी बजटीय सीमाओं के कारण बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

इस ओर ध्यान दिलाते हुए कि राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद बहुपक्षीय सहयोग में बाधा बन रहे हैं, उन्होंने वैश्विक समुदाय से यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाने को कहा कि लचीले, जवाबदेह और देश संचालित उपायों के माध्यम से महत्वपूर्ण संसाधन जरूरतमंदों तक अवश्य ही पहुंच जाएं। श्री मून की टिप्पणियों का विशेष महत्व है क्योंकि वैश्विक विशेषज्ञों और संयुक्त राष्ट्र, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने वैक्सीन राष्ट्रवाद और उन निर्यात पाबंदियों के खिलाफ आगाह किया है जिनकी वजह से विशेषकर गरीब देशों में कोविड–19 वैक्सीन का वितरण बाधित हो रहा है और इसके चलते आर्थिक बेहतरी की गति धीमी हो रही है।

श्री मून, जो 'द एल्डर्स (वैश्विक नेताओं का एक स्वतंत्र समूह)' के उपाध्यक्ष हैं, ने इस ओर भी ध्यान

दिलाया कि विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के कई देशों को वर्ष 2021 में बढ़ती बजटीय सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'पारंपरिक दानदाता ऐसे समय में सहायता राशि में कटौती कर रहे हैं जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बावजूद हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लानी चाहिए कि महत्वपूर्ण संसाधन सर्वाधिक जरूरतमंदों तक अवश्य ही पहुंचते रहें और यह सहायता लचीली, जवाबदेह एवं देश–संचालित हो। हमें यह अवश्य ही स्मरण रखना चाहिए कि यह निरंतरता, समावेशिता और समृद्धि में एक अच्छा निवेश है।'

यह बात रेखांकित करते हुए कि महामारी और आने वाले वैश्विक आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप विकास सहयोग भारी दबाव में है, श्री मून ने कहा कि एजेंडा 2030 के आह्वान, ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने और वर्तमान महामारी के कहर से निपटने के तरीकों की खोज के तहत वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं मुहैया कराने एवं सर्वसुलभ संसाधनों के संरक्षण के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की भी सख्त आवश्यकता है।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और उभरती ताकतों दोनों से ही वैश्विक व्यवस्था में निरंतर सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, 'आपके देश हमारे बहुपक्षीय भविष्य का ख्याल रखते हैं। वास्तव में, जब आपने लाखों लोगों को गरीबी से उबारा है, तो आप लाखों और लोगों की मदद अवश्य कर सकते हैं।' श्री मून ने कहा कि जहां एक ओर कोविड–19 महामारी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और सामूहिक प्रयासों की कड़ी परीक्षा ली है, वहीं दूसरी ओर इसने आपसी सहयोग बढ़ाने के अवसर भी पैदा किए हैं, ताकि इस महामारी से जल्द उबरने में मदद मिल सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पीछे न छूटे। इस वेबिनार के दौरान विकासशील देशों (दक्षिणीय सहयोग या एसएससी) के बीच सहयोग से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई, ताकि इन देशों को मौजूदा कोविड–19 संकट से बेहतर तरीके से उबरने में मदद मिल सके। वर्ष 2013 से ही दक्षिणी प्रदाताओं का सम्मेलन (दिल्ली प्रक्रिया) एसएससी से जुड़े मुद्दों और उभरती चुनौतियों पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करता रहा है। एसएससी के लिए संयुक्त राष्ट्र का समर्थन इन प्रयासों का एक अभिन्न अंग रहा है। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ इस बात पर गौर करने के लिए ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है कि संयुक्त राष्ट्र और 'दक्षिण' यानी इसके अधिकतर सदस्य देशों के बीच संबंध आखिरकार किस तरह से विकसित हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पूर्व विशेष सलाहकार राजदूत विजय नांबियार; डॉ. स्वेन ग्रिम, अंतर– और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रशिक्षण, डीआईई पर अनुसंधान कार्यक्रम के प्रमुख; और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में प्रतिष्ठित पैनलिस्टों के साथ चर्चा भी की गई। विवरण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँः विकास सहयोग

डिजिटलीकरण और विकासः एशिया से उभरते विचार

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) से 'असाधारण पोर्टेबिलिटी' का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे इसके सभी नागरिकों का देश भर में कहीं भी इलाज किया जा सकेगा और इसके साथ ही उन्हें टेलीमेडिसिन की सुविधा मिलेगी जिनमें सभी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के हिस्से के रूप में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्थापित किए जा रहे 150,000 स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों में यह सुविधा मिलना भी शामिल है।

एनडीएचएम के 'स्वास्थ्य डोमेन सिद्धांतों के अनुसार, 'एनडीएचएम की मौजूदगी पूरे देश में होगी और यह एक हेल्थ आईडी – व्यक्तिगत स्वास्थ्य पहचानकर्ता के माध्यम से पूरे देश में निर्बाध पोर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सूचना मानकों को अपनाने सहित सहायक ब्लॉक राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।'

आरआईएस द्वारा ओईसीडी और ईआरआईए के सहयोग से 5 मार्च 2021 को "डिजिटलीकरण और विकासः एशिया से उभरते विचार' विषय पर आयोजित वेबिनार में डॉ. कुमार ने कहा, 'नीति आयोग एनडीएचएम की स्थापना पर बारीकी से गौर कर रहा है जिसे डिजी–स्टैक में जोड़ा गया है। भारत में पहले से ही डिजी–लॉकर हैं और ऑनलाइन शिक्षा बड़े पैमाने पर चल रही है। एनजीएचएम से हमारे सभी नागरिकों को असाधारण पोर्टेबिलिटी सुलभ होगी, ताकि उनका देश में कहीं भी इलाज किया जा सके और टेलीमेडिसिन तक उनकी पहुंच हो सके, जिसे अब हम बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा रहे हैं।' वेबिनार का आयोजन आरआईएस द्वारा ओईसीडी विकास केंद्र और ईआरआईए, जकार्ता के सहयोग से किया गया।

डॉ. कुमार ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत स्थापित किए जा रहे 150,000 स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों को टेलीमेडिसिन क्षमताओं से लैस किया जाएगा, ताकि मरीजों को व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा सेवा प्रदाताओं यानी डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत न पड़े।

उन्होंने कहा कि सरकार सुव्यवस्थित कृषि के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को इस तरह से प्रोत्साहित कर रही है जिससे कि पानी के संरक्षण में मदद मिले और देश को विकास एवं पर्यावरण के बीच संतुलन सुनिश्चित करने में मदद मिले, न कि इनमें से एक को पाने के बदले में दूसरे को गंवाना पड़ जाए।

प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा का उल्लेख करते हुए कि अगले 1,000 दिनों में भारत के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा, उन्होंने कहा कि 150,000 ग्राम पंचायतों को पहले ही ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है एवं अगले दो वर्षों में 100,000 और ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, 'फिर हम इसे हर गांव में फैलाना चाहते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी गांवों को पहले ही बिजली प्रदान कर दी है।' उन्होंने यह भी कहा, 'हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल तकनीक सभी के लिए सुलभ हो।'

उन्होंने कहा कि देश भर में खोले गए 350,000 साझा सेवा केंद्र (सीएससी) 50 से भी अधिक केंद्रीय योजनाओं और राज्य सरकारों की 300 से भी अधिक योजनाओं से लोगों को अवगत कराने में मदद कर रहे हैं और इसके साथ ही विभिन्न सेवाओं से संबंधित सेवाओं जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र को ऑनलाइन उपलब्ध कराने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 400 से भी अधिक सरकारी अनुदान योजनाओं का लाभ हस्तांतरित करने में सक्षम रहे हैं। 200,000 और सीएससी जल्द ही स्थापित किए जाने वाले हैं।' उन्होंने कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी की विशिष्ट क्षमता एवं संभावनाओं से काफी हद तक परिचित है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह भारत के लिए न केवल हमारे विकास एजेंडे में छलांग लगाने, बल्कि काफी ऊंची छलांग लगाने का भी मौका है और इस तरह से हमारे यहां विकास के प्रतिमान को हर जगह से बिल्कुल अलग दिखाने का अहम अवसर है।

दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और भारत के लिए ओईसीडी का आर्थिक आउटलुक वेबिनार के दौरान 'दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और भारत के लिए ओईसीडी का आर्थिक आउटलुक 2021ः डिजिटलीकरण के लिए संसाधनों का पुनर्वितरण' का भारत में विमोचन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, 'कोविड–19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में विकास में आई सुस्ती

उभरते एशिया (आसियान–10, चीन और भारत) को काफी हद तक प्रभावित करेगी।' रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, 'वर्ष 2021 में ज्यादातर उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक उत्पादन के महामारी पूर्व स्तरों पर लौटने की संभावना नहीं है।'

डॉ. केंसुके तनाका, एशिया डेस्क के प्रमुख, ओईसीडी विकास केंद्र, पेरिस ने कहा कि भारत की आर्थिक चुनौतियों में किसी ठोस युक्ति या उपाय के लिए कम होती मौद्रिक एवं राजकोषीय गुंजाइश, ढांचागत मुद्दों (जैसे कि वित्तीय प्रणाली के कमजोर होने; विनिर्माण संबंधी चुनौतियां; बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की कमी; विशेषकर छोटी फर्मों के बीच डिजिटलीकरण का स्तर) और बढ़ती असमानताएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ता कर्ज स्तर भारत सहित कई देशों में कर्ज अदायगी क्षमता के कम हो जाने का जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, 'जब तक कोविड–19 के खिलाफ कोई प्रभावकारी या कारगर टीका व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक वायरस का संचरण स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर काफी दबाव डालता रहेगा। इस तरह के हालात में सामाजिक पाबंदियों को समय पर वापस लिया जाना और सामान्य आर्थिक स्थितियों की बहाली भी संभव नहीं हो पाएगी।' रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति निर्माताओं को इस अवधि के दौरान अपनी महामारी प्रबंधन रणनीतियों का निरंतर विस्तार करने और इसके साथ ही टीकों के कुशल भंडारण एवं समान वितरण की गारंटी देने की जरूरत है।

रिपोर्ट के अनुसार, 'डिजिटल स्वास्थ्य उद्योग द्वारा महामारी के दौरान अपनी सेवाओं का विस्तार किए जाने को देखते हुए नीति निर्माताओं को डेटा की सुरक्षा के लिए एक ऐसी स्पष्ट कानूनी रूपरेखा स्थापित करने की आवश्यकता है जो मरीजों से जुड़े डेटा के संग्रह, भंडारण, प्रोसेसिंग और साझाकरण का उचित नियमन करे।' रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों को विश्वसनीय, किफायती और उपयोग में अत्यंत आसान उपकरणों तक लोगों की समान पहुंच सुनिश्चित करके डिजिटल स्वास्थ्य लाभों के समान वितरण की गारंटी देनी चाहिए।

श्री शेषाद्री चारी, सदस्य, संचालन परिषद, आरआईएस; डॉ. मारियो पेजिनी, निदेशक, ओईसीडी विकास केंद्र, पेरिस; और डॉ. नागेश कुमार, निदेशक, यूएनएस्कैप, एसएसडब्ल्यूए कार्यालय, भारत ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त, किए। डॉ. प्रियदर्शी दाश, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस ने वेबिनार के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत किए और धन्यवाद ज्ञापन किया।

मुक्त, खुले और समावेशी हिंद–प्रशांत के लिए कनेक्टिविटी सहयोग

आरआईएस और आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने नई दिल्ली स्थित जापान के दूतावास (ईओजे) और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 18 मार्च 2021 को वर्चुअल मोड में 'मुक्त, खुले और समावेशी हिंद–प्रशांत के लिए कनेक्टिविटी सहयोग' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में स्वागत भाषण प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने और उद्घाटन भाषण डॉ. मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस ने दिया। माननीय श्री सतोशी सुजुकी, राजदूत असाधारण और पूर्णाधिकारी, जापान दूतावास, नई दिल्ली ने विशेष भाषण दिया। श्रीमती रीवा गांगुली दास, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय (एमईए) ने उद्घाटन भाषण दिया। दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। सत्र I: कनेक्टिविटी परियोजनाओं के सर्वोत्तम तरीके, और सत्र II: नियम–आधारित कनेक्टिविटी सहयोग।

सत्र I की अध्यक्षता श्री रजत नाग, विशिष्ट फेलो, एनसीएईआर और पूर्व एमडीजी, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), नई दिल्ली ने की। सत्र I में वक्तागण ये थेः श्री ताकेओ कोनिशी, कंट्री डायरेक्टर, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), नई दिल्ली; श्री जगजीत सिंह, उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), गुरुग्राम; और डॉ. योस रिजल दामुरी, अनुसंधान निदेशक, रणनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र (सीएसआईएस), जकार्ता। सत्र II की अध्यक्षता डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर, आरआईएस, नई दिल्ली ने की। सत्र II में वक्तागण ये थेः प्रो. फुकुनारी किमुरा, कीओ विश्वविद्यालय, टोक्यो, एवं मुख्य अर्थशास्त्री, आसियान व पूर्वी एशिया का आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए), जकार्ता; और डॉ. जयंत मेनन, विजिटिंग फेलो, दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान (आईएसईएएस), सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूएस) , सिंगापुर।

आपदा जोखिम प्रबंधन पर *'डीसीआर'* के विशेष अंक का विमोचन

आरआईएस *'विकास सहयोग समीक्षा* (डीसीआर)' नामक विशिष्ट पत्रिका प्रकाशित करता है जो वैश्विक विकास सहयोग से जुड़ी समग्र गाथा या विवरण को प्रस्तुत करने और दक्षिणी या विकासशील देशों की अगुवाई में विकास सहयोग प्रक्रिया के सिद्धांत, अनुभवजन्य सत्यापन और प्रलेखन या पुष्टिकरण में व्याप्त महत्वपूर्ण ज्ञान अंतर को पाटने की आकांक्षा रखती है। 'आपदा जोखिम प्रबंधन' पर इस पत्रिका के एक विशेष अंक का विमोचन किया गया जिसमें भारतीय संदर्भ के साथ–साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक संदर्भ में भी कोविड–19 और संबंधित आयामों के आधार पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

इस 'विशेष अंक' का वर्चुअल विमोचन 5 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया। इसके बाद एक पैनल परिचर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण और श्री राजीव इस्सर, यूएनडीपी, क्राइसिस ब्यूरो, ग्लोबल डीआरआर टीम द्वारा इस विशेष अंक के संदर्भ निर्धारण के साथ हुई। 'डीसीआर' के प्रबंध संपादक प्रोफेसर मिलिंदो चक्रबर्ती ने *'डीसीआर'* के बारे में जानकारी दी। श्री कमल किशोर, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार ने विशेष भाषण दिया। श्री अखिलेश मिश्रा, अपर सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने सत्र की अध्यक्षता की। श्री राजीव इस्सर ने भी पैनल परिचर्चा की अध्यक्षता की। पैनलिस्ट ये थेः डॉ. एमिली विलकिंसन, विदेश विकास संस्थान (ओडीआई), लंदन; डॉ. ए. सुब्बैया, निदेशक, क्षेत्रीय एकीकृत बहु–जोखिम ईडब्ल्यू सिस्टम (आरआईएमईएस), बैंकॉक; और श्री गतकुओथ काई, डीआरआर के तकनीकी समन्वयक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि विभाग, एयू आयोग। राजदूत अमर सिन्हा, विशिष्ट फेलो, आरआईएस ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। डॉ. मोना छाबड़ा, निदेशक, अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) ने समापन भाषण दिया।

विस्तृत विवरण के लिएः http://ris.org.in/journals-n-newsletters/Development-Cooperation-Review

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ: विकास सहयोग

प्रकाशन कार्यक्रम

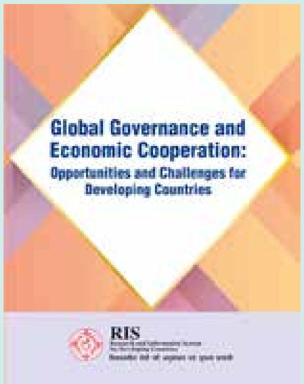

रिपोर्ट

वैश्विक शासन और आर्थिक सहयोगरू विकासशील देशों के लिए अवसर और चुनौतियां, आरआईएस, नई दिल्ली, 2020

जो बाइडन की सरकार पर वर्चुअल पैनल चर्चा पर रिपोर्ट, *आरआईएस, नई दिल्ली, 2021*

विकास सहयोग समीक्षा

- खंडः 3 संख्याः 2: अक्टूबर, 2020

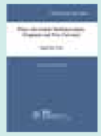

परिचर्चा प्रपत्र

#262: कोविड के बाद की चुनौतियां: संयुक्त राष्ट्र को कायापलट की आवश्यकता – इसकी प्राथमिकता और उपयोगिता को फिर से तलाशना *द्वारा अरुणा शर्मा*

#255, व्हाट एल्स ग्लोबल मल्टीलेटरलिज्म प्रोग्नोसिस एंड वे फॉरवर्ड द्वारा ऑगस्टाइन पीटर

#256, ब्रेटन वुड्स इन हिंडसाइट पर बातचीत द्वारा मनमोहन अग्रवाल

#251, आईएमएफ और 1970 के दशक में टूटने तक इसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय तरलता और समायोजन के लिए निहितार्थ द्वारा मनमोहन अग्रवाल

#250, भारत–यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारीः संभावित और चुनौतियां द्वारा अरुण एस. नायर

#249 जल और स्वच्छता बड़े भारतीय राज्यों की उपलब्धि

नीतिगत सार–पत्र

#98, कोविड–19: आर्थिक पतन और रिकवरी द्वारा मनमोहन अग्रवाल

#97, पोस्ट–कोविड के लिए वैश्विक लक्ष्य (एसडीजी): वैश्विक गरीबी के उलटफेर और वैश्विक गरीबी से निपटना द्वारा सब्यसाची साहा और प्रतिभा शॉ

#93, प्रौद्योगिकी और संस्थागत वास्तुकला का वैश्विक शासन द्वारा सचिन चतुर्वेदी

#92, कोविड–19 पाठ – विघटनकारी जीपीडीपी के लिए एक समय द्वारा डॉ पी के आनंद और श्री कृष्ण कुमार

#89, कोरोना महामारी के समय में बौद्धिक संपदा अधिकार और नवाचार द्वारा डॉ. कृष्णा रवि श्रीनिवास

प्रदान की गई विश्लेषणात्मक सहायता

- यूरोप में काम कर रहे और वहां रहने वाले भारतीय डायस्पोरा (प्रवासियों) का डेटाबेस तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान किए गए।
- अप्रैल 2021 में आयोजित तुलनात्मक और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी के सम्मेलन के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए भारत की पहल के बारे में संयुक्त रूप से जानकारी प्रदान की।
- 'भारत और अफ्रीकाः भविष्य की ओरः समकालीन वास्तविकताएं एवं उभरती हुई संभावनाएं' पर विदेश मंत्रालय को एक विवरण प्रदान किया गया।
- विदेश मंत्रालय को 'भारत–फ्रांस–ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता–शैक्षणिक मंच' पर एक नोट प्रदान किया गया।
- भारत–फ्रांस–ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता (ट्रैक 1.5 वार्ता) पर जानकारी उपलब्ध कराई गई।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँः विकास सहयोग

नई पहलकदमियां

विकास सहयोग

इस परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में, कोई भी देश सभी विकासात्मक चुनौतियों का सामना करने की स्थिति में नहीं है, चाहे उसके विकास का स्तर कोई भी हो। विकास सहयोग देशों के बीच संसाधनों, विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी को साझा करने का सबसे प्रभावी और स्वीकृत तरीका रहा है। इस समय, विश्व अर्थव्यवस्था कोविड –19 महामारी के विनाशकारी प्रभावों का सामना कर रही है, जो संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए विकास सहयोग के नवोन्मेषी स्वरूपों, जैसे एसएससी और टीआरसी मॉडल, को अनिवार्य बना देता है। एफओआईपी समावेशी और संधारणीय विकास के सिद्धांतों के अनुरूप व्यापक आधार पर आर्थिक सहयोग के लिए अवसर प्रदान करता है।

विकास सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण व्यापक है और इसमें सहायता अनुदान, लाइन ऑफ क्रेडिट, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता सहित कई साधन शामिल हैं। अधिकतर, भारतीय सहयोग परियोजनाएं मांग–संचालित हैं और भागीदार देशों की प्राथमिकताओं पर आधारित हैं। आरआईएस पर आधारित जीडीसी विकास सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधान करता है और एशिया और अफ्रीका में भागीदार देशों के साथ विभिन्न विकास हस्तक्षेपों पर ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने को बढ़ावा देता है। जीडीसी सहयोगी देशों के विभिन्न हितधारकों, जैसे शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ), सरकारी निकायों, परोपकारी फाउंडेशनों और निजी क्षेत्र को भी साथ लाता है। जैसा कि एफओआईपी समावेशन पर जोर देता है, जीडीसी का लक्ष्य समग्र विकास के लिए साझेदारी को बढ़ावा देना है। उस परिप्रेक्ष्य में, जीडीसी में हिंद–प्रशांत अनुसंधान कार्यक्रम के एक स्तंभ के रूप में विकास सहयोग एफओआईपी के बड़े विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी मूलभूत अंग प्रदान करेगा।

3
ब्रिक्स

वैश्विक आर्थिक शासन और सहयोग स्तंभ के तहत, आरआईएस ने विशेष दक्षता विकसित की है और ब्रिक्स सहयोग पर एक समर्पित कार्यक्रम तैयार किया है। पिछले वर्षों में प्रकाशित रिपोर्ट, चर्चा पत्र और नीति संक्षेप जैसे इन–हाउस प्रकाशनों के समृद्ध प्रदर्शनों के अलावा, आरआईएस संकाय ने विश्व स्तर पर कई प्रकाशनों में भी योगदान दिया है। आरआईएस ब्रिक्स शैक्षणिक संस्थानों, थिंक–टैंक और नागरिक समाज संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है और अतीत में ब्रिक्स सिविल फोरम और ब्रिक्स अकादमिक फोरम की मेजबानी कर चुका है। आरआईएस विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य विभागों को नियमित रूप से ब्रिक्स पर नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। इस वर्ष, आरआईएस को एक बार फिर विदेश मंत्रालय द्वारा भारत के ब्रिक्स प्रेसीडेंसी 2021 को चिह्नित करने के लिए ब्रिक्स सिविल फोरम 2021 और ब्रिक्स अकादमिक फोरम 2021 के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में तैयारियां और कार्यशालाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। आरआईएस को प्रस्तावित ब्रिक्स आर्थिक सम्मेलन 2021 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा ज्ञान भागीदार के रूप में भी नामित किया गया है। आरआईएस ने 2016 में भी ब्रिक्स आर्थिक मंच के लिए वित्त मंत्रालय के साथ भागीदारी की थी। यह खंड किए गए कुछ प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालता है।

ब्रिक्स सिविल फोरम और ब्रिक्स अकादमिक फोरम

प्रो सचिन चतुर्वेदी, डॉ सब्यसाची साहा, डॉ बीना पांडे, डॉ अमित कुमार, डॉ कपिल पाटिल, सुश्री प्रतिभा शॉ, श्री सिद्धार्थ नायडू, श्री अमित अरोड़ा और प्रो एस के मोहंती, डॉ प्रियदर्शी दास, डॉ पी के आनंद, श्री कृष्ण कुमार के समर्थन और इनपुट के साथ

भारत ने 2021 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता संभाली है। ब्रिक्स@15 के समग्र दृष्टिकोण के तहत – निरंतरता के साथ इंट्रा ब्रिक्स सहयोग, सुधारित बहुपक्षवाद के लिए समेकन और सहमति, आतंकवाद विरोधी सहयोग, सतत विकास लक्ष्यों के लिए तकनीकी और डिजिटल समाधान और पी2पी सहयोग को बढ़ाते हुए, भारत द्वारा एक वर्ष की अवधि में 100 से अधिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

RIS पिछले वर्षों में ब्रिक्स अकादमिक फोरम/ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल (BTTC)/ब्रिक्स सिविल फोरम में भाग लेता रहा है, और 2016 में ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता के दौरान, जैसा कि विदेश मंत्रालय द्वारा समुनदेशित था, ब्रिक्स सिविल फोरम 2016 और ब्रिक्स इकोनॉमिक फोरम 2016 के आयोजन का (अनन्य रूप से), और ब्रिक्स अकादमिक फोरम 2016 के आयोजन का (ORF के साथ संयुक्त रूप से) बीड़ा उठाया। उसी अभ्यास का अनुसरण करते हुए, विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स सिविल फोरम 2021 (अनन्य रूप से) और ब्रिक्स अकादमिक फोरम 2021 और बीटीटीसी (ORF के साथ संयुक्त रूप से) आयोजित करने का दायित्व आरआईएस को सौंपा है।

RIS को भारत के ब्रिक्स प्रेसीडेंसी के दौरान ब्रिक्स सिविल फोरम 2021 की मेजबानी करने का दायित्व विदेश मंत्रालय द्वारा सौंपा गया है – इसमें विभिन्न विषयगत प्राथमिकताओं पर अप्रैल–जुलाई 2021 के दौरान बैठकों की श्रृंखला शामिल है।

RIS भारत के ब्रिक्स प्रेसीडेंसी के दौरान ORF के साथ संयुक्त रूप से ब्रिक्स अकादमिक फोरम 2021 की मेजबानी भी कर रहा है – इसमें विभिन्न विषयगत प्राथमिकताओं पर मई–जुलाई 2021 के दौरान आरआईएस के नेतृत्व में 3 बैठकें शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय के लिए रिपोर्टः विदेश मंत्रालय द्वारा RIS को ब्रिक्स जुड़ाव के समेकन पर एक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है, साथ ही ब्रिक्स में सतत उपभोग और उत्पादन पर एक रिपोर्ट। (जारी है)

ब्रिक्स वित्त पर अध्ययन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ ज्ञान भागीदार के रूप में आरआईएस

प्रो सचिन चतुर्वेदी, डॉ प्रियदर्शी दाश

आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 2021 में भारत के ब्रिक्स प्रेसीडेंसी के दौरान वित्त स्तंभ की गतिविधियों के लिए 'ज्ञान भागीदार' बनने के लिए आरआईएस से संपर्क किया है। इस सहयोग के हिस्से के रूप में, आरआईएस इनपुट प्रदान करेगा और संभावित रूप से सितंबर 2021 में होने वाले ब्रिक्स आर्थिक सम्मेलन का आयोजन करेगा। डीईए से स्तंभ और अन्य गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

ब्रिक्स सिविल फोरम 2021ः साझेदारों से परामर्श

अप्रैल 2021 में ब्रिक्स सिविल फोरम पूर्वावलोकन के लिए अपनी तैयारी के हिस्से के रूप में आरआईएस ने 27 मार्च, 2021 को वर्चुअल प्रारूप में 'साझेदारों के बीच परामर्श' का आयोजन किया। सभी ब्रिक्स देशों के प्रमुख सीएसओ और थिंक–टैंकों के कई शोधकर्ताओं/प्रोफेशनलों ने इस आयोजन में भाग लिया। ब्रिक्स सिविल फोरम की वेबसाइट को इस बैठक में लॉन्च किया गया जो ब्रिक्स सिविल फोरम की समस्त गतिविधियों के लिए सूचना भंडार होगी। इससे पहले आरआईएस ने 21 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में श्री पी. हरीश, भारत के ब्रिक्स सूस शेरपा और भारत के अनेक सीएसओ के प्रतिनिधियों के एक समूह के साथ एक आंतरिक संवाद का आयोजन किया था।

साझेदारों के बीच परामर्श में उद्घाटन सत्र शामिल था जिसके बाद इन चार प्रमुख मुद्दों पर राय एवं सुझाव मांगने के लिए एक गोलमेज चर्चा आयोजित की गईः विभिन्न थीम का विकल्प; संसाधन व्यक्ति एवं हितधारक; समेकन का प्रारूप; और अपेक्षित परिणाम। इस बैठक का मार्गदर्शन और संचालन आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने किया।

संदर्भ निर्धारण के दौरान प्रोफेसर चतुर्वेदी ने ब्रिक्स सिविल फोरम में उन प्रमुख मुद्दों का उल्लेख किया, जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता है जैसे कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2021 की 3सी (निरंतरता, समेकन और आम सहमति) वाली थीम के साथ ब्रिक्स सिविल फोरम के एजेंडे को कैसे समायोजित करें। उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि ब्रिक्स सिविल फोरम को

आखिरकार कैसे संस्थागत स्वरूप दिया जाए, जैसा कि ब्रिक्स अकादमिक फोरम (ब्रिक्स थिंक–टैंक काउंसिल यानी बीटीटीसी बनाकर) के मामले में किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि ब्रिक्स सिविल के व्यापक प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या होने चाहिए; ब्रिक्स सिविल को कैसे समेकित या एकीकृत किया जाए; सिविल फोरम को एक स्थायी प्लेटफॉर्म कैसे बनाया जाए; भागीदारी बढ़ाने के लिए पी2पी को कैसे बढ़ाया जाए; और ब्रिक्स सिविल को और भी अधिक जीवंत फोरम कैसे बनाया जाए।

राजदूत अमर सिन्हा, विशिष्ट फेलो, आरआईएस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में समय–समय पर ब्रिक्स के एजेंडे में विभिन्न महत्वपूर्ण थीम और विषयों को शामिल करने का उल्लेख किया। इन विषयों में से एक विषय रूस में वर्ष 2015 में 'ब्रिक्स सिविल फोरम' की स्थापना करना था।

प्रकाशन कार्यक्रम

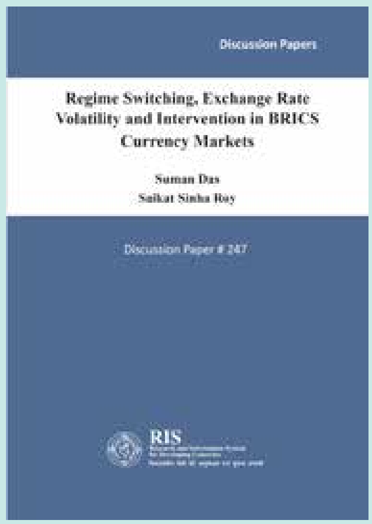

परिचर्चा प्रपत्र

#247: ब्रिक्स मुद्रा बाजारों में शासन स्विचिंग, विनिमय दर अस्थिरता और हस्तक्षेप द्वारा सुमन दास और सैकत सिन्हा रॉय

4

इब्सा

व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग स्तंभ के हिस्से के रूप में, आरआईएस इब्सा सहयोग के शुरुआती प्रतिपादकों और समर्थकों में से एक है। आरआईएस ने विगत में दो बार अपनी प्रमुख रिपोर्ट *ट्रिनिटी ऑफ द साउथ* प्रकाशित की है। इसके अलावा, आरआईएस ने दक्षिणीय सहयोग के दृष्टिकोण से इब्सा साझेदारी को मजबूत करने के लिए अन्य लेख, चर्चा पत्र और नीति संक्षिप्त भी प्रकाशित किए हैं। आरआईएस वर्तमान में इब्सा फेलोशिप कार्यक्रम की मेजबानी करता है जिसे 2016 में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था और अब तक यह कार्यक्रम के दो संस्करण आयोजित कर चुका है। इस वर्ष आरआईएस ने दूसरे दौर में इब्सा अध्येताओं के शोध कार्यों के आधार पर *'इब्सा में बढ़ता सहयोगः प्रमुख क्षेत्रों से परिप्रेक्ष्य'* शीर्षक से दूसरी रिपोर्ट प्रकाशित की। इब्सा फैलोशिप कार्यक्रम के तीसरे दौर की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। आरआईएस इब्सा के भागीदार थिंक–टैंक के साथ भी मजबूती से जुड़ा हुआ है, इब्सा अकादमिक फोरम की मेजबानी करता है और इब्सा मामलों पर विदेश मंत्रालय को नियमित रूप से नीतिगत *इनपुट* प्रदान करता है।

इब्सा विजिटिंग फेलोशिप प्रोग्राम

आरआईएस (RIS) ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आईबीएसए (IBSA) विजिटिंग फेलोशिप कार्यक्रम के तीसरे दौर के शुभारंभ की घोषणा की। कार्यक्रम के तहत, आरआईएस छह महीने तक की अवधि के लिए ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के दो शोध विद्वानों/शिक्षाविदों को फेलोशिप प्रदान करता है। मुख्य फोकस क्षेत्र हैंः सुसंगत और अभिन्न तरीके से संधारणीय विकास के समन्वय, सहयोग और उसे सक्षम करने के लिए एक प्रभावी बहुपक्षीय संस्थागत ढांचे का विकास; विकासशील देशों में संधारणीय सुधार और निरंतर विकास के लिए सूक्ष्म बृहत् आर्थिक नीति समन्वय में वृद्धि; अधिक लचीली वित्तीय प्रणाली और पूंजी प्रवाह के सुसंगत प्रबंधन की दिशा में निरीक्षण और पर्यवेक्षण में सुधार; बौद्धिक संपदा को नियंत्रित करने वाले नियमों की एक समान और संतुलित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का विकास, जो आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग और रोकथाम के खिलाफ स्वदेशी ज्ञान प्रणाली के संरक्षण की अनुमति देता है; संधारणीय और वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के क्षेत्र और कोई अन्य क्षेत्र जो आईबीएसए ढांचे के भीतर रुचि के हो सकते हैं में सहयोग और सूचना के आदान–प्रदान के लिए संयुक्त अनुसंधान।

इब्सा व्याख्यान श्रृंखला और न्यूजलेटर

आरआईएस एक आईबीएसए व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की भी योजना बना रहा है और साथ ही एक आईबीएसए न्यूजलेटर प्रकाशित करने की भी योजना बना रहा है, जो आईबीएसए को और अधिक दृश्यमान और कार्योन्मुखी बनाने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नीति मंडलों और थिंक टैंक समुदाय में नई आईबीएसए फंड परियोजनाओं पर नई पहल, विकास, अनुसंधान अंतर्दृष्टि, गतिविधियों, समाचार, राय और जानकारी के प्रसार के लिए एक त्रैमासिक पत्रिका होगी।

इब्सा में बढ़ता सहयोगः प्रमुख क्षेत्रों से परिप्रेक्ष्य

आरआईएस ने 10 नवंबर, 2020 को *'इब्सा में बढ़ता सहयोगः महत्वपूर्ण क्षेत्रों से परिप्रेक्ष्य'* नामक इब्सा रिपोर्ट का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया। अपने आरंभिक संबोधन के दौरान डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस ने इब्सा रिपोर्ट की वर्चुअल लॉन्चिंग में उपस्थित सभी प्रतिष्ठित मेहमानों और इब्सा फेलो का स्वागत किया। कार्यक्रम के संदर्भ का उल्लेख करते हुए आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और इब्सा के अपार योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इब्सा साझेदारी दरअसल दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) की अभिव्यक्ति है। बहुपक्षीय समाजों का उदय, लोकतंत्रों में सामंजस्य, वैश्विक विकास की संरचना के प्रति बहुपक्षवाद और संसाधनों तक सरकारों की पहुंच अत्यंत आवश्यक है। आरआईएस अपनी स्थापना के समय से ही इब्सा और इसके प्रयासों के केंद्र में रहा है। आरआईएस ने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से युवा विद्वानों के अकादमिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2016 में इब्सा विजिटिंग फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। यह फेलोशिप कार्यक्रम कृषि, वैश्विक उत्पादन नेटवर्कों, व्यापार और निवेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित है। इब्सा फेलो के पहले बैच (2017–2018) ने आरआईएस द्वारा प्रकाशित प्रथम रिपोर्ट में अपना अहम योगदान दिलचस्प शोध लेखों के रूप में दिया। दूसरे बैच ने भी अपने शोध लेखों का योगदान वर्तमान रिपोर्ट में दिया था, जिसे एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक योगदान के रूप में जाना जाता है। प्रो. चतुर्वेदी ने इब्सा फेलो द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी शोध पत्रों के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की और दक्षिणीय सहयोग एवं इन देशों के थिंक–टैंकों के बीच संवाद पर संयुक्त इब्सा घोषणा पत्र जारी करने की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए एक–दूसरे से सहयोग और सीखने के लिए इब्सा के विशेष महत्व को दोहराया।

आरआईएस के चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार ने लॉन्चिंग वाले सत्र की अध्यक्षता की। डॉ. कुमार ने कहा कि बहुलवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरा विश्वास रखने वाला इब्सा विभिन्न लोकतंत्रों के वैश्विक गठबंधन या वैश्विक शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि इब्सा का संयुक्त घोषणा पत्र, जिसमें एसएससी पर विभिन्न सिद्धांतों और शर्तों को रेखांकित किया गया है, एक मार्गदर्शक चार्टर या संहिता के रूप में कार्य कर सकता है। उन्होंने विभिन्न फेलो द्वारा लिखे गए शोध लेखों में दी गई मुख्य दलीलों पर संक्षेप में चर्चा की।

श्री राहुल छाबड़ा, सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से *'इब्सा में बढ़ता सहयोगः प्रमुख क्षेत्रों से परिप्रेक्ष्य'* नामक इब्सा रिपोर्ट का विमोचन किया। श्री छाबड़ा ने एसएससी में इब्सा के विशेष महत्व को सराहा जो सहिष्णुता, बहुसंस्कृतिवाद को मजबूत करने, सहभागी लोकतंत्र के लिए समर्पित समान विचारधारा वाले देशों का समूह है और जो सतत विकास, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ एवं स्वस्थ रहने, डब्ल्यूटीओ मुद्दों, अप्रसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों, इत्यादि पर समान विचारों को साझा करता है। उन्होंने वर्तमान मुद्दों एवं चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षीय संस्थानों की सीमा को रेखांकित किया और बहुपक्षवाद एवं बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इब्सा के विशेष महत्व पर प्रकाश डाला। वर्ष 2004 में अनूठा इब्सा फंड और फिर इसके बाद इब्सा फेलोशिप शुरू करना लोगों की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में महत्वपूर्ण अध्ययन शामिल हैं जिन्हें नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं द्वारा संदर्भित किया जाएगा।

श्री छाबड़ा के संबोधन के बाद इब्सा फेलो ने अपने–अपने शोध पत्रों में दिए गए प्रमुख तर्क पेश किए। ब्राजील की सुश्री एलिस वीरिया डॉस सैंटोस ने इब्सा देशों के बीच मतदान व्यवहार एवं पारस्परिक समर्थन का विश्लेषण किया, और इसके साथ ही यह दलील दी कि उनके मतदान व्यवहार और पारस्परिक समर्थन में व्यापक सामंजस्य है। उन्होंने पारस्परिक समर्थन में सामंजस्य एवं असमानता वाले क्षेत्रों का आकलन किया, और संकेत दिया कि इब्सा को कोई खास पारस्परिक समर्थन नहीं मिला है, और विशिष्ट मुद्दों पर इनके समर्थन को मजबूत करने की व्यापक प्रवृत्ति को देखते हुए आपसी हित के विषयों, विशेषकर स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। उन्होंने कहा चूंकि इब्सा मजबूत लोकतांत्रिक बुनियाद पर आधारित है, इसलिए यह बहुपक्षवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ब्राजील की ही रहने वाली सुश्री पोलियाना बेलिसारियो जोरजल ने एक अवरोध के रूप में पेटेंट का उपयोग करके इब्सा जैव विविधता संरक्षण का आह्वान किया, ताकि कानूनी तौर पर उनके प्राकृतिक आनुवांशिक संसाधनों की रक्षा की जा सके। उन्होंने इब्सा के लिए दो दृष्टिकोणों को अपनाने का तर्क दिया, ताकि उनकी सामान्य बहुपक्षीय संस्थागत रूपरेखा को सुदृढ़ किया जा सके। इनमें राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों के बीच सामंजस्यपूर्ण दिशा–निर्देश और उनके राष्ट्रीय नियमों में सामंजस्य स्थापित करते हुए प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) आवश्यकताओं के लिए समान मानक कानूनों को लागू करना शामिल हैं। अनुसंधान संस्थानों के बीच इब्सा सहयोग को व्यापक बनाने; और आनुवांशिक डेटा की प्राप्ति, पहुंच एवं लाभ साझा करने के लिए एक व्यापक विश्लेषणात्मक डेटा की आवश्यकता दरअसल आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण हेतु आपस में समन्वय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दक्षिण अफ्रीका की सुश्री कारिन क्रिटिंजगर ने अक्षय ऊर्जा की दिशा में प्रगति में रूफ–टॉप सौर की भूमिका पर

इब्सा देशों के बीच सहयोग में सामंजस्य, मतभेद और इसकी गुंजाइश का विश्लेषण किया। इस प्रस्तुतकर्ता ने इब्सा देशों में नवीकरणीय ऊर्जा की गुंजाइश को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और शुल्क दरों (टैरिफ) की मजबूत संभावनाओं पर विशेष जोर दिया।

एक भारतीय जानकार श्री कमलेश गोयल ने स्वास्थ्य सेवा में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने अनुसंधान एवं विकास, पारंपरिक चिकित्सा के पेटेंट संरक्षण, और संयुक्त क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सामंजस्य, एवं सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।

भारत की ही रहने वाली सुश्री राबिया खातुन ने बैंकिंग सेवाओं के व्यवसाय में बाधा उत्पन्न करने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया और उन सिफारिशों का एक समूह प्रस्तुत किया जो इब्सा देशों में इसकी गुंजाइश को मजबूत करने और आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं।

डॉ. बीना पांडे, अनुसंधान सहयोगी, आरआईएस ने इब्सा फंड के माध्यम से की गई विभिन्नं पहलों के अनूठे स्वरूप एवं दायरे का अध्ययन किया, और इसके साथ ही विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन, ऋण परियोजनाओं, कृषि, रोजगार एवं आजीविका, युवाओं की सहभागिता, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और एड्स की समस्याओ से निपटने के लिए क्षमता निर्माण में इसके विशेष महत्व को रेखांकित किया।

माननीय श्री आंद्रे अरन्हा कॉररिया डो लैगो, राजदूत, ब्राजील का दूतावास, नई दिल्ली ने कहा कि यह रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है और संबंधित शोध पत्र इब्सा के एजेंडे को उत्कृष्ट एवं समृद्ध बनाने में काफी मदद करेंगे। उन्होंने नई सड़कों या क्षेत्रों को खोलने में इब्सा की विशिष्ट अहमियत को स्वीकार किया जहां इब्सा देश सहयोग और गठबंधन के माध्यम से एक साथ आगे बढ़ सकते हैं और जिसके लिए तीन देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति भी काफी मायने रखती है। उन्होंने कहा कि इब्सा ऐसी प्रथम बहुपक्षीय व्यवस्थां है जिसमें ब्राजील ने सहभागिता की है और इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत और ब्राजील के बीच सहयोग के परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तीनों ही देश इब्सा के एजेंडे को मजबूत करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं और इसके साथ ही उन्होंने सहयोग के जरिए हासिल किए गए शानदार परिणामों और भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने आरआईएस के ठोस प्रयासों के साथ–साथ इसके द्वारा निभाई गई अद्‌भुत भूमिका को सराहा।

श्री सिबुसिसो एनडेबेल, राजदूत, दक्षिण अफ्रीका का दूतावास, नई दिल्ली ने इब्सा फंड के लिए दक्षिण अफ्रीका की वित्तीय प्रतिबद्ध ता और उसके द्वारा इब्सा एवं इसकी पहलों को दिए जा रहे विशेष महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने अतीत में इब्सा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के साथ–साथ चुनौतियों को स्वीकार करने और संबंधित देशों के बीच अनुभवों के अकादमिक आदान–प्रदान में इसकी अहम भूमिका को सराहा तथा विभिन्न लोकतंत्रों के गठबंधन की एकजुट मजबूत आवाज के रूप में इब्सा का अनुमोदन किया।

इस अवसर पर तंजानिया के उच्चायुक्त माननीय बाराक हरान लुवंदा की मौजूदगी की ओर सबका ध्यान गया और फिर उनसे अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने आरआईएस को बधाई दी और इब्सा के अथक प्रयासों को सराहा। श्री छाबड़ा ने समापन भाषण दिया। डॉ. मोहन कुमार और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने भावी आयोजनों को लेकर उम्मीदें जताने एवं इब्सा सहयोग को और भी अधिक मजबूत करने पर अपना विजन साझा किया। प्रतिष्ठित अतिथियों और वर्चुअल लॉन्चिंग समारोह के प्रतिभागियों के समापन संबोधन के बाद डॉ. सब्यसाची साहा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम: इब्सा

प्रकाशन कार्यक्रम

रिपोर्ट

आईबीएसए में गहराता सहयोग:
प्रमुख क्षेत्रों के दृष्टिकोण, आरआईएस,
नई दिल्ली, 2020

5
व्यापार

आरआईएस में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तर पर व्यापार के मुद्दों पर चर्चा, शोध और विश्लेषण जारी है। संकाय दक्षिण एशियाई देशों जैसे ईरान, मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित क्षेत्रों में संलग्न हैं। भारत और चीन के बीच व्यापार को 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के संदर्भ में परखा जाता है। आरआईएस की प्रमुख रिपोर्टें – *'विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट'* और *'दक्षिण एशिया विकास सहयोग रिपोर्ट'* – प्रकाशित करने की तैयारी चल रही है। क्षेत्रीय स्तर पर, बिम्सटेक और अफ्रीका महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते (AfCFTA) पर अध्ययन चल रहे हैं। विश्व स्तर पर, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के संरचनात्मक सुधार, ई–कॉमर्स, व्यापार और पर्यावरण सहित व्यापार से संबंधित नए मुद्दों, विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT), वैश्विक और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला और प्रतिस्पर्धा नीति के मुद्दों पर शोध किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में उपयोगी चर्चा के लिए, आरआईएस ने 'वैश्विक व्यापार शासन प्रणाली और बहुपक्षीय रूपरेखा' और 'डब्ल्यूटीओ@25 श्रृंखला' पर वेबिनार का आयोजन किया। निम्नलिखित अनुच्छेद व्यापार के क्षेत्र में कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं।

ईरान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंध

प्रोफेसर एस के मोहंती

यह अध्ययन ईरान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापक द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य चयनित दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव के वर्तमान स्तर की जांच करना और व्यापार और निवेश में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना है। यह भारत की प्रतिस्पर्धा के आधार पर उनके साथ द्विपक्षीय व्यापक साझेदारी समझौते की संभावना की छानबीन करेगा। ईएचएस, पीटीए, एफटीए, सीईपीए आदि के लिए बातचीत की संभावना की भी जांच की जाएगी। विश्लेषण के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार में प्रदर्शन, व्यापार क्षमता, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, दीर्घकालिक आयात हित, टैरिफ, एनटीबी, व्यापार विविधीकरण, तीसरे देश से प्रतिस्पर्धा, वरीयता में अंतर की अनुमति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि शामिल होंगे। इस तरह की रणनीति लक्षित उत्पादों, केंद्रित क्षेत्रों, व्यापार क्षमता, निवेश के अवसरों, व्यापार नीति में बदलाव आदि के संदर्भ में विचाराधीन दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपने व्यापार संबंधों में भारत की प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करेगी। इसे भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

RCEP से बाहर निकलने के भारत के निर्णय पर पुनर्विचार

डॉ पंखुरी गौर

आरसीईपी वार्ता से भारत का बाहर निकलना ऐसे समय में हुआ था जब वैश्विक मंदी की निरंतरता के बीच क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक स्थिति स्थिर थी। 2019 के बाद वैश्विक महामारी और आयात की वैश्विक मात्रा में कमी, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में व्यवधान, वैश्विक व्यापार का एकतरफा मांग पैटर्न, एफडीआई के प्रवाह में रुकावट, अशांत विकास परिदृश्य, श्रम का बड़े पैमाने पर पलायन और कोविड –19 के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की मौत, जैसे उच्च प्रभाव वाले प्रकरणों के साथ स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। ऐसी स्थिति में, भारत आरसीईपी सदस्य देशों के लिए अपना बड़ा बाजार खोलकर उनका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बन सकता था, जहां अन्य बाजार बहुतों के लिए बंद थे। भारत अपने विशाल बाजार आकार और क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता के कारण समूह के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि, विनिर्माण वस्तुओं की डंपिंग का निरंतर खतरा, चीन के साथ निरंतर व्यापार असंतुलन और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से संवेदनशील डेयरी आयात का जोखिम, ये कुछ ऐसी आशंकाएं थीं, जो 2019 में भारत के आरसीईपी से हटने की वजह बनीं। हालांकि सदस्यों ने बाद में भारत के लिए क्षेत्रीय गुट में शामिल होने का रास्ता खोल दिया, लेकिन समूह के भीतर कई मतभेद बने हुए हैं। विभिन्न सदस्य देश विशेष और विभेदक व्यवहार पर वार्ता की मेज पर भारत की अनुचित अपेक्षाओं को लेकर आलोचनात्मक हैं, जबकि उन्होंने स्वयं अन्य क्षेत्रीय या द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में उन्हीं पर सहमति व्यक्त की है। एक संशोधित समझौते के साथ, आरसीईपी में भारत की भागीदारी से न केवल भारत को बल्कि आरसीईपी सदस्य देशों को भी लाभ होगा, जहां वे लचीली आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के साथ–साथ चीन से परे व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सक्षम होंगे। यह अध्ययन उन कारणों की प्रासंगिकता का विश्लेषण करेगा जो भारत ने आरसीईपी से बाहर होने के लिए तर्क दिया। नया दृष्टिकोण भारत और आरसीईपी सदस्य देशों, दोनों के लिए गहन व्यापार एकीकरण के लिए एक मध्य मार्ग प्रदान कर सकता है, जो कि कोविड–19 के कारण क्षेत्र की बाधित आपूर्ति श्रृंखला को सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

गैर–टैरिफ उपायः डेटाबेस

प्रोफेसर एस के मोहंती

गैर–टैरिफ उपाय यानी नॉन टैरिफ मेजर्स (एनटीएम) द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के लिए भविष्य की व्यापार नीति के साधन हैं। एक ही अध्ययन में एनटीएम के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना अनिवार्य है, जो नीति निर्माताओं, छात्रों और व्यापार डेटा के सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होगा। यद्यपि अध्ययन के अधिकांश भाग में विषयवस्तु के एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण को शामिल किया जाएगा, लेकिन अध्ययन का उद्देश्य इस अवधि में एक एनटीएम डेटाबेस विकसित करना जारी रखने में एनटीएम के निरंतर योगदान के बारे में समावेशी या विवादास्पद शैक्षणिक आख्यानों के अनावश्यक विस्तार से बचना है। विचार एनटीएम के व्यापार प्रभावों का जहां भी जरूरत हो अनुभवजन्य मूल्यांकन करना है।

AfCFTA-पश्चात के अफ्रीका में व्यापार एकीकरणः एक आकलन

डॉ प्रियदर्शी दाश और सुश्री सोनल गर्ग

अफ्रीका व्यापार और निवेश, औद्योगीकरण, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, सेवाओं और डिजिटल अर्थव्यवस्था आदि के क्षेत्र में मूक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अफ्रीका में विदेशी निवेश के प्रवाह में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है, और यह धारणा बढ़ रही है कि राजनीतिक स्थिरता और भविष्यसूचक व्यापक आर्थिक नीतियों के साथ, अफ्रीका में जल्द ही एक अच्छा बदलाव आ सकता है। तमाम लोग AfCFTA को उसी दिशा में एक कदम मानते हैं। यह लेख क्षेत्र में व्यापार एकीकरण की वर्तमान स्थिति का और उसे वायदे का जो AfCFTA अफ्रीका के लोगों को प्रदान करता है आकलन करता है। वर्णनात्मक और अर्थमितीय तकनीकों के मिश्रण को नियोजित करके, यह लेख वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में देखे गए शैलीगत पैटर्न और अफसीएफटीए के बाद के युग के लिए विकसित रोडमैप की जांच करने का प्रयास करता है।
AfCFTA पर अगले दो वर्षों के लिए एक संयुक्त RIS-CII पहल अफ्रीकी व्यापार एकीकरण पर अनुसंधान को मजबूत करेगी।

वैश्विक व्यापार नियमन और बहुपक्षीय रूपरेखा

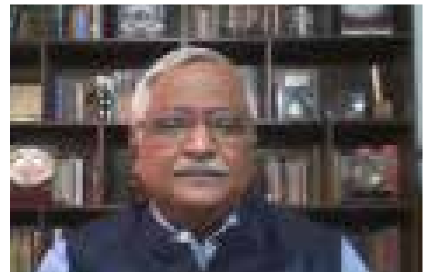

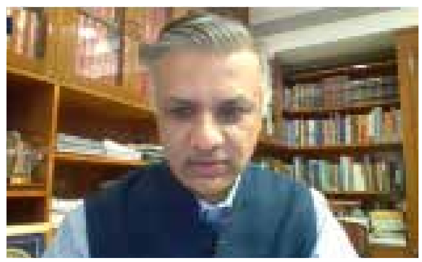

आरआईएस ने डब्ल्यूटीओ@25 में 'वैश्विक व्यापार नियमन और बहुपक्षीय रूपरेखाः आगे की राह' विषय पर दूसरे वेबिनार की मेजबानी की। वेबिनार श्रृंखला दरअसल आरआईएस द्वारा प्रकाशित की जाने वाली आगामी विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 के लिए हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ संवाद करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यहां तक कि एफटीए नियम भी काफी हद तक डब्ल्यूटीओ नियमन द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, इसलिए इस वेबिनार में वैश्विक व्यापार नियमन की केंद्रीय संस्थागत संरचना के रूप में डब्ल्यूटीओ के विशेष महत्व पर चर्चा की गई। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि विश्व व्यापार संगठन में निरंतर गतिरोध जारी है और डब्ल्यूटीओ पिछले कई वर्षों में सही ढंग से कार्य नहीं कर पाया है, पैनल ने 3 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया, ताकि विश्व व्यापार संगठन के पुनरुद्धार हेतु आगे की राह सुझाई जा सके या व्यापार बहुपक्षवाद को बचाने की प्रक्रिया के साथ देशों के विभिन्न समूहों को पुनः अधिक–से–अधिक जोड़ा जा सके।

सबसे पहले, पैनलिस्टों ने विवाद निपटान व्यवस्था (डीएसएम) में सुधार और अपीलीय निकाय में नियुक्तियां से जुड़े मतभेदों पर विचार–विमर्श किया। डब्ल्यूटीओ के अगले महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया में निहित मौजूदा बाधाओं पर भी चर्चा की गई। अमेरिका में नेतृत्व परिवर्तन के आसार को ध्यान में रखते हुए इन दोनों ही संदर्भों में अमेरिका की भूमिका का विश्लेषण किया गया। डब्ल्यूटीओ प्रणाली के कामकाज में डीएसएम की अहम भूमिका रही है। लेकिन संबंधित व्यवस्था की रूपरेखा और इसकी कार्य प्रणाली के बारे में विगत वर्षों में प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए विकसित और विकासशील दोनों ही देशों को सुधार प्रस्तावों की खासियतों को आंकना होगा। यह तथ्य अत्यंत अहम है कि अमेरिका डीएसएम में सुधारों को लागू करने की आवश्यकता के मुद्दे पर बेहद अडिग रहा है और इसने विश्व व्यापार संगठन के साथ अपने सार्थक जुड़ाव के लिए इसे एक पूर्व शर्त बताया है।

दूसरा प्रमुख फोकस क्षेत्र विकासशील देशों को दी गई विशेष एवं भिन्न (एसएंडडी) तरजीह और दोहा दौर की वार्ताओं का ठप हो जाना है जिनका व्यापक असर बहुपक्षीय वार्ताओं में एसएंडडी प्रावधानों के भविष्य पर पड़ेगा। पैनलिस्टों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत इस तरह के प्रावधानों के काफी कमजोर हो जाने पर प्रकाश डाला। कुछ विकसित देशों, विशेषकर अमेरिका के सख्त रुख से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे यह चाहते हैं कि विश्व व्यापार में व्यापक हिस्सेदारी वाले बड़े विकासशील देशों को इस तरह का लाभ पाने से वंचित कर दिया जाए। विकासशील देशों की आय और व्यापारिक क्षमताओं में भारी विविधता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि, लंबे समय से जारी विकासात्मक जरूरतों और चुनौतियों को कम करके नहीं आंका जा सकता है। यह सुझाव दिया गया कि चुनिंदा विकासशील देशों के रुख में हाल में आए बदलावों को ध्यान में रखते हुए विकासशील देशों को अवश्य ही उन मुद्दों का विश्लेषण करना चाहिए जो उनके लिए दांव पर लगे हुए हैं और इसके साथ ही उन्हें विश्व व्यापार संगठन में नए गठबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए।

डब्ल्यूटीओ में सुधार लाने की प्रक्रिया और विकासशील देशों के रुख या नजरिए के तहत नए मुद्दों को भी विभिन्नि मुद्दों के तीसरे सेट में शामिल किया गया। यह सुझाव दिया गया कि औद्योगिक सब्सिडी, सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों एवं डिजिटल वाणिज्य के साथ–साथ मत्स्य सब्सिडी से जुड़े प्रस्तावों के काफी दूरगामी परिणाम विकासशील देशों के लिए हो सकते हैं, और इनसे विकासशील देशों की क्षेत्रवार प्रतिस्पर्धी क्षमता की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए निपटना चाहिए। वैश्विक व्यापार प्रणाली के साथ एकीकरण के हिस्से के रूप में आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्वायत्तता के बारे में भी ठीक इसी तरह की विशिष्ट सोच है।

डब्ल्यूटीओ@25 श्रृंखला

डब्ल्यूटीओ@25 श्रृंखला पर आरंभिक वेबिनार 22 अक्टूबर 2020 को उन परिस्थितियों में आयोजित किया गया जब महामारी के बाद वैश्विक व्यापार का परिदृश्य उत्साहजनक नहीं है और आने वाले समय में अनिश्चितताएं व्याप्त रहने को लेकर आशंकाएं हैं। उत्पादन एवं आपूर्ति में अचानक व्यवधान आ गया है और इसके साथ ही बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में व्यापक गतिरोध जारी है जो दरअसल महामारी के प्रकोप से पहले से ही बरकरार है।

वेबिनार में उत्तर और दक्षिण के अनेक टिप्पणीकार एवं बुद्धिजीवी एकजुट हुए और इस दौरान विभिन्न निहितार्थों एवं आगे की राह पर विचार–विमर्श किया गया। इस ओर ध्यान दिलाया गया कि कुछ विकासशील देश तो मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाओं से लाभान्वित हुए हैं, लेकिन इनका एक बड़ा वर्ग इससे वंचित रहा है और यहां तक कि विकसित देशों को हुए लाभ भी एकसमान नहीं रहे हैं। उभरती बहुध्रुवीयता के साथ–साथ विश्व शक्ति की अनचाही दिशा के कारण भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। वर्तमान परिस्थितियां दरअसल 'गैट' के दौर से बहुत भिन्न हैं, क्योंकि आज जो सबसे बड़ा व्यापारिक राष्ट्र है वह एक विकासशील देश है। मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाएं प्रौद्योगिकी के मजबूत प्रभाव और संबंधित नए मुद्दों से निपटने में असमर्थ रही हैं। डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) प्रणाली को अस्तित्व के संकट से उबारने के लिए पैनल द्वारा कई सिफारिशें पेश की गईं।

सबसे पहले, विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय स्वरूप को संरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थाओं की भरमार की ही तरह बहुपक्षीय समझौतों से संबंधित अनेक प्रस्तावों के कारण डब्ल्यूटीओ प्रणाली का आगे और भी अधिक विखंडन हो सकता है। दूसरा, सुधारों के बजाय डब्ल्यूटीओ को संभवतः पुनर्संतुलन की आवश्यकता है। यह आवश्यक है क्योंकि विकसित देशों द्वारा प्रायोजित कई सुधार प्रस्तावों के कारण विकासशील देशों में कृषि, औद्योगिक सब्सिडी, निवेश, डेटा, इत्यादि सहित कई खंडों में विकास प्रभावित हो सकता है। यही नहीं, डब्ल्यूटीओ प्रणाली विकसित देशों की एकतरफा कार्रवाई से निपटने में असमर्थ रही है। तीसरा, लागू करने योग्य नियमों को बनाने और विवाद निपटान व्यवस्था में नई जान फूंकने पर अवश्य ही विशेष जोर होना चाहिए।

पैनल ने डब्ल्यूटीओ द्वारा आगे बढ़ाई जा रही एकल प्रतिबद्धता व्यवस्थाओं से जुड़ी चिंता और सब्सिडी एवं आईपीआर जैसे मुद्दों में निहित जटिलताओं पर भी चर्चा की।

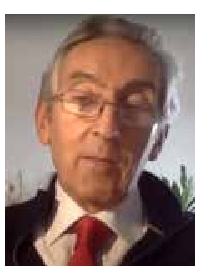

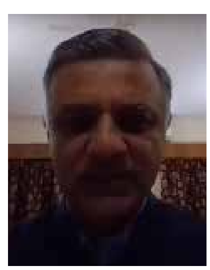

सदस्यों ने विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय और क्षमताओं में व्यापक अंतर को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूटीओ प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विकासशील देशों को दी गई विशेष एवं भिन्न (एसएंडडी) तरजीह से जुड़े प्रावधानों के स्वरूप और विकासशील देशों की उभरती जरूरतों के लिए आवश्यक धनराशि की ओर ध्यान दिलाया। इसे भी ध्यान में रखते हुए विकासशील देशों को दी गई विशेष एवं भिन्न (एसएंडडी) तरजीह के साथ–साथ यहां तक कि क्षेत्रीय समझौतों में भी निहित इस तरह के प्रावधानों के लिए एक अलग नजरिया अपनाना आवश्यक हो सकता है। यह अफ्रीका के एलडीसी के लिए विशेष रूप से सच है जो क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ और भी अधिक मजबूती से एकीकृत करने की इच्छा रखते हैं। अफ्रीकी संदर्भ में वहां की अर्थव्यवस्थाओं के विविधीकरण के लिए नवोदित उद्योग के संरक्षण के संबंध में विशेष एवं भिन्न (एसएंडडी) तरजीह की आवश्यकता निश्चित रूप से चिंता का प्रमुख विषय है। इनमें से कई देश डब्ल्यूटीओ के कई विभागों में शीर्ष नेतृत्व पाने एवं निर्णय लेने में भागीदारी की इच्छा जताने के अलावा अपने यहां घटिया उत्पादों की डंपिंग जैसे मुद्दों से निपटने के लिए डब्ल्यूटीओ में मजबूत विवाद निपटान व्यंवस्था स्थापित करने की भी मांग कर रहे हैं।

आखिर में, इस ओर ध्यान दिलाया गया कि मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं की बढ़ती जरूरतों, आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और टीकों एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए जी20 इस मोड़ पर बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

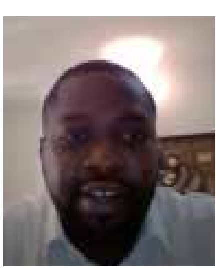

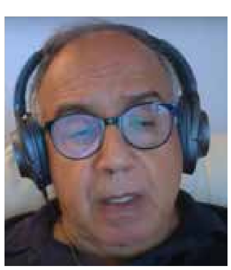

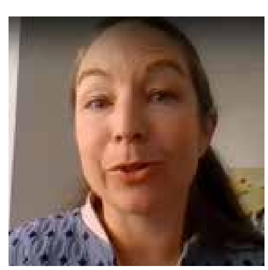

प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रमः व्यापार

प्रकाशन कार्यक्रम

रिपोर्ट

परिचर्चा पत्र

#253 भारतीय विनिर्माण क्षेत्र, वित्त और विकास, मनमोहन अग्रवाल, रूमी अजीम और नेहा बेताई द्वारा

#244 चुनौतियों से पार पाना, व्यापार के नए अवसरों में नकद, दम्मू रवि द्वारा

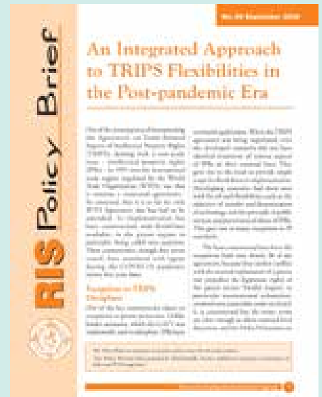

नीतिगत सार

#95 महामारी के बाद के युग में ट्रिप्स लचीलेपन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण, अतुल कौशिक द्वारा

#88 चीन में कपड़ा क्षेत्र का रोबोटाइजेशनःप्रभाव और अनिवार्यता, अमित कुमार द्वारा

प्रदान की गई विश्लेषणात्मक सहायता

- भारत–चीन रिपोर्ट के आधार पर भारत–चीन व्यापार विश्लेषण, विदेश मंत्रालय को प्रदान किया गया।
- दक्षिण–दक्षिण व्यापार और निवेशः कोविड–19 के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एक उपाय – विदेश मंत्रालय को जानकारी प्रदान की गई।
- 'हिंद प्रशांत महासागरीय पहल (आईपीओआई) का 7वां स्तंभः व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन – आईपीओ के 7वें स्तंभ को मजबूत करने के लिए भारत–जापान सहयोग की एक रूपरेखा' पर संयुक्त सचिव (आईपी), विदेश मंत्रालय को एक नोट प्रदान किया गया।
- 'निवेश पर यूरोपीय संघ–चीन व्यापक समझौताः भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उभरता रुझान और आगे की राह' पर आर्थिक कूटनीति प्रभाग, विदेश मंत्रालय को एक नोट प्रदान किया गया।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नाफ्टा डिवीजन को 'भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता – व्यापार सौदे के मुद्दे' पर एक पेपर प्रदान किया गया।
- ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 2021 की विज्ञप्ति के लिए 'व्यापार का मुद्दों के सामंजस्य' पर इनपुट प्रदान किए गए।

नई पहलकदमियां

भारत में औद्योगीकरण के नए युग के लिए स्टार्ट–अप सहयोग

हाल के वर्षों में भारत के साथ–साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में भी स्टार्ट–अप पर अधिक ध्यान दिया गया है। स्टार्ट–अप की संख्या बढ़ रही है और विशेष रूप से विकासशील दुनिया में इसे विकास और रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण इंजन के रूप में देखा जा रहा है। स्टार्ट–अप सामाजिक–आर्थिक विकास और परिवर्तन के माध्यम के रूप में कार्य करते हुए, नवाचार और स्केलेबल प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावपूर्ण समाधान दे सकते हैं। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र है, और इसके प्रति वर्ष 12 से 15 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। दिलचस्प बात यह है कि महिला उद्यमी बड़ी संख्या में सामने आ रही हैं और ये देश में नई पीढ़ी के स्टार्ट–अप की चालक हो सकती हैं। स्टार्ट–अप के व्यवस्थित विकास के लिए, भारत सरकार ने 'स्टार्ट–अप इंडिया' और 'स्टैंड–अप इंडिया' सहित कई पहलें शुरू की हैं। कार्य योजना तीन स्तंभों के आसपास बनाई गई हैः सरलीकरण और संबल, वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन, और उद्योग–अकादमिक साझेदारी और ऊष्मायन। राष्ट्रीय पहलों के अलावा, स्टार्ट–अप को पोषित करने और स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में देशों के बीच सीखने और सहयोग की पर्याप्त गुंजाइश है। स्टार्ट–अप के उदय और व्यापार और निवेश में सहयोग और निहितार्थ के दायरे को समझने के लिए, आरआईएस ने आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी), नई दिल्ली के सहयोग से एक विस्तृत अध्ययन करने का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल अध्ययन प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

व्यापार सुविधा और कनेक्टिविटी

टैरिफ और गैर–टैरिफ उपायों में पर्याप्त कमी के साथ, देशों के बीच व्यापार और निवेश की उच्च संभावनाएं अब पहले की तुलना में बहुत उज्जवल हैं। हालांकि, व्यापार नीति और नियामक क्षेत्र में सुधार के कुछ क्षेत्रों की आवश्यकता है, जिसमें सीमा शुल्क सुधार, सीमा अवसंरचना, परस्पर मान्यता समझौते, जोखिम प्रबंधन, आदि शामिल हैं। उन बाधाओं की मौजूदगी में, निर्यातकों और आयातकों को उच्च व्यापार लागत का सामना करना पड़ता है, जो न केवल उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने से हतोत्साहित करता है, बल्कि उनके भविष्य के विकास और व्यवसायों को भी प्रभावित करता है, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए। हिंद–प्रशांत क्षेत्र, दुनिया के कई प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रों के इसमें अवस्थित होने के कारण, उपर्युक्त मुद्दों पर अलग–अलग व्यापार नीति व्यवस्थाएं रखने का जोखिम नहीं उठा सकता। हालांकि डब्ल्यूटीओ व्यापार सुविधा समझौता (टीएफए) 2015 से लागू है, परंतु समझौते की विभिन्न प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन में भारी अंतर है। इसलिए, इसे व्यापक हिंद–प्रशांत पहल के हिस्से के रूप में व्यापार सुविधा और संपर्क सुधारों के विभिन्न रूप–रेखाओं की जांच करने की आवश्यकता है। आरआईएस ने विगत में दक्षिण एशिया, बिम्सटेक और एशिया–अफ्रीका सहयोग के संदर्भ में इनमें से अधिकांश क्षेत्रों पर कई अध्ययन किए हैं। इसी प्रयास को जारी रखते हुए, व्यापार सुविधा और संपर्क प्रस्तावित हिंद–प्रशांत अनुसंधान कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होगा।

डिजिटल अर्थव्यवस्था

डिजिटल अर्थव्यवस्था दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), ब्लॉक चेन, रोबोटिक्स, बिग डेटा आदि जैसी उन्नत आईटी प्रौद्योगिकियों ने आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन, बिक्री और वितरण के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है। ऐसे क्षेत्र जो डिजिटलीकरण की तेज लहर का अनुभव कर रहे हैं, उनमें बैंकिंग, फिनटेक, ई–कॉमर्स, डिजिटल स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं। इसके साथ – साथ, इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और मोबाइल के उपयोग ने डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार किया है; जिसके लाभ बड़े पैमाने पर लेनदेन की कम लागत, आसान डिजिटल भुगतान विकल्प आदि में परिलक्षित होते हैं। हिंद–प्रशांत क्षेत्र डिजिटल अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की सीमाओं का विस्तार करने और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए एक प्रवर्तक के रूप में डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ उठा सकता है। प्रौद्योगिकी विकास के अलावा, डिजिटल अर्थव्यवस्था अक्सर डेटा चोरी, स्थानीयकरण और साइबर सुरक्षा सरोकारों के मुद्दों का मुकाबला करती

नई पहलकदमियां

है। त्रिकोणीय सहयोग के तहत क्षेत्रीय नीति संवाद और ज्ञान–साझाकरण विकासशील देशों और क्षेत्र के एलडीसी की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। हिंद–प्रशांत इकोनॉमिक विजन के तहत यूएस–आसियान डिजिटल डिप्लोमेसी क्षमता निर्माण और विशेषज्ञता साझा करने के लिए ऐसा ही एक कार्यक्षेत्र प्रदान करता है। इस तरह की पहल का भारत की हिंद–प्रशांत महासागरीय पहल के तहत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग के साथ, एक स्तंभ के रूप में बाकी देशों, विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीकी देश, में विस्तार किया जाना चाहिए। एक महत्वाकांक्षी विजन होने के नाते, एफओआईपी को निकट भविष्य में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का लाभ उठाना चाहिए।

खाद्य और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापार पर आरआईएस–आईएफपीआरआई (RIS-IFPRI) सहयोगात्मक अध्ययन

दक्षिण एशिया में कृषि व्यापार पर अनुभवजन्य अनुसंधान में अक्सर डेटा और क्षमता अंतराल देखे जाते हैं। आरआईएस और आईएफपीआरआई कृषि में व्यापार के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से खाद्य और कृषि–प्रसंस्करण क्षेत्रों में, एमएसएमई पर व्यापक डेटाबेस विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार और विकास और आईएफपीआरआई व्यापार प्रवाह विश्लेषण पर व्यापक डेटाबेस का उपयोग करके अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से दक्षिण एशिया में बौद्धिक क्षमता का निर्माण करना है। 2020 में, आरआईएस के दो युवा शोधकर्ताओं ने आईएफपीआरआई क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी प्रस्तुति को चर्चा पत्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) के दृष्टिकोण से प्रसंस्करण क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, कार्यक्रम का लक्ष्य 2021 से आगे इसे बिम्सटेक तक बढ़ाना है। इस संबंध में आरआईएस इसे आगे बढ़ाने के लिए विदेश मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के संपर्क में है। इसके अलावा, आरआईएस बीएनपीटीटी के लिए इंडिया फोकल प्वाइंट के रूप में बिम्सटेक सचिवालय के सीधे संपर्क में है। आरआईएस और आईएफपीआरआई दोनों, कृषि पर मौजूदा कार्यक्रम को औपचारिक रूप देने और भविष्य में अन्य क्षेत्रों में संभावित विस्तार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर विचार कर रहे हैं।

दक्षिण एशिया में विदेशी उच्च शिक्षा में वापसी: एक अनुभवजन्य विश्लेषण

सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग, बांग्लादेश द्वारा आरआईएस से दक्षिण एशिया के साझेदार प्रबुद्ध मंडल के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय "दक्षिण एशिया में विदेशी उच्च शिक्षा की ओर वापसी: एक अनुभवजन्य विश्लेषण" पर 5–देश के शोध अध्ययन में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया है। जनसांख्यिकीय लाभांश के बावजूद, दक्षिण एशिया में शिक्षा क्षेत्र और श्रम बाजार की गतिशीलता क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती रही हैं। आरआईएस दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के एजेंडे में अपने योगदान को लेकर दृढ़ रहा है और विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों के साझेदार प्रबुद्ध मंडल के साथ घनिष्ठ सहयोग और बातचीत करता रहा है। युवा आबादी के बीच अंतरराष्ट्रीय प्रवास और विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में कथित लाभ के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, संभावनाओं और रूपात्मकता पर भागीदारों के बीच गहन विचार–विमर्श के बाद अध्ययन का प्रस्ताव जारी किया गया है। अध्ययन का परिणाम देश–विशिष्ट संदर्भों में समानता और भिन्नता में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और क्षेत्र से निकलने वाली प्रतिभा और कौशल का दोहन करने और लगातार चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर नीति निर्माण का मार्गदर्शन कर सकता है। अध्ययन 2022 में शुरू होने की उम्मीद है।

6 वित्त

दुनिया भर में वित्तीय क्षेत्र नए उत्पादों और सेवाओं, संबद्ध जोखिमों, व्यापार मॉडल और विनियमों के रूप में तेजी से विकसित हो रहे हैं। फिनटेक, डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो संपत्तियां नए वित्तीय नवाचार हैं, जो स्पष्ट रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए वित्तीय मध्यस्थता के पारंपरिक मॉडल से कुछ क्षेत्रों को अलग करने और इसे बहुत कम लागत और ग्राहकों की सुगमता पर कुशलतापूर्वक पैकेज करने की बड़ी क्षमता प्रदान करते हैं। तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय डोमेन की यह नई लहर आकस्मिक जोखिम और सुभेद्यताओं का आकलन करने और आवश्यक नियामक परिवर्तन करने के लिए केंद्रीय बैंकों और मौद्रिक प्राधिकरणों द्वारा समान ध्यान देने की मांग करती है, विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। वित्तीय क्षेत्र के बढ़ते और नवोन्मेषी क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ–साथ, कुछ पारंपरिक मुद्दे जैसे अवसंरचना वित्तपोषण और विकास वित्तपोषण हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण हो गए हैं। अवसंरचना के वित्तपोषण और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण में अंतराल को पाटने के लिए विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) की महत्वपूर्ण भूमिका दुनिया के कई देशों में फिर से सामने आई है। इनमें से कुछ क्षेत्रों में अवसरों, जोखिमों और चुनौतियों की जांच करने के लिए, आरआईएस ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से वर्ष 2020–2021 में कई शोध अध्ययन और वेबिनार श्रृंखला शुरू की। डीएफआई की रूपरेखा की और जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुभाग अधिक विवरण प्रस्तुत करता है।

डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो–मुद्रा

डॉ प्रियदर्शी दाश

भुगतान और निपटान की दुनिया में डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो–मुद्रा नए प्रचलित शब्द हैं। कैशलेस लेनदेन के लिए बढ़ती प्राथमिकता और उपभोक्ताओं के नजरिये से भुगतान में आसानी को प्राथमिकता को देखते हुए लोग इसे अधिदिष्ट मुद्रा या कागजी मुद्रा (फिएट मुद्रा) के लिए खतरा समझ रहे हैं। जहां डिजिटल मुद्राओं और संबंधित तकनीकी और नियामक मानकों को अपनाने पर एक समान वैश्विक स्थिति अभी विकसित हो ही रही है, वहीं कई केंद्रीय बैंकों (या नीति–निर्माताओं) ने या तो इसे अपनाने के लिए नीतिगत उपाय किए हैं या वित्तीय प्रणाली के बचाव, सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए वे ऐसे उपकरणों के निहितार्थों का अध्ययन कर रहे हैं। डिजिटल और क्रिप्टो–मुद्राओं के उपयोग में नियामक खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन ग्राहकों के लिए फिएट मुद्रा–आधारित भुगतान और निपटान प्रणाली को अधिक आकर्षक, उपयोगकर्ता के अनुकूल और सस्ता बनाना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि अक्सर फिएट मुद्रा से डिजिटल मुद्रा में स्विच करने वाले व्यक्तियों के लिए इन्हीं बातों को आकर्षण का कारण माना जाता है। चूंकि डिजिटल प्रौद्योगिकियां और ई–कॉमर्स प्रसरणशील ताकतें हैं जिन्हें इतनी आसानी से उलट नहीं किया जा सकता, इसलिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं की ओर बढ़ने पर विचार कर सकते हैं, बजाय समानांतर प्रणाली को कार्य करने और वित्तीय स्थिरता को विकृत करने देने के। हालांकि, भारत डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो–मुद्राओं के मुद्दे पर धीरे–धीरे आगे बढ़ने का विकल्प चुनता है, इसके लिए पर्याप्त होमवर्क करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि देश में ई–कॉमर्स और भुगतान के डिजिटल मोड के विमोहित यानी कैप्टिव उपयोगकर्ता तेजी से बढ़ रहे हैं।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँः वित्त

भारत के लिए विकास बैंक और नीतिगत विकल्प

विकास बैंक निर्माण पूर्व लंबी अवधि वाली विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कई संस्थागत अवसर प्रदान करते हैं। औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और आवश्यक बुनियादी ढांचागत सुविधाएं तैयार करने में विकास वित्त संस्थानों की अहम भूमिका पर चर्चा करने के लिए आरआईएस ने वित्त एवं विकास पर गहन फोकस वाला एक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है। इस संदर्भ में आरआईएस ने 14 जुलाई 2020 को 'एक नए विकास बैंक की स्थापना की आवश्यकता' विषय पर एक परिचर्चा पत्र के मद्देनजर भारत के लिए विकास बैंकों और नीतिगत विकल्पों पर आईडीबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक श्री जी.ए. टाडस के विशेष संबोधन वाले एक वेबिनार का आयोजन किया। श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर एवं एचडीएफसी की वर्तमान चेयरपर्सन ने इस वेबिनार की अध्यक्षता की।

श्री टाडस की प्रस्तुति के बाद एक पैनल परिचर्चा आयोजित की गई। प्रतिष्ठित पैनलिस्ट ये थेः प्रोफेसर स्टेफनी ग्रिफिथ–जोन्स, वित्तीय बाजार निदेशक, नीतिगत संवाद के लिए पहल, कोलंबिया विश्वविद्यालय; और डॉ. जन्मेजय सिन्हा, चेयरमैन, भारत, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मुंबई।

अपनी प्रस्तुति में श्री जी.ए. टाडस ने विशेष जोर देते हुए कहा कि देश की आजादी

के बाद गठित किए गए आईएफसीआई, आईडीबीआई और आईसीआईसीआई जैसे विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) ने भारत के औद्योगीकरण में व्यापक योगदान दिया। हालांकि, वर्ष 1991 से ही लागू वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधारों के कारण डीएफआई के लिए किफायती फंडों तक पहुंच धीरे–धीरे बंद हो गई और ऐसे में आईडीबीआई एवं आईसीआईसीआई जैसे अग्रणी संस्थानों को स्वयं को वाणिज्यिक बैंकों में बदलना पड़ गया, जबकि आईएफसीआई भारी वित्तीय दबाव के दौर से गुजरता रहा है। चाहे विकसित राष्ट्र हों या विकासशील देश, दुनिया भर में विकास बैंकों का गठन तब किया गया जब नई या मौजूदा कंपनियों को बढ़ावा देने और इस तरह से औद्योगीकरण एवं बुनियादी ढांचागत विकास को प्रोत्साहित करने हेतु उद्यमिता गतिविधियों के लिए आवश्यक वित्तपोषण प्रदान करने में बाजार विफल साबित होने लगे थे। ऐसे समय में जब भारत की विकास संबंधी जरूरतें बहुत अधिक हैं और जिसके लिए व्यापक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है, विशेषकर अल्प विकसित दीर्घकालिक बांड बाजार के संदर्भ में मौजूदा डीएफआई का समापन या बंद होना निश्चित तौर पर समय से पहले यानी असामयिक प्रतीत होता है।

प्रमुख डीएफआई को स्थापित करने का समय अब आ गया है, ताकि बुनियादी ढांचागत एवं निर्माण पूर्व लंबी अवधि वाली अन्य परियोजनाओं को मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के साथ–साथ उन नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों को भी बढ़ावा दिया जा सके जिनके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कम पड़ रही राशि को पूरा करने या बाजार सृजित व्यवस्था के रूप में आवश्यक सहायता नहीं प्राप्त होती है। विकसित और विकासशील देशों के विकास बैंकों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का अध्ययन करके संसाधनों को जुटाने के अभिनव तरीकों की खोज करने की आवश्यकता हो सकती है। डीएफआई को सौंपी गई विभिन्न जिम्मेदारियों की समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था की बदलती प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रासंगिक बनी रहें। परिचर्चा पत्र आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे भी व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है।

फिनटेक और फिनटेक सक्षम सेवाओं में यूके– भारत दिपक्षीय व्यापार

भारत– यूके द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ई एस आर सी भारत के एक संयुक्त आह्वान के जवाब में आर आई एस अन्य अध्ययन भागीदारों के साथ एसेकस विश्वविद्यालय यूके के सहयोग से भारत –यूके द्विपक्षीय व्यापार की क्षमता पर एक अध्ययन कर रहा है। फिनटेक और फिनटेक सक्षम सेवाओं में अध्ययन का उद्देश्य फिनटेक के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना जो वित्तीय सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं, स्टार्टअप विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और उभरते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं और पियर रिव्यू जनरल पेपर के प्रकाशन के अलावा अध्ययन का उद्देश्य वित्तीय समावेशन और विकास सेंटर के योगदान पर दोनों देशों में जन जागरूकता पैदा करता हैं।

डिजिटल मुद्राओं और क्रिप्टो–करेंसी पर वेबिनार

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य मौजूदा समय में बगैर किसी चर्चा के व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों में नवाचारों की बदौलत ही संभव हो रहा है। हाल के वर्षों में विशेष रूप से वित्तीय प्रौद्योगिकियों पर काफी ध्यान दिया गया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ–साथ उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग में काफी तेजी से प्रगति देखने को मिल रही है। इस डिजिटल युग में विभिन्न देश यह पता लगा रहे हैं कि क्या पैसे के नए स्वरूप जैसे कि डिजिटल मुद्राएं और क्रिप्टो–करेंसी गेम चेंजर साबित होंगी। डिजिटल और क्रिप्टो–करेंसी के उपयोग से जुड़ी नियामकीय एवं पर्यवेक्षी या निरीक्षणात्मक चुनौतियों को लेकर कई आशंकाएं हैं। विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के अलावा जी20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े अवसरों एवं बाधाओं और इसमें अंतर्निहित मानकों पर

चर्चाएं की जा रही हैं।

आरआईएस विशेष रूप से जी20 के संदर्भ में व्यापार, निवेश एवं औद्योगिक नीति के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और फिनटेक के क्षेत्र पर काम करता रहा है। डिजिटल मुद्राओं और क्रिप्टो–करेंसी की जटिलताओं को समझने के लिए आरआईएस ने 7 मई, 2020 को 'भविष्य की डिजिटल मुद्राएं एवं क्रिप्टो–करेंसीः नीतिगत विकल्प और आगे की राह' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

कार्यक्रम की शुरुआत आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ हुई। भारत के माननीय जी2–शेरपा श्री सुरेश प्रभु ने इस वेबिनार की थीम के विशेष महत्व के बारे में बताया और इसके साथ ही अपना दृष्टिकोण साझा किया। डॉ. मार्टिन सस्टर, निदेशक (अनुसंधान), नेशनल बैंक ऑफ स्लोवाकिया ने मुख्य प्रस्तुति दी और इसके बाद एक पैनल परिचर्चा आयोजित की गई। प्रतिष्ठित पैनलिस्ट ये थेः प्रोफेसर बिश्वजीत बनर्जी, सहायक वरिष्ठ फेलो, आरआईएस एवं अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, अशोक विश्वविद्यालय; डॉ. श्रीनिवास यानामंद्रा, प्रमुख (अनुपालन), न्यू डेवलपमेंट बैंक, शंघाई, चीन; प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल, पूर्व प्रोफेसर, जेएनयू; और डॉ. प्रियदर्शी दाश, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस।

बिम्सटेक में वित्तीय सहयोग

डॉ प्रियदर्शी दाश

विनिमय दर में उतार–चढ़ाव निर्यात और आयात के मूल्य में अनिश्चितता का कारण बनता है और हेजिंग की लागत के मामले में व्यापारियों के लिए महंगा हो जाता है। इस पहलू पर वित्तीय सहयोग के संदर्भ में चर्चा की गई है जो देशों के बीच मुद्रा विनिमय व्यवस्था के उदय में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, अकेले चीन ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार को सुगम बनाने के लिए 31 मुद्रा विनिमय व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह, जापान भी अपने एशियाई और अन्य व्यापार भागीदारों के साथ कई मुद्रा विनिमय व्यवस्थाओं का एक पक्ष है। कई मुद्रा विनिमय व्यवस्थाओं के अलावा, भारत ने नेपाल, ईरान और अतीत में रूस के साथ रुपया व्यापार व्यवस्था लागू की है। इस पृष्ठभूमि में, बिम्सटेक देश यादृच्छिक विनिमय दर में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली वित्तीय भेद्यता को कम करने के साधन के रूप में स्थानीय मुद्रा में व्यापार की संभावना भी आजमा सकते हैं। ब्लॉक चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि जैसी उभरती वित्तीय तकनीकों ने न केवल वित्तीय क्षेत्रों को बदल दिया है बल्कि लोगों और समाज को भी सशक्त बनाया है।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः
सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ: वित्त

विकास वित्त संस्थान

आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्री राकेश मोहन ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित नए विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) को 'दीर्घकालिक पूंजी' निवेशकों के साथ–साथ इसके बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन में प्रमुख विशेषज्ञों को आकर्षित करने की आवश्यकता है। श्री मोहन, जो आईएमएफ में एक पूर्व कार्यकारी निदेशक भी थे, ने 19 फरवरी 2021 को आरआईएस और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) द्वारा आयोजित एक वेबिनार के दौरान ये विचार व्यक्त किए।

केंद्रीय बजट 2021–2022 में बुनियादी ढांचागत यानी अवसंरचना क्षेत्र की दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं को स्वीकार किए जाने के साथ–साथ 'अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए एक प्रदाता, व्यवस्थापक और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने' के लिए एक 'प्रोफेशनल रूप से प्रबंधित' डीएफआई का प्रस्ताव किए जाने के मद्देनजर ही उपर्युक्त विचार व्यक्त किए गए हैं। माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा था कि एक 'डीएफआई' की स्थापना के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने इस संस्थान का पूंजीकरण करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये प्रदान किए थे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा था, 'इस डीएफआई के लिए तीन साल में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने की महत्वाकांक्षा है।' वित्तीय सेवा विभाग में सचिव श्री देबाशीष पांडा ने कथित तौर पर कहा था कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को नए डीएफआई 'राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक' में सम्मिलित या समाहित किया जा सकता है। प्रस्तावित डीएफआई इसके साथ ही 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसके तहत लगभग 7,000 परियोजनाओं की पहचान की गई है और जिनमें वर्ष 2020 और वर्ष 2025 के बीच 111 लाख करोड़ रुपये का निवेश किए जाने का अनुमान है।

श्री राकेश मोहन ने यह भी प्रस्तावित किया कि नए डीएफआई का मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में होना चाहिए और प्रस्तावित डीएफआई का पहला सीईओ या सीएमडी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखे। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्री मोहन की राय से सहमति जताते हुए सुश्री श्यामला गोपीनाथ ने यह भी कहा कि सुशासन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अनुबंध पर अमल करने और परियोजना की लाभप्रदता जैसे मुद्दों पर फोकस करने की जरूरत है।

इस अवसर पर आईडीबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉ. जी.ए. टाडास ने कहा कि इस संस्थान के पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपये प्रदान करने का बजट प्रस्ताव वर्ष 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली बुनियादी ढांचागत या अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और देश को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो को प्राप्त करने के लिए डीएफआई की आरंभिक पूंजी को बढ़ाकर कम से कम 50,000–60,000 करोड़ रुपये करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है।

प्रोफेसर स्टेफनी ग्रिफिथ–जोन्स, वित्तीय बाजार निदेशक, इनिशिएटिव फॉर पॉलिसी डायलॉग, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने कहा कि डीएफआई का फोकस अब देशों को 'हरित विकास' हासिल करने में मदद करने, नवाचार को बढ़ावा देने, न केवल बुनियादी ढांचागत क्षेत्र को, बल्कि स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अन्य सामाजिक सेक्टरों को भी प्रति–चक्रीय वित्त प्रदान करने पर है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में डीएफआई का कहीं अधिक प्रभाव हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड–19 महामारी के प्रकोप के बाद डीएफआई का पुनरुत्थान देखने को मिल रहा है।

भारत में घटती बचत दर – नए नीतिगत विकल्प

आरआईएस और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने बैंकों एवं वित्तीय क्षेत्र से जुड़े समूचे परिदृश्य का विश्लेषण करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए आपसी साझेदारी में वेबिनार की श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला में पहली पैनल परिचर्चा 20 जनवरी 2021 को 'भारत में घटती बचत दर – नए नीतिगत विकल्प' पर आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण से हुई। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) के अध्यक्ष श्री एन.एन. वोहरा ने उद्घाटन भाषण दिया। श्री रजनीश कुमार, पूर्व चेयरमैन, भारतीय स्टेट बैंक ने पैनल परिचर्चा की अध्यक्षता की। पैनलिस्टों में ये शामिल थे: प्रोफेसर अनंत नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर (सहायक), सार्वजनिक नीति के प्रमुख, एसपीजेआईएमआर, मुंबई; डॉ. अमेय सप्रे, सहायक प्रोफेसर, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली; और प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल, सीनियर एडजंक्ट फेलो, आरआईएस।

वेबिनार में इस बात पर आम सहमति थी कि हमें दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए नए प्रपत्रों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की जरूरत है। पेंशन फंडों को भी सक्रिय करने की आवश्यकता है। डेटा संबंधी सीमाओं पर काम किया जाना चाहिए। जमाराशियों को बेहतर रिटर्न के साथ सुरक्षित होना चाहिए। अधिकारियों को इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि किस तरह के प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएं और किस तरह के उत्पाद निश्चित रूप से बचत को आकर्षित करेंगे और बेहतर एवं तेज विकास हेतु लाभकारी निवेश के लिए उपलब्ध पूंजी के कुल कोष या धनराशि में वृद्धि करेंगे।

डिजिटल भुगतान और क्यूआर कोडः आगे की राह

32वां विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (स्टिप) फोरम व्याख्यान 23 जनवरी 2021 को प्रोफेसर दीपक बी. फाटक, प्रोफेसर एमेरिटस, आईआईटी–बॉम्बे ने 'डिजिटल भुगतान और क्यूआर कोडः आगे की राह क्या है?" विषय पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया। डॉ. किरण कार्णिक, चेयरमैन, रीबिट और पूर्व अध्यक्ष, नैसकॉम ने सत्र की अध्यक्षता की। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद टेरी के महानिदेशक डॉ. अजय माथुर और आईएचसी के निदेशक श्री सुनीत टंडन ने भाषण दिए। अपने उदघाटन भाषण में प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने प्रौद्योगिकी के साथ वित्तीय क्षेत्र के जुड़ाव की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और यह बताया कि कैसे इसने भारत में वित्तीय लेन–देन और भुगतान प्रणालियों में व्यापक बदलाव लाया है।

प्रोफेसर दीपक बी. फाटक ने समय के साथ भुगतान प्रणालियों के विकास की व्याख्या करते हुए अपने अत्यंत सहज व्याख्यान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने वस्तु विनिमय प्रणाली से मुद्रा में और फिर मुद्रा से वित्तीय प्रपत्रों जैसे कि चेक में बदलने की बात कही। इसके बाद उन्होंने बैंकिंग प्रणालियों में स्वचालन के महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे डिजिटल भुगतान की प्रणाली संभव हो पाई और जिसमें स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट–बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग शामिल हैं। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है और सावधानियां बरत रहा है कि डिजिटल भुगतान से लोगों को हो रही सहूलियत और सुरक्षा एवं हिफाजत (जैसे कि साइबर चोरी, इत्यादि) के बीच संतुलन अवश्य बना रहे।

इसके बाद प्रोफेसर फाटक ने भारत में डिजिटल भुगतान की ताजा स्थिति के बारे में विस्तार से बताया, जिसके तहत उन्होंने आरटीजीएस, एनईएफटी, एसएफएमएस, यूपीआई (भीम), आईएमपीएस, रुपे डेबिट कार्ड, 'आधार' पर आधारित केवाईसी मानक जैसी कुछ सफल भारतीय पहलों के बारे में बताया। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि भारत में 'दो तरीकों से सत्यापन (सीवीवी एवं ओटीपी)' कई विकसित देशों में अपनाई जा रही प्रक्रियाओं की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित प्रक्रिया है।

वक्ता ने आगे यह बताया कि क्यूआर (क्विक रिस्पांस) कोड का विकास किस तरह से हुआ। उन्होंने कहा कि क्यूआर कोड का आविष्कार जापान में वर्ष 1995 में हुआ था और यह अपने पूर्ववर्ती कोड यानी 'बार कोड' की तुलना में हाल ही में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने कहा कि कैमरा युक्त मोबाइल फोन की व्यापक उपलब्धता और उपयोग से ही इस नए कोड को व्यापक रूप से अपनाना संभव हो पा रहा है। बार कोड, जिसे स्कैन करने के लिए विक्रेता अथवा दुकानदार की डेस्क या टेबल पर एक पीओएस डिवाइस को लगाने की आवश्यकता होती है, के विपरीत क्यूआर कोड को ग्राहकों के मोबाइल फोन के कैमरे का उपयोग करके आसानी से और जल्दी से स्कैन किया जा सकता है। इसकी बदौलत यहां तक कि पारंपरिक पीओएस डिवाइस के बिना भी डिजिटल भुगतान करना संभव है।

प्रोफेसर फाटक ने आगे की राह का उल्लेख करते हुए इस बात पर विशेष जोर दिया कि देश में होने वाले सभी खुदरा लेन–देन में डिजिटल लेन–देन की हिस्सेदारी को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, जिसका मतलब यही है कि नकद लेन–देन को आदर्श रूप से शून्य हो जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने 'आधार' सत्यापन को और भी अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि अल्पावधि में कारोबारियों को इससे जोड़ने का काम निरंतर जारी रहना चाहिए और ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं) एवं कमोडिटी (वस्तु या जिंस) विक्रेताओं द्वारा क्यूआर कोड का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। आखिर में, अध्यक्ष डॉ. किरण कार्णिक ने अपने संबोधन में ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों के मद्देनजर डिजिटल मुद्राओं के भविष्य के बारे में संकेत दिया और इसके साथ ही साइबर संबंधी संभावित किफायत के मद्देनजर डिजिटल लेन–देन की मजबूती के बारे में बताया।

विकास वित्त संस्थानों का स्वरूप, नए अवसर और नीतिगत विकल्प

जैसा कि पहले बताया गया था, आरआईएस ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बैंकिंग और वित्त पर वेबिनार की नई श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला के भाग के रूप में पहला वेबिनार 'भारत में घटती बचत दर – नए नीतिगत विकल्प' (20 जनवरी 2021) और दूसरा वेबिनार 19 फरवरी 2021 को विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) पर आयोजित किया गया था। इस श्रृंखला में तीसरा वेबिनार 17 मार्च 2021 को 'विकास वित्त संस्थानों को सही स्वरूप देनाः नए अवसर और नीतिगत विकल्प' पर आयोजित किया गया था।

बजट 2021 में विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) की स्थापना की घोषणा की गई है। वैसे तो डीएफआई के बारे में विवरण अब भी प्रतीक्षित है, लेकिन यह बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के बारे में दीर्घकालिक विजन विकसित करने और घरेलू संसाधनों को जुटाने के लिए कई तौर–तरीकों का अध्ययन करने का व्यापक अवसर देता है। उभरते परिदृश्य के संदर्भ में इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पैनल परिचर्चा के दौरान इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर फोकस किया गया।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। पैनलिस्टों में श्री के.वी. कामथ, पूर्व प्रेसिडेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक; डॉ. विश्वपति त्रिवेदी, पूर्व सचिव, भारत सरकार; डॉ. पार्थ मुखोपाध्याय, सीनियर फेलो, नीतिगत अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली; और श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, सहायक सीनियर फेलो, आरआईएस शामिल थे।

प्रकाशन कार्यक्रम

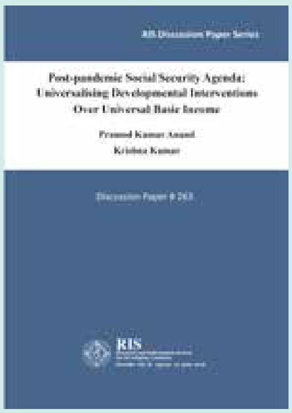

परिचर्चा पत्र

#263: महामारी के बाद सामाजिक सुरक्षा एजेंडा: सार्वभौमिक बुनियादी आय पर विकास संबंधी हस्तक्षेपों को सार्वभौमिक बनाना, प्रमोद कुमार आनंद और कृष्ण कुमार द्वारा

#260: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: मौद्रिक नीति, विकास और मुद्रास्फीति, मनमोहन अग्रवाल और अम्मू लावण्या द्वारा

#254: एक नए विकास बैंक की स्थापना की आवश्यकता

जी ए तडास द्वारा

#248: विनिमय दर संकट: भारत, पूर्वी एशिया और लैटिन अमेरिका का अनुभव, मनमोहन अग्रवाल और टी. आर. वंदना द्वारा

#246: 2008 वित्तीय संकट और आर्थिक शक्ति में बदलाव, मनमोहन अग्रवाल और अमृता ब्रह्मो द्वारा

#245: आर्थिक बहुपक्षवाद संकट में, द्वारा मनमोहन अग्रवाल

नीतिगत सार

#91: क्रिप्टो मुद्राएं: तीन प्रश्न, प्रो मनमोहन अग्रवाल द्वारा

7
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई)

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) पर आरआईएस का कार्यक्रम सार्वजनिक वस्तुओं की सेवा के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के अनुप्रयोगों पर केंद्रित सबसे गतिशील और वैविध्यपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक है। जटिल सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करने में एसटीआई की केंद्रीयता का लाभ उठाते हुए, आरआईएस का कार्यक्रम मौजूदा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करता है और समकालीन विकासात्मक चुनौतियों की एक श्रृंखला को संबोधित करने की दिशा में उनके निर्माण, व्यावसायीकरण, प्रसार के लिए नीतिगत पथमार्ग तलाशता है। तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तन अक्सर अपने साथ कई तरह के लाभ और जोखिम लेकर आते हैं, जिनकी मजबूत नीति निर्माण के लिए बेहतर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। निष्पक्ष और न्यायसंगत तरक्की और विकास को बढ़ावा देने के लिए एसटीआई के अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में एसटीआई का कार्यक्रम परिवर्तनकारी विकास पथों को बढ़ावा देने की दिशा में अंतरराष्ट्रीय एस एंड टी के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान कूटनीति और संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर कार्यक्रमों के साथ मिलकर काम करता है। इस दिशा में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण।

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे – वर्तमान और प्रस्तावित अनुसंधान

नई प्रौद्योगिकियों और विकास के मुद्दों पर प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार कार्यक्रम के तहत कार्य किया जा रहा है।
इसके अंतर्गत दो उप–कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं:

विज्ञान नीति कार्यक्रम

डॉ अमित कुमार और डॉ कपिल पाटिल के साथ डॉ कृष्णा रवि श्रीनिवास

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचारः इसमें अन्य बातों के साथ–साथ जैव प्रौद्योगिकी, उभरती हुई प्रौद्योगिकी, एसडीजी रोड मैपिंग के लिए एसटीआई, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण और वैश्विक संवाद और नीति निर्माण में योगदान, नवाचार, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और नवाचार के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं। इन विषयों के तहत, अनुसंधान और गतिविधियों को अपने दम पर और अन्य संस्थानों के सहयोग से किया जाता है। आरआईएस इनके तहत बाहरी रूप से वित्त पोषित/ समर्थित अनुसंधान परियोजनाओं का हिस्सा है। उभरती तकनीकियों में वर्तमान शोध कृत्रिम बुधिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स (एआई), रोबोटिक्स, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और/ संधारणीय विकास के लिए है। एआई और रोबोटिक्स पर वर्तमान शोध में आचार नीति और शासन–विधि पर भी शोध शामिल है, और आरआईएस इसमें यूनेस्को के साथ काम कर रहा है।

इसमें एआई, स्वास्थ्य देखभाल और नैतिकता पर एक अन्य उप–विषय भी है। आरआईएस इस पर वेबिनार आयोजित करने और प्रकाशनों पर काम करने के लिए आईसीएमआर के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा, भविष्य में एआई और रोबोटिक्स में विभिन्न मुद्दों पर शोध किया जाएगा और वेबिनार/परामर्श आयोजित किए जाएंगे।

अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर वर्तमान शोध में क्वांटम प्रौद्योगिकियों का संचालन, डिजिटलीकरण और डेटा संचालन शामिल है। अन्य बातों के साथ–साथ बायोटेक्नोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, जीन ड्राइव्स और जीनोम एडिटिंग को कवर करते हुए जीवन विज्ञान और जीव विज्ञान पर एक और शाखा है। इन पर प्रकाशनों और कार्यक्रमों की योजना है। नए मुद्दों/ विषयों/ प्रसंगों की पहचान की जाएगी और आरआईएस के लिए उनकी प्रासंगिकता और भारत सरकार व वैश्विक विकास द्वारा निर्धारित उनके महत्व एवं प्राथमिकताओं के आधार पर उन पर शोध किया जाएगा।

एशियन बायोटेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट रिव्यू (एबीडीआर) लगभग पच्चीस वर्षों से प्रकाशित हो रहा है, जिसका खंड 24 इस साल से शुरू हो रहा है। ABDR एक खुली पहुंच वाला, अंतर्राष्ट्रीय, समकक्षा द्वारा समीक्षा की गई पत्रिका है जो अन्य बातों के साथ–साथ स्कोपस (Scopus), ईबीएससीओ होस्ट (EBSCO Host) में अनुक्रमित है। इसे यूजीसी द्वारा स्वीकृत पत्रिकाओं के यूजीसी–केयर सूची समूह II के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक अंक फरवरी (नवंबर 2020 अंक) में प्रकाशित हुआ है।

विज्ञान कूटनीति पर परियोजना

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डॉ बी बालकृष्णन, डॉ कृष्णा रवि श्रीनिवास, डॉ अमित कुमार, डॉ कपिल पाटिल, सुश्री स्नेहा सिन्हा और डॉ देबंजना डे

विज्ञान कूटनीति पर आरआईएस और एनआईएएस के संयुक्त कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, विविध क्षेत्रों/विषयगत क्षेत्रों के प्रख्यात पेशेवरों और विद्वानों को विज्ञान कूटनीति पर केस अध्ययन का कार्य सौंपा गया था। इंटरनेशनल सेंटर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी (ICGEB) के लिए केस अध्ययन की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। आरआईएस ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा (STEM) क्षेत्रों में काम कर रहे प्रवासी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पेशेवरों का एक डेटाबेस तैयार किया है। डेटाबेस 12 विकसित देशों के प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों और सीमांत प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला में शोध करने वाले 600 से अधिक भारतीय मूल के विद्वानों का विवरण प्रदान करता है। भारतीय STEM प्रवासी जुड़ाव गतिविधियों पर समन्वय और सहयोग पर चर्चा करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के साथ एक गोष्ठि आयोजित की गई। सीएसआईआर ने राजदूत ध्यानेश्वर मुले की अध्यक्षता में 'प्रवासी भारतीय अकादमिक और वैज्ञानिक संपर्क' (प्रभास) नामक एकल राष्ट्रीय पोर्टल विकसित करने के लिए एक अंतर–मंत्रालयी कार्य समूह की स्थापना की है। विज्ञान कूटनीति समाचार अलर्ट (*साइंस डिप्लोमेसी न्यूज अलर्ट*) वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी प्रगति, कोविड–19 संबंधित तकनीकी विकास, विज्ञान कूटनीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति और शासन में भारतीय और वैश्विक विकास पर एक पाक्षिक अद्यतन (अपडेट) है।

साइंस डिप्लोमेसी रिव्यू (एसडीआर) आरआईएस द्वारा प्रकाशित एक बहु–विषयक, समकक्ष–समीक्षित पत्रिका है। यह सिद्धांत और व्यवहार में, भारतीय विज्ञान कूटनीति को दृष्टिकोण, और विज्ञान कूटनीति पर साहित्य में योगदान पर चर्चा के लिए जगह प्रदान करता है। विकसित हो रहे नेटवर्क के लिए, संस्थानों की निर्देशिका 125 ऐसे संस्थानों की सूची प्रस्तुत करती है, जो दुनिया भर में विज्ञान कूटनीति, विज्ञान नीति गतिविधियों/पाठ्यक्रमों में संलग्न हैं। इस अवधि के दौरान डेटाबेस में पंद्रह संस्थानों को जोड़ा गया है। एसटीआई पर एक संयुक्त प्रकाशन और एक रूसी प्रबुद्ध मंडल और भारतीय दूतावास, मॉस्को के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परामर्शदाता के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा जारी है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रौद्योगिकी और नवाचार (ईईटीआई) पेपर श्रृंखला, जिसका उद्देश्य भारत के लिए रणनीतिक प्रासंगिकता वाले देशों के एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र का पता लगाना, समझना और विश्लेषण करना है, उनकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियों, एसटीआई क्षमता, नवाचार के लिए प्रोत्साहन, व्यापार, प्रमुख और फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों, एसटीआई सहयोग और विज्ञान कूटनीति पर फोकस करेगा। पहला पेपर चीन पर है और समीक्षा के लिए अगस्त तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

उल्लिखित जारी गतिविधियों के अलावा, आरआईएस समकालीन विज्ञान कूटनीति से जुड़े विभिन्न विषयों और मुद्दों पर प्रमुख भारतीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के लिए अगस्त 2021 में विज्ञान कूटनीति पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहा है।

आरआईएस ने विज्ञान कूटनीति पर विदेशों में तैनात हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी परामर्शदाताओं के साथ एक ऑनलाइन परामर्श बैठक आयोजित करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य कोविड–19 प्रतिक्रिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक पहल, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, बड़ी अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाएं और भविष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत करने में विज्ञान कूटनीति की भूमिका पर चर्चा करना है। एसडीजी के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। आने वाले महीनों में 'हराइज़न यूरोप' और 'वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति' पर FISD व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख मुद्दों पर नीतिगत संक्षिप्त विवरण का काम जारी है। विषयों में लिंग और विज्ञान कूटनीति, भारत का मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग और विज्ञान कूटनीति और दक्षिण एशिया, आदि शामिल हैं।

डीएसटी के साथ विज्ञान कूटनीति पर एक नई और बड़ी परियोजना पर चर्चा हुई है। विज्ञान कूटनीति, जो अन्य बातों के साथ–साथ, इस परियोजना के दौरान तय होगी। परियोजना विषयगत कवरेज, गतिविधियों, प्रकाशनों सहित अन्य प्रदेय और कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों के संदर्भ में अधिक महत्वाकांक्षी है। चर्चा के आधार पर कहा जा सकता है कि परियोजना प्रस्ताव को संशोधित किया जा रहा है और प्रारंभिक समीक्षा के लिए जल्द ही डीएसटी को प्रस्तुत किया जाएगा।

एसडीजी के लिए एसटीआई

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डॉ भास्कर बालकृष्णन, डॉ पी के आनंद, श्री कृष्ण कुमार, डॉ के रवि श्रीनिवास, डॉ सब्यसाची साहा, और डॉ कपिल धनराज पाटिल

यह यूएन–आईएटीटी (UN-IATT) द्वारा शुरू किए गए एसडीजी (SDG) के रोडमैप के लिए एसटीआई पर वैश्विक पायलट कार्यक्रम में एक पायलट देश के रूप में भारत की भागीदारी के हिस्से के रूप में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा वित्त पोषित आरआईएस (RIS) में एक 3–वर्षीय परियोजना है। परियोजना की शुरुआत इसी वित्तीय वर्ष में की गई थी। इस परियोजना को महानिदेशक के नेतृत्व में आरआईएस में एक अंतर–अनुशासनात्मक अनुसंधान दल द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

a) भारत में एसडीजी के लिए एसटीआई के लिए सांकेतिक प्रौद्योगिकी मानचित्रण का निर्माण – पहला मसौदा पीएसए के कार्यालय को प्रस्तुत किया गया।

b) मई 2021 में एसटीआई फोरम में भारत की भागीदारी के लिए इनपुट।

c) संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित अन्य टीएफएम संबंधित बैठकों के लिए इनपुट जहां आरआईएस आमंत्रित है।

d) जनवरी और मार्च 2021 में एसडीजी 2 और 6 को कवर करने वाले एसडीजी के लिए एसटीआई पर दो राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन बैठकों में लाइन मंत्रालयों, भारत सरकार की एजेंसियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

सभी पायलट देशों और संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक और साथ ही, एसडीजी–विशिष्ट राष्ट्रीय कार्यशालाओं की तैयारी चल रही है।

भारत की 'स्टिप नीति 2020' बनाना

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के. विजयराघवन ने 30 सितंबर 2020 को 'भारत की स्टिप नीति 2020 बनाना' विषय पर 29वां स्टिप व्याख्यान दिया। श्री संजय किर्लोस्कर, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड ने सत्र की अध्यक्षता की।

अपने व्याख्यान में प्रोफेसर विजयराघवन ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में भारत की वर्तमान स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए और इसके साथ ही यह बताया कि स्टिप, 2020 के जरिए हमारे वैज्ञानिक उद्देश्यों (समावेशी विकास के साथ) को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए इस संदर्भ में और क्या करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर विजयराघवन ने तीन सवाल पूछ कर अपना व्याख्यान शुरू कियाः (1) हम कहां से आए हैं?; (2) हम अपने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अब किस ओर जा रहे हैं?; और (3) हम यहां से अब कहां जाएंगे? प्रोफेसर विजयराघवन ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया में वैज्ञानिक और तकनीकी मापदंडों की क्षमताओं का पूरी तरह से दोहन करने के लिए लोगों के नजरिए में बदलाव लाना अत्यंत आवश्यक है। इसी तर्ज पर हमारे कुछ उद्योगपतियों ने चुनौती स्वीकार की, जमीनी स्तर पर प्रयोग किए और सफलता भी हासिल की। प्रोफेसर विजयराघवन ने कहा कि यदि हम भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र पर गौर करें, तो हम यह पाते हैं कि हमारे पास बड़ी संख्या में बेहतरीन और कुशल लोग हैं, जो मुख्य रूप से इन दो कारणों से संभव हो पाया हैः युवा लोगों में एक–दूसरे से आगे निकलने की महत्वाकांक्षा और सीखने के उपकरण जैसे कि कंप्यूटर एवं उन्नत उपकरण डिजाइन अब और भी अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। एसडीजी लक्ष्यों के साथ एसटीआई नीति के उचित समायोजन के संबंध में उन्होंने कहा कि यदि भारत एसडीजी को तेज गति से प्राप्त करना चाहता है, तो दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम पैसे में बेहतरीन चीजें हासिल करना चाहता है। वर्तमान समय में कृत्रिम रूप से कम कीमतें अदा करके हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भविष्य में अधिक कष्ट झेलने पर विवश कर देंगे। दूरदर्शी दृष्टिकोण यही है कि हमारे उत्पादों की कीमतें बिल्कुल वाजिब तय करना आवश्यक है जिसमें पर्यावरण और स्वच्छता एवं साफ–सफाई से जुड़ी अन्य सभी लागतें अवश्य ही कवर होनी चाहिए। यदि हम अपने उत्पादों की कीमतें बिल्कुल सही तरीके से तय करते हैं जिसमें अन्य सभी लागतों को समायोजित किया जा सके, तो एसडीजी की प्राप्ति की गति आने वाले समय में काफी तेज हो जाएगी।

'आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का आकलनः वैश्विक निहितार्थ' पर पुस्तक विमोचन वेबिनार

'आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का आकलनः वैश्विक निहितार्थ' पर पुस्तक विमोचन वेबिनार 6 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ हुआ। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने 'सोशियो–इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफायड क्रॉप्सः ग्लोबल इम्प्लीकेशन्स" नामक पुस्तक का विमोचन किया।

परियोजना के निष्कर्ष अध्ययन दल के इन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गएः प्रोफेसर पी. जी. चेंगप्पा, पूर्व कुलपति, यूएएस, बेंगलुरू; प्रोफेसर ई. हरिबाबू, सहायक वरिष्ठ फेलो, एवं समाजशास्त्र के प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), हैदराबाद विश्वविद्यालय; प्रोफेसर एन. ललिता, गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद; प्रोफेसर रबीन्द्र पडरिया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; प्रोफेसर के. श्रीनिवास, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, हैदराबाद; प्रोफेसर सुरेश पाटिल, डीन, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर; प्रोफेसर के. आर. अशोक, निदेशक, कृषि एवं ग्रामीण विकास अध्ययन केंद्र (काड्र्स), तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर; डॉ. ए.वी. मंजूनाथ, निदेशक (आकलन), कर्नाटक आकलन प्राधिकरण, बेंगलुरू; और डॉ. के. रवि श्रीनिवास, सलाहकार, आरआईएस। इसके बाद एक पैनल परिचर्चा आयोजित की गई। डॉ. एस.आर. राव, उपाध्यक्ष, श्री बालाजी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, पुडुचेरी एवं पूर्व सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने इसकी अध्यक्षता की। मुख्य पैनलिस्ट ये थेः डॉ. रंजिनी वारियर, पूर्व सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; डॉ. अश्विनी महाजन, राष्ट्रीय सह–संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच; प्रोफेसर एम.के. रमेश, नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी, बेंगलुरू; श्री हरीश दामोदरन, संपादक, ग्रामीण मामले एवं कृषि, इंडियन एक्सप्रेस; प्रोफेसर एन. चंद्रशेखर राव, आर्थिक विकास संस्थान, और डॉ. कोएन बेमर, यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय, नीदरलैंड। कार्यक्रम का समापन डॉ. के. रवि श्रीनिवास के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

पहुंच, समानता एवं समावेश (एईआई) और विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवाचार (एसटीआई) पर परामर्श

आरआईएस विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवाचार (एसटीआई) से जुड़े मुद्दों पर काम करता रहा है और एसटीआई, विशेषकर उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास निहितार्थों में आरआईएस की काफी रुचि रही है। वैसे तो आरआईएस ने उभरती प्रौद्योगिकियों के बीच कृषि जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी और सिंथेटिक बायोलॉजी पर काम किया है, लेकिन एक ऐसे वैकल्पिक प्रतिमान की आवश्यकता है जो एसटीआई के सामाजिक निहितार्थों का आकलन करने के लिए प्रभाव आकलन के पारंपरिक तौर–तरीकों से परे हो। इस संबंध में आरआईएस ने 3 सितंबर 2020 को पहुंच, समानता एवं समावेश (एईआई) और विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवाचार (एसटीआई) पर एक परामर्श का आयोजन किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर

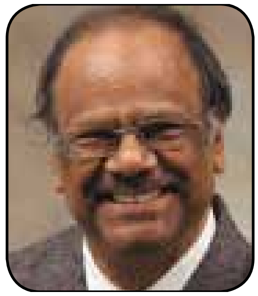

प्रो. मनमोहन अग्रवाल

सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। 'पहुंच, समानता एवं समावेश और एसटीआईः ताजा स्थिति व एईआई प्रतिमान के लिए आगे की राह' पर पहले सत्र की अध्यक्षता गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन (गिफ्ट), तिरुवनंतपुरम के निदेशक प्रो. के. जे. जोसफ ने की।

इस अवसर पर वक्ता ये थेः प्रो. मनमोहन अग्रवाल, पूर्व प्रोफेसर, व्यापार एवं विकास केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और वर्तमान में सहायक वरिष्ठ फेलो, आरआईएस; प्रो. दिनेश अबरोल, प्रोफेसर, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी); डॉ. सरदिन्दु भादुड़ी, एसोसिएट प्रोफेसर, विज्ञान नीति अध्ययन केंद्र, जेएनयू; और डॉ. अरुल स्कारिया, एसोसिएट प्रोफेसर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली। 'महिला–पुरुष, एसटीआई और एईआई' पर आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर करुणा चानना, पूर्व प्रोफेसर, जाकिर हुसैन शैक्षणिक अध्ययन केंद्र, जेएनयू; प्रो. वी. सुजाता, प्रोफेसर, सामाजिक प्रणाली अध्ययन केंद्र, जेएनयू; और डॉ. निमिता पांडेय, डीएसटी–विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति फेलो, नीतिगत अनुसंधान के लिए डीएसटी केंद्र, आईआईएससी, बेंगलुरू। डॉ. कृष्ण रवि श्रीनिवास, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

कोविड–19 से तेजी से उबरने और हालात फिर से बेहतर करने के लिए दक्षिण एशियाई सहयोग

'कोविड–19 से तेजी से उबरने और हालात फिर से बेहतर करने के लिए दक्षिण एशियाई सहयोग' पर एक नीतिगत संवाद 9 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र एस्कैप, यूएन75 2020 एवं परे और सासेप्स द्वारा आरआईएस, भारत; एसएडब्ल्यूटीईई, नेपाल; एसडीपीआई, पाकिस्तान; आईपीएस, श्रीलंका; और बिरुनी इंस्टीट्यूट के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। नीतिगत संवाद की शुरुआत डॉ. नागेश कुमार, निदेशक, संयुक्त राष्ट्र एस्कैप–एसएसडब्ल्यूए; और प्रोफेसर दीपक नय्यर, प्रोफेसर–एमेरिटस, जेएनयू एवं सह–अध्यक्ष, सासेप्स (यानी एसएसीईपीएस) के आरंभिक भाषणों के साथ हुई। इसका संचालन प्रो. अकमल हुसैन, डीन, आईटीयू, लाहौर और सह–अध्यक्ष, सासेप्स ने किया। इस अवसर पर प्रतिष्ठित वक्ता ये थेः डॉ. फहमीदा खातुन, कार्यकारी निदेशक, सीपीडी, बांग्लादेश; श्री वांगचुक नमगे, प्रमुख, विकास सहयोग प्रभाग, जीएनएचसी, भूटान; प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; डॉ. पॉश राज पांडेय, अध्यक्ष, एसएडब्ल्यूटीईई, नेपाल; डॉ. आबिद सुलेरी, कार्यकारी निदेशक, एसडीपीआई एवं पीएमईएसी के सदस्य, पाकिस्तान; और डॉ. दुशनी वीराकून, कार्यकारी निदेशक, आईपीएस, श्रीलंका।

संयुक्त राष्ट्र एस्कैप द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नीतिगत संवाद में दक्षिण एशियाई सहयोग के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण विजन, देश संबंधी दृष्टिकोण और रणनीतियों का उल्लेख किया गया है। वैसे तो संकट से उबरने के लिए प्रस्ताव राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए थे, लेकिन क्षेत्रीय सहयोग रणनीतियों और एक क्षेत्रीय मास्टर प्लान पर विशेष जोर दिया गया, ताकि भविष्य में विभिन्न प्रकोपों से निपटने के लिए आवश्यक सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके और इसके साथ ही हालात फिर से बेहतर करने के लिए संबंधित देशों को सहायता दी जा सके। खुली परिचर्चा के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र निश्चित रूप से क्षेत्रीय स्तर पर ऋण राहत के लिए मजबूत दलील दे सकता है। जहां तक भारत का सवाल है, वह विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों (एलडीसी) की सहायता हेतु ऋण राहत और कर्ज माफी के उपाय सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवाद को सही स्वरूप देने में अगुवाई (उप–क्षेत्रीय और द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में अपनी

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ: एसटीआई

भूमिका को देखते हुए) कर सकता है। वैसे तो कोविड–19 से निपटने के लिए अपने संसाधनों को कहीं और लगा देने से एसडीजी को प्राप्त करने के प्रयासों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, लेकिन संकट से निपटने के लिए घोषित किए गए राष्ट्रीय प्रोत्साहन पैकेजों को एसडीजी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं जैसे कि 'स्वच्छ एवं हरित आर्थिक रिकवरी एवं सतत विकास के लिए पेरिस समझौते' के साथ जोड़ा जा सकता है। संकट की वजह से बढ़ते महिला–पुरुष भेदभाव की समस्या से पार पाने के लिए एक उपयुक्त रणनीति बनाकर महिलाओं की शिक्षा एवं उन्हें पुनः कुशल बनाने के साथ–साथ डिजिटल प्रौद्योगिकियों और प्लेटफॉर्मों तक पहुंच के जरिए स्वरोजगार एवं उद्यमिता के अवसर सृजित करने पर भी फोकस करना चाहिए। वैसे तो विभिन्न देशों के असुरक्षित या संवेदनशील होने का स्तर अलग–अलग हो सकता है, लेकिन एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया निश्चित रूप से पारिस्थितिकी आपदाओं और भावी महामारियों की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने से आवश्यक सुरक्षा कवर मिल सकता है और इसके साथ ही वर्तमान संकट एवं भविष्य के प्रकोप से निपटने के लिए इस क्षेत्र की समग्र तैयारी बेहतर हो सकती है। अधिक से अधिक समान एवं व्यापक विकास का मार्ग अपनाने और मध्यम वर्ग एवं गरीबों सहित सभी लोगों की क्षमताओं का इस्तेमाल करने के साथ–साथ विकास प्रक्रिया में इन्हें सक्रिय साझेदार बनाए जाने को भी त्वरित आर्थिक बेहतरी वाले प्रयासों के केंद्र में अवश्य होना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय विकास साझेदार जैसे कि यूएन–एस्कैप विभिन्न क्षेत्रों एवं मुद्दों पर विशिष्ट व विस्तृत सहयोग के जरिए क्षेत्रीय आधार पर दक्षिण एशियाई देशों के बीच अधिक–से–अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।

एसडीजी के लिए एसटीआई पर वेबिनार

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित वैश्विक प्रौद्योगिकी सुविधा व्यवस्था (टीएफएम) की शुरुआत के लिए आयोजित की गई वार्ताओं के पीछे जो प्रमुख ताकतें थीं उनमें से एक भारत भी था। टीएफएम पर ठोस परिचालन कदम मौजूदा समय में 'एसडीजी रोडमैप के लिए एसटीआई पर वैश्विक पायलट कार्यक्रमों' के माध्यम से उठाए जा रहे हैं जो वर्ष 2019 में लॉन्च किए गए थे। भारत इस पहल के तहत पायलट देशों के रूप में चार अन्य राष्ट्रों के साथ जुड़ गया है। यूरोपीय संघ और जापान इस पहल में 'एसडीजी के लिए एसटीआई पर संयुक्त राष्ट्र अंतर–एजेंसी टास्क टीम (आईएटीटी)' के साथ जुड़ गए हैं, ताकि पायलट देशों को उनकी एसडीजी रोडमैप संबंधी कवायद में आवश्यक सहयोग दिया जा सके। भारत में एसडीजी रोडमैप के लिए एसटीआई, जैसा कि तय किया गया है, के तहत चार एसडीजी यथा एसडीजी 2 (कृषि/पोषण); एसडीजी 3 (स्वास्थ्य एवं खुशहाली), एसडीजी 6 (जल व स्वच्छता) और एसडीजी 7 (सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा) पर फोकस किया जाएगा। भारत में एसडीजी रोडमैप संबंधी कवायद के लिए एसटीआई के तहत सुझाया गया महत्वपूर्ण प्रदेय उत्पाद दरअसल भारतीय संदर्भ में अधिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु अनुसंधान एवं विकास पर व्यय की समीक्षा के लिए एक निर्णय प्रणाली तैयार करने की दिशा में काम करना होगा, जिसे पीएसए के कार्यालय में रखा जाएगा। इस बारे में सर्वे संबंधी अध्ययन शुरू कर दिया गया है। भारत एवं जापान एक साथ जुड़ गए हैं और अपने–अपने यहां एसडीजी रोडमैप के लिए एसटीआई को बढ़ावा देने में आपसी रुचि के आधार पर सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही वे अफ्रीकी देशों में इस पहल की सफल पुनरावृत्ति में भी आवश्यक सहयोग दे रहे हैं। इनमें वे देश भी शामिल हैं जो पहले से ही पायलट देशों के रूप में इस कवायद का हिस्सा हैं।

इस कवायद के हिस्से के रूप में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय और पीएसए के साथ ज्ञान साझेदार के रूप में आरआईएस ने जापान सरकार के कैबिनेट कार्यालय (सीएओ) और एसडीजी के लिए एसटीआई पर संयुक्त राष्ट्र अंतर–एजेंसी टास्क टीम (यूएन–आईएटीटी) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 29 जून 2020 को 'सतत विकास के लिए एसटीआई साझेदारियां विकसित करनाः एसडीजी रोडमैप के लिए एसटीआई पर वैश्विक पायलट कार्यक्रम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्यों में तेजी लाना' विषय पर एक आभासी कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यशाला को जुलाई 2020 में उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) की बैठक से पहले टीएफएम के एक आधिकारिक कार्यकलाप कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई है। वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ–साथ पायलट देशों, भारत, जापान और संयुक्त राष्ट्र/भागीदार एजेंसियों के विशेषज्ञ भी इस कार्यशाला में शामिल हुए। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संवाद 23 जून 2020 को आयोजित किया गया जिस दौरान चारों उपर्युक्त एसडीजी के कार्यान्वयन में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से लाभ उठाने पर फोकस किया गया।

विज्ञान और नीति–निर्माण के बीच बेहतर सहयोग के लिए एक चेतावनी है कोविड –19

वैसे तो आधुनिक इतिहास में सदैव ही विज्ञान और नीति निर्माण एक–दूसरे पर निर्भर रहे हैं, यानी वैज्ञानिक अपनी ओर से नीति–निर्माताओं को सूचित करते रहे हैं और नीति–निर्माता अनुसंधान के लिए आवश्यक धनराशि मुहैया कराने एवं प्राथमिकताएं निर्धारित करने का निर्णय लेते रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी इन दोनों के बीच संबंध इतने करीब नहीं रहे हैं और इसके साथ ही इतने जटिल नहीं रहे हैं जैसा कि कोविड–19 महामारी के दौरान देखने को मिला।

वैसे तो वैज्ञानिक अवधारणाएं कोविड–19 से पहले के दौर में भी आर्थिक या सामाजिक नीतियों का निर्धारण करते समय नीति निर्माताओं द्वारा गौर की जाने वाली अलग–अलग जानकारियों में शामिल हुआ करती थीं, लेकिन अब वे ही ऐसे नीतिगत निर्णयों के लिए मुख्य आधार बन गई हैं जो या तो लाखों लोगों के जीवन को बचा सकते हैं या उन्हें खतरे में डाल सकते हैं, अथवा समस्त अर्थव्यवस्थाओं को या तो तबाह कर सकते हैं या सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। चूंकि जलवायु परिवर्तन या पर्यावरणीय क्षति जैसे वैश्विक मुद्दे, जिनके समाधान के लिए विज्ञान और नीति निर्माताओं के बीच समान रूप से गहन सहयोग की आवश्यकता होगी, अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, अतः ऐसे में यह सवाल काफी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है कि क्या कोविड–19 ने अब विज्ञान एवं नीति निर्माण के बीच नए सिरे से सहयोग करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

यूएनडीपी सियोल नीतिगत केंद्र और आरआईएस द्वारा 11 दिसंबर 2020 को संयुक्त रूप से आयोजित विशेष सत्र के दौरान कई उदाहरण पेश करते हुए यह जानकारी दी गई कि किस तरह से विभिन्न देशों और संस्थानों ने कोविड–19 को फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच ज्ञान एवं अच्छी प्रथाओं या तौर–तरीकों को आपस में साझा करने को सुविधाजनक बनाया। इसे ध्यान में रखते हुए विज्ञान और नीति के बीच प्रभावकारी सामंजस्य के लिए विभिन्न मॉडलों और संस्थागत संरचनाओं पर विचार किया जाएगा, ताकि यह दर्शाया जा सके कि किस तरह से विभिन्न देशों ने वैज्ञानिक ज्ञान या अवधारणाओं को नीतिगत निर्णयों में तब्दील कर दिया है।

इस सत्र का उद्देश्य यह पता लगाना था कि किस तरह से ज्ञान साझा करने वाले विशेषज्ञ कोविड–19 महामारी के दौरान विभिन्न नेटवर्कों को बनाने और नीति निर्माताओं एवं वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में हासिल हुए अनुभवों को सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन अन्य मुद्दों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी संबंधित हितधारकों के बीच साझा किया जा सके, जिनके लिए प्रभावकारी विज्ञान–नीति सामंजस्य आवश्यक होता है। सत्र के दौरान इस विषय पर भी चर्चा की गई कि क्या देश विशेष के स्तर पर हासिल अनुभवों को आगे समेकित करने के साथ–साथ संस्थागत रूप दिया जा सकता है, ताकि वैश्विक मुद्दों से निपटने वाली बहुपक्षीय रूपरेखाओं और नजरिए में इन्हें समाहित किया जा सके।

इस दौरान प्रतिभागियों ने जिन–जिन प्रश्नों के जवाब दिए उनमें से मुख्य प्रश्न ये हैं: कोविड–19 से संबंधित मुद्दों पर विज्ञान और नीति निर्माण के बीच प्रभावकारी सहयोग को बढ़ावा देने में कौन–कौन से तरीके और संस्थागत संरचनाएं सबसे सफल साबित हुई हैं? क्या वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालने के उद्देश्य से विज्ञान–नीति के सामंजस्य वाली संस्थागत संरचना को उन्नत करके बहुपक्षीय स्तर तक बढ़ाया जा सकता है; यदि हां, तो कैसे?, और ज्ञान विशेषज्ञ यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वैश्विक प्रासंगिकता वाले अन्य मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर फोकस करते हुए उनके उत्कृष्ट कार्य महामारी से परे भी जाकर विज्ञान–नीति में प्रभावकारी सहयोग को बनाए रखने में मददगार साबित हों।

कार्यक्रम की शुरुआत आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के आरंभिक भाषण के साथ हुई। श्री आर्टेमी इज्मेसटीव, नीति विशेषज्ञ, यूएनडीपी सियोल नीतिगत केंद्र ने इसका संचालन किया। मुख्य वक्ता ये थे: डॉ. चेख म्बो, फ्यूचर अफ्रीका के निदेशक; डॉ. अरबिंद मित्रा, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव; डॉ. झांग चुआनहोंग, चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान के सचिव; डॉ. रथिन रॉय, प्रबंध निदेशक – अनुसंधान एवं नीति, ओडीआई; और डॉ. सानुशा नायडू, वैश्विक संवाद संस्थान में वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी। यूएनडीपी सियोल नीतिगत केंद्र के निदेशक श्री स्टीफन क्लिंगबिएल ने समापन भाषण दिया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँः एसटीआई

'क्रिस्पर' के लिए नोबेल पुरस्कार

क्रिस्पर' पर उल्लेखनीय कार्य के लिए दो अग्रणी वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से नवाजे जाने के बाद क्रिस्पर तकनीक जिस तरह से आम जनता और मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उसे ध्यान में रखते हुए आरआईएस ने 29 अक्टूबर 2020 को 'क्रिस्पर के लिए नोबेल पुरस्कार' विषय पर वेबिनार आयोजित किया। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पालिंड्रोमिक रिपीट्स (क्रिस्पर) दरअसल डीएनए अनुक्रमों के एक विशिष्ट परिवार या वर्ग को कहते हैं और इसका उपयोग जीनोम एडिटिंग में किया जाता है। इस साल रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से जेनिफर डॉडना और एमैनुएल चारपेंटियर को 'क्रिस्पर' पर उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए नवाजा गया जिसकी बदौलत ही इसका व्यापक उपयोग संभव हो पाया।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में कई क्षेत्रों में शोध और इसके अनुप्रयोगों में 'क्रिस्पर' के विशेष महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आरआईएस विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार कार्यक्रम के तहत जैव प्रौद्योगिकियों के प्रभावों और निहितार्थों पर काम करता रहा है। इस व्याख्यान का आयोजन इसलिए किया गया, ताकि क्रिस्पर, स्वास्थ्य एवं कृषि में इसके अनुप्रयोगों और इस प्रौद्योगिकी के संचालन से जुड़े मुद्दों को आसानी से समझा जा सके। प्रोफेसर बी के थेल्मड, जेनेटिक्स विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, और मानव जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के सदस्य ने पैनल परिचर्चा की अध्यक्षता की। उन्होंने आनुवांशिक मानव जीनोम एडिटिंग के बारे में 'मानव जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग के क्लीनिकल उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग' की सिफारिशों और रिपोर्ट के आधार पर एक प्रस्तुति दी।

डॉ. देबज्योति चक्रबर्ती, सीएसआईआर – जीनोमिक्स और एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान (आईजीआईबी) ने बताया कि क्रिस्पर तकनीक कैसे विकसित हुई और आखिरकार यह क्या–क्या करने में सक्षम है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में स्टेम सेल सहित थेरेपी और उपचारों की एक विस्तृत श्रृंखला में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों के बारे में बताया। सीएसआईआर की सिकल सेल एनीमिया (रक्त की लाल कोशिकाओं की कमी) परियोजना की एक केस स्टडी का उल्लेख करते हुए उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे इस तरह की शारीरिक हालत का सटीक उपचार ढूंढ़ने के लिए क्रिस्पर का उपयोग किया जा रहा है जिससे आदिवासी लोग व्यापक रूप से ग्रस्त रहते हैं। डॉ. एम. के. रेड्डी, ग्रुप लीडर, अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीजीईबी) ने चावल से जुड़े अपने विशिष्ट अनुसंधान का उदाहरण देते हुए कृषि क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग की सचित्र व्याख्या पेश की। इसके साथ ही उन्होंने इस बारे में विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया कि किस तरह से चावल की पैदावार व्यापक रूप से बढ़ाने में 'क्रिस्पर' काफी मददगार साबित हो सकती है।

आईसीएमआर की जैवनैतिकता इकाई की प्रमुख डॉ. रोली माथुर ने सार्वजनिक समझ विकसित करने की जरूरत के साथ–साथ मानव स्वास्थ्य में इसके अनुप्रयोग के नियमन के लिए दिशा–निर्देश विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। जीन थेरेपी के लिए दिशा–निर्देश विकसित करने पर आईसीएमआर द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ण भरोसा और लोगों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि केवल तभी इस प्रौद्योगिकी को सहर्ष स्वीकार किया जा सकेगा। पैनल परिचर्चा के बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया। डॉ. कृष्णा रवि श्रीनिवास ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

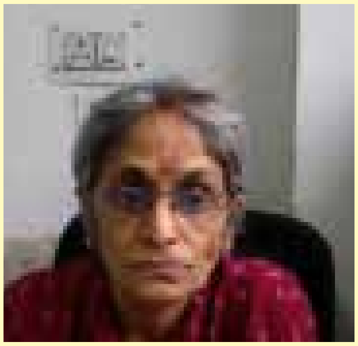

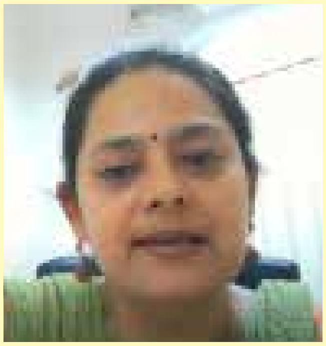
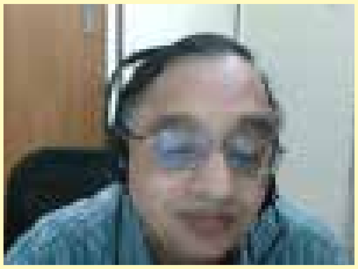
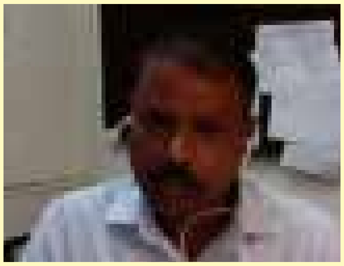
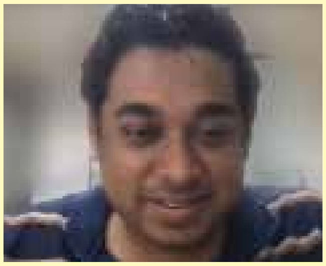

व्याख्यान प्रगति पर है जिसका यह स्क्रीनशॉट है

31वां स्टिप फोरम व्याख्यान

31वां स्टिप फोरम व्याख्यान प्रो. आशुतोष शर्मा, सचिव, डीएसटी द्वारा 17 दिसंबर 2020 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया गया। इस सार्वजनिक व्याख्यान की थीम यह थीः 'निडर नई दुनिया में विज्ञान का चमत्कार'। इस आयोजन की अध्यक्षता डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान कूटनीति फेलो, आरआईएस ने की। डॉ. पूर्णिमा रूपल, निदेशक, सीईएफआईपीआरए, और डॉ. आर. रमणन, मिशन निदेशक, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग भी इस आयोजन के दौरान उपस्थित थे।

अपने अत्यंत दूरदर्शी संबोधन में प्रो. आशुतोष शर्मा ने भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहु–विषयक और समस्या–केंद्रित दृष्टिकोण के विशेष महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि एसटीआई का भविष्य दरअसल विभिन्न प्रौद्योगिकी धाराओं में सामंजस्य के बारे में है। प्रो. आशुतोष शर्मा ने कहा, 'कोविड–19 ने हमें यह याद दिलाया है कि विघटनकारी बदलाव बेहद तीव्र गति से हो रहे हैं। हम आज एक निडर दुनिया में रह रहे हैं क्योंकि हमें बदलाव से निपटना ही होगा। नई दुनिया के बदलावों से निपटने के लिए हमें प्रौद्योगिकी की मांगों को पूरा करने की जरूरत है।'

उन्होंने हमारे एसटीआई और शिक्षा परिवेश को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा, 'उद्योग 4.0 दरअसल डेटा, सूचनाओं और ज्ञान के प्रवाह को नियंत्रित करने के बारे में है। सूचना और ज्ञान को साझा करना ही आने वाले हर समय के लिए भावी दिशा तय करेगा।'

प्रो. शर्मा ने एसटीआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की अनिवार्यता जताई। इतना ही नहीं, प्रो. शर्मा ने आत्मनिर्भरता के तीन पहलुओं यथा आत्म विश्वास, आत्म सम्मान और आत्म चिंतन को प्रस्तुत किया।

नवाचार एवं टीकों तक पहुंच और स्वास्थ्य प्रभाव कोष

आरआईएस ने 19 जनवरी 2021 को नवाचार एवं टीकों तक पहुंच और स्वास्थ्य प्रभाव कोष (एचआईएफ) पर एक वेबिनार का आयोजन किया। एचआईएफ दरअसल दवाओं एवं फार्मास्यूटिकल्स में नवाचार को प्रोत्साहित करने और बेहतर पहुंच को सक्षम करने के लिए एक वैकल्पिक मॉडल के रूप में येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थॉमस पोगे द्वारा प्रस्तावित एक अवधारणा है। इस वेबिनार का आयोजन सार्वजनिक स्वास्थ्य पर शिक्षाविदों, उद्योग के प्रतिनिधियों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाने के लिए किया गया था, ताकि टीकों तक पहुंच, उनमें नवाचार के मुद्दों पर चर्चाएं की जा सकें।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में टीकों तक पहुंच के मुद्दे के साथ–साथ इस बात पर भी प्रकाश डाला कि क्यों नवाचार से अक्सर पर्याप्त पहुंच संभव नहीं होती है। इसके साथ ही उन्होंने पहुंच और नवाचार दोनों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाओं की पहचान करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। डॉ. एस. आर. राव, उपाध्यक्ष, श्री बालाजी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, पांडिचेरी और पूर्व सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने इस सत्र की अध्यक्षता की और नवाचार के लिए विभिन्न विकल्पों पर बहस की आवश्यकता को रेखांकित किया। अपनी प्रस्तुति में प्रोफेसर पोगे ने एचआईएफ की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और यह दलील दी कि यह विकासशील देशों को टीकों एवं अन्य आवश्यक दवाओं के साथ–साथ उपेक्षित बीमारियों की दवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में आखिरकार कैसे मदद कर सकता है। उन्होंने बताया कि एचआईएफ दरअसल पहुंच को सक्षम करने के लिए अन्वेषकों को प्रोत्साहित करता है क्योंकि प्रभाव के अधिक होने पर वे अधिक लाभान्वित होते हैं। प्रोफेसर एडन हॉलिस ने अपनी प्रस्तुति में एचआईएफ की काफी वकालत करते हुए इस ओर ध्यान दिलाया कि पायलट कार्यक्रमों के माध्यम से इसे आजमाना उचित रहेगा और इसके साथ ही उन्होंने विकसित एवं विकासशील देशों में लोगों तक पहुंच में भारी असमानताओं को देखते हुए किफायती टीके और दवाएं लाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।

श्री अशोक मदान ने उद्योग के नजरिए से अवगत कराया और जेनरिक के महत्व के बारे में विस्तार से बताया और इसके साथ ही यह भी बताया कि जेनेरिक उद्योग ने किस तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य में अहम योगदान दिया है। एचआईएफ के बारे में उन्होंने यह संकेत दिया कि उद्योग इसके खिलाफ नहीं होगा। डॉ. मुरली ने बायोफार्मा उद्योग के नजरिए से अवगत कराया और बेहतर एवं अधिक नवाचार के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि एचआईएफ के लिए अधिक अन्वेषण जरूरी है और इसके साथ ही व्यापक सहयोग देने की आवश्यकता है। डॉ. वाई. माधवी ने वर्ष 1947 के बाद भारत में टीके के विकास एवं उपलब्धियों और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में चर्चा की। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि टीकों में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए था और इसके लिए आवश्यक सहयोग दिया जाना चाहिए था। प्रोफेसर पोगे ने भारत में एचआईएफ पर दर्शकों और पैनलिस्टों की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब दिए। डॉ. कृष्णा रवि श्रीनिवास ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

सार्वजनिक नीति और आर्थिक विकासः भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग पर अध्ययन

आरआईएस ने 'सार्वजनिक नीति और आर्थिक विकासः भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग की केस स्टडी' पर वाणिज्य मंत्रालय की ओर से किए जा रहे फार्मास्युटिकल अध्ययन पर 20 जनवरी 2021 को वर्चुअल परिचर्चा का आयोजन किया। विविध पृष्ठभूमि के विशेषज्ञों को इस अध्ययन के निष्कर्षों को साझा करने और इस पर अपने विचार एवं सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया था, ताकि यह अध्ययन नीति निर्माताओं के लिए और भी अधिक उपयोगी साबित हो सके।

प्रमुख विशेषज्ञ ये थेः श्री श्यामल मिश्रा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय; डॉ. एस.जे.एस. फ्लोरा, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (नाइपर); डॉ. ज्ञानेंद्र नाथ सिंह, पूर्व औषधि महानियंत्रक; श्री वी.वी. कृष्णा रेड्डी, अध्यक्ष, बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (बीडीएमए); श्री अशोक कुमार मदान, कार्यकारी निदेशक, इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए); श्री सुदर्शन जैन, महासचिव, इंडियन फार्मास्युटिकल एलायंस (आईपीए); श्री प्रवीण के. मित्तल, वरिष्ठ निदेशक, फिक्की; श्री लंका श्रीनिवास, एलिक्स ग्लोबल; श्री रघु कोचर, उपाध्यक्ष, काउंसिल फॉर हेल्थकेयर एंड फार्मा (सीएचपी); और श्री अरुण साहनी, पूर्व सीईओ, रैनबैक्सी, इत्यादि।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में इतनी विशाल आबादी वाले भारत जैसे देश के लिए दवा उद्योग के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला। आरआईएस के विशिष्ट फेलो श्री राजीव खेर, जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की, ने अपने उद्‌घाटन भाषण में विशेषकर वर्ष 2005 के बाद इस उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न मुद्दों जैसे कि अनुसंधान एवं विकास में निवेश, जैव प्रौद्योगिकी, शैक्षणिक प्रणाली, इत्यादि की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री श्यामल मिश्रा ने दुनिया भर में भारतीय जेनेरिक दवाओं और टीकों के बढ़ते महत्व, मान्यता, एवं विश्वसनीयता को रेखांकित किया और इसके साथ ही आने वाले वर्षों में विशेषकर गुणवत्ता मानकों, नियामकीय सुविधा, इत्यादि के क्षेत्र में निरंतर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए संबंधित चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया। डॉ. दिनेश कुमार, आरआईएस और डॉ. दीपिका चावला, आरआईएस द्वारा एक प्रस्तुति दी गई। इसके बाद इस अध्ययन पर विशेषज्ञों द्वारा व्यापक अवलोकन किए गए जिनके तहत विशेषकर अनुसंधान एवं विकास व्यय के लिए 352 एबी– निगेटिव प्रोत्साहन को हाल ही में वापस लिए जाने और किण्वन–आधारित बल्क ड्रग्स उद्योग, जिसमें अन्य बातों के अलावा पूंजी–गहन और समय–अंतराल भी अत्यंत व्यापक है, द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय बाधाओं पर प्रकाश डाला गया। इस अध्ययन के दायरे को और भी अधिक व्यापक बनाने का भी सुझाव दिया गया, जिसके तहत विशेषकर उन पेटेंट प्राप्त दवाओं की पहचान करने पर जोर दिया गया जिनका पेटेंट जल्द ही समाप्त होने वाला है। निर्यात को और बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों, विशेषकर यूरोपीय देशों के साथ समझौता या पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) करने; दुनिया भर में भारतीय औषधकोश (फार्माकोपिया) की अधिक मान्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने; बायोसिमिलर एवं बायोलॉजिक्स के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक नियामकीय प्रोत्साहन/सुविधा देने; घरेलू दवा उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानकों को उन्नत करके आखिरकार कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप किया जा सकता है, इस बारे में भी अध्ययन करने के सुझाव दिए गए। आरआईएस के प्रोफेसर टी.सी. जेम्स ने समापन भाषण दिया और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण अवलोकन एवं सुझाव प्रदान करने के लिए सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ: एसटीआई

एसडीजी 2 के लिए एसटीआई रोडमैप

आरआईएस ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 27 जनवरी 2021 को 'एसडीजी 2 के लिए एसटीआई रोडमैप तैयार करनाः भारत के लिए प्रौद्योगिकी के अधिशेष और कमी का संकेतक आधारित आकलन' विषय पर प्रथम राष्ट्रीय स्तर की वर्चुअल गोलमेज चर्चा की मेजबानी की। यह कार्यशाला एसडीजी के लिए एसटीआई रोडमैप तैयार करने में भारत की राष्ट्रीय पहल का हिस्सा थी। इस गोलमेज चर्चा में दो सत्र शामिल थे। पहला सत्र पोषण सुरक्षा पर था जिसमें पोषण और सक्षम या संभव खाद्य प्रसंस्करण एवं डिजिटल प्रौद्योगिकियों के मुद्दों को कवर किया गया। दूसरे सत्र में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं निरंतरता के मुद्दों और सतत खाद्य प्रणालियों एवं आईसीटी प्रौद्योगिकियों में उभरने वाले संबंधित नवाचारों को कवर किया गया।

डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान कूटनीति फेलो, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद पीएसए के कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव डॉ. अरबिंद मित्रा ने विशेष भाषण दिया। उद्घाटन भाषण भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के. विजय राघवन ने दिया। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि कृषि में एसटीआई संबंधी ठोस उपाय अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बीसवीं शताब्दी में औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन और वितरण प्रणालियों की परिकल्पना की गई थी जो आज के समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसके अलावा, उन्होंने कुछ ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख किया जिनमें एसटीआई भारत में कृषि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान की पेशकश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उपर्युक्त क्षेत्र ये थेः ए) बिजली एवं पानी तक पहुंच बढ़ाना बी) जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ठोस उपाय करना सी) ऐसे विकेंद्रीकृत स्थानीय समाधानों का पता लगाना जो भौगोलिक संदर्भ के लिए विशिष्ट हों और डी) डेटा की उपलब्धता एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं से कनेक्टिविटी।

'पोषण सुरक्षा की ओर' विषय पर आयोजित पहले सत्र का संचालन पीएसए के कार्यालय में ओएसडी डॉ. आयशा चौधरी ने किया। सत्र की शुरुआत डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस द्वारा दी गई एक प्रस्तुति के साथ हुई जिन्होंने आरआईएस में एसडीजी के लिए एसटीआई रोडमैप विकसित करने के लिए निरंतर जारी कार्य पर प्रकाश डाला। इसके बाद सत्र के विभिन्न वक्ताओं ने प्रस्तुतियां दीं, जो ये थेः सुश्री अदिति दास राउत, संयुक्त सचिव (पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएं), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय; डॉ. सी. वासुदेवप्पा, कुलपति, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम); डॉ. प्रवीण मलिक, पशुपालन आयुक्त, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय; और डॉ. बी. दयाकर राव, प्रधान वैज्ञानिक एवं सीईओ, न्यूट्रीहब, टीबीआई, आईसीएआर–भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान।

इस सत्र में चिन्हित किए गए प्रमुख मुद्दे ये थेः 1) भारतीय आहार प्रणाली, विशेषकर पीडीएस के माध्यम से वितरित भोजन में पोषण की कुल मात्रा (सूक्ष्म पोषक तत्व एवं विटामिन) और उच्च कैलोरी सेवन की कमी, 2) खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखने/बढ़ाने के लिए सहायक बुनियादी ढांचागत सुविधाओं (उदाहरण के लिए कोल्ड स्टोरेज, जैव–सुदृढ़ीकरण जैसी नई खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, इत्यादि) की कमी 3) आपूर्ति श्रृंखलाओं के असंगठित नेटवर्क 4) घटिया मानकों वाली प्रणाली जो निर्यात को सीमित कर देती है, और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में वित्तपोषण की कमी। इस सत्र में सार्वजनिक सेवा वितरण में अमल में लाए गए कई सफल एसटीआई उपायों जैसे कि पोषण एटलस, राष्ट्रीय मानसून मिशन, इत्यादि और बाजरे के प्रसंस्करण से संबंधित अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने पर भी प्रकाश डाला गया।

सतत और सुदृढ़ कृषि' पर आयोजित दूसरे सत्र का संचालन डॉ. कृष्णा रवि श्रीनिवास, सलाहकार, आरआईएस ने किया। इस सत्र में भाग लेने वाले वक्ताओं में ये शामिल थेः सुश्री जोआना केन–पोटाका, एडीजी (बाह्य संबंध), इक्रीसैट; डॉ. श्रीकांत रूपावतरम, वैज्ञानिक, डिजिटल कृषि, इक्रीसैट (एआई और कृषि); श्री रोशन लाल तमक, कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ (चीनी का कारोबार), डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, और डॉ. प्रवीर देशमुख, सलाहकार, सतत विकास के लिए सीआईआई–आईटीसी उत्कृष्टता केंद्र।

इस सत्र में चर्चा वाले प्रमुख मुद्दे ये थेः 1) उभरती प्रौद्योगिकियों का किफायती होना 2) संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करना 3) गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल/मशीनीकरण तक पहुंच 4) प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण 5) घटता या गिरता मृदा स्वास्थ्य और जल संरक्षण 6) 'मुख्य उपज' से विविधीकरण करना। इस सत्र के दौरान इस क्षेत्र में, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जारी कुछ पहलों पर भी प्रकाश डाला गया। इन दोनों ही सत्रों का समापन वक्ताओं के बीच संक्षिप्त चर्चा के साथ हुआ।

एसडीजी 6: भारत के लिए प्रौद्योगिकी के अधिशेष का आकलन

आरआईएस ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 25 मार्च 2021 को 'एसडीजी 6 के लिए एसटीआई रोडमैप तैयार करनाः भारत के लिए प्रौद्योगिकी के अधिशेष और कमी का संकेतक आधारित आकलन' पर परामर्श बैठक की मेजबानी की। इस दौरान चर्चा एसडीजी–6 के अंतर्गत तीन प्रमुख क्षेत्रों यथा पेयजल, जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन, और जल प्रदूषण पर केंद्रित रही। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया, जिसके बाद पीएसए के कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव डॉ. अरबिंद मित्रा ने विशेष भाषण दिया।

उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि एक प्रभावकारी एसटीआई रोडमैप बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग अत्यंत आवश्यक है जिनमें उद्योग, शिक्षाविद, स्टार्ट–अप्स और सरकार शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह की साझेदारियों के प्रयासों में ऐसी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं जो वैश्विक भलाई में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

डॉ. मित्रा के भाषण के बाद हुई परिचर्चा का संचालन डॉ. पी. के. आनंद, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने किया। इसकी शुरुआत डॉ. सब्यसाची साहा, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्तुति देने के साथ हुई, जिन्होंने आरआईएस में एसडीजी के रोडमैप हेतु एसटीआई विकसित करने के लिए निरंतर जारी कार्यों पर प्रकाश डाला। इसके बाद प्रत्येक वक्ता ने प्रस्तुति दी/भाषण दिया। वक्ताओं में ये सभी शामिल थेः डॉ. संजय बाजपेयी, प्रमुख, प्रौद्योगिकी मिशन प्रभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय; डॉ. एम. दीनदयालन, सलाहकार (पीएचईई), केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन, आवास व शहरी कार्य मंत्रालय; डॉ. पवन लाभसेत्वंर, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रमुख, जल प्रौद्योगिकी और प्रबंधन प्रभाग, सीएसआईआर–नीरी; डॉ. डी. ज्ञानसुंदर, निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना; श्री सुनील कुमार, निदेशक (बेसिन योजना–1), केंद्रीय जल आयोग, श्री वी.के. माधवन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाटर एड इंडिया; और श्री के श्री हर्ष, संस्थापक, कृत्सनाम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड।

बैठक में निर्धारित किए गए प्रमुख मुद्दे ये थेः प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए सामाजिक स्वीकार्यता एवं पर्यावरणीय चिंतन–मनन; जल गुणवत्ता के गतिशील स्वरूप को देखते हुए जल संवर्धन/शुद्धिकरण प्रौद्योगिकियों का विकास; उच्च गैर–राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) (30–60ः); जल वितरण नेटवर्क में नई तकनीकों जैसे कि सेंसर, एआई, इत्यादि का उपयोग; एक सामान्य मानक के सापेक्ष प्रौद्योगिकियों के मानदंड तय करना; एक मजबूत एवं सामान्य या आम जल स्रोत सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए जल स्रोतों का मानचित्रण; सतही जल के भंडारण पर फोकस करते हुए जल अवसंरचना का विकास; वर्षा जल के संचयन के लिए सहायक अवसंरचना की कमी; और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में धूसर जल के प्रबंधन की योजना बनाना।

शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार के लिए आदर्श माहौल

34वां स्टिप फोरम व्याख्यान 24 मार्च 2021 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मुख्य नवाचार अधिकारी डॉ. अभय जेरे ने दिया। इस सार्वजनिक व्याख्यान का विषय 'शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार के लिए आदर्श माहौल बनाना' था। इस कार्यक्रम का संचालन विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉ. नकुल पाराशर ने किया। डॉ. किंकिनी दासगुप्ता मिश्रा, वैज्ञानिक–एफ, विज्ञान प्रसार ने स्वागत भाषण दिया।

डॉ अभय जेरे ने अपने अत्यंत सहज संबोधन में भारत में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में एक जीवंत और आदर्श माहौल बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि शैक्षणिक संस्थानों में एक ऐसे व्यवस्थित माहौल या परिवेश का नितांत अभाव है, जो विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है एवं उन्हें और भी अधिक रचनात्मक होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उन्होंने लीक से हटकर सोचने और अभिनव आइडिया विकसित करने एवं उसका अधिकार अपने पास रखने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को या तो अपने अभिनव आइडिया को प्रौद्योगिकी में बदलने का प्रयास करना चाहिए या उन्हें अपने बेहतरीन आइडिया के लिए आईपीआर/पेटेंट प्राप्त करना चाहिए। डॉ. जेरे ने एक ऐसा आदर्श माहौल या परिवेश (इकोसिस्टम) बनाने पर जोर दिया जो विद्यार्थियों या शोधकर्ताओं को अपने अभिनव आइडिया और सृजन के लिए पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित करे। उन्होंने एक वार्षिक 'स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन' आयोजित करने की अपनी स्वयं की पहल के बारे में विस्तार से बताया, जो अब 'दुनिया के सबसे बड़े हैकाथॉन और सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल' के रूप में विकसित हो

गया है। डॉ. जेरे ने भारत में सभी शिक्षण संस्थानों को उनकी नवाचार उपलब्धियों पर उन्हें रैंकिंग देने के लिए अपनी तरह के पहले 'अटल इनोवेशन रैंकिंग फ्रेमवर्क (एआरआईआईए)' को अमल में लाए जाने के बारे में चर्चा की।

उन्होंने यह भी बताया कि 'संकाय एवं विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्ट–अप नीति 2019', जो उनके द्वारा ही स्टार्ट–अप संस्कृति और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई थी, उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को किस तरह से अपने–अपने नवाचार, स्टार्ट–अप और उद्यमों पर आगे काम करने में सक्षम बना रही है। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने डॉ. जेरे द्वारा परिकल्पित 'नवाचार और उद्यमिता' में एक अनूठे एमबीए प्रोग्राम की भी घोषणा की है।

अपने भाषण के आखिर में वक्ता जेरे ने भारत में शैक्षणिक संस्थानों में मौजूदा माहौल या परिवेश (इकोसिस्टम) को व्यापक रूप से सुधारने की अनिवार्यता और देश में 'नवाचार–संस्कृति' को बढ़ावा देने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में भारत–ताइवान सहयोग

आरआईएस और प्रॉस्पेक्ट फाउंडेशन, ताइपे द्वारा 25 फरवरी 2021 को संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में बहु–क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और ताइवान के प्रमुख हितधारक एकजुट हुए। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और डॉ. आई–चुंग लाई, प्रेसिडेंट, प्रॉस्पेक्ट फाउंडेशन द्वारा दिए गए आरंभिक भाषणों में इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों पर फोकस करने के साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत और ताइवान के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने आरआईएस और प्रॉस्पेक्ट फाउंडेशन के बीच साझेदारी को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया, ताकि इन सहयोगों को मूर्त रूप देने के लिए नीतिगत रोडमैप तैयार किए जा सकें और फिर इन्हें नीति निर्माताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके, जिसके लिए वेबिनार आगे की राह हो सकता है। इस कार्यक्रम में ये चार व्यापक विषय कवर किए गए – विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं वैश्विक आर्थिक व्यवस्था; आईसीटी और सेमीकंडक्टर उद्योग; स्मार्ट विनिर्माण एवं उद्योग 4.0, और भारत एवं ताइवान में विज्ञान पार्क– पारस्परिक रूप से सीखने के लिए अनुभव और गुंजाइश।

पहले सत्र में वैश्विक आर्थिक परिवेश से जुड़े प्रमुख रुझान पर फोकस किया गया और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सही स्वरूप देने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का आकलन किया गया। दूसरे सत्र में आईसीटी और सेमीकंडक्टर से जुड़े भारत के नीतिगत दृष्टिकोण के साथ–साथ ताइवान के नीतिगत दृष्टिकोण का भी अवलोकन प्रस्तुत किया गया। तीसरे सत्र में भारत एवं ताइवान में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग व मशीन टूल्स के विकास और आपस में सीखने और सहयोग की गुंजाइश पर फोकस किया गया। चौथे एवं अंतिम सत्र में भारत में विज्ञान पार्कों और विभिन्न क्लस्टरों के विकास पर चर्चा हुई।

भारत की ओर से प्रमुख वक्ता ये थेः डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान कूटनीति फेलो, आरआईएस; प्रोफेसर वी. कामाकोटि, आईआईटी–मद्रास; श्री कल्याण राम, सीईओ, इलेक्ट्रोनो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एवं उप निदेशक, स्वचालन उद्योग संघ; और डॉ. दीपनविता चट्टोपाध्याय, चेयरमैन व सीईओ, आईकेपी नॉलेज पार्क। ताइवान की ओर से मुख्य वक्ता ये थेः डॉ. रॉय ली, वरिष्ठ उप निदेशक, ताइवान डब्ल्यूटीओ एवं आरटीए केंद्र, चुंग–हुआ आर्थिक अनुसंधान संस्थान (सीआईईआर); श्री स्टेनली वांग, उप महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, सूचना उद्योग संस्थान; डॉ. याउ–जूनियर लियू, उपाध्यक्ष, ताइपे समुद्री प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय; और सुश्री विवियन हुआंग, महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, सूचना उद्योग संस्थान।

प्रकाशन कार्यक्रम

रिपोर्ट

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) में भारत–वियतनाम सहयोग को बढ़ावा देने पर रिपोर्टः परिप्रेक्ष्य और संभावनाएं, *आरआईएस, वियतनाम दूतावास, नई दिल्ली, 2021*

विज्ञान कूटनीति पर दक्षिणी परिप्रेक्ष्य, *आरआईएस, नई दिल्ली, 2020*

नीतिगत सार

#96ः सार्वजनिक सामान और एसटीआई नीति, रवि के श्रीनिवास द्वारा

#94ः पहुंच, इक्विटी और समावेशन और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, रवि के श्रीनिवास द्वारा

प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रमः एसटीआई

नई पहलकदमियां

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार

चूंकि हिंद–प्रशांत क्षेत्र के देशों का लक्ष्य उद्योग 4.0 में परिवर्तित होना है, ऐसे में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) इस औद्योगिक परिवर्तन की रीढ़ हैं। औद्योगिक विकास में एसटीआई की भूमिका के अलावा, यह एसडीजी प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारिस्थितिक तंत्र के दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास और स्थानीय नवाचारों को बढ़ावा देना – विश्वविद्यालय और उद्योग के बीच सहक्रियात्मक सहयोग – महत्वपूर्ण होना चाहिए। एसटीआई में सहयोग में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) में सुधार, अनुसंधान एवं विकास व्यय में वृद्धि, वैज्ञानिक संस्थानों के बीच विद्वानों का आदान–प्रदान, और युवा विद्वानों द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन की शुरुआत जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रौद्योगिकी सुविधा तंत्र (टीएफएम) एसटीआई का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए। एसटीआई में क्षेत्रीय सहयोग न केवल हिंद–प्रशांत–उन्मुख मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि इन देशों को व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष रूप से मूल्यवान हो सकता है। इसीप्रकार, एसडीजी के लिए एसटीआई नवाचार, तकनीकी–उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, और एसडीजी पर प्रगति हासिल करने हेतु इस अधिकार क्षेत्र में हिंद–प्रशांत संरचना और सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण बाध्यकारी कारक हो सकता है। एक मजबूत एसटीआई सहयोग हिंद–प्रशांत ढांचे को रेखांकित करते हुए सार्थक रूप से अति महत्वपूर्ण रणनीतिक तर्क का पूरक हो सकता है और भागीदार देशों को सामूहिक सुरक्षा निर्माण की दिशा में प्रगति करने में सक्षम बना सकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की समीक्षा – विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए विशेष रिपोर्ट

माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के पूर्व सचिव डॉ अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों (डीएसटी, डीबीटी, डीएसआईआर/सीएसआईआर और एमओईएस) द्वारा कार्यान्वित अन्य देशों के साथ – विभिन्न समझौतों के माध्यम से और साथ ही साथ, आईयूएसटीएफ, ईएफसीपीएआर और आईजीएसटीसी जैसे उनके संस्थानों द्वारा – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) गतिविधियों की जांच और समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अंततः इन विभागों/मंत्रालयों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभागों को एक प्रश्नावली के माध्यम से पिछले पांच वर्षों में किए गए अपने आईसी पहलों और समझौतों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष ने मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और समिति के समक्ष और बाद में माननीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी समिति के एक सदस्य, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डीजी, आरआईएस को सौंपी थी। विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट और अपने व्यापक विश्लेषण के आधार पर, आरआईएस ने मसौदा रिपोर्ट को पूरा कर लिया है। वर्तमान परिदृश्य, चुनौतियों, अवसरों और आगे की राह के सुसंगत मूल्यांकन पर पहुंचने के लिए इस दस्तावेज़ को आकार देने के आरआईएस द्वारा विशेष प्रयास किए गए थे। एक प्रमुख योगदान प्रभावी रणनीतियों, मजबूत भागीदारी, संधारणीय जुड़ाव के लिए भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रयासों और घरेलू आर्थिक विकास, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता, और सबसे महत्वपूर्ण समावेशी और सतत विकास के लिए भारत के बाहरी संपर्कों का लाभ उठाने के ठोस परिणाम के लिए एक सांकेतिक मूल्यांकन ढांचे की रूपरेखा रेखांकित करने के संदर्भ में रहा है।

यह उम्मीद की जाती है कि रिपोर्ट में व्यक्त की गई सिफारिशों और विचारों की व्यापक प्रासंगिकता होगी और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और इसकी प्रभावशीलता/प्रभाव को बढ़ाने में योगदान देगा।

8 स्वास्थ्य

आरआईएस के स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य और कल्याण के व्यापक पहलुओं को शामिल किया गया है जो वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में सीधे प्रासंगिक हैं और नीति निर्माताओं को आकर्षित करते हैं। कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा वितरण और सहयोग के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसलिए, कार्यक्रम का फोकस औषध नीति, पारंपरिक औषधि, स्वास्थ्य कूटनीति, एसडीजी –3 सभी के लिए स्वास्थ्य और भलाई, एवं कल्याण और भलाई की अवधारणाएं पर है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। टीम नियमित रूप से डोमेन विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सीएसओ और नीति निर्माताओं के साथ परामर्श, सेमिनार / वेबिनार और सम्मेलनों के माध्यम से मिलकर काम करती है। कार्यवाही, प्रमुख निष्कर्ष और महत्वपूर्ण विषयों को नीति संक्षिप्त, रिपोर्ट और चर्चा पत्रों के रूप में प्रकाशित किया जाता है। अनुभाग कुछ विवरण प्रदान करता है।

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर फोरम (FITM)

प्रोफेसर टीसी जेम्स, डॉ नम्रता पाठक और श्री अपूर्व भटनागर)

आयुष मंत्रालय द्वारा आरआईएस में स्थापित FITM का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन (टीएम) के क्षेत्र में व्यावहारिक नीति निर्माण में योगदान करना है। फोरम ने तीन साल का पहला कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और आयुष मंत्रालय, आरआईएस, उद्योग और शिक्षाविदों के प्रतिनिधियों से युक्त एक नए शासी बोर्ड के साथ आयुष मंत्रालय द्वारा इसे एक बार और तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जैसा कि नीचे चर्चा की गई है, इसने कई पहलकदमियां की हैं:

FITM रिसर्च फेलोशिप

फेलोशिप का उद्देश्य युवा विद्वानों को भारतीय पारंपरिक चिकित्सा (आईटीएम) से संबंधित विषयों और क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं पर गहन जांच और शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पूछताछ के परिणामस्वरूप पुस्तकों सहित प्रकाशनों का उद्देश्य आईटीएम के प्रचार पर नीति–संबंधी अनुसंधान इनपुट प्रदान करना है। आईटीएम से संबंधित विभिन्न विषयों पर डोमेन विशेषज्ञों द्वारा आमंत्रित वार्ता भी इस परियोजना का एक हिस्सा है। आरआईएस फेलोशिप के अनुदान और आगे के प्रकाशनों का प्रबंधन करेगा। पंजाब और उत्तराखंड में औषधीय पौधों पर दो शोध अध्ययन पूरे हो चुके हैं।

आयुष एमएसएमई पर अध्ययनः घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विकास में चुनौतियां और संभावनाएं

आयुष क्षेत्र में संख्यात्मक रूप से एमएसएमई (MSME) का दबदबा है। राष्ट्रीय और वैश्विक प्रचार के लिए रणनीतियों के परिणामस्वरूप कड़े मानकों की सदस्यता की आवश्यकता को समझा गया है। नतीजतन, मजबूत नियमों का कार्यान्वयन देखा जा रहा है। कई कारणों से इन मानकों को पूरा करने के प्रयासों में एमएसएमई को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें संचालन और प्रौद्योगिकी के सापेक्ष निम्न स्तर शामिल हैं। मुख्यधारा के बाजारों के साथ एकीकरण की कमी, ब्रांडिंग और उद्यमशीलता की आक्रामकता की कमी इस क्षेत्र से जुड़ी अन्य चुनौतियां हैं। गुणवत्ता वाले कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति भी एक अड़चन है जिसके कारण अक्सर इस क्षेत्र द्वारा मानकों की सदस्यता लेने में असमर्थता होती है। गहन अध्ययन से निर्यात को बढ़ावा देने सहित संधारणीय विकास की रणनीतियों के विकास की दिशा में आयुष एमएसएमई क्षेत्र के प्रभावी क्षमता निर्माण के तंत्र का पता चलेगा।

प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रमः स्वास्थ्य

चुनिंदा अफ्रीकी देशों में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली पर अध्ययनः सहयोग के लिए कानूनी उपकरणों और अवसरों की समीक्षा

तमाम देशों में पारंपरिक चिकित्सा के प्रति नए सिरे से आकर्षण देखा जा रहा है। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल में और गैर–संचारी रोगों के लिए एक पूरक चिकित्सा के रूप में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका का स्वीकरण सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरने के साथ, यह समझना महत्वपूर्ण है कि चुनिंदा देशों और क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग, विनियमन और प्रचार कैसे किया जा रहा है। यह इन बाजारों में आयुष से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ाने की संभावनाओं को समझने में मदद करेगा। शुरुआत के लिए अफ्रीका में प्रासंगिक देशों का अध्ययन करने का प्रस्ताव है। बाद में, पड़ोसी देशों, पश्चिम एशियाई देशों और दक्षिण अमेरिका पर फोकस किया जाएगा।

औषधीय वनस्पतियों की संरचना, विश्लेषण और अनुसंधान अध्ययन डेटा औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945ः अनुसूची टी(ए) के तहत प्रस्तुत किया गया

औषधीय प्लांट क्षेत्र बढ़ते हुए हर्बल उत्पाद उद्योग में प्राथमिक घटक के रूप में उत्तरोत्तर अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप, बढ़ते आपूर्ति अंतर ने वैकल्पिक और स्थायी आपूर्ति मार्गों का आकलन करने की आवश्यकता उत्पन्न की है। अध्ययन के दोहरे उद्देश्य हैं (i) भारत में औषधीय प्लांट क्षेत्र पर एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना और उसे बनाए रखना, और (ii) डेटा के आधार पर अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय औषधीय प्लांट बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

पारंपरिक चिकित्सा समीक्षा

वर्तमान में भारत में पारंपरिक चिकित्सा पर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के अध्ययन के प्रकाशन के लिए कोई समर्पित पत्रिका नहीं है। इसलिए, पारंपरिक चिकित्सा समीक्षा शुरू करने का प्रस्ताव है। यह FITM की एक आवधिक पत्रिका होगी जिसमें पारंपरिक चिकित्सा पर सहकर्मी–समीक्षित लेख और पत्र होंगे।

बिम्सटेक में स्वास्थ्य क्षेत्र का सहयोग

भारत की "लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट" की रणनीति के हिस्से के रूप में, भारत और अन्य बिम्सटेक देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास सहयोग पर एक अध्ययन की योजना है। यह अध्ययन इस बात की भी छानबीन करेगा कि सीमावर्ती जिलों का विकास और पड़ोसी देशों के साथ भारत का सहयोग आपस में कैसे जुड़ सकेंगे। इसके हिस्से के रूप में, 'त्रिपुरा में स्वास्थ्य देखभाल के सार्वजनीकरण की स्थिति का वास्तविक विश्लेषण' तैयार किया गया है और नीति आयोग के साथ साझा किया गया है। भूटान में स्वास्थ्य देखभाल पर एक तथ्यात्मक स्थिति पत्र तैयार किया गया है और उसके आधार पर, नीति प्रबुद्ध मंडल के बिम्सटेक नेटवर्क में, बिम्सटेक में स्वास्थ्य क्षेत्र के वित्त पोषण के तुलनात्मक विश्लेषण पर एक अध्ययन का प्रस्ताव रखा गया, जिसका सबने स्वागत किया। अध्ययन में निम्नलिखित मुद्दों की छानबीन की जाएगीः (iii) स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त सार्वजनिक व्यय उपलब्ध कराने में लोक–नीति की क्या चुनौतियां हैं? (ii) क्या समान वित्तपोषण पैटर्न हो सकते हैं? (iii) 2030 तक यूएचसी की उपलब्धि के लिए लागत प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए क्या नीति और रणनीति हस्तक्षेप किए जा सकते हैं? (iv) स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यप्रणाली क्या हैं जिन्हें देशों के बीच साझा किया जा सकता है? और (v) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंडा, जिसका आरआईएस इस अध्ययन के हिस्से के रूप में पायलट करने का प्रस्ताव करता है, के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के वित्तपोषण में बाहरी सहायता का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है। बिम्सटेक में स्वास्थ्य क्षेत्र के वित्त पोषण के तुलनात्मक विश्लेषण के वित्तपोषण पर एक प्रारंभिक पेपर प्रारूप के चरण में है। 'बिम्सटेक में स्वास्थ्य देखभाल सहयोगः चुनौतियां और संभावनाएं' पर एक अन्य पेपर मसौदा के चरण में है।

"जी –20 ढांचे में प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में तेजी" पर नीति का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया गया है।

भारतीय औषधि उद्योग की सार्वजनिक नीति और आर्थिक विकास विषय अध्ययन पर आगामी अध्ययन

चर्चा का उद्देश्य अतीत में सभी प्रमुख नीतिगत विकास पर चर्चा करना और उनका दस्तावेजों करण करना है, जिन्होंने भारत में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के विकास को प्रभावित किया है यह नीतियों और कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेगा और जहां कहीं भी दोष रेखाएं हैं उन क्षेत्रों की पहचान करेगा। यह विस्तार से व्यापार डाटा की जांच करेगा और उन उत्पादों की पहचान करेगा जहां उद्योग को भविष्य में ध्यान केंद्रित करना होगा। आयुष उद्योग के क्षेत्र में चुनौतियों और संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी।

भारत में नोवल सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री का पुनः निरीक्षण उपलब्धि और भविष्य की चुनौतियां

डॉ प्रशांत कुमार घोष

स्वास्थ्य मुद्दों पर अपने कार्य और कार्यक्रम के हिस्सों के रूप में आर आई एस सक्रिय रूप से फार्मास्युटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन करने में लगा हुआ है इससे पहले आर आई एस ने इस संबंध में कई प्रकाशन निकाले और बड़ी संख्या में हित धारकों के साथ कई नीतिगत संवाद भी आयोजित किए, इस संबंध में डॉ प्रशांत कुमार घोष की रिपोर्ट रिविजिटिंग नोवल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट फ्रोम इंडियाः एचीवमेंट एंड फ्यूचर चैलेंजस प्रकाशित की जाएगी। यह नई दवाओं की खोज से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा भारत में खोजी गई नई रसायनिक संस्थाएं एंड सीआई और एपीआई में विभिन्न अभिनेताओं द्वारा नोवल एपीआई पर किए गए प्रयास और भारत से निर्मित और निर्यात की जाने वाली प्रमुख जेनेरिक दवाओं और भारत सरकार द्वारा ए पी आई पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की पहल का पता लगाना भी शामिल है।

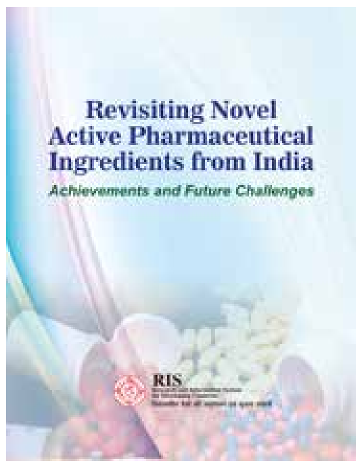

प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रमः स्वास्थ्य

प्रकाशन कार्यक्रम

रिपोर्ट

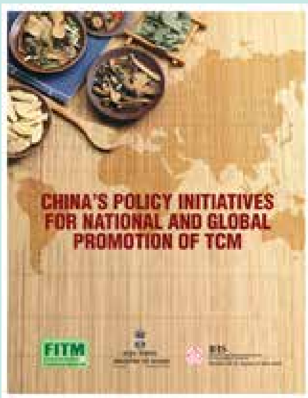

टीसीएम के राष्ट्रीय और वैश्विक संवर्धन के लिए चीन की नीतिगत पहल *आरआईएस, एफआईटीएम, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली, 2021*

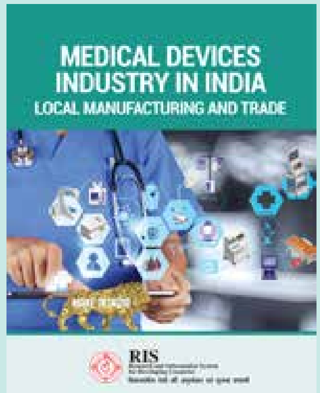

भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग स्थानीय विनिर्माण और व्यापार, *आरआईएस, नई दिल्ली, 2020*

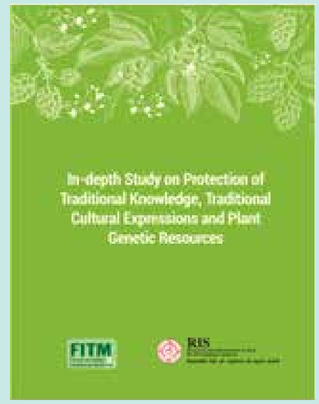

पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और पादप आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण पर गहन अध्ययन, *आरआईएस, एफआईटीएम, नई दिल्ली, 2021*

प्रदान की गई विश्लेषणात्मक सहायता

- विदेश मंत्रालय को 'भारत की स्वास्थ्य देखभाल कूटनीति पहल' पर वार्ता के बिंदु प्रदान किए।
- आईएसएम और हर्बल उत्पादों के व्यापार वर्गीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण के विस्तार के संदर्भ में टास्क फोर्स की रिपोर्ट आयुष मंत्रालय को सौंपी गई।
- 'भारत में कृषि–व्यवसायों और औषधीय पौधों की खेती के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वायबिलिटी गैप फंडिंग) उद्यम पूंजी वित्तपोषण (वेंचर कैपिटल फंडिंग)' पर एक टिप्पणी राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड को प्रस्तुत किया गया।
- आयुष मंत्रालय के लिए "एसएसए के सात चिह्नित देशों के औषध उत्पादों के व्यापार और टैरिफ विश्लेषण" पर भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर फोरम (एफआईटीएम) द्वारा विवरण पत्र तैयार किया गया।
- विदेश मंत्रालय को 'भारत–अफ्रीका संवादः स्वास्थ्य देखभाल में संभावनाएं' पर वार्ता बिंदु प्रदान किए।
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष के लिए 'कोविड–19 महामारी और भारत के विकास और विकल्पों के अन्य अवरोधकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव' पर चर्चा के बिंदु प्रदान किए गए।

प्रकाशन कार्यक्रम

परिचर्चा पत्र

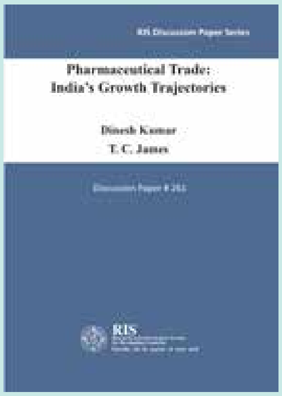

#261: दवाओं का व्यापार: भारत का विकास पथ *द्वारा दिनेश कुमार और टी. सी. जेम्स*

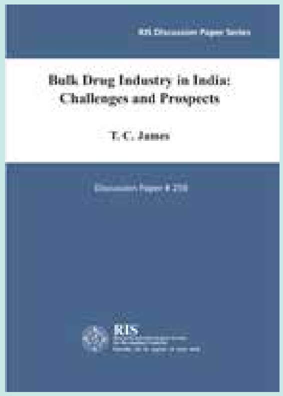

#259: भारत में बल्क ड्रग उद्योग: चुनौतियां और संभावनाएं *द्वारा टी.सी.जेम्स*

#257: तपेदिक और कोविड–19 का पता लगाने के लिए भारत में 'TrueNat' इनोवेशन सिस्टम का विकास एक प्रणाली आधारित परिप्रेक्ष्य, *निधि सिंह और कीर्ति त्यागी द्वारा*

#252: ग्लोबल हेल्थकेयर पार्टनरशिप के लिए केस, *राजीव खेर और अरुण एस. नायर द्वारा*

नीतिगत सार

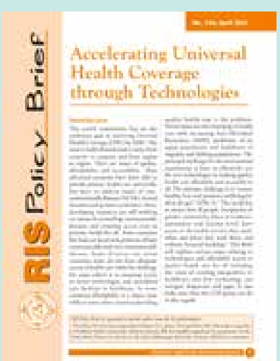

#102: प्रौद्योगिकियों के जरिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में तेजी लाना *टी. सी. जेम्स द्वारा*

#90: कोविड–19 महामारी और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी: सुधार के रास्ते, *जयदीप सी मेनन और डेनी जॉन द्वारा*

एफआईटीएम नीतिगत सार

#7: SDG&3 और कोविड–19 पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाना

#6: आयुष प्रणाली और कोरोना वायरस: वायरल रोगों में अनुसंधान एवं विकास का आकलन

#5: आयुष प्रणाली और कोविड–19 महामारी

9

नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनमी)

पर्यावरण संधारणीयता को ध्यान में रखते हुए उच्च आर्थिक विकास को लक्षित करने के लिए ब्लू इकोनॉमी (बीई) में समुद्र और महासागरों से परे गतिविधियों, हितधारकों और नीतियों को शामिल किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बीई के योगदान के आकलन के लिए कोई आम सहमति का वैश्विक ढांचा नहीं है, इसलिए आरआईएस वर्तमान में भारत और उसके पड़ोसी मुल्कों में बीई के आकलन के लिए एक रूपरेखा विकसित करने पर काम कर रहा है। इसके अलावा, ब्लू ट्रेड यानी नीला व्यापार, जो कि समुद्री व्यापार से अलग है, वैश्विक व्यापार साहित्य में एक नई अवधारणा के रूप में उभर रहा है। आरआईएस ने ब्लू ट्रेड के आकलन के लिए एक ढांचा विकसित किया है। भारत में, ब्लू ट्रेड जीडीपी और देश के समग्र व्यापार की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। बीई के एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में, मात्स्यिकी सब्सिडी को कम करने / समाप्त करने के लिए विश्व व्यापार संगठन में मत्स्य सब्सिडी वार्ता भारत में छोटे और सीमांत मछुआरों और अन्य संसाधन गरीब तटीय देशों के लिए महत्वपूर्ण है। आरआईएस विश्व व्यापार संगठन में मत्स्य सब्सिडी वार्ता के मुद्दे का विश्लेषण कर रहा है। बीई के विभिन्न आयामों पर बहस को बढ़ावा देने के लिए, आरआईएस ने विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों/नीति निर्माताओं की धारणाओं को साझा करने के लिए ब्लू इकोनॉमी फोरम (बीईएफ) के रूप में एक मंच का गठन किया है। बीईएफ के तहत, एक त्रैमासिक समाचार पत्र – *ब्लू इकोनॉमी इनसाइट्स,* आरआईएस द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो ब्लू तकनीकियों, क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि, क्षेत्रीय देशों की बीई गतिविधियों के लिए नियमित रूप से सुविधाएं प्रदान करता है। आरआईएस और आईओआरए सचिवालय के बीच समझौता ज्ञापन के तहत, 'महामारी के बाद हिंद महासागर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगः आगे की राह' पर एक वेबिनार ट्रैक–टू प्रक्रिया के तहत आयोजित किया गया था। विवरण निम्नानुसार हैं।

नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनमी) पर कार्य योजना

ब्लू इकोनॉमी ने विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण विकास प्रतिमान के रूप में लगातार प्रगति की है। उच्च विकास और आर्थिक संधारणीयता के अपने दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई देशों ने इसे अपनी विकास नीति के मुख्य आधार के रूप में अपनाया है। आरआईएस ने 2015 में एक प्रमुख कार्य योजना शुरू की और विशिष्ट क्षेत्रों जैसे समग्र अर्थव्यवस्था में ब्लू इकोनॉमी के योगदान का अनुमान, ब्लू ट्रेड, सेवाओं में समुद्री व्यापार आदि में पद्धतिगत विकास लाने में पर्याप्त योगदान देकर अपनी वैश्विक उपस्थिति दर्ज कराई है। आरआईएस ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे IORA, आसियान, EAS, हिंद–प्रशांत, बिम्सटेक, आदि में विकास संबंधी बहस छेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरआईएस ने भारत में नीति निर्माण प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में राष्ट्रीय नीली अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय समुद्री नीति पर हाल ही में विकसित नीतियों में, आरआईएस ने मसौदा दस्तावेज तैयार करने में पर्याप्त योगदान दिया है। राष्ट्रीय नीली अर्थव्यवस्था नीति पर सात खंडों के दस्तावेजों और राष्ट्रीय समुद्री नीति के आठ खंडों के प्रारूपण में, आरआईएस ने इन दस्तावेजों को तैयार करने में नीति आयोग और पीएम–ईएसी (PM-EAC) के साथ मिलकर काम करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

ब्लू इकोनॉमी पर कार्य योजना में, RIS नियमित रूप से रिपोर्ट, किताबें, न्यूजलेटर, चर्चा पत्र, नीति संक्षेप आदि के रूप में कई प्रकाशन निकाल रहा है। RIS के बाहर अन्य मंचों में भी यह योगदान दे रहा है। विचारों के प्रसार और इस विषय पर बहस शुरू करने के लिए, RIS ने एक मंच विकसित किया है जिसे *ब्लू इकोनॉमी फोरम* के नाम से जाना जाता है। हाल ही में, RIS ने IORA सचिवालय के साथ इस विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया और कई IORA सदस्य राज्यों को इसमें शामिल किया। RIS में ब्लू इकोनॉमी पर एक समर्पित वेबसाइट है, जो संस्थान के विभिन्न प्रकाशनों को प्रस्तुत करती है और हिंद महासागर क्षेत्र में हाल के विकास का ट्रैक भी रख रही है। ब्लू इकोनॉमी के लिए RIS का एक समर्पित ट्विटर हैंडल भी है। हाल ही में, RIS ने इस विषय पर *ब्लू इकोनॉमी इनसाइट्स* के नाम से एक त्रैमासिक न्यूज़लेटर निकालना भी शुरू किया है। AIC नियमित रूप से आसियान और EAS के साथ ब्लू इकोनॉमी सम्मेलन आयोजित कर रहा है।

ब्लू इकोनॉमी इनसाइट

एस के मोहंती, प्रियदर्शी दाश, पंखुड़ी गौर, चांदनी धवानी और सुनंदा महाजन

RIS ने शैक्षणिक और नीति समन्वय में क्षेत्र के साथ प्रभावी जुड़ाव के लिए IORA सचिवालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नीली अर्थव्यवस्था IORA का फोकस क्षेत्र रहा है और RIS का एक प्रमुख कार्य स्तंभ भी है। ब्लू इकोनॉमी के विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए, RIS का एक खुला संवाद मंच है जिसे 'ब्लू इकोनॉमी फोरम (BEF)' के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से IORA क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी के बारे में अनुसंधान इनपुट और गहरी समझ के प्रसार के लिए, RIS एक आवधिक न्यूजलेटर भी निकाल रहा है, जिसे *'ब्लू इकोनॉमी इनसाइट्स'* के नाम से जाना जाता है। न्यूजलेटर RIS का एक त्रैमासिक प्रकाशन है और इसे आंतरिक शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। न्यूजलेटर में कई विशेषताएं हैं जो नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और व्यवसाय करने वालों के लिए आकर्षक होती जा रही हैं। नियमित आधार पर, न्यूजलेटर में ब्लू तकनीक पर, जो IORA क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है, एक फीचर लेख शामिल होता है। प्रत्येक अंक में, IORA सदस्य देश की ब्लू इकोनॉमी पर RIS इन–हाउस शोध और अर्थव्यवस्था पर मौजूदा साहित्य के आधार पर चर्चा की जाती है। IORA क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी के किसी एक क्षेत्र पर रिपोर्टिंग न्यूजलेटर की एक और विशेषता है। इन मुद्दों के अलावा, इसमें अन्य विशेषताएं शामिल हैं जैसे कि पुस्तक समीक्षा, ब्लू इकोनॉमी पर क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास, ब्लू इकोनॉमी पर क्षेत्रीय विशेषज्ञों के दृष्टिकोण, आदि। RIS न्यूजलेटर के दो अंक निकाल भी चुका है और तीसरा अंक प्रक्रिया में है।

IORA में नीली अर्थव्यवस्था के आकलन का क्षेत्रीय ढांचा

एस के मोहंती और पंखुड़ी गौर

2019 में IORA $8.7 ट्रिलियन जीडीपी के साथ एक गतिशील अर्थव्यवस्था है, जो उछाल के दौरान 6.7 प्रतिशत और मंदी के दौरान 3.1 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। ब्लू इकोनॉमी पर पिछले दो मंत्रिस्तरीय और एक शिखर बैठक में, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं ने वैकल्पिक विकास प्रतिमान के रूप में बीई (BE) की प्रभावकारिता के बारे में अपने विश्वास को दोहराया है जो इस क्षेत्र को उच्च विकास पथ पर ले जा सकता है, हालांकि क्षेत्रीय देश अपने समुद्री संसाधन निधि में भिन्न हैं। कुछ सदस्य देशों ने पहले ही अपने सकल घरेलू उत्पाद में BE के योगदान का अनुमान लगा लिया है, और अन्य ने अभी तक अनुमान की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। यहां तक कि कुछ सदस्य देशों ने भी BE के ढांचे के आधार पर अपनी विकास रणनीति की योजना बनाई है। लेकिन, आम सहमती के ढांचे का उपयोग करके IORA क्षेत्र के BE जीडीपी का व्यापक रूप से अनुमान लगाने का अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस संबंध में, क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने हेतु BE में उत्पादन, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग की योजना बनाने के लिए IORA और इसके क्षेत्रों के लिए BE का एक व्यापक अनुमान क्षेत्र के लिए एक नमूना प्रस्तुत कर सकता है। ब्लू इकोनॉमी विशिष्ट क्षेत्रों में ज्यादातर प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होती है। क्षेत्र के सदस्य देश और संवाद भागीदार न केवल तटीय अर्थव्यवस्थाओं के समूह में शामिल हैं, ब्लू प्रौद्योगिकियों की किस्मों से भी संपन्न हैं। इस क्षेत्र में ब्लू प्रौद्योगिकियों की एक व्यापक योजना दुनिया में अत्याधुनिक ब्लू प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एक केंद्रीय स्थल बनाने के विचार को मजबूती दे सकती है। इस क्षेत्र ने ब्लू हाई–टेक एसएमई (SME) के लिए आधार बनाने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं। यूरोप के संवाद भागीदार पहले भी इस तरह के उपक्रमों के साथ प्रयोग कर चुके हैं। IORA में BE का अनुमान विभिन्न क्षेत्रकों में सहयोग के लिए क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार खोलेगा।

क्या ब्लू ट्रेड एक अर्थव्यवस्था में विकास को गति दे सकता है?: भारत के लिए एक खोजपूर्ण अध्ययन

एस के मोहंती

ब्लू इकोनॉमी साहित्य में ब्लू ट्रेड एक उभरती हुई अवधारणा है और यह समुद्री व्यापार से काफी अलग है। ब्लू ट्रेड उन इनपुट से सन्निहित वस्तुओं और सेवाओं में हो सकता है जो या तो समुद्र में आ रही हैं या जा रही हैं। ब्लू ट्रेड में वस्तुओं का व्यापार और सेवाओं का व्यापार शामिल है। इसमें बढ़ने की उच्च क्षमता है और यह बाहरी झटके झेलने की क्षमता रखता है। एक सामान्य स्थिति में, बीई एक तटवर्ती देश की समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ता है, लेकिन ब्लू ट्रेड समग्र व्यापार और बीई की तुलना में और भी तेजी से बढ़ता है। बीई का योगदान गतिविधियों पर आधारित है जो ब्लू औद्योगिक वर्गीकरण से प्राप्त होता है, लेकिन ब्लू ट्रेड उत्पाद स्तर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ब्लू औद्योगिक क्षेत्र के और अधिक पृथक्करण से प्राप्त होता है। अब तक का वैश्विक प्रयोग नीले उद्योगों से गतिविधियों के वर्गीकरण के लिए किया गया है और ब्लू ट्रेड के लिए नई डेटा श्रृंखला उत्पन्न करने के लिए इसे उत्पाद स्तर तक आगे विच्छेदित किया जा सकता है। अध्ययन दुनिया और भारत में ब्लू ट्रेड का विश्लेषण करेगा, जो हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) पर आधारित है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन और व्यापार में नई संभावनाएं या शोध के लिए रास्ते खोल सकता है। भारत जैसे देश जो हमेशा से व्यापार घाटे की अर्थव्यवस्था रहे हैं, ब्लू ट्रेड से अपनी समग्र व्यापार असंतुलन की स्थिति को कम करने के लिए कुशन प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि ब्लू ट्रेड में उच्च विकास और लचीलापन प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, यह भारत को वर्तमान गतिरोध से बाहर निकलने में आराम दे सकता है जो देश में लंबे समय तक मंदी और महामारी के प्रसार के कारण व्याप्त है।

मत्स्योद्योग सब्सिडी और एस एंड डीटी मुद्दे: संसाधन गरीब मछुआरों को संरक्षण की प्रकृति

एस के मोहंती, पंखुरी गौर और चांदनी धवानी

मत्स्योद्योग सब्सिडी पर बातचीत के पिछले दो दशकों के दौरान, विकासशील देशों की मुख्य चिंता विकासशील देशों में छोटे और संसाधन–गरीब मछुआरों को सुरक्षा देने के लिए एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजना है। विश्व व्यापार संगठन वार्ता में प्रमुख धारणा संसाधन–गरीब मछुआरों के पक्ष में रही है। 11 मई और 30 जून को हाल ही में जारी मसौदा मत्स्योद्योग सब्सिडी 'ड्राफ्ट टेक्स्ट' में; और 15–16 जुलाई, 2021 को व्यापार मंत्रियों की बैठक में, विकासशील देशों में छोटे किसानों के लिए मत्स्योद्योग सब्सिडी के मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं दिखी। हालांकि मत्स्योद्योग सब्सिडी का मुद्दा एलडीसी और एसआईडीएस, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एसआईडीएस अर्थव्यवस्थाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। विकासशील देशों में संसाधन–गरीब छोटे मछुआरों के लिए दोनों ही विषय वस्तु में विशेष और विभेदक उपचार (एस एंड डीटी) प्रावधान अनुच्छेद 3.8, अनुच्छेद 4.4 और अनुच्छेद 5.5 में बताए गए हैं, लेकिन मसौदा समझौते में इन देशों की अपेक्षाओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं किया गया है। इसके विपरीत, संसाधन संपन्न मछुआरों के लिए एस एंड डीटी का उलट अनुच्छेद 4.3 और अनुच्छेद 5.1.1 में प्रस्तुत किया गया है। संसाधन संपन्न देशों द्वारा मत्स्योद्योग सब्सिडी जारी रखने के तर्क पाठ में अच्छी तरह से व्यक्त किए गए हैं, लेकिन मसौदा पत्र में चयनित संकेतकों के एक सेट के माध्यम से अनुपालन तंत्र मजबूत नहीं है। इसके अलावा, वर्तमान वार्ता में मत्स्योद्योग सब्सिडी पर एसडीजी की रेखांकित भावना की अनदेखी की गई। विकासशील देशों में संसाधन–गरीब मछुआरों के साथ असमान व्यवहार के कारण एमसी12 में मात्स्यिकी सब्सिडी वार्ता के विफल होने का जोखिम है। अध्ययन का उद्देश्य 'मसौदा पत्र' में लेखों की आलोचनात्मक परीक्षा पर ध्यान देना और बातचीत के उन बिंदुओं को भी उजागर करना है जो विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

महामारी के बाद हिंद महासागर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग

आईओआरए एक बहुत बड़ा गतिशील आर्थिक समूह है। इसमें इस क्षेत्र में विकसित होने की असीम संभावनाएं हैं और यह आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, जहां के वृहद बुनियादी आर्थिक तत्व विकास, महंगाई और अन्य वृहद मापदंडों की दृष्टि से अत्यंत मजबूत हैं। आईओआरए की नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) कार्यक्रम के लिए भी अत्यंत मजबूत प्रतिबद्धता है। यही नहीं, नीली अर्थव्यवस्था प्रक्रिया के साथ इसके मजबूत जुड़ाव की बदौलत इस क्षेत्र से एक मजबूत 'ब्लू वॉयस' निकल रही है जो इस क्षेत्र में नए विकास प्रतिमान की प्रासंगिकता को दर्शाती है।

इस क्षेत्र के कई देश जैसे कि मलेशिया, मॉरीशस, सेशेल्स, इत्यादि अपने यहां नीली अर्थव्यवस्था नीतियों को लागू करते हुए विश्व अर्थव्यवस्था के लिए रोल मॉडल बनते जा रहे हैं।

इन सभी तथ्यों के मद्देनजर आरआईएस ने आईओआरए सचिवालय के सहयोग से 25 नवंबर 2020 को 'महामारी के बाद हिंद महासागर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगः आगे की राह' विषय पर एकदिवसीय वेबिनार आयोजित किया। माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने उद्‌घाटन भाषण दिया। उन्होंने इसके सदस्य देशों के बीच और इस क्षेत्र के अन्य समूहों के साथ सहयोग बढ़ाकर आईओआरए को सुदृढ़ करने की भारतीय प्रतिबद्धता पर विशेष जोर दिया, ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। वर्ष 2011 में आईओआरए की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती भू–रणनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसमें नई जान फूंकने और इसे सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत सक्रियतापूर्वक काम किया था। पिछले कुछ वर्षों में हम नियमित बैठकें कर, नई संरचनाओं का निर्माण करके, सचिवालय की दक्षता बढ़ाकर, संवाद साझेदारों के साथ अधिक–से–अधिक सहयोग बढ़ाकर, और आईओआरए के विभिन्न प्राथमिकता वाले एवं परस्पर संबंधित क्षेत्रों में ठोस पहल करके आईओआरए को मजबूत करने के मार्ग पर और आगे बढ़ गए हैं। वैसे तो सहयोग के कई क्षेत्र हैं, लेकिन मंत्री ने इस क्षेत्र में पर्यटन में नए प्राण डालने के लिए एक अहम कदम के रूप में पर्यटन उद्योग में सुधार या बेहतरी बहाल करने और आयुर्वेद एवं वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारत को आईओआरए के भीतर ब्लू इकोनॉमी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अधिक–से–अधिक काम किए जाने में भी काफी लाभ नजर आ रहा है। प्रदूषण, विशेषकर प्लास्टिक कचरे एवं तेल रिसाव के खतरे और अवैध, गुप्त और अनियंत्रित ढंग से मछली पकड़ने जैसे संसाधनों के अनियंत्रित दोहन से रचनात्मक समाधानों और लोगों की भागीदारी के जरिए निपटने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने न केवल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, बल्कि एक विविध एवं सुदृढ़ हिंद–प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारी क्षेत्रीय संरचना को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस के लिए भी हमारी आपस में जुड़ी दुनिया में कोविड–19 महामारी से निपटने में बहुपक्षवाद की केंद्रीयता को रेखांकित किया। उन्होंने *'ब्लू इकोनॉमी इनसाइट'* पत्रिका का विमोचन भी किया। माननीया डॉ. नोमव्यूमयो नोकवे, महासचिव, आईओआरए सचिवालय ने विशेष भाषण दिया। राजदूत अनिल सुकलाल, उप महानिदेशक, दक्षिण अफ्रीका; राजदूत खुर्शीद आलम, सचिव, समुद्री मामले, बांग्लादेश, और सुश्री रीनात संधू, अपर सचिव (आईपी, दक्षिण और ओशिनिया), विदेश मंत्रालय और विभिन्न

माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन उद्‌घाटन भाषण देते हुए।

आईओआरए देशों के 13 तकनीकी विशेषज्ञों ने इस वेबिनार में भाग लिया। आरआईएस की ओर से प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक; और प्रोफेसर एस. के. मोहंती ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

माननीया डॉ. नोकवे ने आईओआरए सचिवालय द्वारा पिछले पांच वर्षों में नीली अर्थव्यवस्था को दिए गए विशेष महत्व को रेखांकित किया जिसमें मॉरीशस, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में नीली अर्थव्यवस्था पर आयोजित की गई उच्च स्तर की तीन मंत्रिस्तरीय बैठकें भी शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में स्थिरता की हिफाजत करते हुए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान महासागरों एवं समुद्री संसाधनों का दोहन करने, आर्थिक विकास की गति तेज करने, रोजगार सृजन और नवाचार के लिए की गई है। इसके साथ ही पहली बैठक में जकार्ता समझौते को अपनाया गया, जिसमें समावेशी आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और शिक्षा के एक प्रमुख स्रोत के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए आईओआरए की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। इसके अलावा, उन्होंने नीली अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में प्लास्टिक से जुड़े प्रदूषण, एसडीजी और अन्य क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया। मानव एवं वित्तीय संसाधनों दोनों ही के लिए आईओआरए के सदस्य

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ: नीली अर्थव्यवस्था

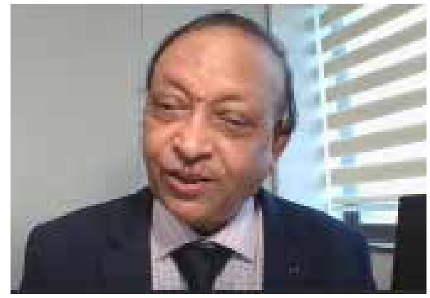

देशों के बीच और संवाद साझेदारों के मध्य सहयोग बढ़ाना सर्वाधिक आवश्यक है, ताकि कोविड–19 से उत्पंन्न चुनौतियों से कारगर ढंग से निपटा जा सके। मानव और वित्तीय दोनों ही संसाधन इस दिशा में अनुकूलन के साथ–साथ इसमें कमी सुनिश्चित करने की चुनौतियों का सामना करने और तूफान से सुरक्षित ढंग से निकल जाने के लिए आवश्यक हैं।

सुश्री संधू ने सरकार द्वारा आईओआरए के लिए हाल ही में की गई कुछ पहलों पर प्रकाश डाला। विशेषकर वर्ष 2011 में भारत की अध्यक्षता के दौरान व्यापक पुनरुद्धार के साथ–साथ आईओआरए की प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने को ही सर्वाधिक अहमियत दी गई। वर्ष 2011 में मंत्रिपरिषद की 11वीं बैठक में एक भारतीय प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता वाले छह क्षेत्रों की पहचान की गई थी, ताकि आने वाले वर्षों में आईओआरए के सदस्य देशों के बीच सहयोग पर फोकस किया जा सके। आपदा जोखिम का प्रबंधन, और अकादमिक, विज्ञान

Blue Economy Insight

DEEP-SEA MINING TECHNOLOGY FOR EXPLORATION DEVELOPED BY INDIA

एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग जैसे आईओआरए के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अग्रणी देश के रूप में भारत ने आईओआरए के सदस्य देशों की क्षमताओं को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर ठोस काम किया है। भारत ने आईओआरए विशेष कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, आईओआरए सचिवालय को मजबूत करने के लिए इस वर्ष सितंबर में भारत की ओर से एक आईटी विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति की है, संवाद साझेदारों के साथ आईओआरए के जुड़ाव को सही स्वरूप देने, आईओआरए की संस्थागत रूपरेखाओं को मजबूत करने, अन्य क्षेत्रीय संगठनों के साथ आईओआरए के जुड़ाव को बढ़ावा देने, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग करने, सूचना समेकन केंद्र 'आईएफसी–आईओआर' के साथ समुद्री जानकारियां साझा करने, और आखिर में आईओआरए क्षेत्र के लिए एचएडीआर दिशा–निर्देशों को तैयार करने में अगुवाई की है।

दो तकनीकी सत्रों में उपस्थित पैनलिस्टों ने आईओआरए क्षेत्रीय सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए विभिन्न मुद्दों और प्राथमिकताओं पर चर्चाएं कीं। विचार–विमर्श के दौरान समुद्री सुरक्षा, मत्स्य पालन, नीली अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय महासागर ऊर्जा, समुद्री प्रौद्योगिकियों, ऐतिहासिक और समुद्री जुड़ाव, इत्यादि को व्यापक रूप से कवर किया गया। इस तरह के सत्रों में विचार–विमर्श के दौरान विभिन्न सिफारिशें उभर कर सामने आती हैं, ताकि आगे की कार्रवाई करने के साथ–साथ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रमः नीली अर्थव्यवस्था

प्रकाशन कार्यक्रम

आईओआरए प्रकाशन

Blue Economy Insight

March 2021

Country/Region: Maldives
Blue Economy of Maldives
Page 2

Sectoral Issue: Blue Services
Blue Services in Indian Ocean Rim Association (IORA)
Page 4

From Editor's Desk

OCEAN THERMAL ENERGY CONVERSION

Viewpoint:
Draft Blue Economy Policy of India
Page 5

Book Reviews:
Global Challenges in Maritime Security
Page 6

Blue Economy News:
Shipping Ministry to develop product specific warehouses near ports to ease logistics
Page 7

ब्लू इकोनॉमी इनसाइट, मार्च, 2020

Blue Economy Insight

November 2020

Country/Region: India
Blue Economy: Ocean Resources for Inclusive Development in India
Page 2

Sectoral Issue: Blue Trade
Blue Trade: A High Potential with Least Understood Sector
Page 4

From Editor's Desk

DEEP-SEA MINING TECHNOLOGY FOR EXPLORATION DEVELOPED BY INDIA

Viewpoint:
Blue Economy: A Promising Idea for the World
Page 5

Book Reviews:
Blue Economy of India: Emerging Trends
Page 6

Blue Economy News:
Govt to form committee for development of minor ports
Page 7

ब्लू इकोनॉमी इनसाइट, नवंबर, 2020

प्रदान की गई विश्लेषणात्मक सहायता

- 'समुद्री और नीली अर्थव्यवस्था अनुसंधान केंद्र' पर एक परिकल्पना प्रपत्र (विजन पेपर) तैयार किया गया और आईएमयू को प्रस्तुत किया गया।

10

ऊर्जा

दक्षिण एशिया ग्रुप ऑन एनर्जी (एसएजीई) भारत और उसके पड़ोसियों के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आरआईएस द्वारा शुरू की गई एक अनूठी पहल है। प्रख्यात विशेषज्ञों, व्यवसायियों और उद्योग प्रतिनिधियों के नेतृत्व में, यह समूह नीतिगत रास्ते तलाश रहा है और भारत के पड़ोस के बीच बिजली के अंतर्संबंधों के निर्माण के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर रहा है। क्षेत्रीय बिजली व्यापार के पारस्परिक लाभ को स्वीकार करते हुए, एसएजीई क्षेत्रीय सहयोग नेटवर्क भी बना रहा है और एक क्षेत्र–व्यापी बिजली व्यापार नेटवर्क बनाने के लिए प्रमुख हितधारकों के बीच संवाद को सुगम बना रहा है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों के दोहन और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में क्षेत्रीय सहयोग और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नेटवर्क महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित अनुभाग अतिरिक्त विवरणों पर प्रकाश डालता है।

ऊर्जा पर दक्षिण एशिया समूह

2020 में RIS में गठित दक्षिण एशिया ग्रुप ऑन एनर्जी को आपसी समझ और सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना के संतुलित और इष्टतम विकास को प्राप्त करने की दिशा में काम करना अनिवार्य है। 10 मार्च, 2021 को भारत के विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटन किए गए इस समूह ने म्यांमार में बिजली की मांग और आपूर्ति में चिंताजनक बेमेल और द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक महत्व को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर म्यांमार के साथ बिजली व्यापार का मुद्दा उठाया। 24 मार्च को आयोजित अपनी पहली बैठक में, पावर ग्रिड के सीएमडी श्री के श्रीकांत और अदानी पावर के एमडी और सीईओ श्री अनिल सरदाना के नेतृत्व में एक छोटे उप–समूह ने म्यांमार के साथ बिजली सहयोग के विषय पर विस्तार से चर्चा की।

टीम ने एक बहुत विस्तृत लेख तैयार किया है जो विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। 8 मई, 2021 को आयोजित सेज की दूसरी बैठक में, समूह के सदस्यों ने दृष्टिकोण पत्र के मसौदे पर विस्तृत विचार–विमर्श किया और उपस्थित सदस्यों ने भारत और म्यांमार के बीच उच्च–वोल्टेज पावर अंतःसंयोजन स्थापित करने के कुछ विकल्पों का आगे मूल्यांकन करने के कई सुझाव दिए। इस बैठक में, क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक देश पर ध्यान देने और संबंधित दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिए पांच – बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका, प्रत्येक पर एक–एक – उप समूह गठित करने का भी सामान्य निर्णय लिया गया।

म्यांमार के लिए उप समूह ने सेज की बैठक में हुई चर्चा के आधार पर दृष्टिकोण रिपोर्ट को संशोधित किया है। इस समूह ने आगे के तरीके सहित आवश्यक विवरण के साथ दृष्टिकोण पत्र को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है, और रिपोर्ट को विदेश मंत्रालय के बीएम डिवीजन को प्रस्तुत किया गया है। यह आशा की जाती है कि रिपोर्ट से उपयुक्त प्राधिकारियों के स्तर पर निर्णय लेने में सुविधा होगी, जिसके बाद कार्यान्वयन होगा। समूह वर्तमान में अन्य देशों – बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका – के लिए दृष्टिकोण पत्रों को पूरा करने के उन्नत चरण में है।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ: ऊर्जा

श्री हर्षवर्धन श्रृंगला प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

ऊर्जा पर दक्षिण एशिया समूह का गठन

सेज के सदस्यों की नीतिगत सिफारिशें इस क्षेत्र के नियामकीय ढांचों और दिशा–निर्देशों में अंतर को समाप्त करने में 'गेम–चेंजर' साबित हो सकती हैं।

-श्री हर्षवर्धन श्रृंगला
विदेश सचिव
भारत सरकार

दक्षिण एशिया को विद्युत पारेषण की लागत में कमी करने, खरीदारों एवं विक्रेताओं को एक साथ लाकर बिजली व्यापार की क्षमता का दोहन करने, नियामकीय ढांचे में सामंजस्य स्थापित करने, और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 'एकीकृत ग्रिड' की नितांत आवश्यकता है। यह बात भारत के विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने 10 मार्च 2021 को आरआईएस में 'ऊर्जा पर दक्षिण एशिया समूह (सेज)' का गठन करते हुए कही।

श्री श्रृंगला ने अपने संबोधन में भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला, जिनमें बांग्लादेश, भूटान एवं नेपाल जैसे देशों के साथ गैस पाइपलाइन और सीमा–पार अंतर्संबंध शामिल हैं।

क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्री श्रृंगला ने क्षेत्रीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने, और क्षेत्रीय विद्युत अवसंरचना के विकास में निवेश आकर्षित करने की आवश्यकता की पहचान की। उन्होंने विशेषकर स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों में सहभागिता बढ़ाने और संभावनाओं की पहचान करने का आह्वान किया जो इस क्षेत्र को सामूहिक रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सक्षम बनाएगा।

उन्होंने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि सेज के सदस्यों की नीतिगत सिफारिशें इस क्षेत्र के नियामकीय ढांचों और दिशा–निर्देशों में अंतर को समाप्त करने में 'गेम–चेंजर' साबित हो सकती हैं।

'सेज' के लिए महत्वपूर्ण विचारार्थ विषयों में विद्युत पारेषण कनेक्टिविटी में मौजूद ढांचागत बाधाओं की पहचान करना और इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक उपयुक्त रणनीति सुझाना शामिल हैं। यह पैनल ऊर्जा व्यापार एवं निवेश में संभावनाओं की पहचान भी करेगा और इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में इस सेक्टर से जुड़ी नियामकीय नीतियों में अंतर को समाप्त करने के उपाय सुझाएगा।

इसके अलावा, यह पैनल विद्युत क्षेत्र में बिजली के उत्पादन और पारेषण दोनों में ही प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रीय समाधानों की पहचान करेगा, और क्षेत्रीय परियोजना के वित्तपोषण संबंधी विकल्पों के साथ–साथ इस पहल के लिए धनराशि के स्रोत के बारे में सुझाव देगा। इसके अलावा, यह पैनल परियोजना कार्यान्वयन की योजना बनाने एवं निगरानी के लिए एक संस्थागत ढांचा सुझाएगा और इसके साथ ही क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों के बारे में प्रस्ताव रखेगा।

वर्तमान में इस क्षेत्र के चार देशों यथा भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच लगभग 3,000 मेगावाट बिजली का व्यापार किया जा रहा है। भारत भूटान से जलविद्युत प्राप्त करता है और इसके साथ ही बांग्लादेश एवं नेपाल को ताप विद्युत और जलविद्युत दोनों की आपूर्ति भी करता है। अन्य देशों के साथ–साथ भूटान पिछले दो दशकों में भारत को जलविद्युत के एक महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत को अधिशेष जलविद्युत (लगभग 1400 मेगावाट) बेचना भूटान के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। बिजली व्यापार के माध्यम से अर्जित राजस्व का इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 25 प्रतिशत योगदान है और इसने इसे सीमेंट एवं स्टील जैसे पूंजी–गहन क्षेत्रों में निवेश करने में सक्षम बनाया है। इसके फलस्वरूप सीमा पार ऊर्जा व्यापार को सभी क्षेत्रीय खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद माना जाता है जो बिजली तक समग्र पहुंच को बेहतर कर सकता है, ऊर्जा उत्पादन संसाधनों का अनुकूलन कर सकता है, और आर्थिक उन्नति एवं विकास की गति को तेज कर सकता है।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपने संबोधन में कहा, 'ऊर्जा इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हमें क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में बाह्य आर्थिक जुड़ाव सुनिश्चित करने की नितांत आवश्यकता है।' विस्तृत कार्यक्रम आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ऊर्जा इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हमें क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में बाह्य आर्थिक जुड़ाव सुनिश्चित करने की नितांत आवश्यकता है।

-प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक, आरआईएस

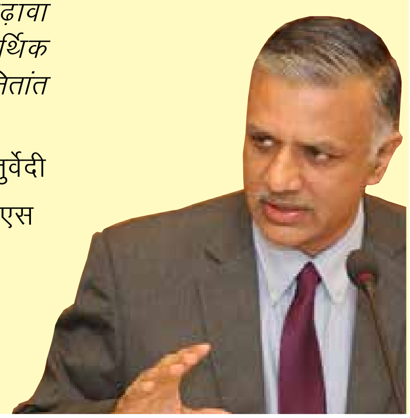

प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम: ऊर्जा

प्रकाशन कार्यक्रम

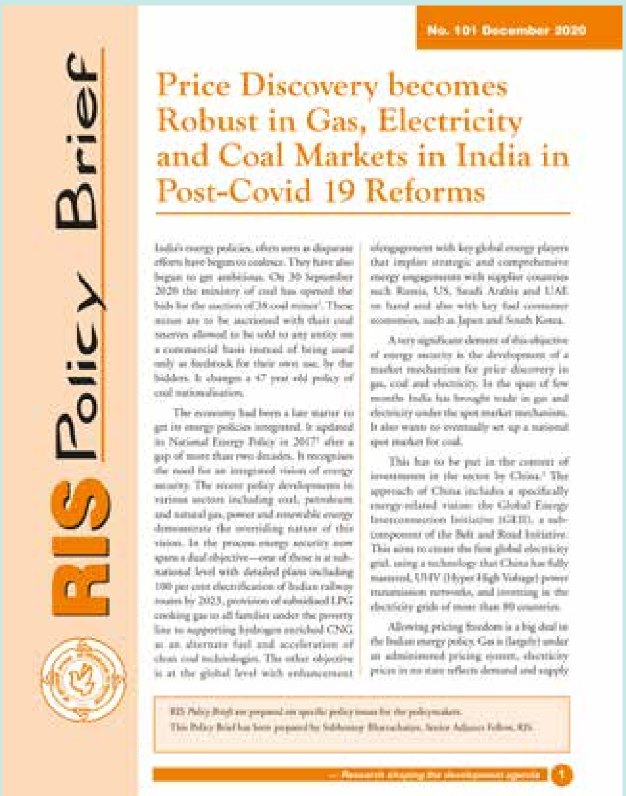
No. 101 December 2020

RIS Policy Brief

Price Discovery becomes Robust in Gas, Electricity and Coal Markets in India in Post-Covid 19 Reforms

India's energy policies, often seen as disparate efforts have begun to coalesce. They have also begun to get ambitious. On 30 September 2020 the ministry of coal has opened the bids for the auction of 38 coal mines[1]. These mines are to be auctioned with their coal reserves allowed to be sold to any entity on a commercial basis instead of being used only as feedstock for their own use by the bidders. It changes a 47 year old policy of coal nationalisation.

The economy had been a late starter to get its energy policies integrated. It updated its National Energy Policy in 2017[2] after a gap of more than two decades. It recognises the need for an integrated vision of energy security. The recent policy developments in various sectors including coal, petroleum and natural gas, power and renewable energy demonstrate the overriding nature of this vision. In the process energy security now spans a dual objective—one of these is at sub-national level with detailed plans including 100 per cent electrification of Indian railway routes by 2023, provision of subsidised LPG cooking gas to all families under the poverty line to supporting hydrogen enriched CNG as an alternate fuel and acceleration of clean coal technologies. The other objective is at the global level with enhancement of engagement with key global energy players that implies strategic and comprehensive energy engagements with supplier countries such Russia, US, Saudi Arabia and UAE on hand and also with key fuel consumer economies, such as Japan and South Korea.

A very significant element of this objective of energy security is the development of a market mechanism for price discovery in gas, coal and electricity. In the span of few months India has brought trade in gas and electricity under the spot market mechanism. It also wants to eventually set up a national spot market for coal.

This has to be put in the context of investments in the sector by China.[3] The approach of China includes a specifically energy-related vision: the Global Energy Interconnection Initiative (GEII), a sub-component of the Belt and Road Initiative. This aims to create the first global electricity grid, using a technology that China has fully mastered, UHV (Hyper High Voltage) power transmission networks, and investing in the electricity grids of more than 80 countries.

Allowing pricing freedom is a big deal in the Indian energy policy. Gas is (largely) under an administered pricing system, electricity prices in no state reflects demand and supply

RIS Policy Briefs are prepared on specific policy issues for the policymakers.
This Policy Brief has been prepared by Subhomoy Bhattacharjee, Senior Adjunct Fellow, RIS.

— Research shaping the development agenda 1

नीतिगत सार

#101 कोविड काल के बाद के सुधारों से भारत में गैस, बिजली और कोयला बाजारों में मूल्य रिकवरी मजबूत हो गई है
द्वारा सुभोमय भट्टाचार्जी

प्रदान की गई विश्लेषणात्मक सहायता

- विदेश मंत्रालय को ऊर्जा संरक्षण पर नोट उपलब्ध कराए गए।

11
वैश्विक विकास केंद्र (जीडीसी)

RIS ने भारतीय विकास के अनुभव को दूसरे देशों तक ले जाने के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर (GDC) आरंभ किया है। यह भारत के स्वदेशी रूप से विकसित विकास सहयोग मानदंडों के माध्यम से भारत के कुछ विश्व स्तर पर प्रशंसित अनुभव और प्रथाओं को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने का प्रयास करता है जो वैश्विक दक्षिण में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और सार्वभौमिक लचीलापन और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। GDC क्रॉस–लर्निंग यानी विनिमयी शिक्षा और नवाचार में वृद्धि लाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डोमेन में प्रभाव रखने वाली सरकारी एजेंसियों, थिंक–टैंक और सिविल सोसाइटी संगठनों जैसे भागीदार संस्थानों के साथ जुड़ने को प्रोत्साहित करता है। आरआईएस में जीडीसी द्वारा किए गए कार्यों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

कोविड–१६ महामारी ने वैश्विक संकट को बढ़ा दिया और मानव विकास के संपूर्ण संवैधानिक तत्वों पर कड़ा प्रहार किया। इस महामारी ने जीडीसी की सुविचार एक कार्य योजना को पंगु बना दिया ,जिसमें भौतिक बातचीत परामर्श संवाद विकास संबंधी मुद्दों पर साक्ष्य आधारित शोध एशिया और अफ्रीका में सक्रिय पहुंच और गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है हालांकि अभूतपूर्व अप्रत्याशित और अ प्रभावित जी डी सी ने भारत और विदेशों में अपने पहचाने गए लक्ष्य देशों और भागीदारों तक अधिकतम संभव सीमा तक पहुंचने के लिए डिजिटल मार्ग के साथ–साथ हाइब्रिड दृष्टिकोण अपनाया और इसके प्रयासों के परिणाम इस रिपोर्ट में स्वयं स्पष्ट है इस बीच विकास सहयोग रिपोर्ट नियमित रूप से लाई गई और एशिया और अफ्रीका में इस के भागीदार देशों के लिए महत्वपूर्ण महत्व के प्रमुख उभरते मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

जी डी सी ने भारत के प्रमुख कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करने वाले कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं को साक्षात करने के अपने जनादेश का अथक प्रयास किया जो भारत और अफ्रीका व एशिया में जी डी सी भागीदार देशों के बीच अधिक से अधिक वर्धा वर्धा एकीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है।

महामारी शमन पर जीडीसी की पहल

विकासशील देशों को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले अभूतपूर्व कोविड संकट से निपटने के लिए अपने भागीदारों का मार्गदर्शन करने की तत्काल आवश्यकता के जवाब में, GDC ने प्रतिष्ठित पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI) के सहयोग से कोविड–19 पर 4 ई–कार्यशालाएं आयोजित कीं और 40 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रतिभागियों तक पहुंच बनाई। प्रतिभागियों में से लगभग 565 विभिन्न सरकारी संस्थानों से संबद्ध थे और उनमें से 41 अपने–अपने देशों के विभिन्न मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार, GDC इन क्षेत्रों में भारत के ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता को इतनी बड़ी संख्या में सरकारी और गैर–सरकारी स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ साझा करने में सक्षम था। विशेषज्ञों में से कई अपने देशों में नीति निर्माताओं और आकार देने वालों को काफी प्रभावित करते थे और उनसे जुड़े हुए थे। ई–कार्यशालाएं निम्नानुसार आयोजित की गईं:

कोविड–19 का प्रबंधन, 15–18 अप्रैल 2020

प्राथमिक ध्यान विदेशों से भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के स्वास्थ्य पेशेवरों की क्षमता बढ़ाने और कोविड–19 महामारी के उभरते पहलुओं और भारत द्वारा नीतिगत प्रतिक्रियाओं के विषय में उनके ज्ञान और समझ को अद्यतन करने में उनकी सहायता करने पर था। विषय महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे महामारी विज्ञान, रोकथाम, परीक्षण, प्रबंधन, सह–रुग्णता स्थिति प्रबंधन, कोविड प्रतिक्रिया और प्रभावी संचार के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार करने पर केंद्रित थे।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः
सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ: जीडीसी

कोविड–19 का प्रबंधन, 25–28 अप्रैल, 2020

पहले वेबिनार की निरंतरता में, इसमें हस्तक्षेप के अतिरिक्त क्षेत्र भी शामिल थे जो महामारी से निपटने के लिए प्रासंगिक थे – महामारी, जो कई रूपों में प्रकट हो रहा था। विषयों में महामारी विज्ञान और रोकथाम, निगरानी और संरोधनय सामाजिक दूरी के नियमों को बढ़ावा देना; नियमित टीकाकरण, आपदा कार्य योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, कोविड मामलों का प्रबंधन, स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा, एम्बुलेंस संचालन, मृत्युदर प्रबंधन और रोगियों और उनके प्रियजनों को संभालने में बेहतर पारस्परिक संचार कौशल विकसित करना कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण थे।

कोविड–19 के संदर्भ में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, 9–13 मई, 2020

इसका उद्देश्य नई और आकस्मिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं से निपटने के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के बारे में ज्ञान और जागरूकता बढ़ाना था। कार्यशाला ने प्रतिभागियों की विस्तृत श्रृंखला को सफलतापूर्वक महामारी की तत्काल आवश्यकता से निपटने और कार्यस्थल विशेष रूप से उद्योगों और स्वास्थ्य सुविधाओं को फिर से खोलने की तैयारी के बारे में ज्ञान दिया।

लॉकडाउन के बाद: स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और व्यवस्था की तैयारी और कोविड–19 के लिए प्रतिक्रिया, 6–9 जून, 2020

इसमें कोविड स्क्रीनिंग, निदान और प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा, महामारी के लैंगिक प्रभाव सहित अस्पताल सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक नई चुनौती से जूझ रहे भाग लेने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा समय पर पहल की अत्यधिक सराहना की गई। स्वास्थ्य के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ–साथ नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ आगे संबंध बनाने में जीडीसी की सहायता के लिए यह एक वांछित पहल थी।

जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन

आपदा जोखिम प्रबंधन पर विकास सहयोग समीक्षा का विशेष अंक

विकास सहयोग समीक्षा (DCR) के आपदा जोखिम प्रबंधन (DRM) पर एक विशेष अंक 5 फरवरी, 2021 को GDC की पहल के तहत एक वेबिनार के माध्यम से लॉन्च किया गया। इसके मुख्य योगदानकर्ताओं में वैश्विक दक्षिण से संबंधित मुद्दों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रख्यात अत्यधिक विशिष्ट व्यक्तित्वों का एक दल शामिल था। वे कड़े संदेश के साथ सामने आए कि प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए चरम मौसम प्रतिरूप (पैटर्न) और पूर्वानुमान सेवाओं पर समन्वित मूल्यांकन के लिए क्षेत्रीय आधार पर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। ऐसी आपात स्थितियों से निपटने में अपने पड़ोसी देशों के लिए प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में भारत की भूमिका की अत्यधिक सराहना की गई और भागीदार देशों ने आपदा प्रबंधन और रिकवरी प्रक्रिया में भारत के अनुभव और विशेषज्ञता से लाभ उठाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। GDC ने भागीदार देशों को आश्वासन दिया कि वह आपदा तैयारियों के लिए अनुभव साझा करने और क्षमता निर्माण के लिए CDRI के साथ उनके जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने में उन्हें यथासंभव सहायता प्रदान करेगा।

वित्तीय समावेशन – डिजिटल नवाचार, फिनटेक समाधान & उत्पाद

GDC भागीदार देशों में डिजिटल भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में साझेदारी बनाने के लिए NPCI–इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) के साथ सहयोग करना

भारत के संस्थानों के साथ, जिन्होंने देश में डिजिटल वित्तीय सेवाओं सहित अपने अभिनव कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक शुरू किया है, संबंध बनाने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में GDC ने 3 मार्च, 2021 को NIPL के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया ताकि अफ्रीका में उनके संस्थागत पारिस्थिति की तंत्र और सेवाओं की संभावित प्रतिकृति के लिए इसके (GDC) साथ संबंध बनाने के लिए उनकी (NIPL) तत्परता का पता लगाया जा सके। दोनों पक्ष GDC मंच के माध्यम से NPCI के अनुभवों को भागीदार देशों तक ले जाने के लिए NIPL और GDC के बीच एक साझेदारी विकसित करने और अनुबंध की रूपात्मकता तैयार करने पर सहमत हुए। NIPL के साथ GDC का गठबंधन इसके भागीदार देशों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए उनकी सेवाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारत और कोत दिव्वार (Côte d'Ivoire) के बीच सहयोग की पहल को सुदृढ़ करना, 17 सितंबर 2020

RIS&GDC ने आबिदजान में भारतीय दूतावास और राष्ट्रपति कार्यालय, आइवरी कोस्ट सरकार के साथ साझेदारी में भारत और कोत दिव्वार के बीच सहयोग की पहल को मजबूत करने पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इसका उद्देश्य विकास संबंधी नीतियों, संरचनाओं, संगठनों, सुधारों और विचारों पर व्यापक अभिविन्यास के साथ कोत दिव्वार को नेतृत्व प्रदान करना और GDC के साथ उनका संबंध बनाना था। भारत के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर महत्वपूर्ण जानकारी, विशेष रूप से किसानों की आय को दोगुना करने (Doubling Farmers' Income & DFI) पर सरकार की पहल, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), आयुष्मान भारत–प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB&PMJAY), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" योजना। राष्ट्रपति कार्यालय ने, उनके माननीय मंत्री सहित, GDC पहल की अत्यंत सराहना की और आबिदजान में भारतीय मिशन के अनुसार, उनकी सरकार अपनी योजना प्रक्रियाओं में GDC द्वारा प्रदान किए गए इनपुट का उपयोग करेगी।

पेरिस शांति मंच (पेरिस पीस फोरम) के साथ सहयोग

जीडीसी ने पश्चिम अफ्रीका और एशिया में अपने साझेदार देशों के बीच भारत की कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं को ले जाने के लिए पेरिस पीस फोरम (PPF) के साथ एक कार्य साझेदारी स्थापित की है। PPF दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर एक सत्र समर्पित करने के लिए सहमत हो गया है, जिसे 2021 संस्करण के लिए GDC के समर्थन से RIS द्वारा क्यूरेट किया जाएगा। यह GDC को PPF भागीदारों के बीच अपनी पहुंच का विस्तार करने और ग्लोबल साउथ को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर आगे सहयोग और सहकार्य के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी अवसरों का निर्माण करने में सक्षम करेगा।

भारत–यूके साझेदारी को मजबूत करना: यूके–भारत सहकार्यता के तहत वैश्विक नवाचार कार्यक्रम

चयनित अफ्रीकी, एशियाई और हिंद–प्रशांत देशों को भारत के सफल समावेशी, कम लागत / मितव्ययी / जमीनी नवाचारों को स्थानांतरित करने पर वैश्विक नवाचार कार्यक्रम (Global Innovation Programme & GIP) के रूप में भारत–ब्रिटेन सहकार्यता पर एक पहल होगी। परस्पर प्रवीणता के हिस्से के रूप में और अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग के क्षेत्र में ब्रिटेन की विशेषज्ञता से लाभ उठाने के लिए GDC यूनाइटेड किंगडम के साथ भागीदार संस्थानों के जुड़ाव को और मजबूत करने हेतु ज्ञान एकत्र करने के लिए और विशेष अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों सहित यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने हेतु GDC ने कुछ प्रारंभिक कदम उठाए हैं, जो कोविड के अभूतपूर्व प्रभाव से मंद हो गए हैं। कोविड के मौजूदा खतरे से मुक्त होकर, जीडीसी यात्राओं के आदान–प्रदान का आयोजन करके यूनाइटेड किंगडम के विशेषज्ञों के साथ संबंध बनाने के लिए इस क्षेत्र को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देगा।

"पौधों की किस्मों के संरक्षण, बीज परीक्षण और प्रमाणन" पर अध्ययन कार्यक्रम

GDC ने "पौधों की विविधता संरक्षण, बीज परीक्षण और प्रमाणन" पर एक अध्ययन कार्यक्रम के लिए भारत आए केन्या प्लांट हेल्थ इंस्पेक्टरेट सर्विस (KEPHIS) के 5 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की थी, जिसे GDC द्वारा बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ICAR-IARI, दिल्ली में 17 से 28 जनवरी, 2020 तक आयोजित किया गया था। प्रतिनिधिमंडल में श्री जैकब किपचिरचिर चेप्टैवा, प्रधान निरीक्षक– KEPHIS मुख्यालय; श्री जेफ्री मुइंडे मालेम्बा, क्षेत्रीय प्रबंधक– KEPHIS किसुमु; श्री एप्रैम नजोरोगे वाचिरा, प्रभारी अधिकारी, KEPHIS एम्बू; श्री जेम्स गाकु मुथी, प्लांट परीक्षक – KEPHIS मुख्यालय और श्री जोनाह मैना कहवाई, इंस्पेक्टर II, KEPHIS नाकुरु शामिल थे। इस कार्यक्रम के दौरान, जीडीसी ने भुंगरू (Bhungroo) द्वारा तूफान जल प्रबंधन समाधान के लिए जलभृत भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया पर एक प्रस्तुति देने के अवसर का उपयोग किया, जिन्हें विश्व बैंक विकास बाजार और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा वर्षा जल प्रबंधन, आपदा न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में विशेषज्ञता वाले भारत के सर्वश्रेष्ठ सामाजिक नवाचारों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

GDC विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए केन्या विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का भी प्रयास करेगा। एक मसौदा समझौता ज्ञापन सक्रिय रूप से उनके विचाराधीन है।

12

आसियान–भारत

आसियान–भारत प्रख्यात व्यक्ति समूह (ASEAN & India Eminent Persons Group & AIEPG) के कार्यों और शांति, प्रगति व साझा समृद्धि के लिए एक करीबी साझेदारी बनाने की सिफारिशों के साथ इसकी रिपोर्ट पर विचार करते हुए, 19–20 दिसंबर, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित आसियान–भारत स्मारकीय शिखर सम्मेलन 2012 में आसियान और भारत के राष्ट्र / सरकार के प्रमुखों ने नई दिल्ली में आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) की स्थापना की सिफारिश की। 21 जून, 2013 को भारत के विदेश मंत्री द्वारा आरआईएस में औपचारिक रूप से एआईसी का उद्घाटन किया गया था। एआईसी आसियान देशों और भारत के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य सहयोग को मजबूत करना और उनके बीच संबंधों को पोषित करना है। AIC आसियान–भारत संबंधों को मूल्यवान और व्यवहार्य दिशा प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम नेतृत्व में काम करता है। 2020–21 में, एआईसी ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए आभासी सम्मेलन और अध्ययन किए: (i) हिंद–प्रशांत में व्यापार, संपर्क और समुद्री परिवहनय (ii) आसियान और भारत के बीच उत्पादन नेटवर्क– क्षेत्रीय विश्लेषणय (iii) आसियान और भारत के बीच ऊर्जा सहयोगय (iv) ACMECS–भारत सहयोग; और (v) त्रिपक्षीय राजमार्ग और भारत के पूर्वोत्तर पर प्रभाव। विवरण निम्नलिखित अनुच्छेद में प्रदान किया गया है।

हिंद–प्रशांत में व्यापार, संपर्क और समुद्री परिवहन

4 नवंबर, 2019 को बैंकॉक में आयोजित 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में, भारतीय प्रधान मंत्री ने हिंद–प्रशांत के विस्तृत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंद–प्रशांत महासागरीय पहल (IPOI) की घोषणा की। हिंद–प्रशांत महासागरीय पहल (IPOI) पर सहयोग के सात स्तंभ हैं: (i) समुद्री पारिस्थितिकी, (ii) समुद्री सुरक्षा, (iii) समुद्री संसाधन, (iv) क्षमता निर्माण और संसाधन साझेदारी, (v) आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन, (vi) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग, (viii) व्यापार, संपर्क और समुद्री परिवहन। जिनमें से, विदेश मंत्रालय ने AIC, RIS को अनुसंधान कार्य शुरू करने और हिंद–प्रशांत महासागरीय पहल (IPOI) के व्यापार/कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन (7वें स्तंभ) के प्रभावी प्रचार और कार्यान्वयन के लिए एक ज्ञान भागीदार बनाने के लिए कहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य हिंद–प्रशांत में व्यापार के अवसरों का आकलन करना, व्यापार, संपर्क और समुद्री परिवहन में चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना और आगे की राह तय करना है।

आसियान और भारत के बीच उत्पादन नेटवर्क का आकलन: क्षेत्रीय विश्लेषण

इस अध्ययन का उद्देश्य आसियान के साथ भारत के उभरते (या संभावित) वैश्विक मूल्य श्रृंखला या ग्लोबल वैल्यू चेन (जीवीसी)/आरवीसी का पता लगाना है, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र, जैसे मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल उद्योगों में। यह अध्ययन उन उद्योगों के भीतर सीमा पार नेटवर्क को मजबूत करने की संभावनाओं की भी जांच करेगा, जिन पर भारत की विनिर्माण क्षमता और पूरकताएं आसियान की मांग या आपूर्ति क्षमता से मेल खाती हैं और इसके विपरीत। इसके अलावा, यह उत्पादन नेटवर्क और शमन रणनीति बनाने में आने वाली चुनौतियों की भी पहचान करेगा। अध्ययन, विशेष रूप से, आसियान और भारत के बीच उत्पादन नेटवर्क को बढ़ावा देने में व्यापार सुविधा में मौजूद अंतराल की पहचान करने और संभावित उपचार प्रदान करने का प्रयास करेगा। अध्ययन के परिणाम से वस्तुओं के संदर्भ में आसियान–भारत मुक्त व्यापार समझौते या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट (एफटीए) की चल रही समीक्षा प्रक्रिया में मदद मिलेगी।

आसियान आर्थिक समुदाय 2025 के निहितार्थ

2015 में आसियान आर्थिक समुदाय या आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी (एईसी) की स्थापना आसियान में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण एजेंडा का एक प्रमुख मील का पत्थर है, जो 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 622 मिलियन से अधिक लोगों के विशाल बाजार के रूप में अवसर प्रदान करता है। 2015 में कुआलालंपुर में 27वें आसियान शिखर सम्मेलन में आसियान नेताओं द्वारा अपनाया गया एईसी ब्लूप्रिंट 2025 रणनीतिक उपायों के माध्यम से 2016 से 2025 तक के लिए एईसी को व्यापक दिशा प्रदान करता है। एईसी ब्लूप्रिंट 2025 का उद्देश्य 2025 तक आसियान आर्थिक समुदाय गठित होने के विजन को प्राप्त करना है, जो अत्यधिक एकीकृत और एकजुट; प्रतिस्पर्धी, अभिनव और गतिशील; संवर्धित संपर्क और क्षेत्रीय सहयोग के साथ; और एक अधिक लचीला, समावेशी, और जन–उन्मुख, जन–केंद्रित समुदाय, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होगा। आसियान सदस्य देशों का 2025 तक एईसी पूरा करने का लक्ष्य है। एईसी के कार्यान्वयन के भारत के लिए आर्थिक और सामरिक निहितार्थ हैं। यह अध्ययन विशेष रूप से क्षेत्रीय संपर्क के संदर्भ में भारत के लिए एईसी के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

आसियान–भारत एफटीए मूल्यांकन

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों में से एक है। आसियान–भारत एफटीए 1 जनवरी, 2010 से प्रभावी है। तब से दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2009–10 में लगभग 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018–19 में 97 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2019–20 में द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। आसियान से भारत का आयात आसियान को भारतीय निर्यात की तुलना में काफी अधिक दर से बढ़ा है। आसियान–भारत मुक्त व्यापार समझौते (एआईएफटीए) के पूर्व–पश्च प्रभाव से पता चलता है कि आसियान के साथ भारत का व्यापार संतुलन बिगड़ गया है और टैरिफ सुधारों और व्यापार विस्तार के बीच एक कमजोर तदनुरूपता है। आयात में तेज वृद्धि के परिणामस्वरूप आसियान के साथ भारत के व्यापार घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) से बाहर होने का फैसला किया है, और भारतीय निर्यात और मूल्य श्रृंखलाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए आसियान वार्ता भागीदारों के साथ द्विपक्षीय एफटीए को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वहीं, वस्तुओं पर आसियान–भारत एफटीए 2010 से एक दशक पूरा कर चुका है। आसियान–भारत सेवाओं और निवेश समझौते को अभी लागू किया जाना बाकी है। वैश्विक व्यापार और भू–राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, वस्तुओं पर आसियान–भारत एफटीए के भविष्य की कार्यप्रणाली की पहचान करने के लिए वास्तव में एक अध्ययन की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में, इस अध्ययन का उद्देश्य आसियान–भारत एफटीए का मूल्यांकन करना और 2030 तक आसियान देशों के साथ भारत की व्यापार संभावनाओं की जांच करना है। यह अध्ययन आसियान और भारत के बीच मूल्य श्रृंखला संबंधों पर भारत आसियान एफटीए के प्रभाव का भी विश्लेषण करेगा और भारत से आसियान को निर्यात में वृद्धि के लिए नीतिगत सिफारिशें भी प्रदान करेगा।

आसियान और भारत के बीच ऊर्जा सहयोग

पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच के मामले में आसियान और भारत के पास अपार संभावनाएं और पूरकताएं हैं। आसियान और भारत 2030 तक सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, संधारणीय और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने और अक्षय ऊर्जा स्रोत के विभिन्न साधनों को बढ़ावा देने के माध्यम से कम कार्बन विकास पथ की ओर बढ़ने के लिए संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। यदि हम आसियान–भारत कार्ययोजना (2021–2025) के तहत देशों की प्रतिबद्धताओं पर विचार करें, तो आसियान और भारत के बीच ऊर्जा सहयोग अधिक आशाजनक प्रतीत होता है। ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास ने नए सिरे से जोर दिया है। ग्रिड स्थिरता, स्वच्छ गहन प्रबंधन और हरित प्रबंधन सहयोग के संभावित क्षेत्र हैं। पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा, दोनों में निजी क्षेत्र को शामिल करने को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य आसियान और भारत के बीच ऊर्जा सहयोग की वर्तमान स्थिति की जांच करना और ऊर्जा सहयोग में भविष्य के दायरे पर चर्चा करना है। यह आसियान और भारत के बीच ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के लिए नीतिगत सिफारिशों का एक सेट भी प्रस्तुत करेगा। शोध परिणामों का एक पुराना संस्करण पहले ही AIC वर्किंग पेपर और AIDCR 2021 के अध्याय के रूप में प्रकाशित हो चुका था। यह शोध परियोजना कार्ययोजना (2021–2025) के अनुरूप अगला चरण शुरू करेगी।

संपर्क और आपूर्ति श्रृंखला तन्यकता *(Resilience)*

आसियान–भारत कार्ययोजना (2021–2025) की प्रमुख सिफारिशों में से एक संपर्क के मुद्दों पर आसियान और भारत के बीच परामर्श और संवाद जारी रखना है। आसियान और भारत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच लापता लिंक को पूरा करके इस क्षेत्र में भौतिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भी मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के प्रासंगिक हिस्सों को पूरा करने में तेजी लाना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही, एक आर्थिक गलियारा बनाने और कंबोडिया, लाओ पीडीआर, और वियतनाम तक इसके विस्तार के लिए सहयोगी कदम; और सड़कों और रेलवे और प्रासंगिक प्रचालन–तन्त्र के नेटवर्क के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति हुई है। एक निर्बाध रूप से संबद्ध और एकीकृत आसियान को प्राप्त करने के लिए और संधारणीय सामाजिक–आर्थिक तरक्की और विकास सुनिश्चित करने के लिए दोनों ने मजबूत मानकों के गुणवत्तापूर्ण, संधारणीय और पारदर्शी अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने का भी फैसला किया है। कोविड –19 महामारी ने हमें आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन के महत्व को समझाया है। लागत और समय दोनों के संदर्भ में व्यवधानों से बचने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत लचीलेपन की आवश्यकता है। साथ ही, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन मूल्य श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करने या सीमाओं के पार मूल्य श्रृंखला की व्यापकता को मजबूत करने में मदद करेगा। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 'सप्लाई चैन रेजीलिएंस इनीशिएटिव' या आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई) शुरू करने में रुचि दिखाई है। आसियान के एससीआरआई में शामिल होने की संभावना है। उपर्युक्त को देखते हुए, इस अध्ययन का उद्देश्य एससीआरआई के निहितार्थों का, और यह कैसे व्यापार संबंधों को मजबूत कर सकता है, का आकलन करना है।

जन स्वास्थ्य सहयोग

चल रहे कोविड–19 महामारी को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य सहयोग को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। भारत और आसियान वैज्ञानिकों, टीकों, प्रौद्योगिकी आदि के आदान–प्रदान सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। आसियान–भारत कार्ययोजना (2021–2025) स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के वर्गों के तहत आसियान स्वास्थ्य क्षेत्र की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के लिए प्रासंगिक सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में जानकारी साझा करने; सभी खतरों और उभरते खतरों का जवाब देने; स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देखभाल तक पहुंच; और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने को बढ़ावा देने के लिए सहमत हो गया है। यह अध्ययन, आसियान प्रबुद्ध मंडल के सहयोग से, सार्वजनिक स्वास्थ्य में आसियान और भारत के बीच सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक स्कोपिंग पेपर तैयार करेगा।

IMT-GT सहयोग और भारत की विकास भागीदारी

इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड रणनीतिक रूप से हिंद–प्रशांत के केंद्र में स्थित हैं और एक त्रिकोण बनाते हैं। इंडोनेशिया–मलेशिया–थाईलैंड ग्रोथ ट्राएंगल (आईएमटी–जीटी) पहल का उद्देश्य इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आईएमटी–जीटी आर्थिक सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक उप–क्षेत्रीय ढांचा प्रदान करता है। आईएमटी–जीटी (IMT-GT) के नियंत्रण में आसियान में पर्याप्त संपत्तियां हैं। आईएमटी–जीटी देशों के लिए सबसे बड़ा अवस्थिति लाभ विश्व स्तर पर एक व्यापक व्यापार नेटवर्क तक पहुंच है। भारत आईएमटी–जीटी का सभ्यतागत भागीदार है। आईएमटी–जीटी के ढांचे के तहत इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के साथ भारत की विकास साझेदारी का आसियान ढांचे के भीतर की गई साझेदारी से कायाकल्प हो सकता है। इस अध्ययन का उद्देश्य आईएमटी–जीटी के पहलुओं, उनकी गतिविधियों की श्रृंखला और परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा करना है। यह आईएमटी–जीटी के साथ भारत के सहयोग से उत्पन्न होने वाले अवसरों की भी जांच करेगा।

आसियान–भारतः कोविड काल के बाद साझेदारी को मजबूत बनाना

थिंक टैंकों के आसियान–भारत नेटवर्क (एआईएनटीटी) के छठे गोलमेज सम्मेलन की वीडियो कॉन्फ्रेंस 20–21 अगस्त 2020 को आयोजित की गई। भारत के माननीय विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने आरंभिक भाषण दिया और यह रेखांकित किया कि हमारे सहयोग की भावी दिशा पर हमारी सरकार को नीतिगत जानकारियां प्रदान करने के लिए एआईएनटीटी की स्थापना की गई। हमें इस संबंध में कुछ सफलता मिली है, लेकिन उन्होंने थिंक टैंकों, विशेषकर हमारे देश के थिंक टैंकों से वर्तमान वैश्विक हालात में और भी अधिक अभिनव एवं क्रांतिकारी आइडिया देने का आग्रह किया है। यहां तक कि सामान्य हालात में भी नए विचारों या आइडिया की नितांत आवश्यकता और व्यापक गुंजाइश है क्योंकि यह स्पष्ट है कि अकेले सरकार के भीतर ही सब कुछ सृजित नहीं किया जा सकता है। हमें अतीत में भी विद्वानों, मीडिया, कारोबारी जगत और सिविल सोसायटी की ओर से अभिनव आइडिया मिलते रहे हैं।

दुनिया को एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हममें से किसी ने भी इससे पहले इस स्तर का गंभीर संकट या इस तरह की अनिश्चितता वास्तव में नहीं देखी है। विश्व अर्थव्यवस्था में जिस भारी गिरावट के अनुमान व्यक्त किए जा रहे हैं वह निश्चित रूप से महामंदी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट साबित होगी। भारत और आसियान के बीच समकालीन संबंध दरअसल वैश्वीकरण में हमारे साझा हितों पर ही काफी हद तक आधारित था। वैसे तो वैश्वीकरण को व्यापार, यात्रा और वित्तीय प्रवाह के रूप में परिलक्षित किया जा सकता है, लेकिन सही मायनों में यह अलग हटकर ऐसा कुछ है जो अत्यंत व्यापक है। वास्तव में महामारी ने हमें जो अहसास कराया है, वह मानव के अस्तित्व से जुड़ा अभिन्न पहलू है जो वैश्वीकरण को रेखांकित करता है। चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद हो या वास्तव में महामारी हो, ये ऐसी चुनौतियां नहीं हैं, जिनसे प्रभावित लोगों के पास कोई विकल्प होता है। विशुद्ध रूप से महज राष्ट्रीय स्तर पर ही विभिन्न कदम उठाने की सीमाएं या सच्चाई से इनकार करने की नौबत अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अतः अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता यही है कि वह सामूहिक समाधानों की तलाश करने के लिए और भी अधिक ईमानदारी से एक साथ मिलकर काम करें।

इस बारे में चिंतन–मनन करने के दौरान जो बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आता है वह केवल आर्थिक हालात, समाज को हुए नुकसान या गवर्नेंस से जुड़ी चुनौती ही नहीं है। यह वास्तव में वैश्विक मामलों की भावी दिशा के साथ–साथ इस सवाल पर भी बहस का विषय है कि हमें आगे चलकर आखिरकार किस प्रकार की विश्व व्यवस्था या बिगड़ी हुई व्यवस्था में रहने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप आज जो चीज अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संभवतः सबसे अधिक मूल्यवान है, वह कुछ और नहीं, बल्कि परस्पर विश्वास ही है।

संकट काल में विभिन्न देशों द्वारा उठाए जाने कदम ही यह तय करते हैं कि इस बारे में दुनिया का नजरिया वास्तव में क्या है। बेशक, इन देशों ने मौजूदा वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित कई जोखिमों को सामने लाया है। इसके फलस्वरूप आपूर्ति में परिवर्तन को लेकर आज जो चिंताएं हैं उन्हें विविधीकरण और लचीलेपन पर अधिक जोर देकर तो कम किया ही जा सकता है। वास्तव में इन्हीं कारणों से इन चुनौतियों के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना और सहयोग का एक अधिक सकारात्मक एवं व्यावहारिक मॉडल प्रस्तुत करना हम सभी पर निर्भर करता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि यहां तक कि संकट काल में भी दुनिया में अच्छे उदाहरणों का अभाव है। आखिरकार बहुत से ऐसे लोग या संगठन भी रहे हैं जिन्होंने इस दौर में भी वह सब कुछ साझा किया जो उनके पास था, चाहे वह दवाएं हों, आवश्यक आपूर्ति हों या संसाधन ही क्यों न हों। वास्तव में, इन सभी ने अपने–अपने कार्यों के माध्यम से जो प्रदर्शित किया वह व्यापक पुनर्संतुलन के साथ–साथ एक कहीं अधिक उदार और न्यायसंगत वैश्विक नजरिए की आवश्यकता थी। भारत के लिए आज, अन्य बातों के अलावा, इसका अर्थ यही है कि अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करने की नितांत आवश्यकता है। यह सामाजिक अस्तित्व के महत्वपूर्ण पहलुओं विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर जोखिम उठाने और इसके साथ ही न केवल लाभ उत्पन्न करने वाली अर्थव्यवस्था, बल्कि रोजगार सृजित करने वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण की घरेलू प्राथमिकता को पूरक बनाने के महत्व को रेखांकित करता है, जिसे हम 'आत्मनिर्भर भारत' कहते हैं।

आसियान दरअसल वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न चौराहों में से एक है। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम न केवल एक दूसरे के समीप हैं, बल्कि साथ मिलकर एशिया और दुनिया को सही स्वरूप देने में भी मदद करते हैं। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हम इस नाजुक मोड़ पर व्यापक सलाह–मशविरा अवश्य करें। बहस करने के लिए कई वैचारिक मुद्दे हैं जिनमें हिंद–प्रशांत भी शामिल है। विचार–विमर्श के लिए पेश की गई हिंद–प्रशांत महासागर से जुड़ी पहलों के बारे में विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है क्योंकि वैश्विक रिश्तों में जो बदलाव आए हैं उनका जायजा हमें भी लेना होगा। जैसे–जैसे हम इस महामारी से उबर रहे हैं, हमें इस तथ्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि दुनिया कभी भी फिर से ठीक वैसी ही नहीं होगी जैसी पहले थी, जिसका अर्थ है नई सोच, नए विचार, अधिक चिंतन–मनन, और ज्यादा खुलापन। चाहे व्यापार हो, या सुरक्षा अथवा राजनीति हो, हमें रूढ़िवादी प्रवृत्तियों या दकियानूसी तौर–तरीकों से परे जाने की सख्त जरूरत है।

कोविड काल के बाद आसियान–भारत साझेदारी

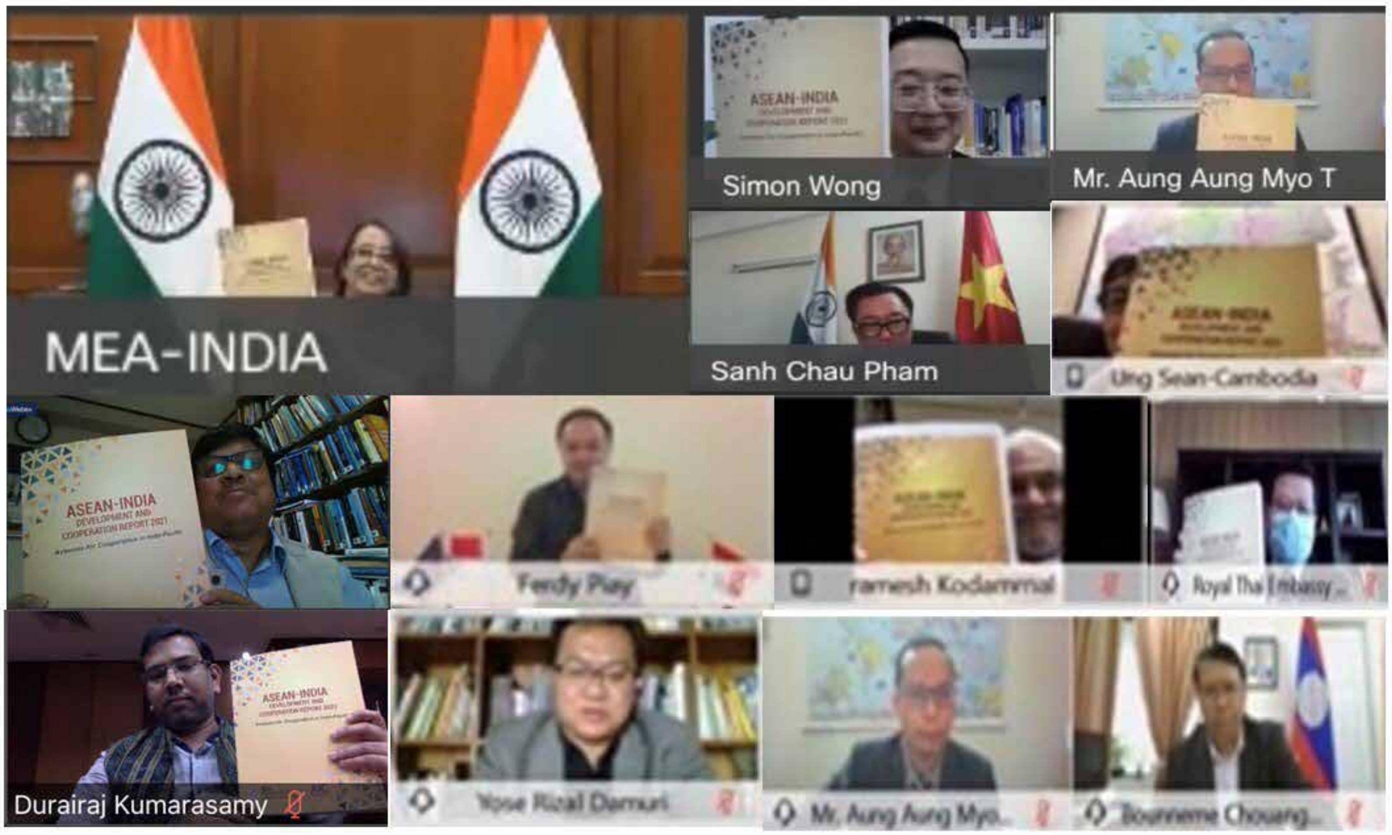

वेबिनार प्रगति पर है जिसका यह स्क्रीनशॉट है

कोविड काल के बाद 17वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन 2020 से पहले आसियान–भारत साझेदारी पर एक वेबिनार 10 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया और इसके साथ ही आसियान–भारत विकास एवं सहयोग रिपोर्ट (एआईडीसीआर) 2021 जारी की गई। आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने स्वागत भाषण दिया। चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार ने सत्र की अध्यक्षता की और विशेष भाषण दिया। श्री फर्डी निको योहानेस पियाए, मिशन के उप प्रमुख, इंडोनेशिया गणराज्य का दूतावास, नई दिल्ली; श्री आंग आंग मयो थीन, मिशन के उप प्रमुख, म्यांमार गणराज्य का दूतावास, नई दिल्ली; माननीय श्री साइमन वोंग, उच्चायुक्त, सिंगापुर गणराज्य का उच्चायोग, नई दिल्ली; और श्री फाम सान्ह चाऊ, राजदूत, वियतनाम समाजवादी गणराज्य का दूतावास, नई दिल्ली ने विशेष भाषण दिया।

राजदूत रिवा गांगुली दास, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया। इसके बाद आरआईएस स्थित एआईसी द्वारा *'आसियान–भारत विकास और सहयोग रिपोर्ट (एआईडीसीआर) 2021: हिंद–प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए अवसर'* जारी की गई।

डॉ. मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस ने इस अवसर पर आयोजित पैनल परिचर्चा की अध्यक्षता की। मुख्य वक्ता ये थे: डॉ. योज रिजाल दमुरी, अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख, रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र (सीएसआईएस), जकार्ता; प्रोः अर्पिता मुखर्जी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर), नई दिल्ली; दातो' रमेश कोडामल, सह–अध्यक्ष, आसियान–भारत व्यवसाय परिषद (एआईबीसी), कुआलालम्पुर; और डॉ. हुयी होआंग गुयेन, निदेशक, दक्षिण–पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान, वियतनाम सामाजिक विज्ञान अकादमी (वीएएसएस), हनोई। आरआईएस स्थित एआईसी की ओर से डॉ. दुरईराज कुमारसामी ने समापन सत्र में धन्यवाद ज्ञापन किया।

बंगाल की खाड़ी आर्थिक संवाद 2021

आरआईएस स्थित आसियान भारत केंद्र (एआईसी) ने सानेम, बांग्लादेश; भूटानी सोसायटी पर अनुसंधान केंद्र (सीआरबीएस), भूटान; व्यापार, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण पर दक्षिण एशिया निगरानी (सावटी), नेपाल; पाथफाइंडर फाउंडेशन, श्रीलंका; और चुलालॉन्गकॉर्न विश्वविद्यालय, थाईलैंड के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 8–11 फरवरी 2021 को 'बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कोविड–19 के बाद की चुनौतियां' विषय पर बंगाल की खाड़ी आर्थिक संवाद 2021 का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में ये सत्र आयोजित किए गए: डिजिटल कनेक्टिविटी एवं ई–कॉमर्स; व्यापार व क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाएं; व्यापार, क्षेत्रीय सहयोग, स्वास्थ्य व शिक्षा, रोजगार की चुनौतियों और संबंधित मुद्दों पर शोध–पत्र प्रस्तुति सत्र; बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी; कोविड–19 के बाद बेहतरी के लिए संस्थागत चुनौतियां; बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना; बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कोविड के बाद की चुनौतियों से निपटना; और संबंधित देशों के लोगों के पारस्परिक संपर्कों को मजबूत करना।

कोविड–19 चुनौतियों और आगे की राह पर वेबिनार, 12 मई, 2020

RIS में आसियान–भारत केंद्र (AIC) ने 12 मई, 2020 को "आसियान–भारत: कोविड–19 चुनौतियों से मुकाबला और आगे की राह" पर एक वेबिनार का आयोजन किया। आसियान देशों के पैनल सदस्यों ने कोविड–19 के प्रति अपने देश की प्रतिक्रिया और महामारी से निपटने के लिए भारत–आसियान सहयोग के लिए सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

कोविड–19 पश्चात आसियान–भारत व्यापार और मूल्य श्रृंखला पर वेबिनार, 22 मई, 2020

RIS में आसियान–भारत केंद्र (AIC) ने 22 मई 2020 को कोविड–19 के बाद के काल में आसियान–भारत व्यापार और मूल्य श्रृंखला पर वेबिनार का आयोजन किया। पैनल के सदस्यों ने तर्क दिया कि MSME, विनिर्माण, पर्यटन और सेवा क्षेत्रों को कोविड–19 की सबसे कठिन मार का सामना करना पड़ा। भारत और आसियान के बीच व्यापार और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने के लिए कोविड के बाद की स्थिति में मजबूत क्षेत्रीय सहयोग की बहुत आवश्यकता है। पैनल के सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण सिफारिशें साझा की गईं और आगे की राह को सुझाव दिया गया।

मेकांग–गंगा सहयोग के 20 वर्षों पर वेबिनार, 28 मई, 2020

आसियान–भारत केंद्र (AIC) ने संयुक्त रूप से 28 मई, 2020 को मेकांग–गंगा सहयोग के 20 साल पर वेबिनार का आयोजन किया। पैनलिस्टों ने कहा कि कोविड की वर्तमान और बाद की स्थिति से निपटने के लिए MGC देशों के बीच अधिक सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है।

विश्व व्यवस्था और हिंद–प्रशांत में सुरक्षा स्थिति पर कोविड –19 महामारी के प्रभाव पर वेबिनार, 12 जून 2020

नैशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (NMF) और आसियान–इंडिया सेंटर (AIC) ने संयुक्त रूप से 12 जून, 2020 को भारत–प्रशांत में विश्व व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव पर एक वेबिनार का आयोजन किया। राजदूत पीएस राघवन ने मुख्य भाषण दिया और वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान ने सत्र का संचालन किया। RIS के अध्यक्ष, राजदूत मोहन कुमार ने हिंद–प्रशांत में नए अवसरों पर अपना दृष्टिकोण साझा किया।

आसियान–भारत मुक्त वस्तु व्यापार क्षेत्र (एफटीए) का एक दशकः उपलब्धियां और आगे का रास्ता, पर वेबिनार, 29 जून, 2020

RIS में आसियान–भारत केंद्र (AIC) ने 29 जून, 2020 को चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय में आसियान अध्ययन केंद्र (ASC) और एशियाई संगम (Asian Confluence) के साथ संयुक्त रूप से आसियान–भारत वस्तु FTA के एक दशक पर वेबिनार का आयोजन किया। वक्ताओं ने रचनात्मक विचारों और व्यापार, निवेश और भारत और आसियान के बीच क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए आगे की राह साझा की।

कोविड –19 युग में ऊर्जा कनेक्टिविटी के लिए चुनौतियों और संभावनाओं पर वेबिनार, 24 जुलाई, 2020

RIS में आसियान–भारत केंद्र (AIC) ने आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ERIA), जकार्ता; एनर्जी स्टडीज इंस्टीट्यूट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर; और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ संयुक्त रूप से 24 जुलाई, 2020 को "कोविड –19 युग में ऊर्जा कनेक्टिविटी के लिए चुनौतियां और संभावनाएं" पर एक वेबिनार का आयोजन किया। पैनल के सदस्य दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के प्रमुख प्रबुद्ध मंडलों (थिंक–टैंक) और विश्वविद्यालयों से थे। लगभग 40 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया, वेबिनार में चर्चा सुनी और प्रश्नोत्तर सत्र में भाग लिया। RIS के अध्यक्ष राजदूत मोहन कुमार ने उद्घाटन भाषण दिया।

प्रकाशन कार्यक्रम

एआईसी

आसियान–भारत विकास और सहयोग रिपोर्ट 2021

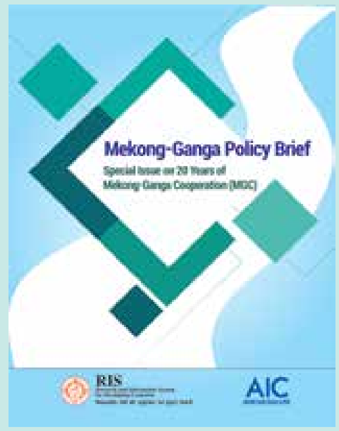

मेकोन्ग–गंगा नीतिगत सार, दिसम्बर 2020

प्रदान की गई विश्लेषणात्मक सहायता

- माननीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के लिए 'पहले भारत–आसियान महासागरीय व्यापार शिखर सम्मेलन और एक्सपो', जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए सहयोग करेगा, के लिए मसौदा वार्ता बिंदु प्रदान किया गया।
- आरआईएस में एआईसी ने हिंद–प्रशांत में समुद्री सुरक्षा सहयोग, आसियान–भारत नीली अर्थव्यवस्था, हिंद–प्रशांत में संपर्क एजेंडा, आसियान और भारत में प्रबुद्ध मंडल के बीच सहयोग, दिल्ली वार्ता, आईपीओआई, ऊर्जा सहयोग, आदि पर विदेश मंत्रालय को नीतिगत इनपुट प्रदान किए हैं।

13

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

आर आई एस में इंटर्नशिप कार्यक्रम

यूनिवर्सिटी थिक टैंक पर पहल के हिस्से के रूप में आर आई एस में इंटर्नशिप कार्यक्रम एक युवा विद्वान मंच के रूप में कार्य करता है। इसके हिस्से के रूप में आर आई एस विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों के छात्रों को अर्थशास्त्र संबंधित विषयों में स्नातक करने के लिए इंटर्नशिप के पेशकश कर रहा है। इन वर्षों में इंटर्नशिप कार्यक्रम की मांग में काफी वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कार्यक्रम की सामग्री पर्यवेक्षण और सीखने के घटकों का पूर्ण गठन हुआ। में कोविड– १६ महामारी के कारण लंबे समय तक लॉकडाउन के मद्देनजर आर आई एस ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम के साथ आया है ,जिसके सकाय और साथियों के साथ बातचीत के नवीन तरीके हैं विभिन्न आर आई एस वेबीनार और वेब आधारित सम्मेलनों में इंटर की भागीदारी की सुविधा प्रदान करते हैं ।लगभग२२ छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया व इंटर्नशिप पूरी की, कार्यक्रम की समाप्ति पर इन भागीदारों ने यूनिवर्सिटी थिंक टैंक इनीशिएटिव यंग स्कॉलर फॉर्म वेबीनार सीरीज के तहत प्रस्तुति दी।

पहला वेबीनार १५ सितंबर को आयोजित किया गया था। डॉ प्रियदर्शी दाश सहायक प्रोफेसर, आर आई एस, ने आर आई एस समर इंटर्नशिप के बारे में सिंहावलोकन किया प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी महा निर्देशक आर आई एस ने अनुसंधान प्राथमिकताएं और आर आई एस विश्वविद्यालय थिंकटैक के बारे में प्रस्तुति की, उसके बाद प्रोफेसर ज्योति चंद्रमणि निर्देशक सिंबोसिस स्कूल आफ इकोनॉमिक्स सिंबायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे और डॉक्टर विवेक चौधरी एसोसिएट प्रोफेसर आई आई एफ टी, कोलकाता, ने टिप्पणी की प्रशिक्षकों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गई।

श्री अरुणाभ साहा द्वारा भारत– चीन व्यापार संबंध व चीन पर भारत की निर्भरता सुश्री प्रगति शर्मा द्वारा डिजिटल मुद्राओं के उपयोग में नियामक और नीतिगत मुद्दे और सुश्री फिरदोस खान द्वारा फिनटेक सेटर एंड अपॉर्चुनिटी श्री चेतन खुराना द्वारा व्यापार में गेम थ्योरी अनुप्रयोगों की समीक्षा और सुश्री बरनालिका प्रधान द्वारा खनन क्षेत्र में कौशल विकास व दक्षिण अफ्रीका का अनुभव जन्य विश्लेषण। १६ सितंबर २०२० को आयोजित दूसरे वेबीनार की अध्यक्षता प्रोफेसर एसके मोहंती प्रोफेसर आर आई एस, डॉक्टर रंजन कुमार दास सहायक प्रोफेसर सिंबोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे ने विशेष टिप्पणी की डॉक्टर प्रियदर्शनी दास सहायक प्रोफेसर आर आई एस द्वारा इंटर्नशिप पत्रों पर एक संक्षिप्त जानकारी दी गई, सुश्री पूर्णिमा चौधरी द्वारा पूर्वोत्तर आकांक्षा आत्मक जिलों में वित्तीय समावेशन व केरल और तमिलनाडु में वित्तीय समावेशन, सुश्री शिल्पा मेरी अगस्टिन द्वारा एक तुलनात्मक अध्ययन सुश्री साक्षी निगम और सुश्री लावण्या सियाल द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास पर कोविड–१६ का प्रभाव ,सुश्री स्वाति वर्मा द्वारा उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल उद्योगों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक सुश्री अमला विवारा भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादन और आयात लिंकेज सुश्री अनुजा माथुर द्वारा दक्षिण एशिया में भारतीय कृषि निर्यात की पूर्णता श्री सौम्यदीप पाल द्वारा भारत में चाय निर्यात का एक अध्ययन और उत्तर पूर्व भारत में बागवानी क्षेत्र पर एक संक्षिप्त अध्ययन और बिम्सटेक के बीच हेल्थ केयर सहयोग व सुश्री आदिति सेन गुप्ता द्वारा नए विकल्पों का प्रस्तुतीकरण।

कोविड–19 पर आरआईएस डायरी के विशेष अंक

आरआईएस डायरी

अप्रैल, 2021

जनवरी, 2021

अक्तूबर, 2020

14

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

आरआईएस संकाय

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

- 24 मार्च 2021 को देव संस्कृति, इंडिया थिंक काउंसिल और पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से आयोजित कुंभ सम्मेलन 2021 में सतत विकास लक्ष्यों पर वीडियो संदेश दिया।
- 19 मार्च 2021 को आरबीआई बोर्ड की बैठक में भारत–चीन व्यापार घाटा और व्यापक व्यापार परिदृश्य पर प्रस्तुति दी।
- 17 मार्च 2021 को यूएनओएसएससी द्वारा आयोजित विकास सहयोग के लिए महानिदेशकों पर उच्च स्तरीय फोरम में 'एसएससी और त्रिकोणीय सहयोग के लिए कोविड–19 संकट से उत्पन्न रुझान, अवसर एवं चुनौतियां' विषय पर प्रस्तुति दी।
- 13 मार्च 2021 को द एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन–2021: मानसिक स्वास्थ्य– 'अवसाद से अच्छी सेहत की ओर' में 'बेहतर मानसिक स्वास्थ्य परिणामों के लिए आर्थिक प्रतिबद्धताएं और मानसिक विकारों की बीमा कवरेज: विमुखता के कारण और समाधान' पर प्रस्तुति दी।
- 9 मार्च 2021 को हैन्स सीडेल फाउंडेशन (एचएसएफ) द्वारा 'विश्व मामलों के फोकस में चीन और भारत' पर आयोजित नई ऑनलाइन श्रृंखला में 'आरसीईपी और एशिया एवं यूरोप के लिए परिणाम' पर प्रस्तुति दी।
- 26 फरवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम ब्रिक्स और सूस शेरपा बैठक में 'ब्रिक्स सिविल फोरम 2021' पर प्रस्तुति दी।
- 17 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 2020 बैच के आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओं की संगोष्ठी में 'दक्षिणीय सहयोग'' पर प्रस्तुति दी।
- 9 फरवरी 2021 को ओईसीडी द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भविष्य' विषय पर आयोजित विशेषज्ञों के कार्यदल के तीसरे विचार–मंथन सत्र में भाग लिया।
- 2 फरवरी 2021 को दूरदर्शन द्वारा भारत–बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की शुरुआत की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित पैनल परिचर्चा में 'भारत–बांग्लादेश' पर प्रस्तुति दी।
- 28 जनवरी 2021 को हैन्स सीडेल फाउंडेशन (एचएसएफ) द्वारा 'विश्व मामलों के फोकस में चीन और भारत' पर आयोजित ऑनलाइन श्रृंखला में 'आरसीईपी पर फोकस के साथ भारत एवं चीन के आर्थिक संबंध और भारत के लिए इसके भू–आर्थिक निहितार्थ' विषय पर प्रस्तुति दी।
- 21 जनवरी 2021 को जर्मन अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र (डीडब्ल्यूआईएच) और जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा (डीएएडी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'भारत–जर्मन संवाद: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विज्ञान कूटनीति' में पैनलिस्ट थे।
- 20 जनवरी 2021 को नीतिगत संवाद केंद्र (सीपीडी), ढाका द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया में विदेशी उच्च शिक्षा के लिए रिटर्न पर प्रस्तावित सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना की 'आरंभिक बैठक' में भाग लिया।
- 12 जनवरी 2021 को विकास अध्ययन केंद्र (सीडीएस) द्वारा 'भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व संबंधी दिशा–निर्देश और कॉरपोरेट संरचना' पर आयोजित वर्चुअल पैनल परिचर्चा के दौरान 'भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व संबंधी दिशा–निर्देश और कॉरपोरेट संरचना' पर प्रस्तुति दी।
- 27 दिसंबर 2020 को भारतीय आर्थिक संघ द्वारा आयोजित आईईए (ऑनलाइन) के 103वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विशेष भाषण दिया।

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

- 23 दिसंबर 2020 को विजनाना भारती (विभा) के सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित छठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) में 'जी20, ब्रिक्स और एससीओ की भारतीय अध्यक्षता के दौरान कूटनीति के लिए विज्ञान एजेंडा तय करना' विषय पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।

- 23 दिसंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा 'भारत के एफटीए (प्रदर्शन, वार्ताओं की स्थिति और आगे की राह)' विषय पर आयोजित बैठक में भाग लिया।

- 19 दिसंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से माननीया वित्त मंत्री के साथ आयोजित अर्थशास्त्रियों की बजट पूर्व परामर्श बैठक में भाग लिया।

- 15 दिसंबर 2020 को एसडीपीआई, यूएन एस्कैप और एसडीजी पर दक्षिण एशिया नेटवर्क द्वारा 'कोविड–19 काल में सतत विकास' विषय पर आयोजित 23वें सतत विकास सम्मेलन के दौरान 'एसडीजी की प्राप्ति में तेजी लाना और दक्षिण एशिया में कोविड–19 महामारी से बेहतर ढंग से आर्थिक बहाली' पर पैनल की वर्चुअल बैठक को संबोधित किया।

- 8 दिसंबर 2020 को दक्षिणीय वैश्विक विचारकः एसएससी के लिए थिंक टैंक नेटवर्क के वैश्विक गठबंधन के लिए यूएनओएसएससी द्वारा आयोजित संचालन समिति की चौथी बैठक में भाग लिया और दक्षिणी थिंक टैंकों के नेटवर्क (नेस्ट) पर अपने विचार व्यक्त किए।

- 4 दिसंबर 2020 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और माननीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में आयुष मंत्रालय के हितधारकों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

- 4 दिसंबर 2020 को 'व्यवधान से निपटनाः कोविड दौर में आर्थिक विकास पर नए सिरे से विचार करना' विषय पर एशिया–प्रशांत फोरम की बैठक में 'क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण' पर आयोजित सत्र को संबोधित किया।

- 3 दिसंबर 2020 को 'वैश्विक समाधान पहल – शहरीकरण (और अवसंरचना): कोविड–19 से सतत रूप से निपटना' विषय पर आयोजित सम्मेलन के दौरान ''बेहतर भविष्य का निर्माण करनाः एक नई सतत अर्थव्यवस्था की अवसंरचना, बदलते बहुपक्षीय क्रम में शहर' पर आयोजित समाधान सत्र में मुख्य वक्ता थे।

- 3 दिसंबर 2020 को 'दक्षिण एशिया में कोविड–19 से सतत और मजबूत आर्थिक बेहतरी को बढ़ावा देने पर एसडीजी' पर चौथे दक्षिण एशिया फोरम की वर्चुअल बैठक में भाग लिया और यूएन एस्कैप एवं मालदीव सरकार द्वारा 'वैश्विक, क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय साझेदारियों का उपयोग करना और दक्षिण एशिया में एसडीजी की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए कार्यान्वयन के साधनः वित्त, प्रौद्योगिकी, डेटा और सांख्यिकी (एसडीजी17)' पर संयुक्त रूप से आयोजित गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया।

- 25 नवंबर 2020 को यूएनडीपी की नई रणनीतिक योजना 2022–2025 पर यूएनडीपी के प्रशासक श्री अचिम स्टीनर के साथ परिचर्चा बैठक में भाग लिया।

- 24 नवंबर 2020 को 'भारत और – भविष्य का ध्यान करना – समकालीन वास्तविकताएं एवं उभरती संभावनाएं, तीसरी भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस –III) पहल' पर आईसीडब्ल्यूए के वेबिनार में भाग लिया और ''एजेंडा 2063 एवं भारत अफ्रीका विकास साझेदारी को परखना' विषय पर आयोजित सत्र ıv को संबोधित किया।

- 24 नवंबर 2020 को विकास केंद्र, ओईसीडी द्वारा ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भविष्य' विषय पर आयोजित विशेषज्ञों के कार्यदल के ऑनलाइन प्रथम विचार मंथन सत्र में भाग लिया।

- 10 नवंबर 2020 को आयोजित विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर जापान–भारत समिति की 10वीं बैठक के दौरान 'एसडीजी के लिए एसटीआई में भारत–जापान सहयोग' विषय पर एक प्रस्तुति दी।

- 5 नवंबर 2020 को जर्मन विकास संस्थान द्वारा बीएमजेड स्थिति पत्र 'ग्लोबल पार्टनर्स' के लिए एमजीजी चिंतन समूह पर आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला में भाग लिया।

- 28 अक्टूबर 2020 को सीआईडीजीए / सीआईडीआरएन द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग ज्ञान, शासन और प्रथा' विषय पर आयोजित वेबिनार के दौरान 'अंतर्राष्ट्रीय विकास संरचना के पुनर्निर्माण में दक्षिणीय सहयोग और त्रिपक्षीय सहयोग की भूमिका' विषय पर खुली परिचर्चा में भाग लिया।

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

- 23 अक्टूबर 2020 को ब्रिक्स अनुसंधान पर राष्ट्रीय समिति, रूस और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा ब्रिक्स अकादमिक फोरम में आयोजित सम्मेलन के दौरान 'विकास के लिए बेहतरीन और सुदृढ़ बुनियादी ढांचा – भारत का हालिया अनुभव' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 22 अक्टूबर 2020 को आईसीडब्ल्यूए द्वारा भारत गणराज्य के आईसीडब्ल्यूए एवं आरआईएस और कोरिया गणराज्य के केएनडीए एवं कीप के बीच द्विपक्षीय संवाद से जुड़े एमओयू पर आयोजित हस्ताक्षर समारोह के दौरान विशेष भाषण दिया।
- 15 अक्टूबर 2020 को आईसीएसएसआर द्वारा 'भारत और फिलीपींस के कोविड–19 से निपटने के तरीकों को परखना' विषय पर आयोजित वेबिनार के दौरान 'कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए भारत के नीतिगत उपाय' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 8 अक्टूबर 2020 को ब्रिक्स इंटरनेशनल स्कूल, ब्रिक्स अनुसंधान पर राष्ट्रीय समिति, रूस और ब्रिक्स रूस 2020 द्वारा ब्रिक्स इंटरनेशनल स्कूल 2020 – ब्रिक्स युवा मार्गदर्शकों के लिए प्रतियोगिता के दौरान 'महामारी काल के बाद वैश्विक शासन और ब्रिक्स सहयोग के लिए निहितार्थ' विषय पर आयोजित सत्र में एक प्रस्तुति दी।
- 6 अक्टूबर, 2020 को इस्टिट्यूटो अफरी इंटरनेशनली (आईएआई) द्वारा 'जी20 की इतालवी अध्यक्षता की ओर: कोविड–19 काल के बाद जी20 एजेंडे के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को फिर से तय करना' विषय पर आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता थे।
- 18 अप्रैल 2020 को जी–20 सतत को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना व डिजिटल ग्लोबल व वैश्विक तालिका पर चर्चा की गई।
- 15 अप्रैल 2020 ए एस सी एस टी ए के द्वारा एक बैठक में सी आई आई के द्व ारा कोविड–19 में होने वाले प्रभाव और अफ्रीका से संबंधित व्यापार पर होने वाले प्रभावों पर एक प्रस्तुति दी गई।
- 16 अप्रैल 2020 को सियोल मैं यू एन डी पी द्वारा कोविड–19 के संभावित प्रभाव व वर्तमान संकट व विकास सहयोग संबंध में एक वेबीनार की प्रस्तुति की गई।
- 7 अप्रैल 2020 को विनिमय केंद्र नई दिल्ली के द्वारा चीन में क्विड उत्पत्ति प्रसार और निहितार्थ विचारों पर एक वक्तव्य पेश किया गया।।
- 4 अप्रैल 2020 को दिल्ली में आर्थिक नीति अनुसंधान सीईपीआर और एसजेएम के द्वारा नियमों को की भूमिका पर गोलमेज सम्मेलन का + 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में सेंटर फॉर संयुक्त आर्थिक नीति अनुसंध ान के द्वारा आयोजित किया गया।

प्रोफेसर एस.के. मोहंती

- 22 फरवरी 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 'भारत दक्षिण एशिया अध्ययनः ईरान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंध' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 11 फरवरी 2021 को इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा आयोजित इंडिया एक्जिम बैंक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान वार्षिक (आईईआरए) पुरस्कार 2020 के एक ज्यूरी सदस्य के रूप में पुरस्कार हेतु सर्वश्रेष्ठ सार के चयन के लिए आईईआरए पुरस्कार समिति 2020 की पहली वर्चुअल बैठक में भाग लिया।
- 9 फरवरी 2021 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सहयोगात्मक पाठ्यक्रमः अंतर्राष्ट्रीय सुव्यवस्थित अध्ययन – सत्र 1ए एवं 1बी में भाग लिया और 'आईओआर में भारत के बढ़ते आर्थिक हित' पर प्रस्तुति दी।
- 9 फरवरी 2021 को सानेम, एआईसी, सावटी, पाथफाइंडर और चुला चुलालॉन्गकॉर्न विश्वविद्यालय, थाईलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'बंगाल की खाड़ी आर्थिक संवाद 2021: बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कोविड–19 के बाद की चुनौतियां (बीओबीईडी 2021)' में भाग लिया और 'शोध पत्र प्रस्तुति सत्रः व्यापार' की अध्यक्षता की।
- 27 दिसंबर 2020 को आयोजित 103वें ऑनलाइन वार्षिक सम्मेलन में भारतीय आर्थिक संघ (आईईए) में 'आर्थिक बेहतरीः प्रमुख क्षेत्रों में स्थिति और चुनौतियां' विषय पर आयोजित सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया और परिचर्चा में भाग लिया।
- 23 दिसंबर 2020 को नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा 'भारत के एफटीए (प्रदर्शन, वार्ताओं की स्थिति और आगे की राह)' विषय पर आयोजित बैठक में भाग लिया और 'भारत के एफटीए की प्रभावकारिताः बहस में शामिल होना' विषय पर एक प्रस्तुति दी।

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

- 16 दिसंबर 2020 को अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग का अनुसंधान संस्थान (आरआईईटीआई), मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, भारत द्वारा आयोजित एमपी–आईडीएसए–आरआईईटीआई वेब सेमिनार में एक मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया और 'भारत के बदलते आयाम – जीवीसी क्षेत्र में व्यापार और निवेश की जापान आर्थिक संबंध संभावना' विषय पर एक प्रस्तुति दी।

- 27 नवंबर 2020 को बर्टेल्समैन स्टिफ्टंग, जर्मन वैश्विक एवं क्षेत्र अध्ययन संस्थान (जीआईजीए), अंतर्राष्ट्रीय व सुरक्षा मामलों के लिए जर्मन संस्थान (एसडब्ल्यूपी) और जर्मन संघीय विदेश कार्यालय द्वारा विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए), आरआईएस एवं भारत के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित भारत–जर्मनी 1.5 ट्रैक संवाद, 2020 में भाग लिया और भारत एवं जर्मनी के बीच आर्थिक साझेदारी के बदलते आयामों पर एक प्रस्तुति दी।

- 18 नवंबर 2020 को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भारत–चीन वेबिनार में भाग लिया और 'भारत एवं चीन आर्थिक संबंधः दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ चीन के बढ़ते जुड़ाव' विषय पर व्याख्यान दिया।

- 26 अक्टूबर 2020 को हिंद महासागर अध्ययन सोसायटी (एसआईओएस) द्वारा 'बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों का सामरिक उपरांत दृष्टिकोण' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भाग लिया।

- 15 अक्टूबर 2020 को ब्लू इकोनॉमी पर संस्थागत सहयोग के बारे में समुद्री अनुसंधान केंद्र (एमआरसी), पुणे के साथ आयोजित संवादात्मक सत्र में भाग लिया।

- 12 अक्टूबर 2020 को ब्लू इकोनॉमी फोरम द्वारा हिंद महासागर अध्ययन केंद्र, मॉरीशस विश्वविद्यालय के सहयोग से 'हिंद महासागर क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी के लिए अवसर एवं चुनौतियां' विषय पर आयोजित पैनल परिचर्चा में विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया और ब्लू इकोनॉमी पर एक प्रस्तुति दी।

श्री राजीव खेर

विशिष्ट फेलो

- 24 मार्च 2021 को अनंत एस्पेन सेंटर द्वारा 'आरसीईपी–ईयू–चीन–भारत' पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

- 24 मार्च 2021 को आईसीआरआईईआर द्वारा 'व्यापार नीति और व्यापार में सुविधा के लिए सुधारः एक अधूरा एजेंडा' पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।

- 17 मार्च 2021 को ट्रू नॉर्थ जर्नीज 2021 में भाग लिया।

- 16 मार्च 2021 को नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित आईपीआरएस 2.0 के लिए गठित संचालन समिति की चौथी बैठक में भाग लिया।

- 12 मार्च 2021 को कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'डेटा गवर्नेंस का भविष्य–विशेषज्ञों की राय सुनें' पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।

- 9 मार्च 2021 को कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'समावेशी आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना' पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।

- 6 मार्च 2021 को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 'डिजिटल युग में रणनीतिक विनिर्माण' पर आयोजित सीआईआई–एसआर की वार्षिक क्षेत्रीय बैठक 2020–21 और उद्योग पुनर्गठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

- 22 और 27 जनवरी – 1 फरवरी एवं 6 मार्च 2021 को भारतीय लेखाकार संस्थान द्वारा आयोजित अनुशासनात्मक समिति – पीठ– ए की बैठक में भाग लिया।

- 5 मार्च 2021 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा 'तीन कृषि कानून और जमीनी हकीकत – भूमि से बाजार तक' पर आयोजित चर्चा में भाग लिया।

- 3 मार्च 2021 को विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित हिंद–प्रशांत विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।

- 3 मार्च 2021 को पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स द्वारा 'सेवाओं के व्यापार में अधिक खुलापन किस तरह से मजबूत आर्थिक बेहतरी में व्यापक सहयोग दे सकता है?' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।

- 26 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा "पड़ोसी पहलेः म्यांमार में तख्तापलटः भारत के लिए निहितार्थ" विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।

- 25 फरवरी 2021 को गुवाहाटी में आईसीआरआईईआर द्वारा 'भारत की

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

एक्ट ईस्ट नीति को सुगम बनानाः भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एलसीएस में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में कमी का आकलन करना' विषय पर आयोजित कार्यशाला में विशेष भाषण दिया।

- 23 फरवरी 2021 को पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल द्वारा 'आगामी नई विदेश व्यापार नीति 2021–26 से उद्योग की उम्मीदें' विषय पर आयोजित वेबिनार में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया।
- 18 फरवरी 2021 को वाशिंगटन डीसी में इंडो अमेरिकन इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईएआईसीसी) के सहयोग से फिक्की द्वारा 'भारत–अमेरिका संबंधों की पुनर्कल्पनाः मोदी–बाइडन–हैरिस युग' पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 17 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'समावेशी आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 9 फरवरी 2021 को सीआईआई द्वारा 'भारत–चीन आर्थिक संबंधः भविष्य के रुझान' विषय पर आयोजित सत्र में भाग लिया।
- 4 फरवरी 2021 को आईसीएआई द्वारा पंजीकृत मूल्यांकक संगठन (आईसीएआई आरवीओ) की संचालन परिषद में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 29 जनवरी 2021 को विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'हिंद–प्रशांत विशेषज्ञ समूह' की बैठक में भाग लिया।
- 29 जनवरी 2021 को 'सीआईआई की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति परिषद' की बैठक में भाग लिया।
- 28 जनवरी 2021 को फिक्की द्वारा कोनराड एडेनॉयर स्टिफ्टुंग (केएएस), ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) एवं राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (एनएमएफ) के सहयोग से 'नीली अर्थव्यवस्थाः उभरते क्षेत्र और नई प्रौद्योगिकियां' विषय पर आयोजित परिचर्चा में भाग लिया।
- 27 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'समावेशी आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 22 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 'चीन पर सीआईआई के कोर ग्रुप' के एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में एयरटेल बैंक द्वारा 'बैंक की प्रगतिशील रणनीति और वित्तीय स्थिति' विषय पर आयोजित परिचर्चा में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 9 एवं 16 अक्टूबर 2020, 9 और 29 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की अनुशासनात्मक समिति (बेंच II) की बैठक में भाग लिया।
- 16 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'बीबीआईएन देशों में लॉजिस्टिक्स कार्य–प्रदर्शन में व्यापक बदलाव लाने' पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 9 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में कट्स इंटरनेशनल द्वारा ''आरसीईपी में भारत को क्यों 'शामिल होना चाहिए या नहीं शामिल होना चाहिए' – फायदा और नुकसान'' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 9 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान द्वारा 'कॉरपोरेट गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय लाभ स्थानांतरणः भारत से साक्ष्य' विषय पर आयोजित निदेशक संगोष्ठी पावर टॉक सीरीज 3 में भाग लिया।
- 8 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित 'आईपीआरएस 2.0 के लिए गठित संचालन समिति की दूसरी बैठक' में भाग लिया।
- 3 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित आईपी विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।
- 3 दिसंबर 2020 को आयोजित ट्रू नॉर्थः वार्षिक एलपी सम्मेलन 2020 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 30 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में जी20ः रियाद शिखर सम्मेलन, 2020 पर आयोजित आईसीआरआईईआर संगोष्ठी सीरीज में भाग लिया।
- 25 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा 'भारत में कृषि–पोषण में जुड़ाव नहींः नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से एक नजर' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 19 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में कलिंग इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा 'अमेरिकी चुनावों की व्याख्या करनाः भारत, क्षेत्र और विश्व के लिए

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

निहितार्थ' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।

- 18 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की हामीदारी में डब्ल्यूटीओ की व्यापक भूमिका' विषय पर आयोजित पास्कल लैमी के साथ प्रदीप मेहता के वार्तालाप में भाग लिया।
- 17 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र (नई दिल्ली) द्वारा दक्षिण केंद्र (जिनेवा), थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क (जिनेवा), नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, केप टाउन विश्वविद्यालय (दक्षिण अफ्रीका), व्यापार व औद्योगिक नीति रणनीतियां (टिप्स), दक्षिण अफ्रीका, और व्यापार प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (कंबोडिया) के साथ साझेदारी में 'विकास व समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करना' विषय पर आयोजित वेबिनारों की एक श्रृंखला में भाग लिया।
- 6 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में गुडइयर इंडिया लिमिटेड की बोर्ड और समिति की बैठकों में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 2 नवंबर 2020 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा आयोजित ऑडिट कमेटी, स्वतंत्र निदेशकों की बैठक, ग्राहक सेवा समिति, आईटी रणनीति समिति और निदेशक मंडल की बैठकों में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 30 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में चीन पर आयोजित सीआईआई के कोर ग्रुप की बैठक में भाग लिया।
- 28 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में सीआरबी द्वारा 'बेहतर ढंग से आर्थिक बहाली के लिए अनुकूल माहौल बनाना– सरकार से गवर्नेंस तक' विषय पर आयोजित प्रथम उच्च स्तरीय पैनल की बैठक में एक संचालक के रूप में भाग लिया।
- 23 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित हिंद– प्रशांत विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।
- 20 अक्टूबर 2020 को डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क, जिनेवा; नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, केप टाउन विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका; व्यापार व औद्योगिक नीति रणनीतियां (टिप्स), दक्षिण अफ्रीका; और व्यापार प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कंबोडिया के सहयोग से 'प्रौद्योगिकी में बढ़त के पीछे सरकार की अदृश्य शक्तिः डब्ल्यूटीओ क्या कर सकता है?' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 16 अक्टूबर 2020 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और निदेशक मंडल की बैठकों में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- .5 जून और 25 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में निर्दलीय के रूप में भाग लिया किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड मैं निर्देशक मंडल की बैठक का आयोजन किया।
- .10 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में निर्दलीय के रूप में भाग लिया। वर्चुअल में निर्देश कोको कोला की संवाद श्रृंखला सीरीज 1 भारतीयों द्वारा आयोजित ऑपरेटिक मामलों के संस्थान आईआईसीए और आई ओ डी के सहयोग से आयोजित किया।
- .9 सितंबर 2020 को आयोजित नई दिल्ली में विदेश व्यापार ने क्रॉस सीमा सब्सिडी और विश्व व्यापार संगठन यूरोपीय संघ में टूल किट का विश्लेषण पर भारतीय संघ शान द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लिया।
- .22 मई 12 जून 11 अगस्त और 4 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में जी आई एल की बैठक और बोर्ड बैठक का लेखा परीक्षा सीमित में भाग लिया।
- विकास और समावेश सेंटर फॉर रिसर्च द्वारा आयोजित विपक्ष के सुदृढ़ीकरण पर व्यापार प्रणाली विकास पर दो–तीन सितंबर 2020 को नई दिल्ली में आयोजित रे बिना श्रृंखला में भाग लिया।
- .3 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में आयोजित पुनरुत्थान का अनिवार्य बहू पक्ष वाद वेबीनार में भाग लिया गया।
- .13 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में आयोजित गुड ईयर की बैठक में वार्षिक समन्वय में निर्दलीय निर्देशक के रूप में भाग लिया।
- .12 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड द्वारा आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठक में निर्दलीय निर्देशक के रूप में भाग लिया।
- .12 अगस्त को नई दिल्ली में भारत चीन आर्थिक भविष्य का भविष्य संबंध डी–कपलिंग की और कम निर्भरता या एक नया संतुलन चीनी अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित वेबीनार में भाग लिया।

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

- .7 अगस्त 2020 को नई दिल्ली सत्र में जोखिम प्रबंधन में एयरटेल द्वारा आयोजित समिति पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में निर्दलीय निर्देशक के रूप भाग लिया।
- .5 अगस्त 2020 को यूसी आईपीपी आईडी संचालन समिति द्वारा आयोजित छठे बैठक सत्र में भाग लिया।
- .22 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में भारतीय परिषद द्वारा आयोजित व्यापार नीति परिषद 2020–21 की पहली बैठक में भाग लिया।
- .9 जुलाई 2020 को नई दिल्ली नीति वकालत की स्थापना बैठक में भाग लिया।
- .26 जून 2020 को एयरटेल द्वारा आयोजित निर्देशकों की पेमेंट बैंक लिमिटेड बोर्ड की बैठक में भाग लिया।
- .25 जून 2020 को नई दिल्ली में आयोजित विश्व मामले" क्या वैश्वीकरण वास्तव में मर चुका है" भारतीय परिषद द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लिया।
- .22 जून 2020 को मुंबई में राजीव डोगरा द्वारा आयोजित ट्रू नॉर्थ मैनेजर एलएलपी मैं भी राजनीतिक सुरक्षा चिंताएं भारत के सत्र निर्देशक के रूप में भाग लिया।
- .10 जून 2020 को नई दिल्ली में आयोजित 2020 को अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन के बिना एक दुनिया में क्या होगा विषय पर सेमिनार में भाग लिया।
- .28 मई 2020 को भारतीय उद्योग परिषद दिल्ली में आयोजित एशिया प्रशांत उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण का निर्यात अवसर बढ़ाने पर सत्र की अध्यक्षता की।
- .22 मई 2020 को दिल्ली में आयोजित गुड ईयर द्वारा आयोजित परिश्रमिक समृद्धि की बैठक में निर्दलीय नामांकन निर्देशक के रूप में भाग लिया।
- .21 मई 2020 को किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड द्वारा अर्थव्यवस्था और व्यापार पर कोविड–19 के प्रभाव विषय में बी सी जी के साथ सत्र में निर्दलीय रूप से भाग लिया।
- .21 मई 2020 को आई सी आर आई ई आर द्वारा भारत के लिए विनिर्माण रणनीति पर वेबीनार में भाग लिया।
- .20 मई 2020 को दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग आईसीसी द्वारा आयोजित विश्व व्यवस्था के लिए एक प्रति परीक्षण विषय पर वेबीनार में भाग लिया।
- .5 मई 2020 को नई दिल्ली में भारतीय परिषद द्वारा आयोजित भारत चीन संगठन @70 का पुनर्निर्माण मील का पत्थर भविष्य की कल्पना एवं विश्व मामलों पर वेबीनार में भाग लिया।
- भारत ने 1 और 6 मई व 11 और 22 मई व 11 जुलाई और 26 से 28 अगस्त को लेखाकार संस्थान द्वारा आयोजित द्वितीय पीठ समिति बैठक में भाग लिया।
- .1 मई 2020 को आई सी आर आई द्वारा आयोजित कोविड–19 का आर्थिक नतीजा व भारत आयोजन वेबीनार में भाग लिया।
- .28 और 30 अप्रैल को नई दिल्ली में एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा आयोजित इंडक्शन मीटिंग निर्देशक के रूप में भाग लिया।
- .29 अप्रैल 2020 को भारतीय परिषद द्वारा आयोजित विश्व मामले एवं वैश्विक संस्थाएं इमेजिंग पर भारत क्या भूमिका निभा सकता है विषय पर वेबीनार में भाग लिया।
- .23 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में आयोजित फार्मा पर आयुष मंत्रालय परियोजना पर चर्चा करने के लिए और वाणिज्य मंत्रालय परियोजना में इंटरएक्टिव सत्र में भाग लिया।
- .14 अप्रैल 19 जून और 10 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में चीन पर सीआईआई कोर ग्रुप की छठी बैठक में भाग लिया।

प्रो. टी. सी. जेम्स

विजिटिंग फेलो

- 19 अक्टूबर, 2020 को केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुथी में 'वर्तमान परिदृश्य में कृषि में आईपीआर–प्रासंगिकता' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 11 अक्टूबर, 2020 को सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, हैदराबाद द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में 'विकास के लिए बौद्धिक संपदा की बदलती गतिशीलता' विषय पर मुख्य भाषण दिया।
- .11 सितंबर 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देहरादून द्वारा आधारित कार्यशाला के दौरान टी आई एफ ए सी नई दिल्ली द्वारा आयोजित संकेत और पारंपारिक ज्ञान पर भौगोलिक व्याख्यान दिया।
- .29 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र नेशनल द्वारा आयोजित भारतीय परिदृश्य के लिए तहत संरक्षण उपयोगिता मॉडल पर गोल मेज वर्चुअल प्रेजेंटेशन दिया।

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

- .20 अगस्त 2020 को नेशनल लॉ स्कूल द्वारा आयोजित भौगोलिक संकेत को की कुंजी विषय पर चुनौतियां व संरक्षण पर भारत विश्वविद्यालय बेंगलुरु की सत्र की अध्यक्षता की।
- .17 अगस्त 2020 बीआईटी रांची द्वारा शैक्षणिक संस्थानों मैं कॉपीराइट मुद्दे पर वेबीनार प्रस्तुति दी।
- .15 जुलाई 2020 को आयुष मंत्रालय द्वारा जैव विविधता अधिनियम संशोधन बैठक में भाग लिया।
- .3 जुलाई 2020 को केरल राज्य फिल्म के साथ सहयोग विकास निगम द्वारा आयोजित जेब का दस्तावेज ई करण के लिए एक परियोजना, केरल की जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत एवं पश्चिम घाट विकास पर वेबीनार प्रस्तुति दी।
- .29 जून 2020 को कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए एक कदम दर कदम, प्रेस्टीज इंस्टिट्यूट ऑफ प्रबंधन और अनुसंधान इंदौर द्वारा वेब प्रस्तुति दी।
- .19 जून 2020 को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा सिक्लिंग इकोसिस्टम में संघीय आईपी और उसके महत्व पर वार्ता प्रस्तुत की।
- 26 अप्रैल 2020 को आईपीआर जागरूकता में हरित भविष्य के लिए इनोवेशन प्रमोशन फोरम पर मुख्य भाषण दिया।
- .26 अप्रैल 2020 को विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा महामारी और हरित नवाचार आईपीआर के सामाजिक पहलुओं की खोज पर प्रस्तुति दी।

डॉ. बी. बालाकृष्णन

विज्ञान कूटनीति फेलो

- 22 मार्च 2021 को नीतिगत अनुसंधान के लिए डीएसटी केंद्रों के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित डीएसटी विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लिया।
- 10 फरवरी 2021 को एवरिस्टर, पेरिस, फ्रांस द्वारा 'भारत की विज्ञान कूटनीति की महत्वाकांक्षाएं और उपलब्धियां' विषय पर आयोजित वेबिनार में वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 24 जनवरी 2021 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 'स्टिप' पर आयोजित विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया।
- 21 दिसंबर 2020 को कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस द्वारा 'भारत में जैव हिफाजत और जैव सुरक्षा' विषय पर आयोजित पैनल परिचर्चा में भाग लिया।
- 21 नवंबर 2020 को वैश्विक युवा अकादमी के दक्षिण एशिया विज्ञान कूटनीति कार्यदल द्वारा आयोजित कार्यशाला में 'विज्ञान कूटनीति– एक परिचय' विषय पर एक मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया।

डॉ. पी.के. आनंद

विजिटिंग फेलो

- 22 मार्च 2021 को आयोजित सह–लेखकों की टी20 टास्क फोर्स 6 की बैठक में भाग लिया, ताकि इस पर नीतिगत सार प्रस्तुत किया जा सके कि 'हम कैसे जानते हैं कि बचपन की नीतियों और प्रथाओं की निगरानी, आकलन एवं योजना बनाना प्रभावकारी एवं सुदृढ़ सामाजिक कल्याण प्रणालियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है' जिसमें 'प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा' शामिल है।
- 2 मार्च 2021 को एसडीजी 12, जो सतत उपभोग और उत्पादन के महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करता है, पर टेरी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सलाहकार गोलमेज संवाद में नीति और आकलन के मुद्दों पर एक चर्चाकर्ता के रूप में भाग लिया।
- 25 फरवरी 2021 को एसडीजी के लिए एसटीआई पर कामकाज को आगे बढ़ाने हेतु विचार–विमर्श के लिए भारत सरकार के डीएसटी में वैज्ञानिक सचिव के साथ बैठक में भाग लिया। परियोजना के तहत आरआईएस प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय का ज्ञान साझेदार है, क्योंकि भारत भी प्रौद्योगिकी सुविधा व्यवस्था पर पायलट कार्यक्रम में अनेक साझेदार देशों में से एक है।
- 10 फरवरी 2021 को आसियान में भारतीय राजदूत के साथ बैठक में भाग लिया, जिसमें आरआईएस टीम के एक सदस्य के रूप में आसियान–भारत सहयोग एवं इसके व्यापक संदर्भ से अवगत कराया और विचार–विमर्श किया।
- 31 अक्टूबर–1 नवंबर 2020 को थिंक टैंक20 (टी20) शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में और 30 नवंबर 2020 को आयोजित 'इटली को सुपुर्द करने के कार्यक्रम' में भाग लिया।
- 4 नवंबर 2020 को 'प्रारंभिक बचपन में देखभाल और निरंतरता' के मुद्दे पर अलग से आयोजित टी20 कार्यक्रम में एक वक्ता के रूप में भाग लिया।

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

- 22 अक्टूबर 2020 को टी20 सऊदी अरब द्वारा आयोजित सभी ग्यारह कार्यदलों की बैठकों में भाग लिया, जिसमें कार्यदल 10 की बैठक भी शामिल है और इस दौरान 'सतत और सुदृढ़ ऊर्जा, जल एवं खाद्य प्रणालियों के लिए एकीकृत संबंधित नीतियों' पर हमारे सह–लेखन वाले नीतिगत सार–पत्र को भी कवर किया गया।
- 1 अक्टूबर 2020 को प्रोफेसर मैथियस, प्रारंभिक बचपन शिक्षा की डेसमंड चेयर, डबलिन सिटी विश्वविद्यालय के साथ बाल देखभाल और शिक्षा से संबंधित मुद्दे पर वेबेक्स परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 24 सितंबर 2020 को कोविड–19 के मद्देनजर ब्रोकेड डिजिटलाइजेशन का चलन पर डब्ल्यू एस पी का वर्चुअल इवेंट टुवर्ड्स पर एक वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 17 सितंबर 2020 को सऊदी अरब में आयोजित टी20 बैठक में सभी 11 टास्क संगोष्ठी में भाग लिया।
- 29 जून 2020 को जापान के साथ सतत के लिए एसबीआई भागीदारी संबंधित 30 जून 2020 के दिन उभरे मुख्य बिंदुओं पर प्रस्तुति दी।
- 9 जून 2020 को राष्ट्रीय नेटवर्क नेपाल द्वारा नेपाल के स्वैच्छिक लोगों की रिपोर्ट एसडीजी 2020 की समीक्षा पर वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया।
- 3 जून 2020 को सऊदी अरब में टी20 टास्क फोर्स द्वारा आयोजित कोविड–19 वर्ल्ड एक पोस्ट में सतत संसाधन वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया।

श्री कृष्ण कुमार

विजिटिंग फेलो

- 10 फरवरी 2021 को आसियान में भारतीय राजदूत के साथ बैठक में भाग लिया, जिसमें आरआईएस टीम के एक सदस्य के रूप में आसियान–भारत सहयोग एवं इसके व्यापक संदर्भ से अवगत कराया और विचार–विमर्श किया।
- 31 अक्टूबर–1 नवंबर 2020 को थिंक टैंक20 (टी20) शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में और 30 नवंबर 2020 को आयोजित 'इटली को सुपुर्द करने के कार्यक्रम' में भाग लिया।
- 22 अक्टूबर 2020 को टी20 सऊदी अरब द्वारा आयोजित सभी ग्यारह कार्यदलों की बैठकों में भाग लिया, जिसमें कार्यदल 10 की बैठक भी शामिल है और इस दौरान 'सतत और सुदृढ़ ऊर्जा, जल एवं खाद्य प्रणालियों के लिए एकीकृत संबंधित नीतियों' पर हमारे सह–लेखन वाले नीतिगत सार–पत्र को भी कवर किया गया।
- 1 अक्टूबर 2020 को प्रोफेसर मैथियस, प्रारंभिक बचपन शिक्षा की डेसमंड चेयर, डबलिन सिटी विश्वविद्यालय के साथ बाल देखभाल और शिक्षा से संबंधित मुद्दे पर वेबेक्स परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 24 सितंबर 2020 को कोविड–19 के मध्य नजर ब्रोकरेज डिजिटल लाइजेशन का डब्ल्यूएफपी का वर्चुअल इवेंट पर दक्षिण की दिशा में प्रभाव संगोष्ठी में वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 17 सितंबर 2020 को सऊदी अरब में टी20 की 11वीं टास्क फोर्स की बैठक में भाग लिया
- 9 जून 2020 को नेपाल में आयोजित एसडीजी 2020 की समीक्षा में नेपाल के लोगों की स्वैच्छिक रिपोर्ट राष्ट्रीय नेटवर्क वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया।
- 3 जून 2020 को सऊदी अरब में टी20 दसवीं टास्क फोर्स संगोष्ठी में कोविड–19 का सतत संसाधन संसाधन वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया।

डॉ. सब्यसाची साहा

सहायक प्रोफेसर

- 26 अक्टूबर 2020 को विधि संकाय (एफडीयूएसपी) और अंतर्राष्ट्रीय एवं तुलनात्मक कानून विभाग (डीआईएन) द्वारा आयोजित साओ पाओलो विश्वविद्यालय (यूएसपी) के चतुर्थ ब्रिक्स सम्मेलन में 'ब्रिक्स देशों पर कोविड–19 का आर्थिक प्रभाव' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 4 जुलाई 2020 को आर आई एस और नेत्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्थानीयकरण पर उत्तर पूर्व श्रृंखला वेबीनार सत्र का उद्घाटन किया।
- एस टी आई टी 2020 विज्ञान की और प्रौद्योगिकी या नवाचार नीति पर सस्टेनेबल समूह मैं एक सदस्य के रूप में भाग लिया।

डॉ. प्रियदर्शी दाश

सहायक प्रोफेसर

- 31 अक्टूबर, 2020 को सोका विश्वविद्यालय, जापान स्थित दक्षिण एशिया अनुसंधान केंद्र द्वारा 'अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जापान–दक्षिण एशिया संबंध' विषय पर आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'फिनटेक और वैश्विक व्यापार

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

का बदलता परिदृश्य' विषय पर एक प्रस्तुति दी।

- 28 अक्टूबर, 2020 को वाणी–एफआईडीसी–हेनरिक बॉल स्टिफटंग द्वारा 'जी20 में भारत के नीतिगत निर्देश के लिए रणनीति तैयार करना' विषय पर आयोजित वेबिनार में अपने विचार व्यक्त किए।
- 13 अक्टूबर, 2020 को ब्रिक्स अकादमिक फोरम में 'विकास के लिए बेहतरीन और सुदृढ़ बुनियादी ढांचा – भारत का हालिया अनुभव' विषय पर प्रस्तुति दी।
- 25 सितंबर 2020 को आई. डी .आई. जेट्रो बैंकॉक रिसर्च केंद्र द्वारा कोविड–19 पर कार्यशाला श्रृंखला, ब्रिक्स और जी20 आर आई एन के अनुभव और महामारी नीति विकल्प पर प्रस्तुति दी।
- 4 जून 2020 को एशिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित संकट में अवसर के रूप में हरित ऊर्जा विषय पर एक पैनलिस्ट के रूप में वेबीनार में शामिल हुए।

लोकप्रिय लेख

चतुर्वेदी, सचिन 2020। 'बाहरी फंडों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें क्योंकि कर्ज बढ़ता रहता है', द डेली स्टार, 28 अक्टूबर, 2020।

चतुर्वेदी, सचिन 2020। 'क्या जो बिडेन व्यापार में ट्रम्पवाद को हरा पाएंगे?, द इकोनॉमिक टाइम्स, 21 दिसंबर 2020।

चतुर्वेदी, सचिन 2020। 'होल्डिंग कॉस प्रमोटरों को बैंकों से अलग करेगा – नियामक वास्तुकला को पतला करने का कोई प्रयास नहीं', द टाइम्स ऑफ इंडिया, 30 नवंबर 2020।

चतुर्वेदी, सचिन। 2020 भारत–अमेरिका साझेदारी की उभरती गतिशीलता–कोविड के समय में सहयोग को गहरा करना, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 11 अप्रैल।

चतुर्वेदी, सचिन। 2020 संरचनात्मक और कार्यात्मक संरचनात्मक और कार्य सम्बन्धी सुधारों के लि, उभरती रणानीति, आज समाज (हिंदी), 20 मई 2020 के लिए उभरती रणनीति।

चतुर्वेदी, सचिन। 2020 भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई पर ध्यान दें, मनीकंट्रोल, 17 जून।

चतुर्वेदी, सचिन। 2020 संकट से लाभ उठाने के अवसर तक, द स्टेट्समैन, 22 मई।

चतुर्वेदी, सचिन। 2020 अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध में कितना वास्तविक है?, मनीकंट्रोल, 20 जनवरी।

चतुर्वेदी, सचिन। 2020 इस दर में कटौती का प्रसारण बहुत तेज होना चाहिए। द इकोनॉमिक टाइम्स, 27 मार्च।

चतुर्वेदी, सचिन। 2020 क्या एफडीआई नीति में बदलाव भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक जरूरतों को पूरा करेगा?, मनीकंट्रोल, 24 अप्रैल।

चतुर्वेदी, सचिन। 2021। 'आर्थिक सर्वेक्षण ने स्थानीय उत्पादन, खपत को बढ़ावा देने के लिए मंच तैयार किया है', इंडियन एक्सप्रेस, 30 जनवरी।

चतुर्वेदी, सचिन। 2021। भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक नए आख्यान की आवश्यकता है, मनीकंट्रोल, 7 जनवरी 2021।

दे, प्रबीर. 2021। 'धैर्य कृपयारू भारत की आसियान यात्रा अभी बहुत आगे है' द मिंट, 25 फरवरी 2021, नई दिल्ली

खेर, राजीव 2020। 'क्या भारत की पीएलआई योजना घोड़े के आगे गाड़ी रखती है?' ब्लूमबर्ग, नवंबर 2020।

मोहंती, एस.के. 2020 'टका टॉक्स इन ए टेलर्ड सूट' एक्सपोर्ट्स, मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था और मैक्रोइकॉनॉमिक स्टेबिलिटी ने 2004 से बांग्लादेश के विकास को बढ़ावा दिया'। आउटलुक इंडिया मैगजीन, 28 दिसंबर।

पीटर, ऑगस्टीन। 2021. नए डब्बलयूटीओ डीजी की प्राथमिकताएँ होनी चाहिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 24 फरवरी।

15

आंकड़ें एवं सूचना केन्द्र

आरआईएस के डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ने हाल के महीनों में नवीनतम विशिष्ट प्रकाशनों, रिपोर्टों, डेटाबेस, ई–जर्नल्स एवं लेखों इत्यादि को हासिल किया है, ताकि आरआईएस की संकाय और आगंतुक विद्वानों को अद्यतन जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकें। यह कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विभिन्न प्रकाशनों या आलेखों के कार्यक्रम का आदान–प्रदान करता है और विभिन्न स्तरों पर विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर और भी अधिक प्रकाशनों या आलेखों तथा अध्ययन कार्यक्रमों को जोड़कर संसाधन आधार को निरंतर समृद्ध करता रहता है।

इस केंद्र के प्रमुख वैश्विक संस्थानों जैसे कि एफएओ, आईएलओ, ओईसीडी, यूएन, अंकटाड, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इत्यादि के साथ घनिष्ठ जुड़ाव हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य–पत्र (वर्किंग पेपर), परिचर्चा पत्र (डिस्कशन पेपर), री–प्रिंट्स, समसामयिक पत्र दरअसल प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में या तो परस्पर आदान–प्रदान किए गए कार्यक्रमों के जरिए प्राप्त होते हैं या संस्थागत वेबसाइटों के माध्यम से डाउनलोड किए जाते हैं। वर्तमान केंद्र में 24,590 से भी अधिक पुस्तकें हैं जिनमें सरकारी प्रकाशन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अन्य शोध संस्थानों के दस्तावेज शामिल हैं। इनके अलावा सजिल्द पुस्तक के रूप में 1850 पत्र–पत्रिकाएं हैं। इस केंद्र ने 434 से भी अधिक प्रिंट और ऑनलाइन पत्र–पत्रिकाओं की सदस्यता भी ले रखी है जिनमें जस्टर, आईएमएफ ई–लाइब्रेरी, एल्सवियर–साइंसडायरेक्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, विली इत्यादि शामिल हैं। इतना ही नहीं, इस केंद्र को प्रतिष्ठित स्रोतों से सम्मानार्थ भेंट के आधार पर लगभग 50 पत्र–पत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। 350 से भी अधिक सीडी रॉम और डेटाबेस हैं। एक और खास बात यह है कि 'डेलनेट' का सदस्य होने के नाते यह संसाधन–साझाकरण को बढ़ावा देता है।

इस केंद्र में आसान पहुंच के लिए इंट्रानेट के माध्यम से ऑनलाइन समृद्ध संग्रह उपलब्ध है।

अभिलेखन केंद्र/पुस्तकालय के संग्रह में ये शामिल हैं

- पुस्तकें
- सांख्यिकीय वार्षिकी
- दस्तावेज–डब्ल्यूपी–ओपी–डीपी
- जर्नल / पत्र–पत्रिकाएं (प्रिंट+ऑनलाइन+सीडी–रॉम)
- भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के समाचार पत्र

- पिछला संस्करण (बैक वॉल्यूम)
- सीडी–रॉम
- सीडी–रॉम में डेटाबेस
- आरआईएस डेटाबैंक

व्यापार, टैरिफ एवं गैर–टैरिफ उपायों, भुगतान संतुलन, वित्तीय सांख्यिकी, विकास सांख्यिकी, औद्योगिक सांख्यिकी, बौद्धिक संपदा सेवाओं और कॉरपोरेट डेटा एवं सूचना पर आरआईएस का वैश्विक डेटाबेस। भारतीय आंकड़े 8– अंकीय स्तर पर व्यापार संबंधी टाइम सीरीज डेटाबेस, भारतीय कंपनियों एवं उनके वित्तीय प्रदर्शन के डेटाबेस, सामाजिक–आर्थिक डेटाबेस और सीमा शुल्क टैरिफ आंकड़ों को कवर करता है।

आरआईएस का डेटा सर्वर

आरआईएस एक आधुनिक डेटा सर्वर का रख–रखाव बिल्कुल सही ढंग से कर रहा है जिसमें उसके आंकड़ो कोष की बढ़ी हुई सुरक्षा के तहत आंकड़ों को नष्ट करने वाले वाइरल या हैकिंग सहित किसी भी संभावित बाहरी हमले से बचाव की पुख्ता व्यवस्था की गई है। आरआईएस ने त्वरित संदर्भ के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टाइम सीरीज आंकड़ा हासिल किया है। इसने टैरिफ आंकड़ा कोष, भारतीय कंपनियों के डेटाबेस, व्यापार आंकड़ों की दिशा (डॉट्स), विश्व विकास संकेतकों (डब्ल्यूडीआई), इत्यादि के साथ इस पर महत्वपूर्ण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़ा (एचएस एंड एसआईटीसी) अपलोड किए हैं। सर्वर पर आंकड़ा कोष को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। यह संकाय के सदस्यों को तत्काल अद्यतन डेटा उपलब्ध कराता है जो उनके साक्ष्य–आधारित शोध अध्ययनों में गहराई से मदद करता है। यही नहीं, ऐसे में व्यक्तिगत आरआईएस संकाय सदस्यों के लिए महंगी बहु–वैश्विक डेटा प्रणालियों को खरीदने की जरूरत नहीं रह जाती है।

आरआईएस की वेबसाइट और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर

(www.ris.org.in)

आरआईएस की वेबसाइट को प्रतिदिन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली एवं यूजर (उपयोगकर्ता) अनुकूल सामग्री के साथ नवीनीकरण किया जाता है और यह नवीनतम सुविधाओं एवं कार्यों से सुसज्जित या लैस है। इसे आरआईएस की आंतरिक टीम द्वारा वास्तविक समय पर अपडेट किया जाता है, ताकि उसके आउटरीच कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में वैश्विक सार्वजनिक डोमेन में गहन अनुसंधान अध्ययनों और संबंधित घटनाक्रमों को उपलब्ध कराया जा सके। यह स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त, निवेश, विकास सहयोग, वैश्विक आर्थिक मुद्दों, क्षेत्रीय सहयोग, दक्षिणीय सहयोग, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित आरआईएस के कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों के बारे में व्यापक अद्यतन जानकारी प्रदान करती है। यह अनुसंधान रिपोर्टों, पत्र–पत्रिकाओं, सूचना–पत्र (न्यूजलेटर) और मीडिया लेखों के रूप में आरआईएस द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकाशनों की विस्तृत श्रृंखला की मुफ्त डाउनलोड सुविधा प्रदान करती है। इसमें आरआईएस द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं का विवरण भी है। चालू वित्त वर्ष (2020–21) के दौरान तीन नए उप–कार्य क्षेत्रों (सब–डोमेन) को आंतरिक तौर पर विकसित किया गया है और फिर उन्हें आरआईएस की वेबसाइट से लिंक कर दिया गया है, ताकि उनकी स्पष्ट और व्यापक पहुंच संभव हो सके। अब आरआईएस की मुख्य वेबसाइट के अंतर्गत ग्यारह उप–कार्य क्षेत्र (सब–डोमेन) हैं। इनमें ये शामिल हैं:

ब्रिक्स
http://bricscivil.ris.org.in

बिमस्टेक
http://bimstec.ris.org.in

एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
http://aagc.ris.org.in

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) पहल
http://iora.ris.org.in

सतत विकास लक्ष्यों पर आरआईएस का कार्यक्रम
http://sdg.ris.org.in

सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल
http://sti4sdg.ris.org.in

भारतीय विकास सहयोग के लिए फोरम
http://fidc.ris.org.in

एफआईएसडी
http://fisd.in

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर फोरम (एफआईटीएम)
http://fitm.ris.org.in

ब्लू इकोनॉमी फोरम
http://blueeconomyforum.ris.org.in

वैश्विक विकास केंद्र
http://gdc.ris.org.in

आसियान भारत केंद्र
http://aic.ris.org.in

न्यू एशिया फोरम
http://newasiaforum.ris.org.in

इसके अलावा, वेबसाइट पर निम्नलिखित वेबसाइट पेज भी हैं :

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
http://ris.org.in/asian-infrastructure-investment-bank

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम
http://ris.org.in/science-technology-and-innovation-policy-stip-forum-and-monthly-lecture-series-0

दिल्ली प्रोसेस
http://ris.org.in/delhi-process

गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर दस्तावेज
http://ris.org.in/documents-non-aligned-movement

समर स्कूल
http://ris.org.in/summer-school-0

पेरिस शांति फोरम
http://ris.org.in/deadline-extended-extra-time-submit-your-project-paris-peace-forum

आरआईएस की देख–रेख वाली अन्य वेबसाइटें

नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक–टैंक्स (नेस्ट)
http://southernthinktanks.org

इब्सा
http://ibsa-trilateral.org

दक्षिण एशिया नीतिगत अध्ययन केंद्र (एसएसीईपीएस)
http://saceps.org.in

चालू वित्त. वर्ष (2019–20) के दौरान आरआईएस की वेबसाइट ने 'हिट' की कुल संख्या में शानदार वृद्धि दर्ज की है। इसने गूगल द्वारा संचालित शीर्ष अनुसंधान परिणामों में से एक का दर्जा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है जो इसकी निरंतर बढ़ती दृश्यता को रेखांकित करता है। आरआईएस नियमित रूप से अपने त्रैमासिक ई–न्यूजलेटर और मासिक ई–पत्रिका को भी प्रकाशित करता है जिन्हें प्रमुख नीति–निर्माताओं एवं आकृतिकारों, थिंक टैंकों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, प्रमुख शिक्षाविदों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रख्यात हस्तियों के बीच दुनिया भर में प्रसारित किया जाता है, ताकि उन्हें विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले मुद्दों पर आरआईएस द्वारा किए जा रहे विश्वसनीय शोध कार्यों की विस्तृत विविधता से अवगत कराया जा सके।

सोशल मीडिया

आरआईएस ने ट्विटर, फेसबुक एवं यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंचो पर अपनी उपस्थिति काफी बढ़ा दी है और बड़ी संख्या में इसके अनुगामी भी हैं। आरआईएस के यूट्यूब चैनल को निरंतर अपडेट रखा जाता है। लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग वाले आयोजनों को इसकी प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराया जाता है। आरआईएस के यूट्यूब चैनल की दर्शक संख्या में अच्छी–खासी वृद्धि दर्ज की गई है तथा उसका ग्राहक आधार भी अब और ज्यादा बढ़ गया है।

आरआईएस फेसबुक और ट्विटर

4 हजार से भी अधिक अनुगामी हैं और इसके पेजों को लोगों की रायशुमारी के आधार पर 5 में से 4.3 रेटिंग दी गई है। ट्विटर हैंडल के 4 हजार से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वास्तविक समय पर लोगों की त्वरित पहुंच के लिए आरआईएस के प्रत्येक प्रमुख कार्यकलाप को इन दोनों ही प्लेटफॉर्मों पर तुरंत उपलब्ध कराया जाता है। यही नहीं, दर्शकों की ओर से मिली प्रतिक्रिया अत्यंत उत्साहजनक है।

आरआईएस की इंट्रानेट सुविधा

संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए इंट्रानेट सुविधा है जो कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से जुड़ी बातों के संबंध में पासवर्ड संरक्षित जानकारियां प्रदान करती है, जिनमें अवकाश का रिकॉर्ड, वेतन पर्ची (सैलरी स्लिप), चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति और अन्य विवरण शामिल होते हैं। यह अपने संकाय के लिए अनुसंधान डेटाबेस भी प्रदान करती है जो सीडी प्रारूप में उपलब्ध होता है और जो अन्य बातों के अलावा व्यापार आंकड़ों की दिशा, कस्टाडा, विश्व विकास संकेतकों, सरकारी वित्तीय आंकड़ों (आईएमएफ) एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आंकड़ों (आईएमएफ) को कवर करता है।

वित्त वर्ष 2020–21 में देशों द्वारा हिट्स

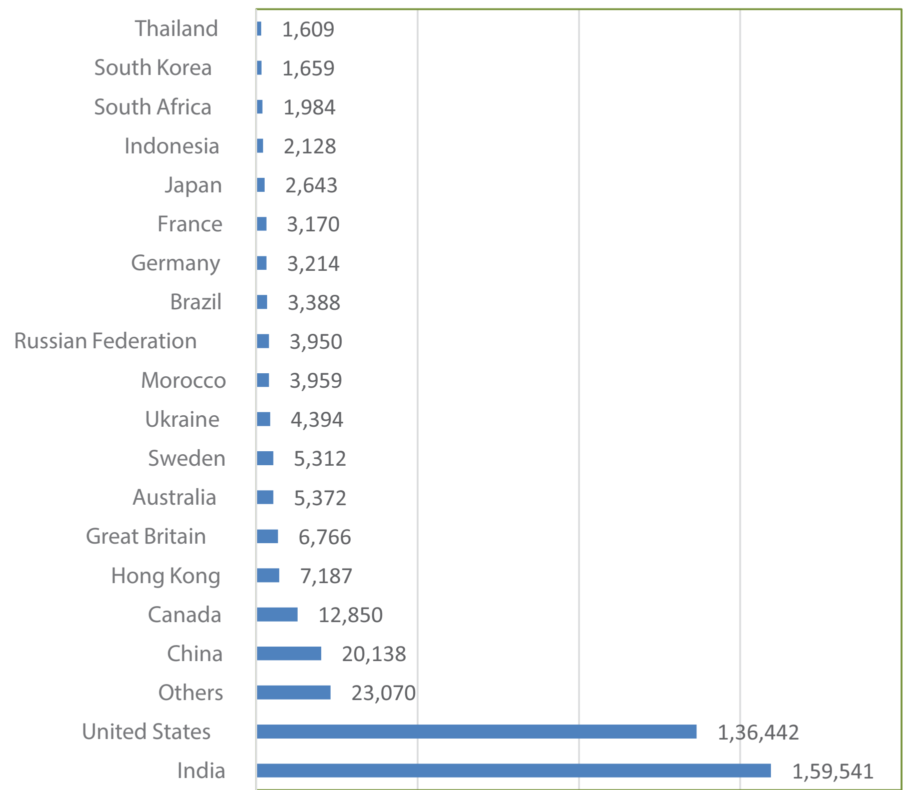

वित्त वर्ष 2019–20 में आरआईएस के सांख्यिकिय हिट्स

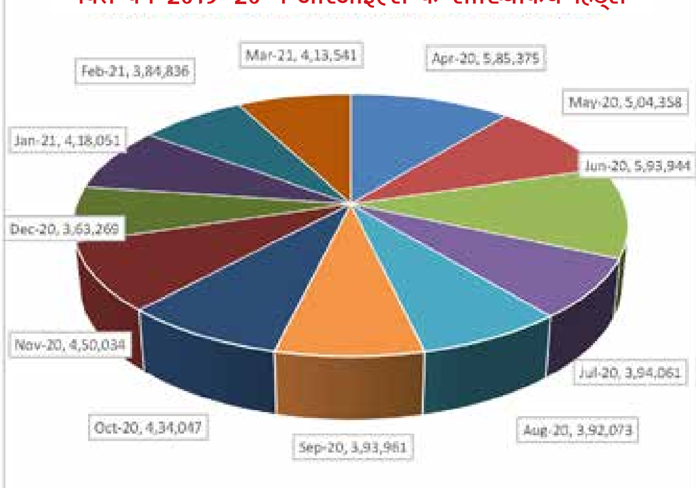

वित्त वर्ष 2019–20 में आरआईएस सब–डोमेन में हिट्स

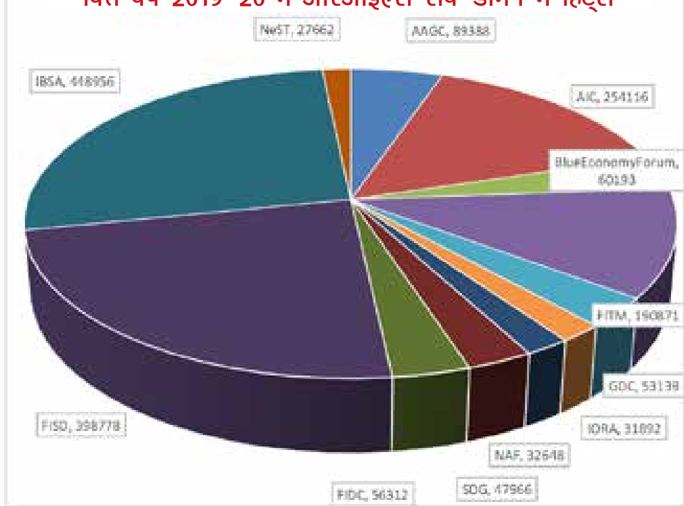

मानव संसाधन

प्रो. सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामले, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तत तथा विकास सहयोग

संकाय

डॉ एस के मोहंती

प्रोफेसर

विशेषज्ञता : वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तथा विकास संबंधी आर्थिक मामले

डॉ सब्यासाची साहा

सहायक प्रोफेसर

(31 जनवरी 2021 तक)

सह प्रोफेसर

(1 फरवरी 2021 से)

विशेषज्ञता : प्रोद्योगिकी एवं विकास, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार, आर्थिक विकास एवं विश्व व्यापार संगठन

डॉ प्रियदर्शी दाश

सहायक प्रोफेसर

(31 जनवरी 2021 तक)

सह प्रोफेसर

(1 फरवरी 2021 से)

विशेषज्ञता : अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त

डॉ पंकज वशिष्ठ

सह प्रोफेसर

(15 मार्च 2021 से)

विशेषज्ञताः व्यापार, प्रौद्योगिकी और श्रम बाजार

डॉ बीना पाण्डेय

अनुसंधान एसोसिएट

विशेषज्ञता : सामाजिक क्षेत्र, जेंडर सशक्तिकरण एवं विकास संबंधी मामले

डॉ. सुशील कुमार

सलाहकार

(31 जनवरी 2021 तक)

सहायक प्रोफेसर

(1 फरवरी 2021 से)

विशेषज्ञताः अतंर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त

डॉ. अमित कुमार

अनुसंधान सहयोगी

(31 जनवरी 2021 तक)

सहायक प्रोफेसर

(1 फरवरी 2021 से)

विशेषज्ञताः नवप्रवर्तन, दूरदर्शिता एवं नियंत्रण

सुश्री पंखुड़ी गौर

सहायक प्रोफेसर

(1 फरवरी 2021 से)

विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नीली अर्थव्यवस्था, एफटीए और मेगा क्षेत्रीय

विशिष्ट फैलो

श्री राजीव खेर

विशिष्ठ फैलो

विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य

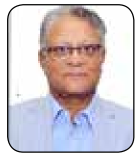

श्री अमर सिन्हा

विशिष्ठ फैलो

विशेषज्ञताः आर्थिक कूटनीति और दक्षिणीय सहयोग

प्रो. अमिताभ कुंडू

विशिष्ठ फैलो

(अप्रैल 2020 तक)

विशेषज्ञताः सतत विकास लक्ष्य एवं क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रभाव आंकलन पद्धति

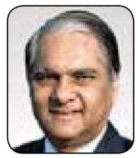

श्री आर वी साही

विशिष्ठ फैलो

(15 सितंबर 2020 से)

विजिटिंग फैलो/सलाहकार/अनुसंधान एसोसिएट

श्री भास्कर बालाकृष्णन

साइंस डिपलोमेसी फैलो

विशेषज्ञताः एसटीआई सहयोग एवं विज्ञान नीति

प्रो. टी सी जेम्स

विजिटिंग फैलो

विशेषज्ञताः बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी (आईपीआर)

प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती

विजिटिंग फैलो

विशेषज्ञताः सूक्ष्म–अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास सहयोग और मूल्यांकन

डॉ. पी के आनन्द

विजिटिंग फैलो

विशेषज्ञताः आर्थिक विकास और विकास

श्री कृष्ण कुमार

विजिटिंग फैलो

विशेषज्ञताः आधिकारिक सांख्यिकी एवं सतत विकास लक्ष्य

डॉ. के रवि श्रीनिवास

विजिटिंग फैलो

विशेषज्ञताः बौद्धिक संपदा अधिकार एवं वैश्विक व्यापार

श्री सुभोमॉय भट्टाचार्य

सलाहकार

विशेषज्ञताः सार्वजनिक नीति एवं ऊर्जा विशेषज्ञ

श्री अरुण सोमाचुदन नायर

सलाहकार

विशेषज्ञताः विदेशी व्यापार एवं निवेश

डॉ. ऑगस्टीन पीटर

विजिटिंग फैलो

विशेषज्ञताः व्यापार निवेश एवं प्रतिस्पर्धा नीती

विजिटिंग फैलो/सलाहकार/अनुसंधान एसोसिएट

डॉ नम्रता पाठक
अनुसंधान सहयोगी
विशेषज्ञताः पारंपरिक ज्ञान

डॉ आभा जैसवाल
विजिटिंग फैलो
(अप्रैल 2020 तक)
विशेषज्ञताः सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और प्रबंधन

डॉ कपिल पाटिल
अनुसंधान सहयोगी
विशेषज्ञताः एसटीआई सहयोग एवं विज्ञान नीति

Dr Sneha Sinha
Research Associate
Specialisation: Science and technology studies

डॉ दिनोज कुमार उपाध्याय
सलाहकार
(10 जनवरी 2021 से)
विशेषज्ञताः व्यापार, प्रौद्योगिकी और श्रम बाजार

डॉ दिनेश कुमार
अनुसंधान एसोसिएट
(28 फरवरी 2021 तक)
विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

डॉ तन्जीम हसनत
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय एवं वित्तीय अर्थशास्त्र

डॉ दीपिका चावला
अनुसंधान एसोसिएट
(28 फरवरी 2021 तक)
विशेषज्ञताः विकास अर्थशास्त्र एवं नवाचार अध्ययन

आसियन–भारत केंद्र

डॉ. प्रबीर डे
प्रोफेसर/समन्वयक, एआईसी
विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं परिवहन संबंधी सुविधाएं, सेवा क्षेत्र में व्यापार

सुश्री श्रेया पान
अनुसंधान सहायक
विशेषज्ञताः वैश्विक व्यापार

डॉ. दूराईराज कुमारासामी
सलाहकार *(31 मार्च 2021 तक)*
विशेषज्ञताः अतंर्राष्ट्रीय व्यापार, एवं विदेश निवेश एवं व्यवहारिक अर्थमित्ति

वैश्विक विकास पर पहल

सुश्री साधना रैलिया
जीडीसी फैलो
(1 दिसंबर 2020 से)

सुश्री रितुप्रना बैनर्जी
जीडीसी मैनेजर
(1 दिसंबर 2020 से)

श्री अमित अरोड़ा
जीडीसी मैनेजर
(1 दिसंबर 2020 से)

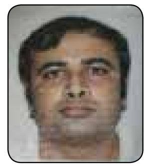

श्री अभिनव झा
अनुसंधान सहायक
(31 जनवरी 2021 तक)

अनुसंधान सहायक

सुश्री प्रतिवा शॉव
एम.ए. (इकोनोमिक्स)

सुश्री अदिति गुप्ता
एम.ए. (इकोनोमिक्स)

श्री अपूर्व भटनागर
एम.ए. (डेवलपमेंट इकोनोमिक्स)

श्री अंकुर जयसवाल
एम.एस.सी (इकोनोमिक्स)
(15 अप्रैल 2020 तक)

सुश्री चांदनी डवानी
एम.ए. (इकोनोमिक्स)

सुश्री सभ्या राय
एम.ए. (इकोनोमिक्स)
(7 मई 2021 तक)

सुश्री सुनन्दा महाजन
एम.ए. (इकोनोमिक्स)

सुश्री नीहारिका
एम.एस.सी (इकोनोमिक्स)
(28 जुलाई 2020 तक)

सुश्री सोनल गर्ग
एम.ए. (इकोनोमिक्स)
(16 अप्रैल 2021 तक)

श्री सिद्घार्थ नायडू
(17 नवंबर 2020 से)

सुश्री देबाजंना डे
(19 नवंबर 2020 से)

सहायक वरिष्ठ अध्येता

प्रोफेसर अनिल सुकलाल
उप महानिदेशक, एशिया और मध्य पूर्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग, दक्षिण अफ्रीका

प्रोफेसर हरिबाबू ईजनवरजला
पूर्व कुलपति प्रभारी, हैदराबाद विश्वविद्यालय

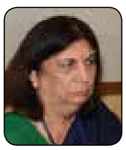

डॉ. बेनू श्नाइडर
पूर्व में संयुक्त राष्ट्र एवं अंकटाड के साथ और भारतीय रिजर्व बैंक में सलाहकार

प्रोफेसर अमृता नार्लीकर
अध्यक्ष, जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (गीगा)

प्रोफेसर मुकुल जी. अशर
प्रोफेसरियल फेलो, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

डॉ. बालाकृष्ण पिसुपति
चेयरपर्सन, फ्लेज और पूर्व अध्यक्ष, एनबीए, चेन्नई

डॉ. बिश्वजीत बनर्जी
मुख्य अर्थशास्त्री, वित्त मंत्रालय, स्लोवाक गणराज्य और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, अशोक विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा

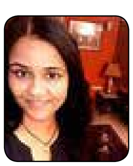

डॉ. मितु सेनगुप्ता
प्रोफेसर, राजनीति और प्रशासन विभाग, रायर्सन यूनिवर्सिटी, कनाडा, विजिटिंग प्रोफेसर काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट (सीएसडी)

प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल
आरबीआई के पूर्व चेयर प्रोफेसर, विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम

प्रोफेसर शाहिद अहमद
प्रोफेसर और प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया

प्रोफेसर श्रीविद्या राघवान
कानून के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा कॉलेज ऑफ लॉ, नॉर्मन, अमेरिका

डॉ. रामकिशन एस. राजन
वाइस–डीन (अनुसंधान) और प्रोफेसर, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

डॉ. सुमा अत्रे
प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस और रणनीति, ब्रुनेल बिजनेस स्कूल, यूके

डॉ. टी. पी. राजेंद्रन
पूर्व सहायक महानिदेशक, आईसीएआर और विजिटिंग फेलो, आरआईएस

प्रोफेसर केविन पी. गालाघेर
प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, बोस्टन यूनिवर्सिटी; सीनियर एसोसिएट, जीडीईई, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी

डॉ गणेशन विग्नराज
एडजंक्ट सीनियर फेलो
सीनियर रिसर्च एसोसिएट, ओवरसीज इंस्टीट्यूट (ODI), लंदन; अनिवासी सीनियर फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज (ISAS)

स्टाफ के अन्य सदस्य

श्री महेश सी अरोड़ा
निदेशक, वित्त एवं प्रशासन

महानिदेशक कार्यालय
श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रभारी, महानिदेशक कार्यालय
श्रे एन एन कृष्णन, निजी सचिव
श्रीमती रितु परनामी, निजी सचिव
सुश्री गोहर नाज, सचिवीय सहायक

प्रकाशन विभाग
श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रकाशन अधिकारी
श्री संजय शर्मा, (संपादकीय) सहायक
श्री सचिन सिंघल, प्रकाशन सहायक (वेब और डिजाइन)

आंकड़ा एवं सूचना केन्द्र
श्रीमती ज्योति, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
श्रीमती सुशीला, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

सूचना प्रौद्योगिकी/डॉटाबेस एकक
श्रीमती सुषमा भट्ट, उपनिदेशक, आंकड़ा प्रबंधन
श्री चन्द्र शेखर पुरी, उपनिदेशक, प्रणाली
श्रीमती पूनम मल्होत्रा, डाटा एंट्री आपॅरेटर
श्री सत्यपाल सिंह रावत, जूनियर सहायक
श्रीमती गीतिका शर्मा, डाटा एंट्री आपॅरेटर
श्री सौम्य रंजन, आईटी सहायक

वित्त एवं प्रशासन
श्री वी कृष्णामणि, उपनिदेशक (वित्त एवं लेखा) *(31 मई 2020 तक)*
प्रशासनिक सलाहकार *(1 जुन 2020 से)*
श्रीमती शीला मल्होत्रा, अनुभाग अधिकारी (लेखा)
श्रीमती अनु बिष्ट, सहायक
श्री सुरजीत, लेखाकार
श्री अनिल कुमार, सहायक
श्री पियूष वर्मा, अवर श्रेणी लिपिकं
श्रीमती शालिनी शर्मा, स्वागती

अनुसंधान सहयोग
सुश्री किरन वाघ, निजी सचिव
श्री संजीव शर्मा, निजी सचिव
श्री सुरेन्द्र कुमार, निजी सहायक
श्रीमती बिन्दु गंभीर, आशुलिपिक
श्री जे. श्रीनिवास राव, सहायक
श्री बैदनाथ पाण्डेय, कार्यालय सहायक

सहायक स्टाफ
श्री सत्यवीर सिंह, स्टाफ कार चालक
श्री जे बी ठाकुरी, स्टाफ कार चालक
श्री बलवान
श्री प्रदीप
श्री राजू
श्री राज कुमार
श्री मनीष कुमार
श्री राज कुमार
श्री सुधीर राणा
श्री बिरजू
श्री प्रदीप नेगी

वित्तीय विवरण

सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटैंट्स

8, सेकेंड फ्लोर, कृष्णा मार्केट, कालका जी, नई दिल्ली–110019

टेलीफोन : 32500444, टेलीफैक्सः 40590344, ई–मेलः skacamail@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली की आम सभा के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरण के ऑडिट पर रिपोर्ट

राय

हमने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, (निकाय), के तहत पंजीकृत एक सोसायटी 'विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली' के वित्तीय विवरण का ऑडिट किया है जिसमें 31 मार्च, 2020 तक की बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण तथा प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा–जोखा, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरण की अनुसूची शामिल हैं।

हमारी राय में, संलग्न वित्तीय विवरण इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक सोसायटी की वित्तीय स्थिति, उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन और प्राप्तियों एवं भुगतान की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी 'ऑडिटिंग पर मानकों (एसए)' के अनुसार अपना ऑडिट किया। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरण के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जवाबदेही' अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार इस निकाय से बिल्कुल पृथक हैं और हमने आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा यह मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है, वह हमारी राय को ठोस आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और बिल्कुल उपयुक्त है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और गवर्नेंस के प्रभारी की जवाबदेही

प्रबंधन पर ही इन वित्तीय विवरण को तैयार करने की जिम्मेदारी होती है जो भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सोसायटी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन की सही व निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं। इस जिम्मेदारी में ऐसे वित्तीय विवरण को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त या प्रासंगिक माने जाने वाले आंतरिक नियंत्रण का स्वरूप निर्धारित करना, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं जो सटीक एवं निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी तरह की तथ्य संबंधी गलतबयानी से मुक्त होते हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन ही 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत या चालू निकाय' के रूप में अपनी कंपनी या सोसायटी की क्षमता का आकलन करने के लिए जवाबदेह होता है। प्रबंधन इसके लिए 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत निकाय' से संबंधित उन तथ्यों का खुलासा करता है, जो मान्य या लागू होते हैं। प्रबंधन इसके साथ ही लेखांकन के 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत निकाय' से संबंधित आधार का उपयोग करता है, बशर्ते कि प्रबंधन या तो अपने निकाय का परिसमापन करने या उसका परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या परिचालन बंद न करने के लिए उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प हो।

गवर्नेंस के प्रभारी लोग संबंधित इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर करीबी नजर रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

वित्तीय विवरण के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जवाबदेही

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी तरह की तथ्य संबंधी गलतबयानी से मुक्त हैं। हमारा उद्देश्य एक ऑडिटर रिपोर्ट जारी करना भी है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत या यथोचित आश्वासन दरअसल आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि 'एसए' के अनुसार किए गए ऑडिट से किसी तथ्य संबंधी गलतबयानी का सदैव पता लग ही जाएगा, बशर्ते कि वह मौजूद हो। गलतबयानी दरअसल धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और

उसे तथ्य संबंधी गलतबयानी तब माना जाता है जब व्यक्तिगत या समग्र रूप से वे इन वित्तीय विवरण के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं (यूजर) के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हों।

'एसए' के अनुसार किए जाने वाले ऑडिट के एक हिस्से के रूप में हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान प्रोफेशनल संशय या तर्कवाद को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- हम धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण की तथ्य संबंधी गलतबयानी के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करते हैं, इन जोखिमों को कम करने में सक्षम ऑडिट प्रक्रियाओं को तैयार एवं निष्पादित करते हैं, और ऐसा ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को ठोस आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं बिल्कुल उपयुक्त होता है। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली तथ्य संबंधी गलतबयानी का पता नहीं लगा पाने का जोखिम दरअसल त्रुटि से उत्पन्न होने वाली तथ्य संबंधी गलतबयानी से जुड़े जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- हम ऑडिट के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले आंतरिक नियंत्रण की समझ विकसित करते हैं, ताकि ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके जो विभिन्न परिस्थितियों में बिल्कुल उपयुक्त होती हैं।
- हम इस्तेमाल में लाई जा चुकी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का आकलन करते हैं।
- हम प्रबंधन द्वारा 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत निकाय' से संबंधित लेखांकन आधार का उपयोग किए जाने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और यह इस प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित होता है कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित ऐसी कोई तथ्य संबंधी अनिश्चितता है जो एक 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत निकाय' के रूप में अपना संचालन निरंतर जारी रखने संबंधी इस निकाय की क्षमता पर संशय प्रकट करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तथ्य संबंधी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी ऑडिटर रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के कारण 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत निकाय' के रूप में इसका संचालन थम सकता है।

हम प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री (कंटेंट) का आकलन करते हैं। हम यह भी आकलन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करना संभव हो।

हम अन्य बातों के अलावा ऑडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश एवं सही समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जो गवर्नेंस के प्रभारी हैं। इसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसकी पहचान हम अपने ऑडिट के दौरान करते हैं।

अन्य आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हम यह बताते हैं कि :

- हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों की मांग की है और उन्हें प्राप्त किया है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं धारणा के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
- हमारी राय में, कानून के तहत आवश्यक माने जाने वाले बही–खाते को निकाय ने अब तक बिल्कुल सही ढंग से सुव्यवस्थित रखा है, जैसा कि हमारे द्वारा बही–खाते की छानबीन से प्रतीत होता है; और
- इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई बैलेंस शीट, आय एवं व्यय का विवरण और प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा–जोखा वस्तुतः बही–खाते के अनुरूप ही हैं।

के लिए, सिंह कृष्ण एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म की पंजीकरण संख्या 008714सी

ह./–
(कृष्ण कुमार सिंह)
भागीदार
एम. संख्या 077494

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 12/10/2021

यूडीआईएन : 21077494AAAAAV7759

आरआईएस

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीतिगत अनुसंधान संस्थान हैं जोकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों पर कार्य करता है। आरआईएस प्रभावशाली नीतिगत वार्ता को बढ़ावा देने एवं वैश्विक एवं क्षेत्रिय आर्थिक मामलों के संबंध में विकासशील देशों में क्षमता निर्माण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

आरआईएस की कार्य योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु दक्षिणीय सहयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय बातचीत में विकासशील देशों के साथ समन्वय करना है। आरआईएस क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के कई प्रयासों की अंतः सरकारी प्रक्रियाओं में कार्यरत है। आरआईएस अपने विचारकों के गहन कार्य के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों एवं विकास भागीदारी के पटल पर नीतिगत सुसंगतता को सुदृढ़ करता है।

आरआईएस एवं इसकी कार्ययोजना के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने क लिए कृपया इसकी वेबसाइटः wwww.ris.org.in देखें।

आरआईएस

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4—बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली—110 003, भारत । दूरभाषः 91—11—24682177—80

फैक्सः 91—11—24682173—74, ई—मेलः dgoffice@ris.org.

वेबसाइटः http://www.ris.org.in